

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



सितंबर 2021

खंड 75 अंक 9

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देबा प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितीकांत पट्टनाईक
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
तुषार बर्मन दास
पुलस्त्या बंदोपाध्याय

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

भारतीय गिल्ट बाज़ार पर विचार श्री शक्तिकांत दास	1
शासन में सुधार के माध्यम से भारत में एक अधिक आघात सहन करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली का निर्माण महेश कुमार जैन	7

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	13
क्षेत्रवार बैंक ऋण आबंटन में परिवर्तन : 2007-08 से हुई प्रगति	51
निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2020-21 में वृद्धि और 2021-22 के लिए दृष्टिकोण	61
वृद्धि पथ को दर्शाती वित्तीय समावेशन योजनाएं	75
भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक	89
वर्तमान सांख्यिकी	97
हाल के प्रकाशन	143

भाषण

भारतीय गिऒट बाज़ार पर विचार
श्री शक्तिकांत दास

शासन में सुधार के माध्यम से भारत में एक अधिक आघात सहन
करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली का निर्माण
महेश कुमार जैन

भारतीय गिल्ट बाजार पर विचार*

श्री शक्तिकांत दास

एआई सम्मेलन में शामिल होना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इस अवसर पर यह दर्ज कराना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक की दृष्टि में भारत में वित्तीय बाजारों के विकास में एफआईएमएडीए (फिन्डा) और पीडीएआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका अत्यंत सराहनीय है। दोनों संगठनों ने ब्याज दर बाजारों की गहराई और तरलता (लिक्विडिटी/चलनिधि) में सुधार करने तथा सरकार द्वारा प्राथमिक निर्गमों (प्राइमरी इश्यूएंस) को अवलंब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भूमिका

पिछले साल मई के दौरान, अपने एक वक्तव्य में मैंने कहा था कि कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है, और एक बार फिर, केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था की रक्षा के दायित्व में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना है। तब से एक साल से अधिक हो चुका है। यद्यपि उबरने के संकेत तो मिल रहे हैं, पर अभी भी इस भंवर से हम बाहर नहीं निकल पाए हैं।

महामारी के अचानक आघात के प्रत्युत्तर में त्वरित और निर्णायक नीतिगत कार्रवाइयों की आवश्यकता थी। इस पर कार्रवाई करते हुए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को कम किया, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और अन्य आस्तियों की बड़े पैमाने पर खरीद के माध्यम से अपनी बैलेंस शीटों का विस्तार किया और वित्तीय प्रणाली में बड़ी मात्रा में तरलता (चलनिधि) डाली। कई केंद्रीय बैंकों ने उन विशिष्ट बाजार क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उपायों को भी लागू किया जो अत्यधिक दबाव का सामना कर रहे थे। कई मामलों में, इन उपायों के साथ-साथ बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों से ऋण प्रवाह को सपोर्ट करने तथा वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने और वित्तीय बाजारों में विश्वास

बहाल करने के उद्देश्य से विनियामकीय छूट (कम पूंजी और चलनिधि आवश्यकताएं) प्रदान किए गए।

रिजर्व बैंक ने भी तेजी से कदम उठाए और मौद्रिक नीति, चलनिधि समर्थन और विनियमन के क्षेत्र में कई पारंपरिक, अपारंपरिक और अभिनव उपाय किए। दुनिया भर के अधिकांश ऋण प्रबंधकों की तरह रिजर्व बैंक को सरकार के अत्यधिक वर्धित ऋण कार्यक्रम का सामना करना पड़ा। विभिन्न उपायों के माध्यम से, रिजर्व बैंक ने उधार कार्यक्रम को बिना उथल-पुथल के पूरा किया और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। पूरे रेटिंग लैंडर पर क्रेडिट स्प्रेड्स के स्थिर होने से 2020-21 में ₹7.72 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किए जा सके। आज अपने संबोधन में मैं सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा जो किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह फिन्डा और पीडीएआई दोनों के लिए अत्यंत रुचि का विषय है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार की विशिष्टताएं

जी-सेक बाजार मूलतः अन्य वित्तीय बाजारों से अलग है - यह वह बाजार है जिसमें जोखिम मुक्त ब्याज दर, जो एक प्रमुख समष्टि-आर्थिक चर है, निर्धारित किया जाता है। जी-सेक प्रतिफल अधिकांश वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए मानक का में कार्य करते हैं। एक सुचारु सरकारी प्रतिभूति बाजार के बिना, वित्तीय प्रणाली कुशलता से कार्य नहीं कर सकती है।

जी-सेक बाजार की अन्य विशिष्टताएं हैं। पहला, विश्व स्तर पर जी-सेक बाजार मुख्य रूप से एक संस्थागत बाजार है, जिसमें प्रमुख प्रतिभागी बैंक और लंबी अवधि के निवेशक हैं, जिनमें निवेश फंड, बीमा फंड, सेवानिवृत्ति फंड शामिल हैं। दूसरा, विभिन्न जी-सेक लिखत अत्यधिक प्रतिस्थापन योग्य (सबस्टीट्यूटेबल) हैं तथा विभेद का एकमात्र कारक लिखतों की अवधि है। यह जी-सेक प्रतिफल कर्व को सार्वजनिक हित की वस्तु के रूप देखे जा सकने के कारणों में एक है, जैसा कि मैं जोर देता रहा हूँ। तीसरा, सरकारी प्रतिभूतियां भुगतान और निपटान प्रणाली, चलनिधि परिचालन और वित्तीय क्षेत्र के अन्य लेनदेन के

* 21वें फिन्डा - पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन में 31 अगस्त, 2021 को श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य भाषण

लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली संपार्श्विक प्रदान करती हैं। चौथा, और एक केंद्रीय बैंक के लिए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है, कि वस्तुतः सभी मौद्रिक परिचालन सरकारी प्रतिभूति बाजार में कार्यान्वित किए जाते हैं। किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संचरण मूलतः एक कुशल जी-सेक बाजार से जुड़ा हुआ है।

अब मैं इस पर प्रकाश डालूंगा कि जी-सेक बाजार को विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या थे तथा सामान्य एवं दबाव वाली अवधियों में भी रिज़र्व बैंक के लिए अपने कई दायित्वों को संतुलित करने में यह भूमिका कैसे सहायक है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की व्यापक सांविधिक संरचना के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में व्हेन इश्यूड (डबल्यू आई) ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग, रिपो लेनदेन, ब्याज दर डेरिवेटिव्स और ऐसे ही अन्य चीजों के विकास में सहायता की है। इसके अलावा, बाजारों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्ष अभिगम को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2018 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 में बाजार दुरुपयोग निवारण निदेश और 2019 में वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेशों को जारी कर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की शुरुआत की है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक ऋण के कुशल प्रबंधन और द्वितीयक बाजारों के विकास के लिए जी-सेक बाजारों हेतु कानूनी व विनियामकीय संरचना विकसित हुई है।

आपूर्ति पक्ष - ऋण के मुद्रीकरण से लेकर बाजार आधारित ऋण प्रबंधन तक

सरकारी ऋण के स्वतः मुद्रीकरण की समाप्ति, निर्गमन हेतु नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत और एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अधिनियमन से जी-सेक बाजार के विकास में काफी सहायता मिली। सुधारों का अगला चरण संस्थागत विकास की दिशा में था जिसमें प्राथमिक डीलरों (पीडी) का संस्थापन; भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) -गारंटीकृत निपटान के लिए एक केंद्रीय प्रतिपक्ष - की स्थापना और फिन्डा

(एफआईएमएमडीए) और पीडीआई जैसे बाजार निकायों का गठन शामिल था। दिसंबर 2015 से, एक मध्यावधि ऋण प्रबंधन रणनीति (एमटीडीएस) तैयार की गई है जो तीन व्यापक स्तंभों, यथा, मध्यम अवधि में कम लागत पर उधार लेना, जोखिम शमन और बाजार विकास के इर्द-गिर्द घूमती है।

सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गमन विभिन्न परिपक्वता वर्गों में किया जाता है, जिससे प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) 40 वर्षों तक का बनता है। पुनर्निर्गम द्वारा निर्गम आकार बनाने के माध्यम से द्वितीयक बाजार चलनिधि को सहायता मिलती है। परिणामी रोलओवर जोखिम प्रबंधन बायबैक/स्विच का उपयोग करके सक्रिय समेकन के माध्यम से किया जाता है।

अप्रैल, 2002 से सरकारी प्रतिभूतियों में नीलामियों के लिए कैलेंडर जारी करने की शुरुआत से आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ाई गई। नीलामी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित की जाती है, जो पारदर्शिता के साथ-साथ कुशलता सुनिश्चित करती है। मुद्रास्फीति से जुड़े बॉन्ड और फ्लोटिंग-रेट बॉन्ड सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से उत्पाद विविधता सुनिश्चित की जाती है। सरकारी नकदी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल जारी किए जाते हैं। जीरो-कूपन यील्ड कर्व के विकास को सुगम बनाने और खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार की ओर आकर्षित करने के लिए प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) जारी करने के विनियामकीय प्रावधान भी किए गए हैं। आगे चलकर, यह वांछनीय होगा कि रिज़र्व बैंक और फिन्डा और पीडीआई जैसे बाजार निकाय स्ट्रिप्स लिखत को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए मिलकर काम करें। खुदरा निवेशकों पर लक्ष्यित विशिष्ट उत्पादों में सरकारी (सॉवरिन) गोल्ड बॉन्ड (स्वर्ण में मूल्यवर्गित सरकारी प्रतिभूति) और बचत बॉन्ड भी शामिल हैं।

मांग पक्ष - विविधता के बीच सुदृढ़ता

जी-सेक बाजार में सुदृढ़ता और विविधता लाने के लिए प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में एनडीएस-ओएम पर ऑड-लॉट खंड और प्राथमिक नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगाने का प्रावधान; बैंकों/प्राथमिक डीलरों/स्टॉक एक्सचेंजों को खुदरा निवेशकों के लिए एग्रीगेटर/सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति देना; खुदरा निवेशकों के लिए उत्पादों (प्रोडक्ट्स) की

शुरूआत आदि शामिल हैं। बाजार की आधार-संरचना - एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम और एनडीएस-ओएम को जोड़कर; और आरबीआई की सब्सिडियरी जनरल लेजर सिस्टम और डिपॉजिटरी की कड़ी जोड़कर अंतरपरिचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

विदेशी निवेशकों को विवेकपूर्ण सीमाओं के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) की शुरूआत जैसे हाल के प्रयासों ने मांग पक्ष को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है। हेजिंग के साथ-साथ ट्रेडिंग के लिए ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों में अनिवासी भागीदारी की अनुमति दी गई है। विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के विनियामक ढांचे को उदार बनाया गया है ताकि निवेशकों को अपने मुद्रा जोखिम को ऑनशोर हेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विदेशी निवेशकों द्वारा 'कारोबार करने में आसानी' को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे व्यापार (ट्रेड्स) का टी+2 निपटान, लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए विस्तारित समय और बैंकों को जी-सेक व्यापारों के लिए मार्जिन को फंड करने की अनुमति देना।

बाजार आधार-संरचना - अत्याधुनिक ट्रेड और पोस्ट-ट्रेड सेवाएं

एक स्वस्थ, मजबूत और सुरक्षित बाजार आधार-संरचना बाहरी आघातों के विरुद्ध सरकारी प्रतिभूति बाजार की प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस) को बढ़ाती है और मूल्य निर्धारण में योगदान करती है। रिज़र्व बैंक ट्रेडिंग और पोस्ट ट्रेड सेवाओं से संबंधित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे को लगातार विकसित करने में लगा हुआ है, जिसमें एकमुश्त (आउटराइट) और रिपो दोनों बाजारों में निपटान, रिपोर्टिंग और व्यापारिक सूचनाओं का समय पर प्रसार शामिल है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह सकता हूँ कि भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार की आधार-संरचना को परिष्कार के मामले में अत्याधुनिक माना जा सकता है। रिज़र्व बैंक की एनडीएस-ओएम प्रणाली- जो एक अनाम ऑर्डर मिलान प्लेटफॉर्म है- कई प्रकार की कार्यात्मकताएं प्रदान करती है, जिसमें मानक और विषम मात्रा आकारों (ऑड लॉट साइज) में ट्रेडिंग और "व्हेन-इश्यूड" बाजार में ट्रेडिंग शामिल है। यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सहित अधिकांश क्षेत्राधिकारों के विपरीत है- जहाँ सरकारी बॉन्ड में ट्रेडिंग प्रधानतः बोलकर मोलभाव (वॉयस नेगोशिएटेड) के

जरिए होती है या कई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर खंडित रूप में। एनडीएस-ओएम शायद अपनी तरह का एकमात्र है क्योंकि (i) इसकी प्री और पोस्ट ट्रेड पारदर्शिता अद्वितीय है; (ii) यह एक ही ऑर्डर बुक उपलब्ध कराकर, समस्त बाजार तरलता (मार्केट लिक्विडिटी) को एकत्र करता है; और (iii) यह ट्रेडिंग में अनामिता (एनॉनिमिटी) की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार छोटे निवेशकों के लिए भी उचित और भेदभाव- रहित कीमत निर्धारण (प्राइस डिस्कवरी) सुनिश्चित करता है।

ट्रेडिंग की आधार-संरचना के पूरक के रूप में सुपुर्दगी-बनाम-भुगतान-आधारित गारंटीकृत निपटान तंत्र है जो निपटान जोखिमों को दूर करता है, बहुपक्षीय निवलीकरण (नेटिंग) के माध्यम से, चलनिधि आवश्यकताओं को कम करता है। यह भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है क्योंकि बहुत से क्षेत्राधिकारों (देशों) में सरकारी प्रतिभूतियों में एक ही स्थान पर सभी नकद और रिपो लेनदेन के लिए केंद्रीय समाशोधन की बात तो जाने दें, सरकारी प्रतिभूतियों का केंद्रीय समाशोधन (क्लीयरिंग) भी नहीं है। वास्तव में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बाजार में गड़बड़ी के हालिया प्रकरणों के बाद, केंद्रीय समाशोधन (क्लीयरिंग) को व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है।

लाइव ऑर्डर का सार्वजनिक प्रसार कर और सभी ट्रेड एनडीएस-ओएम पर निष्पादित कर प्री-ट्रेड और पोस्ट ट्रेड पारदर्शिता के उच्च स्तर सुनिश्चित किए जाते हैं। व्यापार (ट्रेड)-वार ऐतिहासिक डेटा सभी के लिए उपलब्ध है। दिन के अंत में एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक (एफबीआईएल) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के प्रकाशन से मूल्य पारदर्शिता सुधरती है।

पूरक बाजार

सरकारी प्रतिभूतियों के बाजारों को वित्तपोषण बाजारों और जोखिम बाजारों के रूप में सहायक बाजारों की जरूरत है। रिपो बाजार एक फंडिंग बाजार का कार्य करता है। इसी तरह, ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार जोखिम के प्रबंधन को सक्षम बनाता है। 2019 में ओटीसी और एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव दोनों को कवर करते हुए व्यापक निदेश जारी किए गए, जो पात्र संस्थानों, अनुमेय लिखतों, एक्सपोजर सीमा और रिपोर्टिंग के लिए नियमों का औचित्य बताते हैं। वायदा (फ्यूचर्स) और विकल्प (ऑप्शन्स) की

शुरुआत की गई है। बाजारों को गहरा और तरल (लिक्विड) बनाने के प्रयास जारी हैं।

आरबीआई और सरकारी प्रतिभूति बाजार

अब मैं रिजर्व बैंक के कार्यों के प्रभावी निर्वाह के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार की महत्ता की ओर मुड़ता हूँ। मौद्रिक नीति प्राधिकारी, प्रणालीगत तरलता के प्रबंधक, सरकारी ऋण प्रबंधक, ब्याज दर और विदेशी मुद्रा बाजारों के विनियामक, भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियामक और वित्तीय स्थिरता के पर्यवेक्षक के रूप में रिजर्व बैंक की बहुआयामी भूमिका सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार को इन दायित्वों के प्रभावी निर्वाह की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है।

घरेलू वित्तीय बाजारों के विकास और ब्याज दरों के अविनियमन के साथ, मौद्रिक नीति प्रयोजनों का प्रभावी संचरण जी-सेक बाजार के गहरे और तरल (लिक्विड) होने पर निर्भर करता है ताकि भविष्य की अल्पकालिक दरों की अपेक्षाओं को वर्तमान दीर्घकालिक दरों से जोड़कर ब्याज दरों पर इच्छित प्रभाव पैदा किया जा सके।

इसी तरह, एक सुचारु सरकारी प्रतिभूति बाजार लोक ऋण प्रबंधन कुशलतापूर्वक सुनिश्चित करता है। लोक ऋण संरचना अर्थात् मात्रा, गठन और ऋण का स्वामित्व भी मौद्रिक स्थितियों को प्रभावित करती है। महामारी के मद्देनजर की गई राजकोषीय कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जब सरकारी उधार में तेज वृद्धि हुई, रिजर्व बैंक द्वारा किए गए बाजार संचालन ने न केवल उधार कार्यक्रम के गैर-विघटनकारी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया, बल्कि प्रतिफल वक्र के स्थिर और व्यवस्थित विकास को भी सुगम बनाया। इसलिए, मौद्रिक नीति, सरकारी प्रतिभूति बाजार विनियमन और लोक ऋण प्रबंधन को घनिष्ठ समन्वय में संचालित करने की आवश्यकता है, और इस तरह के समन्वय में मुख्यतः सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार पर ध्यान दिया जाता है।

रिजर्व बैंक के पास रहने वाले सरकारी प्रतिभूति भंडार (जी-सेक रिपॉजिटरी) की वर्तमान व्यवस्थाएं निर्बाध चलनिधि परिचालन और सरकारी प्रतिभूति व्यापार के साथ-साथ निपटान की सुविधा प्रदान करती है। यह निवेशकों को विश्वास प्रदान करता है, अभिरक्षा जोखिम को दूर करता है और लेनदेन की लागत को कम करता है। बाजार की आधार-संरचना के स्वामित्व/निगरानी से हासिल होने वाली तत्काल बाजार आसूचना (रीयल-टाइम

मार्केट इंटेलिजेंस) नीति प्रतिक्रियाओं में समय पर अपेक्षित समायोजन के लिए महत्वपूर्ण है।

रिजर्व बैंक द्वारा जी-सेक बाजार के विनियमन का बैंकिंग विनियामक के रूप में अपनी भूमिका के साथ एक मजबूत तालमेल भी है - क्योंकि बैंक इन बाजारों में प्रतिभागियों की सबसे बड़े वर्ग हैं। इस पक्ष के महत्व पर हाल की जी30 रिपोर्ट में भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें अमेरिकी ट्रेजरी बाजारों के खंडित विनियमन की पहचान की गई है, जहाँ बैंकिंग विनियमों का बाजार-निर्माण (मार्केट मेकिंग) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है।

सरकारी प्रतिभूतियों के लिए वर्तमान विनियामक व्यवस्था से निम्नलिखित सहक्रियाजन्य लाभ मिलते हैं: सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एकीकृत बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो, चलनिधि और अन्य मौद्रिक परिचालन, विनियम दर प्रबंधन, प्रमुख डेरिवेटिव बाजारों का विनियमन, लोक ऋण प्रबंधन और बाजार सहभागियों में सबसे बड़े वर्ग बैंकों का विवेकसम्मत विनियमन। प्रमुख समष्टि बाजार चरों (मैक्रो मार्केट वेरिएबल्स) - समग्र वित्तीय बाजार सक्षमता सुनिश्चित करने वाले ब्याज दरों और विनियम दरों - के संबंध में रिजर्व बैंक के दायित्व और वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्थिरता सुनिश्चित करने की अपनी जवाबदेही के बीच सहक्रियाजन्य लाभ को अच्छी स्वीकृति प्राप्त है। दरअसल, विदेशी मुद्रा और ब्याज दर बाजारों में दबाव का प्रभावी प्रबंधन जी-सेक बाजार में सीधी पहुँच और निगरानी से संभव हो पाता है।

भविष्य की कार्यसूची

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में बकाया स्टॉक के संदर्भ में देखें तो, भारतीय सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार का आकार अधिकांश एशियाई समकक्षों की तुलना में बड़ा है। 2019 बीआईएस के एक अध्ययन¹ के अनुसार, भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के लिए औसत बोली-प्रस्तावित दर (बिड-आस्क स्प्रेड) के माध्यम से मापी गई तरलता (लिक्विडिटी) सर्वश्रेष्ठ में से एक है। सरकारी प्रतिभूति बाजार ने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास के लिए एक मजबूत रीढ़ भी प्रदान की है।

भारत में जी-सेक बाजार के अच्छे विकास के बावजूद, उभरती आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए

¹ <https://www.bis.org/publ/cgfs62.pdf>

और विकास की गुंजाइश है। सबसे पहले, टर्नओवर अनुपात द्वारा मापी जाने वाली द्वितीयक बाजार तरलता, (सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी) कई अवसरों पर अपेक्षाकृत कम पाई जाती है और कुछ प्रतिभूतियों और अवधियों में केंद्रित रहती है। प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) तदनुसार व्याकुंचन (किंक) दर्शाता है, जो चुनिंदा प्रतिभूतियों/अवधियों को मिलने वाले चलनिधि प्रीमियम का सूचक है। कुछ हद तक, यह भारत में बाजार व्यष्टि-संरचना का परिणाम है, जिस पर 'खरीद और धारण' (बाइ एंड होल्ड) और 'केवल अधिग्रहण' ('लॉन्ग ओनली') निवेशकों का वर्चस्व है। हमें एक ऐसा प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) विकसित करने की जरूरत है जो सभी अवधियों में तरल हो।

दूसरा, निवेशक आधार का विस्तार बाजार के आगे के विकास की कुंजी है। सरकार के साथ मिलकर आरबीआई यह प्रयास कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति भंडार [इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्क्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ (आईसीएसडी)] के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन का अंतरराष्ट्रीय निपटान हो सके। यह प्रारंभ हो जाए तो, इससे गैर-निवासियों की सरकारी प्रतिभूति बाजार में पहुँच बढ़ेगी, जैसा कि वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (इंडियन जी-सेक) के शामिल होने से होगा, जिसके लिए प्रयास जारी हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, आरबीआई ने 'रिटेल डायरेक्ट' योजना की घोषणा की है, जो व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए एक-ठौरी (वन-स्टॉप) समाधान है।

तीसरा, बढ़ती ब्याज दरों की अवधि के दौरान या अनिश्चितता के समय में सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में तरलता (लिक्विडिटी) सूखने लगती है। 'विशेष रिपो' के लिए बाजार यद्यपि प्रतिभूतियों के उधार की सुविधा प्रदान करता है, उचित होगा कि अन्य विकल्पों को भी देखा जाए जो विभिन्न परिपक्वताओं में बाजार में प्रतिभूतियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। स्मरण हो कि 'खरीद और धारण' ('बाइ एंड होल्ड') प्रकार (जैसे, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड) के निवेशकों को अन्य बाजार सहभागियों को अपनी प्रतिभूतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित कराकर द्वितीयक बाजार चलनिधि (सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी) बढ़ाने के लिए प्रतिभूति उधार लेने-देने की व्यवस्था [सिक्क्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बॉरोइंग मैकेनिज्म (एसएलबीएम)] शुरू करने पर चर्चाएं हुई थीं। इस विषय पर फिमडा और पीडीएआई से उपयोगी राय मिली थी।

मैं आग्रह करूँगा कि इन चर्चाओं को ऐसी बाजार आधारित व्यवस्थाओं को विकसित करने की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए जो बाजार के समग्र विकास के अंग के रूप में प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने में सहायक हों।

चौथा, ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) बाजार ने विगत वर्षों में अपने विकास क्रम में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है। हालांकि, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट (मिबॉर) आधारित ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (ओआईएस) बाजार एकमात्र प्रमुख तरल/चलनिधि उत्पाद बना हुआ है। आईआरडी बाजारों में भागीदारी भी काफी हद तक विदेशी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और प्राथमिक डीलरों तक ही सीमित है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के आधार पर, एफआईएमएमडीए (फिमडा) ने बाजार सहभागियों के परामर्श से ट्रेड-इन स्वैपशन्स के लिए परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए और स्वैपशन्स में ट्रेडिंग शुरू हो गई है। बीमा कंपनियों, भविष्य निधि और पेंशन फंड और कॉरपोरेट्स जैसे बाजार सहभागियों द्वारा दीर्घकालिक ब्याज दर और पुनर्निवेश जोखिम की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) में सहायक नए उपकरणों पर विचार करने का भी यह एक उपयुक्त समय है। अपनी ओर से, रिजर्व बैंक प्रणाली में सुविधाजनक चलनिधि स्थिति बनाए रखने के अपने प्रयास के एक अभिन्न अंग के रूप में सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 6 अगस्त, 2021 के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, मैंने 6 फरवरी, 2020 को घोषित संशोधित चलनीधि प्रबंधन ढाँचे के तहत मुख्य संचालन के रूप में परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामी की क्रमिक बहाली के लिए एक रूपरेखा बताई थी। जैसे-जैसे बाजार नियमित समय पर व्यवस्थित हो जाते हैं तथा कामकाज और चलनिधि संचालन सामान्य हो जाता है, इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अप्रत्याशित और एकमुश्त चलनिधि प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए रिजर्व बैंक समय-समय पर समायोजन वाले कार्य (फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशन्स) भी करेगा ताकि प्रणाली में चलनिधि स्थितियां संतुलित और समानतः वितरित रूप में विकसित हों।

निष्कर्ष

सरकारी प्रतिभूतियां एक पृथक प्रकार का आस्तित्व वर्ग हैं। अर्थव्यवस्था के समग्र समष्टि ब्याज दर परिवेश में सरकारी प्रतिभूति बाजार की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। इधर कुछ वर्षों में, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार और संबद्ध बाजार

आधार-संरचना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माने जा सकने वाले चरण में पहुँच गए हैं। ये घटनाक्रम अन्य प्रमुख वित्तीय बाजारों जैसे कि ब्याज दर डेरिवेटिव व विदेशी मुद्रा बाजारों को विकसित व उदार करने के प्रयासों के तथा विभिन्न बाजारों एवं बाजार

आधार - संरचना में संबंध बनाने के प्रयासों के साथ हुए हैं। देश में वित्तीय बाजारों के विकास में हमने अच्छी प्रगति की है, लेकिन यह एक अनवरत चलने वाली यात्रा है और हम साथ मिलकर इसे और भी मजबूत और जीवंत बना सकते हैं।

धन्यवाद।

शासन में सुधार के माध्यम से भारत में एक अधिक आघात सहन करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली का निर्माण*

महेश कुमार जैन

देवियों और सज्जनों। हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले, मैं एक आघात सहन करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली के निर्माण पर इस बहुत महत्वपूर्ण सत्र की मेजबानी करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को धन्यवाद देता हूं, जब स्वयं समाज की आघात सहन करने की क्षमता कोविड -19 महामारी द्वारा जाँची जा रही है। व्यापक स्तर पर आघात सहन करने की क्षमता को खतरों का सामना कर रही किसी प्रणाली, समुदाय या समाज की ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समय पर और कुशल तरीके से उन खतरों का सामना करती है, उन्हें अवशोषित करती है, समायोजित करती है और उस खतरे के प्रभावों से उबरती है और साथ ही अपनी आवश्यक बुनियादी संरचनाएं और कार्य¹ का संरक्षण और बहाली भी करती है। मुझे विश्वास है कि हम एक देश के रूप में हम बहुत जल्द ही कोविड-19 के प्रभावों का सामना करेंगे, इसे आत्मसात करेंगे, समायोजित करेंगे और इससे उबर जाएंगे।

वित्तीय प्रणाली के आघात सहन करने की क्षमता का अर्थ

वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में, एक आघात सहन करने वाली वित्तीय प्रणाली वह है जो अंतर्जात झटकों के प्रभाव को अवशोषित करने में सक्षम है, जो मूल स्थिति में जल्दी से वापस आती है या नए वातावरण के अनुकूल होती है, और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अपनी भूमिका को जारी रखती है। आघात सहन करने वाली वित्तीय प्रणाली की यह परिभाषा एक स्थिर वित्तीय प्रणाली से अलग है। एक स्थिर वित्तीय प्रणाली वह होती है जो आघातों को अवशोषित करने में समर्थ है जबकि, एक आघात सहन करने वाली वित्तीय प्रणाली आघात के प्रतिउत्तर में इसे अवशोषित करने के अलावा स्वयं को अनुकूलित और समानुरूप बनाने में सक्षम होती है²। सीधे शब्दों में,

* 18 जून, 2021 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री महेश कुमार जैन द्वारा दिया गया भाषण।

¹ आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर यूएनआईएसडीआर शब्दावली, आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर-राष्ट्रीय रणनीति, जिनेवा, स्विट्जरलैंड (2009)।

² मार्क वेल्श, रिसिलिएन्स एंड रिस्पोन्सिबिलिटी : गवर्निंग अंसर्टेनिटी इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, 180 जियोग्राफिकल जे. 15, 20 (2014)।

“..एक मजबूत प्रणाली को 100-वर्ष में एक बार होने वाली घटना का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, उदाहरण के लिए, जोखिम प्रबंधन में उपयोग किया जाने वाला दृष्टिकोण। इसके विपरीत आघात सहन करने की क्षमता संभावित आघात की भयावहता के बारे में कोई धारणा नहीं बनाती है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने की कोशिश करती है जो ऐसे आघातों की पूरी श्रृंखला से निपट सकें..”³

इस प्रकार, हमारे प्रयासों को एक ऐसी वित्तीय प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित होना चाहिए जो न केवल स्थिर हो, बल्कि लचीली भी हो, क्योंकि आघात के प्रकार, स्रोत, परिमाण और आवृत्ति अत्यधिक अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण डिग्री तक गैर-मापनीय हो रहे हैं। तदनुसार, वित्तीय प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि वित्तीय प्रणाली के साथ-साथ व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान न केवल आघात को सहने में सक्षम हैं, बल्कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम हैं।

अब, मैं कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक/सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं, जिन्हें अगर उचित तरीके से संभाला जाए, तो आघात सहन करने की क्षमता में जबरदस्त सुधार करने की क्षमता है।

नैतिक खतरा और आघात सहन करने की क्षमता

नैतिक जोखिम, बल्कि नैतिक जोखिम का अभाव, एक आघात सहन करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बैंक एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के निर्माण में निवेश क्यों करेगा यदि उसे यह पता हो कि जब आघात लगने पर करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल उन्हें बचाने के लिए किया जाएगा? बैंक के शेयरधारकों को बैंक के प्रबंधन से बेहतर प्रशासन और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं की तलाश करने के लिए प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब उनका निवेश जोखिम में हो। एक आघात सहन करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली के निर्माण के लिए मुनाफे का निजीकरण और नुकसान का समाजीकरण अनैतिक है। इसी तरह, एक बैंक के कर्मचारियों को भी इससे असर पड़ना चाहिए।

³ मैरी डॉवेल-जोन्स और रॉस बकले, रि कॉन्सीविंग रेजिलिएंस: ए न्यू गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन?, 37 एनडब्ल्यू जे अंतरराष्ट्रीय एल और बसा 1 (2017)। <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss1/>

आघात सहन करने की क्षमता एक सामूहिक प्रयास है

एक आघात सहन करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली का निर्माण एक सामूहिक प्रयास है और इसे केवल नियामकों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। जहां नियामक उपयुक्त विनियम बनाकर मुख्य रूप से योगदान करते हैं, वहीं बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन के लिए एक टिक बॉक्स दृष्टिकोण का अर्थ होगा कि बाजार की समझदारी को नियामक की समझदारी से बदल दिया गया है। विनियम सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान करते हैं। इसलिए, एक आघात सहन करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली के लिए सभी हितधारकों के योगदान की आवश्यकता होती है और बाजार अनुशासन (अर्थात्, जमाकर्ताओं द्वारा अनुशासन, उधारकर्ताओं द्वारा अनुशासन और निवेशकों द्वारा अनुशासन) एक आघात सहन करने की क्षमता वाली वित्तीय प्रणाली को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त है।

लेमन प्रॉबलम - सूचना विषमता

वित्तीय प्रणाली में आघात सहन करने की क्षमता के निर्माण और ऋण प्रवाह में सुधार की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता 'लेमन प्रॉबलम' की घटनाओं को कम करना है, जिसके लिए उधारकर्ता स्तर पर भी शासन में सुधार की आवश्यकता होगी। यदि ऋणदाता अच्छी गुणवत्ता और खराब गुणवत्ता (लेमन) के उधारकर्ताओं के बीच अंतर नहीं कर सकता है, तो वह केवल ब्याज दर पर ऋण देगा जो अच्छे और बुरे उधारकर्ताओं की औसत गुणवत्ता को दर्शाता है। नतीजा यह है कि उच्च गुणवत्ता वाले उधारकर्ताओं को उनकी तुलना में अधिक ब्याज दर का भुगतान करना होगा क्योंकि निम्न-गुणवत्ता वाले उधारकर्ताओं की तुलना में उन्हें कम ब्याज दर का भुगतान करना चाहिए। इस लेमन प्रॉबलम का एक परिणाम यह है कि कुछ उच्च गुणवत्ता वाले उधारकर्ता बाजार को छोड़ सकते हैं जो आरंभ न की गई लाभदायक निवेश परियोजनाएं होतीं। 'लेमन प्रॉबलम' भी बैंकों की अपने पोर्टफोलियो में जोखिम निर्माण को पहचानने की क्षमता को बाधित करती है। उधारकर्ता संभवतः सबसे पहले अपने संबंधित खंड में कठिनाइयों के शुरुआती संकेत देखते हैं। जब वे अपने उधारदाताओं को जानकारी नहीं देते हैं, इस डर से कि ऋणदाता नए ऋणों को अस्वीकार कर सकता है या मौजूदा ऋणों की शर्तों को कड़ा कर सकता है, तो उधारदाताओं की जोखिम को जल्दी पहचानने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित होती है।

⁴ फ्रेडरिक एस. मिशिकन, एसीमेट्रिक इन्फोर्मेशन एंड फिनेंसियल क्राइसिस : ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फाइनेंसियल मार्केट्स एंड फिनेंसियल क्राइसिस (1991); <https://www.nber.org/system/files/chapters/c11483/c11483.pdf>

आघात सहन करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उपकरण

आघात सहन करने की क्षमता की अवधारणा की व्याख्या करने के बाद, मैं वित्तीय प्रणाली में आघात सहन करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों के बारे में बात करूंगा। आघात सहन करने की क्षमता के 3ए मॉडल की अवधारणा यद्यपि, मूल रूप से जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में की गई थी, यह एक उपयोगी टेम्पलेट प्रदान करता है। आघात सहन करने की क्षमता के 3ए हैं: प्रत्याशित क्षमता, अवशोषण क्षमता और अनुकूलन करने की क्षमता ⁵। प्रत्याशित क्षमता को वित्तीय प्रणाली और उसके घटकों की क्षमता के रूप में माना जा सकता है ताकि वे जल्द से जल्द उभरते जोखिमों को पहचान सकें और माप सकें और सुधारात्मक कार्रवाई करके जोखिमों को कम कर सकें। अवशोषण क्षमता उन नुकसानों को झेलने की क्षमता है जो आघात के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और जिन्हें कम नहीं किया जा सकता या टाला नहीं जा सकता है। अनुकूलन करने की क्षमता नई वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है, चाहे वह बदली हुई नियामक/आर्थिक स्थिति हो या एक नया प्रतिस्पर्धी परिदृश्य।

आघात सहन करने की क्षमता के आयाम

वित्तीय प्रणाली के आघात सहन करने की क्षमता का परीक्षण कई आयामों से किया जा सकता है, जैसे, वित्तीय जोखिम, परिचालन और तकनीकी जोखिम, प्रतिस्पर्धी जोखिम, जलवायु जोखिम आदि, और वित्तीय प्रणाली को उसी का अनुमान लगाने, अवशोषित करने और अनुकूल करने की आवश्यकता होती है।

वित्तीय आघात सहन करने की क्षमता

संकट के बाद और किसी संकट के दौरान वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाने और उसे अवशोषित करने की बैंकों की क्षमता शोधक्षम बनी रहती है और उधार देने की उनकी क्षमता को बनाए रखना वित्तीय आघात सहन करने की क्षमता का एक उपाय है। रिजर्व बैंक सूक्ष्म-विवेकपूर्ण विनियमों का एक सेट निर्धारित करके, जैसे कि न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं, अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान मानदंड, चलनिधि मानदंड, आदि निर्धारित करके उन संस्थानों के वित्तीय आघात सहन करने की क्षमता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है जो इसके द्वारा विनियमित होते हैं। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक भी सिस्टम स्तर के जोखिम

⁵ बहादुर, आदित्य वी., पीटर्स, केटी, विल्किंसन, एमिली, पिचोन, फ्लोरेंस और ग्रे, कस्टी; द 3ए: ट्रैकिंग रेजिलिएशन एक्रॉस ब्रंडा लंदन: विदेशी विकास संस्थान (2015)।

निर्माण होने पर मैक्रो-विवेकपूर्ण उपायों का सहारा लेता है, जिसे अलग-अलग संस्थानों के आघात सहन करने की क्षमता के उद्देश्य से सूक्ष्म-विवेकपूर्ण नियमों द्वारा पूरी तरह से कब्जा नहीं किया जा सकता है।

जबकि विवेकपूर्ण मानदंडों का उद्देश्य व्यक्तिगत संस्थानों के साथ-साथ समग्र रूप से वित्तीय प्रणाली की अवशोषण क्षमता में सुधार करना है, बैंकों में जोखिम प्रशासन में सुधार करके बैंकों की प्रत्याशित क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। वित्तीय संस्थानों के जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए जोखिमों की शीघ्र पहचान करने और उन्हें उचित सटीकता के साथ मापने में सक्षम होने के लिए सुदृढीकरण की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में मौजूदा जोखिमों के चल रहे विश्लेषण के साथ-साथ नए या उभरते जोखिमों की पहचान शामिल होनी चाहिए, क्योंकि वित्तीय प्रणाली के समक्ष पेश आ रहे जोखिम बदलते हैं⁶। बैंक, जो दूसरों से पहले जोखिम का अनुमान लगाने में सक्षम हैं, ऐसी पूंजी जुटाने की लागत कम होने पर भी दूसरों से आगे पूंजी जुटाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, बेहतर जोखिम पहचान क्षमता वाले बैंक अपनी पूंजी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पुनर्गणना करने और पूंजी को अधिक कुशल तरीके से उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं।

वर्तमान और उभरते जोखिमों की पहचान करने के अलावा, वित्तीय संस्थाओं को विभिन्न गंभीर लेकिन संभावित परिदृश्यों के तहत अपने जोखिम को मापने के लिए तनाव परीक्षण भी करना चाहिए। दबाव परीक्षण को संभावित कार्रवाइयों जैसे जोखिम न्यूनीकरण तकनीकों, आकस्मिक योजनाओं, दबावग्रस्त परिस्थितियों में पूंजी और चलनिधि प्रबंधन आदि के संदर्भ में उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।

जबकि व्यक्तिगत वित्तीय संस्थानों की प्रत्याशित और अवशोषित क्षमता प्रणाली स्तर पर उनके आघात सहन करने की क्षमता को बढ़ाती है, रिजर्व बैंक ने अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया में सुधार करके अपनी स्वयं की प्रत्याशित क्षमता को भी बढ़ाया है।

परिचालन और तकनीकी आघात सहन करने की क्षमता

कोविड -19 फैल गया और सामाजिक गड़बड़ी और लॉक-डाउन उपायों सहित महामारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं ने वित्तीय प्रणाली के परिचालन और तकनीकी

आघात सहन करने की क्षमता का परीक्षण किया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि, यह बहुत संतोष की बात है कि रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों दोनों ने जबरदस्त परिचालन आघात सहन करने की क्षमता दिखाया और व्यापार निरंतरता योजनाओं को लागू करके आम जनता के लिए वित्तीय सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की। रिजर्व बैंक ने सुनिश्चित किया कि भुगतान प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है और दैनिक आधार पर डिजिटल बैंकिंग चैनलों की उपलब्धता की निगरानी भी करता है।

प्रौद्योगिकी पर वित्तीय संस्थानों की बढ़ती निर्भरता के संबंध में एक और समान रूप से महत्वपूर्ण गतिविधि, यद्यपि यह महामारी की तरह अचानक नहीं आया है, का आघात सहन करने की क्षमता अब वित्तीय आघात सहन करने की क्षमता के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, यदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं।

महामारी से पहले भी, रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थानों की साइबर आघात सहन करने की क्षमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रिजर्व बैंक विभिन्न प्रमुख साइबर जोखिम संकेतकों का उपयोग करके प्रत्येक बैंक के लिए साइबर जोखिम स्कोर निर्धारित करता है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा ढांचा, तीसरे पक्ष के एटीएम स्विच प्रदाताओं के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण, भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) निर्देश 2021, जिसका उद्देश्य सिस्टम की साइबर आघात सहन करने की क्षमता में सुधार करना है। साइबर आघात सहन करने की क्षमता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने के लिए बैंकों के शीर्ष प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, बोर्ड के पदाधिकारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा पर प्रमाणन/जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य किया गया था।

प्रतिस्पर्धी आघात सहन करने की क्षमता

यहाँ तक कि बैंकों की तकनीक पर निर्भरता तेजी से बढ़ी है, प्रौद्योगिकी भी वित्तीय प्रणाली में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में क्रांति ला रही है। बैंकों के पारंपरिक डोमेन में बिगटेक फर्मों और नवीन फिनटेक खिलाड़ियों के प्रवेश ने वित्तीय लेनदेन करने के तरीके में पहले ही क्रांति ला दी है। बैंकिंग सेवाओं को अलग करना एक वास्तविकता है और इससे बैंकों के काम करने का तरीका बदल जाएगा। यह बैंकों और अन्य पारंपरिक वित्तीय फर्मों की अनुकूलन क्षमता का परीक्षण करेगा। जब तक पारंपरिक फर्में व्यवसाय करने

⁶ बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति, बैंकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांत (जुलाई 2015)।

के नए तरीकों को नहीं अपनाती हैं, वे बहुत जल्द हाशिए पर जा सकती हैं।

तथापि, भले ही अलग-अलग संस्थाएँ नए प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के अनुकूल हों, लेकिन सिस्टम स्तर पर यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि विविधता बनी रहे। यदि अंतर्निहित आर्थिक स्थितियाँ बदलती हैं तो एक समरूप वित्तीय प्रणाली कम आघात सहन करने की क्षमता वाली होगी और प्रणालीगत संकट की संभावना होगी। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय प्रणाली में ऐसी संस्थाएँ हों जो व्यवसाय करने के नए तरीकों को अपनाते हुए भी विभिन्न व्यावसायिक मॉडल का पालन करें।

जलवायु आघात सहन करने की क्षमता

वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु एक प्रमुख जोखिम चालक के रूप में तेजी से उभर रहा है। जबकि बीमा कंपनियाँ सीधे तौर पर जलवायु जोखिम का सामना करती हैं, बैंकों को भी जलवायु जोखिम को अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है। जलवायु जोखिम दो व्यापक चैनलों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, भौतिक जोखिम (विशिष्ट मौसम की घटनाओं और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न) और संक्रमण जोखिम (जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए किए गए प्रयासों से उत्पन्न)। नतीजे में प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों में उधारकर्ताओं की संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट शामिल हो सकती है; जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकारी/सामाजिक प्रतिक्रिया के कारण व्यवसाय मॉडल पर प्रभाव; और दीर्घावधि चलनिधि प्रभाव⁷।

प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और जलवायु चरम सीमाओं का बैंकों के परिचालन आघात सहन करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों और डेटा केंद्रों पर बढ़ती निर्भरता के संदर्भ में। जलवायु जोखिम का आकलन करने और उसे कम करने की निरंतर आवश्यकता है। जलवायु चरम सीमाओं से उत्पन्न होने वाले परिचालन जोखिमों को कम करने के अलावा, देश की विकासात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भी, हरित वित्तपोषण की ओर

बढ़ने के लिए वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता है।

आघात सहन करने की क्षमता और शासन

मेरे विचार में, इन तीन क्षमताओं (प्रत्याशित क्षमता, अवशोषण क्षमता और अनुकूलन क्षमता) के मूल में क्या निहित है, जो एक इकाई के आघात सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है, एक सुशासन ढांचा है। प्रायः, अत्यधिक जोखिम एक्सपोजर, क्रेडिट घाटा, चलनिधि की समस्याएं और पूंजीगत खामियां कॉर्पोरेट प्रशासन में कमजोरी और प्रतिपूर्ति नीतियों और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण के उत्पन्न होती हैं⁸। जबकि उच्च गुणवत्ता वाला शासन जोखिमों के खिलाफ एक विश्वसनीय बचाव के रूप में कार्य करता है, पिछले अनुभव से पता चलता है कि कॉर्पोरेट प्रशासन में कमजोरी वित्तीय प्रणाली की विफलता का कारण बन सकती है और वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकती है। कई पूछताछ और अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन में कमजोरियां थीं। दुनिया ने शासन संरचनाओं की विफलता भी देखी, जिसने ब्याज दर बेंचमार्क सेटिंग प्रक्रिया के ओवरहाल को जरूरी बना दिया। यह देखते हुए कि भविष्य की कमजोरियों के स्रोतों की भविष्यवाणी करना कठिन है, बैंकों को उभरते जोखिमों और फर्म पर उनके संभावित प्रभाव को पहचानने और समझने के लिए जोखिम प्रशासन और प्रबंधन के मजबूत ढांचे की आवश्यकता है। बिजनेस लाइनों, मार्केट प्रेक्टिस और वित्तीय प्रौद्योगिकी जो बैंकों के प्रशासन और जोखिम प्रबंधन का परीक्षण कर सकती है, में चल रहे परिवर्तन को देखते हुए यह बैंक की आघात सहन करने की क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है⁹।

इसके अलावा, निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया में कॉर्पोरेट प्रशासन तेजी से एक प्रमुख कारक है। खराब कॉर्पोरेट प्रशासन को अक्सर मुख्य कारणों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है क्यों निवेशक कुछ बाजारों में कंपनियों में निवेश करने के लिए अनिच्छुक या तैयार नहीं हैं। इससे यह भी समझा सकता है कि क्यों, कुछ अर्थव्यवस्थाओं में, कई कंपनियों के शेयर अपने

⁸ बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति, कमजोर बैंकों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए दिशानिर्देश, जुलाई 2015।

⁹ सीजीएफएस पेपर नंबर 60, संकट के बाद बैंकिंग में संरचनात्मक परिवर्तन, 2018।

⁷ भारतीय रिजर्व बैंक, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, अगस्त 2020।

वास्तविक मूल्य से काफी छूट पर बीचे जाते हैं। यहां तक कि बेहतर शासित कंपनियों को "टार्ड विथ दी सेम ब्रश" किया जाता है, जो कि संबन्धित होने के कारण अपराध बोध का मामला है¹⁰। इस प्रकार, बैंकों की पूंजी जुटाने की क्षमता, जो उनकी अवशोषण क्षमता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी इसकी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं की ताकत का एक कार्य है।

वित्तीय मध्यस्थों में अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन भी संसाधनों के आवंटन और हितधारकों के हितों (जमाकर्ताओं, अन्य ग्राहकों, शेयरधारकों, आदि) के संरक्षण में दक्षता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

शासन की गुणवत्ता काफी हद तक दो तत्वों पर निर्भर करती है - शासन संरचना और संस्कृति। हालांकि सरकार या रिजर्व बैंक के लिए यह संभव है कि किसी बैंक के भीतर शासन संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए कानून/विनियम बनाए जाएं, उपयुक्त संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसे कानून नहीं बनाया जा सकता है। बैंकों और बोर्डों को संगठनों के भीतर वांछित संस्कृति विकसित करनी होगी। एक बेहतर जोखिम संस्कृति प्रभावी जोखिम प्रबंधन, बेहतर जोखिम उठाने को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उभरते जोखिमों या जोखिम उठाने की गतिविधियों, मान्यता प्राप्त मूल्यांकन, परिवर्धित और एक समय पर ढंग से संबोधित कर रहे¹¹। जबकि संस्कृति किसी संगठन के भीतर निर्णय लेने को प्रभावित करती है, इसका आकलन करना कठिन है। फिर भी, बैंकों के भीतर जोखिम संस्कृति का आकलन करने और मूल्यांकन को बैंकों की पर्यवेक्षी रेटिंग में शामिल करने के लिए एक संरचित ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए। फोकस बैंक के मानदंडों, नजरिए और जोखिम के प्रति जागरूकता, रिस्क स्टेकिंग और जोखिम प्रबंधन से संबंधित व्यवहार पर है¹²।

शासन के ढांचे का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व, जिसका वित्तीय

संस्थानों के आघात सहन करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, वह है प्रतिपूर्ति नीतियां। एक क्षतिपूर्ति संरचना, जो दीर्घकालिक जोखिम या नकारात्मक एक्स्टर्नलिटीज़ पर विचार किए बिना अल्पकालिक जोखिम लेने को पुरस्कृत करती है, व्यक्तिगत संस्थानों के आघात सहन करने की क्षमता के साथ-साथ प्रणालीगत आघात सहन करने की क्षमता को भी खतरे में डाल सकती है।

साथ ही, अपर्याप्त प्रतिपूर्ति का वित्तीय संस्थानों के शीर्ष/वरिष्ठ प्रबंधन को वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न आघातों का अनुमान लगाने, अवशोषित करने और अनुकूलन करने की क्षमता विकसित करने में वित्तीय संस्थानों के शीर्ष/वरिष्ठ प्रबंधन को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं करने का भी प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष निकालने के लिए, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है कि भारत और अन्य न्यायालयों में वित्तीय प्रणालियों में परिचालन वातावरण में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है, जो बदलते प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, स्वचालन और बढ़ती नियामक / पर्यवेक्षी अपेक्षाओं की विशेषता है। जोखिमों का स्रोत, प्रकृति, आवृत्ति और परिमाण भी लगातार बदल रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों में शासन में सुधार और उन्हें अधिक लचीला बनाने के लिए विभिन्न नियम बनाए हैं। इसके अलावा, बैंकों ने अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में भी सुधार किया है। फिर भी, बदलते परिचालन और जोखिम के माहौल के लिए बैंकों को सतर्क, मजबूत और चुस्त रहने की आवश्यकता है ताकि जोखिमों की जल्द पहचान हो सके, आघात सह सकें और नई जमीनी वास्तविकताओं के अनुकूल हो सकें। मुझे उम्मीद है कि भारत में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान चुनौती का सामना करेंगे, अपनी आघात सहन करने की क्षमता प्रदर्शित करते रहेंगे और 5 ट्रिलियन और उससे आगे की अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम होंगे।

¹⁰ निक ब्रैडली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस: ए रिस्क वर्थ मेजरिंग?, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चयनित मुद्दे: क्षेत्रीय और देश के अनुभव, अंकटाड, 2003

¹¹ वित्तीय स्थिरता बोर्ड (अप्रैल 2014), जोखिम संस्कृति पर वित्तीय संस्थानों के साथ पर्यवेक्षी बातचीत पर मार्गदर्शन

¹² आईबीआईडी

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

क्षेत्रवार बैंक ऋण आबंटन में परिवर्तन : 2007-08 से हुई प्रगति

निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2020-21 में वृद्धि और
2021-22 के लिए दृष्टिकोण

वृद्धि पथ को दर्शाती वित्तीय समावेशन योजनाएं

भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

महामारी से बचने की गति प्राप्त कर रही अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं उज्ज्वल हो रही हैं क्योंकि दूसरी लहर खत्म हो गई है और भविष्य के लिए तैयारी युद्ध के लिए सचेत होने जैसी है। कुल मांग मजबूत हो रही है, जबकि आपूर्ति पक्ष पर, आईआईपी और मुख्य उद्योग औद्योगिक गतिविधि में सुधार को दर्शाते हैं और सेवा क्षेत्र के संकेतक निरंतर सुधार की ओर इशारा करते हैं। मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र अपेक्षा से अधिक अनुकूल रूप से नीचे जा रहा है। जैसे जैसे महामारी का असर कम होता है और उत्पादकता लाभ के साथ आपूर्ति की स्थिति बहाल हो जाती है, कोर मुद्रास्फीति की निरंतर सहजता की उम्मीद की जा सकती है, जो मौद्रिक नीति के विकास-समर्थक रुख को सुदृढ़ करेगी।

भूमिका

एसओई के अगस्त अंक में, हमने हवा के रुख को भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर भांपते हुए, श्रवण के महीने की शुरुआत की। इसने आनंद से लेकर अपमान तक कई तरह की भावनाओं को जन्म दिया। इन सब में, अगस्त माह कैसा रहा! नए संक्रमण और मृत्यु दर में काफी गिरावट आई और टीकाकरण ने महीने के अंत तक 1.33 करोड़ के दैनिक स्तर के रिकॉर्ड को छूने के लिए कदम उठाया। अगस्त के अंत तक खरीफ की बुवाई सामान्य बुवाई क्षेत्र से अधिक हो गई, इसके बाद सितंबर में वर्षा का पुनरुद्धार हुआ। संभावना है कि इस साल 2020-21 का रिकॉर्ड बुवाई कवरेज भी पार हो जाएगा। मुख्य उद्योगों के उत्पादन के आधार पर, औद्योगिक उत्पादन पूर्व-महामारी के स्तर पर बंद हुआ - जुलाई 2021 का सूचकांक जुलाई 2019 में अपने स्तर से सिर्फ 0.3 प्रतिशत नीचे है खनन और बिजली उत्पादन जुलाई 2019 में पहले ही अपने स्तर से अधिक हो गया है। यह वर्ष के

* यह आलेख डॉ. माइकल देवव्रत पात्र कुणाल प्रियदर्शी, शशिधर एम. लोकरे, राजीव जैन, सार्थक गुलाटी, विनीत कुमार श्रीवास्तव, अभिलाषा, प्रियंका सचदेवा, मधुरेश कुमार, पलक गोदारा, जॉन वी. गुरिया, मनु शर्मा, शोभित गोयल, ऋषभ कुमार, सिद्धांत कुजूर, इशिता पाटी, अवनीश कुमार, राजस सरोय, आशीष थॉमस जॉर्ज, देब प्रसाद रथ और समीर रंजन बेहरा के द्वारा तैयार किया गया है इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

बाकी हिस्सों में औद्योगिक गतिविधि में एक पलटाव के लिए आधार तैयार कर रहा है, यहां तक कि क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) ने इस साल पहली बार अगस्त में लागत दबाव को थोड़ा कम करने की सूचना दी। सिल्वर लाइनिंग पीएमआई सेवा के रूप में आई, जो सेवा प्रदाताओं को दिए गए नए ऑर्डर पर 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो कि अधिक उपभोक्ता के आने, कई फर्मों को फिर से खोलने और आक्रामक विज्ञापन से उपजी है।

निर्यात गेमचेंजर के रूप में उभर रहे हैं और संभावित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए उच्च विकास पथ की धुरी बन रहे हैं। एक गतिशील निर्यात क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था को घरेलू बाजार के आकार के साथ संभावित गति से तेजी से बढ़ने में सक्षम बनाता है। अधिशेष के लिए एक रास्ते के अलावा, निर्यात अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिपक्वता और उत्पादकता की अभिव्यक्ति है। पण्य वस्तु निर्यात लगातार छठे महीने 30 अरब अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा। निर्यात वृद्धि की गति वास्तव में महामारी में निरंतर रही और तेज हुई है, जिससे 2021-22 के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2027-28 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष के दौरान अब तक का निर्यात प्रदर्शन दो अंकों की मात्रा में वृद्धि और बाजार विविधीकरण द्वारा संचालित है। प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि यह भारतीय विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने की दिशा में काम करती है। ज़िले निर्यात केंद्र के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्भव (एमएसएमई) के निर्यात को बढ़ा रहे हैं कुल निर्यात में इसके शेयर 48 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिए और भौगोलिक संकेत वाले उत्पादों (जीआई) के निर्यात से प्रतिस्पर्धा में बढ़त और उत्पाद/बाजार विविधीकरण मिलेगा। कोविड-19 के बाद की अवधि के दौरान कृषि निर्यात मजबूत बना हुआ है। उच्च पोषण और औषधीय गुणों वाले जीआई टैग वाले नए उत्पादों ने भारत की कृषि निर्यात बास्केट में विशिष्टता ला दी है, जिससे लंबे समय में अधिक लाभ होगा।

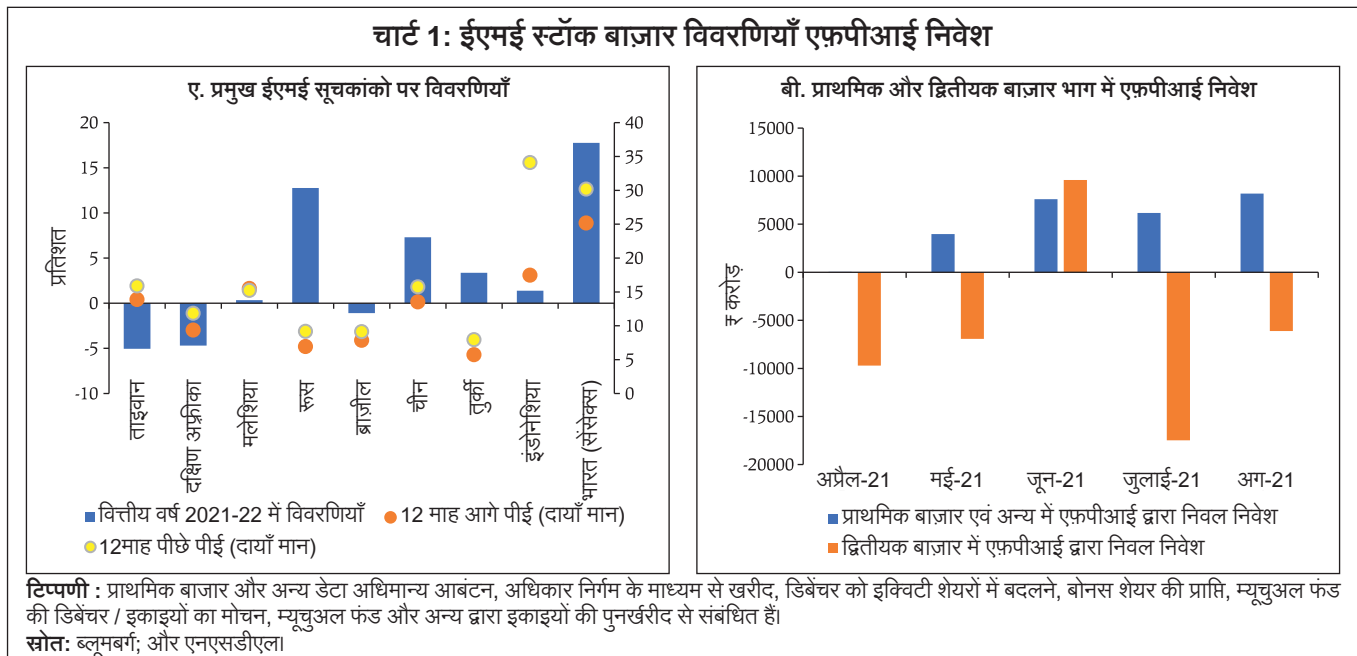
भारत का सेवाओं का निर्यात अप्रैल-जुलाई 2021 में मजबूत रहा, जो सॉफ्टवेयर निर्यात के कारण साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) 15 प्रतिशत बढ़ा। प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों ने अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में ति1: 2021-22 (वर्ष-दर-वर्ष) में 20 प्रतिशत से अधिक की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जिसका नेतृत्व क्लाउड प्लेटफॉर्म सेवाओं, साइबर सुरक्षा, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि और उद्यम अनुप्रयोग सेवाओं की मांग के कारण हुआ। आईटी सेवाओं की मांग जीव विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और उपभोक्ता डिब्बाबंद सामान, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) और विनिर्माण जैसे कार्यक्षेत्रों से उपजी है। आगे बढ़ते हुए, वैश्विक आईटी खर्च (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों) में 2021 में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। बढ़ती मांग की प्रत्याशा में, घरेलू आईटी कंपनियां घरेलू क्लाउड टैलेंट पूल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

वित्तीय बाजारों में, भारतीय इक्विटी ने 2021-22 में अब तक सभी साथी उभरती अर्थव्यवस्था से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो उच्चतम प्रतिलाभ प्रदान कर रहा है। 13 सितंबर तक, बीएसई सेंसेक्स एक वर्ष की तारीख के आधार पर 20 प्रतिशत से अधिक था, चार साल में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक लाभ के लिए ट्रैक

पर था। मूल्यांकन बढ़ाया गया है लेकिन मजबूत आय वृद्धि की उम्मीदों द्वारा समर्थित है (चार्ट 1)। इक्विटी बाजारों में तेजी के चलते रिकॉर्ड 29 कंपनियों¹ ने सार्वजनिक सूचीकरण के लिए विवरणिका का मसौदा दाखिल किया। यह पिछले 17 सालों में एक महीने में सबसे ज्यादा था। वर्ष के शेष महीनों में कम से कम 25 और कंपनियों² के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के साथ आने की उम्मीद है, और तथ्य यह है कि 2020 और 2021 में सूचीबद्ध अधिकांश कंपनियां अपने ऑफर की कीमतों से ऊपर व्यापार कर रही हैं, आईपीओ की भीड़ को बढ़ा रही है।

आमतौर पर, इस तरह की रैलियों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा संचालित किया जाता है और वे बहुत तेजी से खरीद रहे हैं, जैसा कि बाद में चर्चा की गई, लेकिन इस बार, एक घरेलू निवेशक की कहानी उत्साहजनक है अगस्त में लगातार छठे महीने इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने शुद्ध अंतर्वाह आकर्षित किया (चार्ट 2ए)। अकेले अगस्त में पंजीकृत व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) खातों की संख्या सबसे अधिक थी (चार्ट 2बी)। खुदरा निवेशक की घटना डीमैट खातों की संख्या में वृद्धि से भी स्पष्ट होती है।

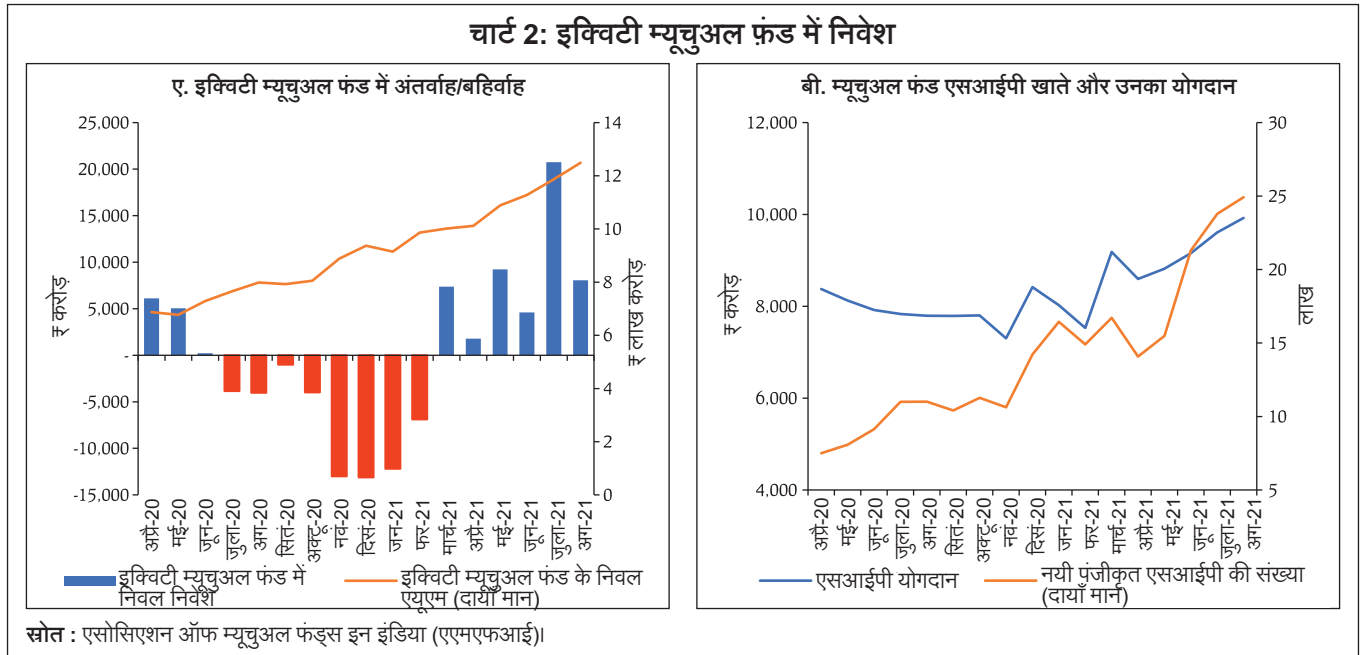
चार्ट 1: ईएमई स्टॉक बाजार विवरणियाँ एफपीआई निवेश



¹ <https://www.livemint.com/market/stock-market-news/august-sees-highest-ipo-filings-in-17-years-11630519874172.html>

² <https://www.moneycontrol.com/news/business/ipo/india-ipo-poised-for-record-in-2021-after-38-firms-raised-rs-71800-crore-7357721.html>

चार्ट 2: इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश

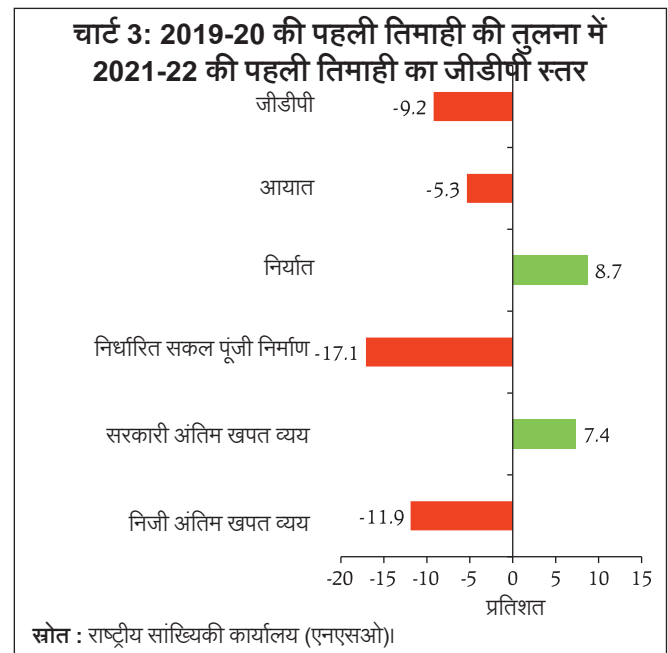


पिछले महीने बाजार में निवल विक्रेताओं से, एफपीआई अगस्त में इक्विटी और ऋण दोनों बाजारों में निवल खरीदार बन गए। नतीजतन, कुल एफपीआई प्रवाह 2021-22 में अब तक के अंतर-वर्ष के शिखर को पार कर गया है। कैलेंडर वर्ष 2021 में चीन और ब्राजील के बाद भारत पोर्टफोलियो इक्विटी प्रवाह का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। ऋण खंड में एफपीआई ब्याज ने हाल के महीनों में बढ़ती उपज अंतर और वृहत-आधार को मजबूत करने की प्रतिक्रिया में कर्षण प्राप्त किया है।

महीने के अंत में, ति1 का जीडीपी डेटा आया। अप्रैल-जून 2021 में, वास्तविक जीडीपी ने 20.1 प्रतिशत की अब तक की सबसे अधिक तिमाही वृद्धि दर्ज की, जो इस लेख के जून संस्करण में प्रस्तुत रिजर्व बैंक के 21.4 प्रतिशत के अनुमान और 22.1 प्रतिशत के हमारे तात्कालिक पूर्वानुमान से कुछ ही कम है। दरअसल, यदि सरकार के अंतिम उपभोग व्यय को हटा दिया जाए, तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 25.0 प्रतिशत हो जाएगी। जबकि मुख्य रूप से आधार प्रभावों और पूर्व-महामारी स्तरों के सापेक्ष कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, महामारी की दूसरी लहर के साथ भयानक अनुभव - जब यह सकल घरेलू उत्पाद को प्रदर्शित किया जा रहा था - को नहीं भूलना चाहिए (चार्ट 3)। दूसरी लहर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का सहज सुदृढ़ीकरण बिलकुल अलग है- व्यवसायों

और उपभोक्ताओं की बेहतर अनुकूलन क्षमता और प्रतिबंधों की स्थानीयकृत प्रकृति के अनुसार ऑनलाइन डिलीवरी और डिजिटल भुगतान में वृद्धि के कारण ति1: 2021-22 में उत्पादन का नुकसान ति1: 2020-21 के दौरान ति1: 2019-20 (पूर्व-महामारी) में दर्ज सकल घरेलू उत्पाद से मापे गए स्तर का 40 प्रतिशत था।

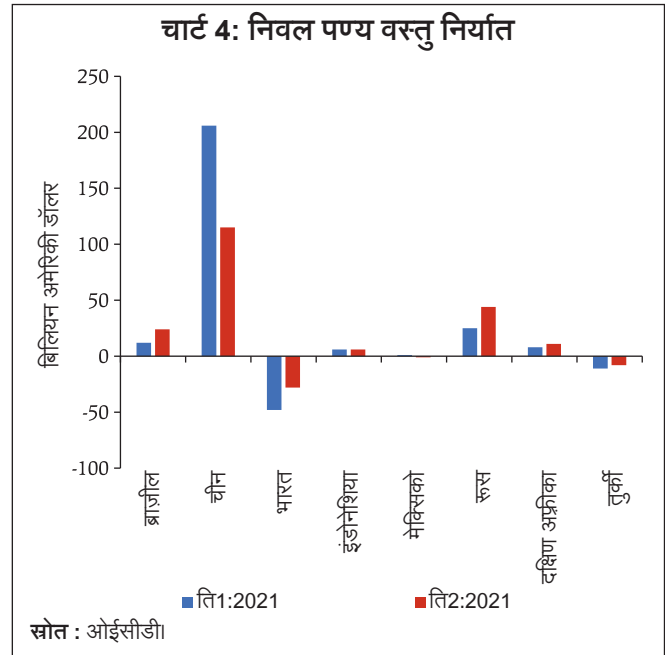
चार्ट 3: 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 2021-22 की पहली तिमाही का जीडीपी स्तर



निर्यात पूर्व-महामारी के स्तर से आगे निकल गया और आयात संतुलन की ओर अग्रसर है, लेकिन निजी खपत और निश्चित निवेश अभी भी प्रगति पर है। आपूर्ति पक्ष पर, कृषि और संबंधित गतिविधियों ने मजबूती से महामारी- का सामना करना जारी रखा और औद्योगिक उत्पादन अपने पूर्व-महामारी स्तर के 97 प्रतिशत तक पहुंच गया। वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएं, जो सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा हैं, पकड़ बनाने के करीब हैं, लेकिन संपर्क-गहन व्यापार, होटल, परिवहन और निर्माण धीमे रहे। संक्रमण के रुकने और टीकाकरण की तेज गति से विभिन्न क्षेत्रों में महामारी से पहले के स्तर तक अभिसरण तेज होने की संभावना है। यद्यपि, पिछले वर्ष के निम्न आधार से समर्थन के साथ लेखक का आर्थिक गतिविधि सूचकांक (कुमार, 2021) 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को 7.7 प्रतिशत पर रखता है।

जो आंकड़े आए हैं उनसे पता चलता है कि वैश्विक सुधार चरम पर है, जो आंशिक रूप से महामारी के माध्यम से उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रास्तों में व्यापक विचलन को दर्शाता है। अब सभी देशों में 2021 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी डेटा उपलब्ध होने के साथ, उभरती दुनिया को अलग करने वाले और भी व्यापक विचलन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो हाल की मौद्रिक नीति कार्रवाइयों में सबसे अधिक दिखाई देता है। कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने मौद्रिक नीति को पहले से ही सख्त करके जिसे वे क्षणिक मुद्रास्फीति मानते हैं उस पर हमला करने के लिए क्यों चुना है, जबकि भारत जैसे अन्य लोगों ने समायोजन के साथ बने रहना और अपने स्वयं के संकेत के सामान्य होने की प्रतीक्षा करना पसंद किया है?

निकटतम उत्तर भिन्न अंतर्निहित समष्टि आर्थिक विन्यास में निहित है। जिन देशों ने मौद्रिक नीति को सख्त किया है, वे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उनमें से कई कमोडिटी और सेवा निर्यातक हैं। कमोडिटी की कीमतों में उछाल और रिवेज टूरिज्म ने व्यापार की अनुकूल शर्तों, बढ़ती आय और मुद्रास्फीति के दबाव में तेजी से वृद्धि का सूत्रपात किया है। कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं



(ईएमई) भी अमेरिका में बेहतर विकास संभावनाओं से अधिप्लावन और व्यापार लाभ के लाभार्थी हैं। 2021 के कुछ सबसे आक्रामक दर से बढ़ने वालों ने पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में निवल निर्यात के लगभग दोगुना निर्यात दर्ज किया (चार्ट 4)। इनमें से कुछ ईएमई 2021 की दूसरी तिमाही तक अपने उत्पादन के पूर्व-महामारी स्तर पर फिर से पहुँच गए।

कमोडिटी आयातक और/या जिनकी आबादी के बहुत कम लोगों ने वैक्सीन ली है उन्हें लक्षित मुद्रास्फीति के ऊपर व्यापार करने के लिए ज़ोर दिया गया। इन देशों ने बड़े पैमाने पर आपूर्ति-पक्ष में व्यवधानों और अन्य महामारी-प्रेरित कारकों द्वारा लायी गए मुद्रास्फीति के जवाब में जल्दबाजी में सख्ती के रूप में एक रुकावट है। जो ऐसे परिदृश्य में विकास की संभावनाओं को रोक सकता है जहां कुल मांग कमजोर पक्ष पर बनी हुई है।

कुछ ईएमई हैं - प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता - जो महामारी की लहरों के बावजूद, आर्थिक विस्तार के साथ कम मुद्रास्फीति का आनंद लेते हैं। हाल के महीनों में विकास रुकने के साथ, उन्होंने आरक्षित आवश्यकता अनुपात में कटौती या उत्पादक मूल्य

सारणी 1: चयनित ईएमई के आर्थिक संकेतक

देश	मुद्रास्फीति लक्ष्य (प्रतिशत)	मुद्रास्फीति (प्रतिशत)		जीडीपी वृद्धि (व-द-व वृद्धि, प्रतिशत)			नीति दर में वाईटीडी परिवर्तन (आधार अंक)	विनिमय दर में वाईटीडी परिवर्तन (प्रतिशत)	स्टॉक मार्केट सूचकांक में वाईटीडी परिवर्तन (प्रतिशत)
		औसत छ1:2021	औसत छ2:2021 अब तक	ति2: 2020	ति1: 2021	ति2: 2021			
मौद्रिक सख्ती: व्यापार लाभार्थी के संदर्भ में									
ब्राजील	3.75 ± 1.5	6.5	9.3	-10.9	1.0	12.4	325	-1.0	-4.0
चिली	3.0 ± 1.0	3.3	4.7	-14.3	0.5	18.1	100	-9.9	6.9
हंगरी	3.0 ± 1.0	4.2	4.8	-13.3	-2.1	17.9	90	0.2	25.5
मेक्सिको	3.0 ± 1.0	5.0	5.7	-18.7	-3.6	19.6	25	0.1	16.9
रूस	4.0	5.8	6.6	-7.8	-0.7	10.5	250	1.2	21.7
दक्षिण अफ्रीका	3.0 - 6.0	4.0	4.6	-16.9	-2.6	19.3	0	3.4	8.2
तुर्क	5.0 ± 2.0	16.3	19.1	-10.4	7.2	21.7	200	-12.2	-2.6
मौद्रिक ठहराव									
भारत	4.0 ± 2.0	5.2	5.4	-24.4	1.6	20.1	0	-0.9	22.1
मलेशिया		2.4	2.2	-17.2	-0.5	16.1	0	-2.8	-3.1
फिलीपींस	3.0 ± 1.0	4.4	4.5	-17.0	-3.9	11.8	0	-3.9	-2.4
सऊदी अरब		5.5	0.4	-7.0	-3.0	1.8	0	0.0	31.4
मौद्रिक सहजता: धीमी वृद्धि									
इंडोनेशिया	3.0 ± 1.0	1.5	1.6	-5.3	-0.7	7.1	-25	-2.4	1.9
थाईलैंड**	1.0 - 3.0	0.9	0.2	-12.1	-2.6	7.5	0	-8.5	8.2
मौद्रिक सहजता: आर्थिक विस्तार तथा कम मुद्रास्फीति									
चीन***		0.5	0.9	3.2	18.3	7.9	0	1.3	6.6

*: अभी तक दरों में वृद्धि नहीं हुई है, ति4: 2021 में दर वृद्धि का संकेत।

** : दरों में कटौती नहीं की गई, पिछली एमपीसी बैठक में रेट कट के लिए एक तिहाई वोट थे।

***: दरों में कटौती नहीं की गई। चलनिधि और उधार को बढ़ावा देने के लिए गैर-दर कार्रवाई।

टिप्पणी: वर्ष-दर-तारीख (वाईटीडी) परिवर्तन 10 सितंबर तक हैं।

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और centralbanking.com।

मुद्रास्फीति में वृद्धि के बावजूद भी लक्षित उधार के माध्यम से मौद्रिक समायोजन शुरू किया है।

ईएमई का एक छोटा समूह कम मुद्रास्फीति का अनुभव कर रहा है, लेकिन विकास वांछनीय दरों से काफी नीचे है (सारणी 1)। ये वे देश हैं जो मौद्रिक प्रोत्साहन को संशोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आगे बढ़ने वाली दरों में कटौती का संकेत दे रहे हैं या परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रमों का विस्तार कर रहे हैं। उनकी प्रतिरक्षित आबादी का अनुपात उन देशों के साथ प्रतिकूल रूप से तुलना करता है जो दृढ़ता से बढ़ रहे हैं या जिनकी बेहतर विकास संभावनाएं हैं।

हमने ईएमई के एक समूह को देखा है। इस चयन में सबसे बड़े ईएमई शामिल हैं, जिसमें ब्रिक्स और जी20 समूह में से कुछ और साथ ही समूह के बाहर से कुछ प्रमुख शामिल हैं। इस चयन में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (आईटी) देश और गैर-आईटी देश दोनों शामिल हैं। इसमें वे देश भी शामिल हैं जिनकी विनिमय दर

डॉलर से आंकी गई है। प्रत्येक महाद्वीप से कम से कम एक देश है।

वृद्धि दर - वर्तमान गति या बाद की तिमाहियों के लिए पूर्वानुमान - विभाजन के लिए मुख्य मानदंड है। जिन देशों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है, उन्हें मुद्रास्फीति के परिणामों के आधार पर और विभाजित किया जाता है। यह देखा गया है कि 'विकास नेताओं' के बीच, आईटी देशों में उच्च मुद्रास्फीति है और चीन जैसे गैर-आईटी देशों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कम है। लगभग सभी आईटी विकास नेताओं ने मौद्रिक नीति को कड़ा किया है या उसी के संकेत दिए हैं। ये सारणी 1 में देशों का पहला समूह हैं। इन देशों में कमोडिटी की कीमतों में उछाल और कुछ मामलों में पर्यटन राजस्व से होने वाले व्यापार लाभ की शर्तों की एक सामान्य विशेषता है। दूसरी ओर, गैर-आईटी विकास नेता मंदी रिकवरी का समर्थन करने के उपाय शुरू कर रहे हैं।

कम वृद्धि वाले देश वे हैं जहां 2021 की दूसरी तिमाही में फिर से उछाल उतना मजबूत नहीं है, जितना कि 2020 की दूसरी तिमाही में गिरावट। इसमें भारत और फिलीपींस जैसे आईटी देश और मलेशिया और सऊदी अरब जैसे गैर-आईटी देश शामिल हैं। बाद के दो भी कमोडिटी निर्यातक हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ विकास के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इनमें से दो में महंगाई चिंता का विषय है। कम वृद्धि वाले देशों में, दो ऐसे देश हैं जहां केंद्रीय बैंकों ने और समर्थन उपाय किए हैं।

स्पष्ट रूप से, एक कारक जो समष्टिआर्थिक प्रदर्शन में अंतर पैदा कर रहा है, वह है वैक्सीन तक पहुंच (तालिका 2)। भारत को इनमें से किसी भी श्रेणी में विभाजित करना मुश्किल है। महामारी के फैलने के बाद से उच्च मुद्रास्फीति के छिटपुट एपिसोड ज्यादातर लॉकडाउन या संक्रमण की लहरों के साथ मेल खाते हैं। जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी जाती है या लहरें कम हो जाती हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति आपूर्ति व्यवधानों के प्रभाव को कम करना शुरू कर देती है। भारत एक दुर्लभ ईएमई है जो ति4:2020 में संकुचन से बाहर हो गया, ति1:2021 में सकारात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ा और दूसरी लहर के बावजूद ति2:2021 में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की। फिर भी, हाल के दिनों में खुराक की रिकॉर्ड बनाने वाली संख्या के बावजूद, कुल मांग कमजोर और पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे बनी हुई है। विश्व आर्थिक परिदृश्य के जुलाई अपडेट में आश्चर्य की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अधिकांश ईएमई के लिए विकास अनुमानों को संशोधित किया, जबकि भारत को नीचे चिह्नित किया गया था। भारत ने दर बढ़ाने वालों के ईएमई बैंडवागन में शामिल नहीं होने का, जिसमें संख्या बढ़ रही है और इसके बजाय, विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए जब तक आवश्यक हो,

सारणी 2: कोविड 19 टीकाकरण स्थिति (12 सितंबर 2021 की स्थिति)

देश	पूर्णतः टीका लेने वाली आबादी का प्रतिशत
ब्राजील	34.6
चिली	72.8
चीन	69.3
भारत*	12.8
इंडोनेशिया	15.6
मलेशिया	52.3
मेक्सिको	30.4
फिलीपींस	15.0
रूस	27.0
सऊदी अरब	49.4
दक्षिण अफ्रीका	12.2
थाइलैंड	16.7
तुर्क	48.5

स्रोत: ब्लूमबर्ग

*: 14 सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार टीका लेने वाली वयस्क आबादी 19 प्रतिशत है।

तब तक एक उदार रुख बनाए रखने के लिए, मुद्रास्फीति द्वारा प्रदान किए गए सीमित स्थान में सहनशीलता स्तर के भीतर, और ऊपर बढ़ने के बावजूद भी इसके बाहर नहीं जाने का निश्चय किया है। यह निर्णायक समय है; यह वृद्धि को कठोर परिस्थिति में बने रहने जैसा है जबकि मुद्रास्फीति में महामारी के उच्च स्तर से धीरे-धीरे गिरावट भी करनी है, उत्पादन हानी को अवस्फीति दायरे तक बढ़ाना है।

इस लेख के बाकी हिस्सों को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II हाल की वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को समाहित करता है। खंड III घरेलू अर्थव्यवस्था की पड़ताल करता है। खंड IV सामने आने वाली वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करता है, और अंतिम खंड कुछ समापन टिप्पणियों को निर्धारित करता है।

II. वैश्विक व्यवस्था

वैश्विक आर्थिक सुधार के आकार को विभिन्न क्षेत्रों और अर्थव्यवस्थाओं में महामारी के प्रभाव में और भौगोलिक क्षेत्रों में टीकाकरण की गति में अंतर द्वारा तराशा जा रहा है। अगस्त के बाद से अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलना आगे से आ रहे डेल्टा वैरिएंट का सामना कर रहा है। वैश्विक सुधार के लिए नकारात्मक जोखिम तदनुसार बढ़ गए हैं।

30 अगस्त को जारी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, ओईसीडी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि - जो क्रय शक्ति समता के संदर्भ में विश्व जीडीपी का 50 प्रतिशत है - एक तिमाही पहले 0.6 प्रतिशत से ति2:2021 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद पूर्व-महामारी स्तर से नीचे है।

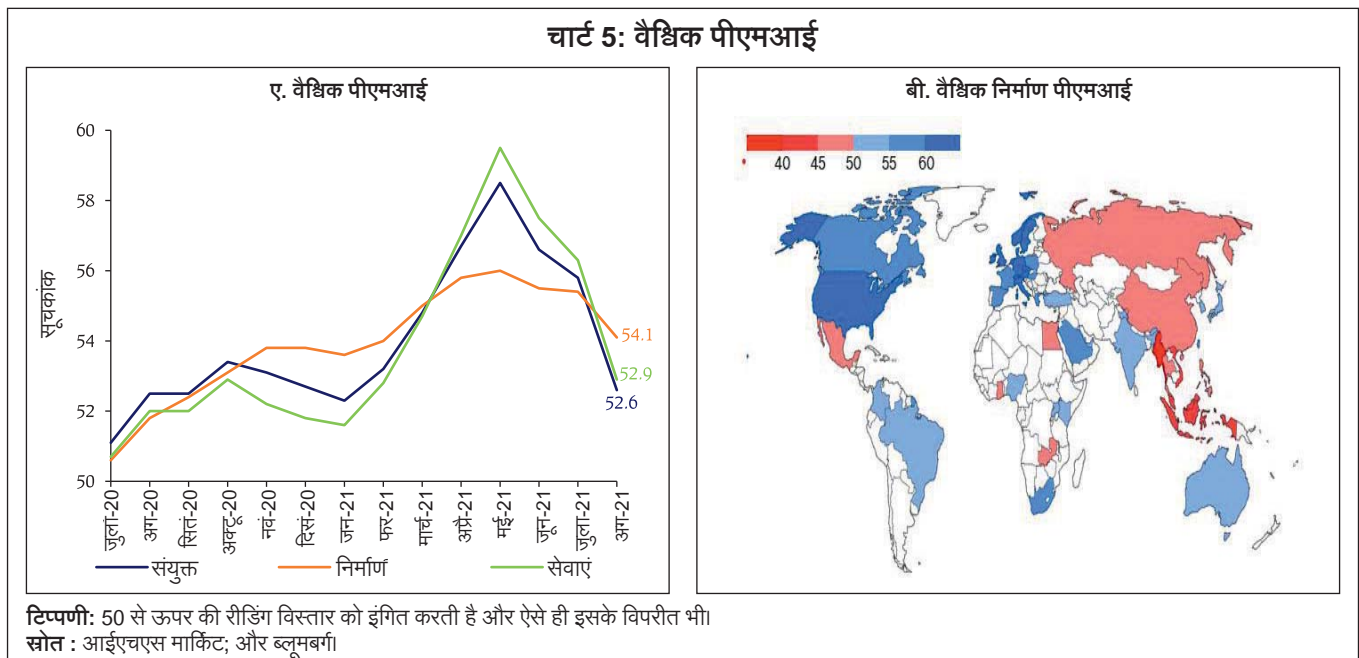
संयुक्त वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अगस्त में सात महीने के निचले स्तर पर आ गया क्योंकि अमेरिका और यूरो क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और एशियाई क्षेत्र में लड़खड़ा गयी (चार्ट 5)। विनिर्माण के भीतर, उपभोक्ता, मध्यवर्ती और निवेश माल उप-समूहों में मंदी देखी गई। तृतीयक क्षेत्र में,

वित्तीय सेवाएं ही एकमात्र उप-समूह था जिसने विकास में तेजी दर्ज की।

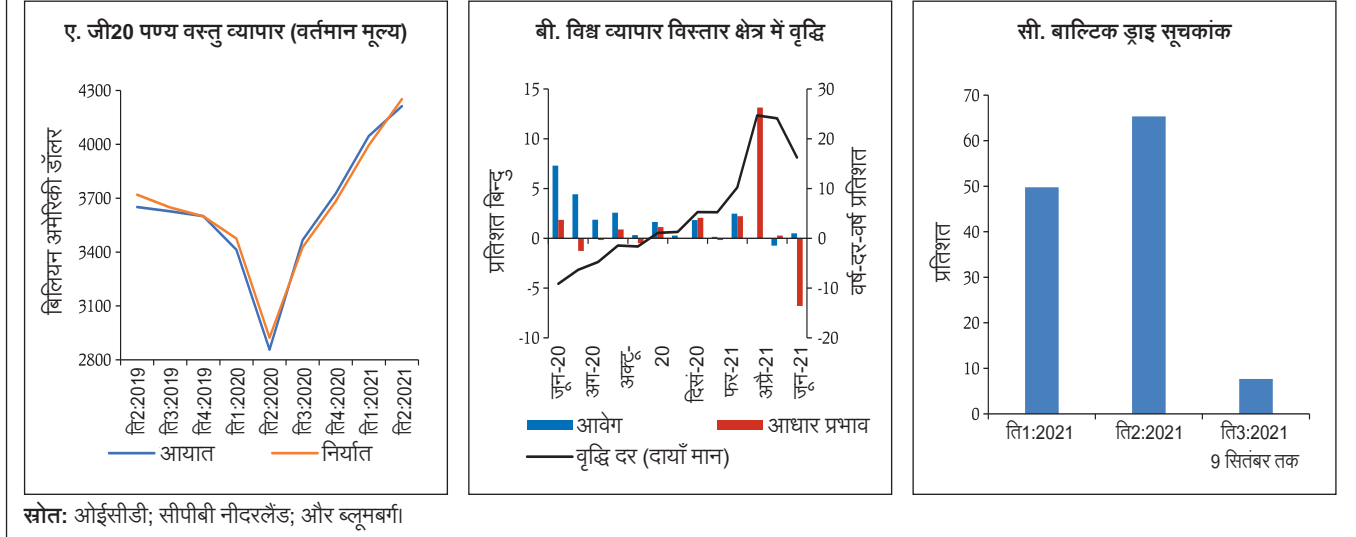
आपूर्ति और रसद बाधाओं, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में कंटेनरों और कर्मियों की कमी, उच्च माल भाड़ा दरों और चिप और अर्धचालकों की आपूर्ति में कमी के बावजूद माल का व्यापार मजबूत बना हुआ है। हालाँकि, ये कारक व्यापारिक वस्तुओं की कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने अगस्त में 2,35,000 नौकरियों का अवसर दिया, जो कि 2021 में अब तक की औसत मासिक नौकरी वृद्धि का लगभग 40 प्रतिशत और जुलाई में सृजित 1.1 मिलियन नौकरियों से एक तेज गिरावट है। कम नौकरियों के आंकड़े देश भर में श्रम की कमी को दूर करते हुए, नियोजन योजनाओं पर बड़े पैमाने पर डेल्टा वैरिएंट के प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत तक कम हो गई - यह मार्च 2020 के बाद से इसकी सबसे अच्छी रीडिंग है - यह श्रम की कमी की मात्रा को समझती है क्योंकि श्रम बल की भागीदारी में रिकवरी काफी पीछे है।

चार्ट 5: वैश्विक पीएमआई



चार्ट 6: विश्व व्यापार और शिपिंग लागत



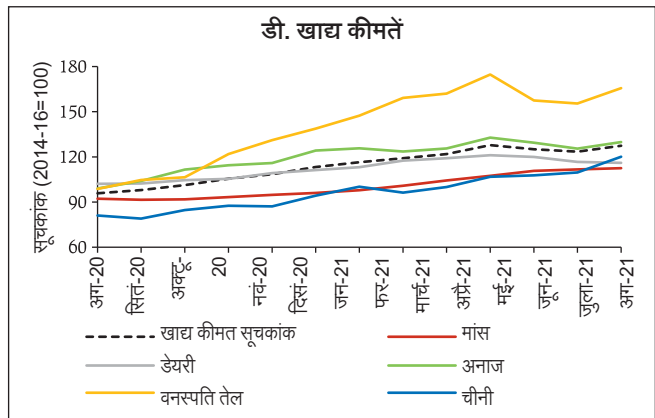
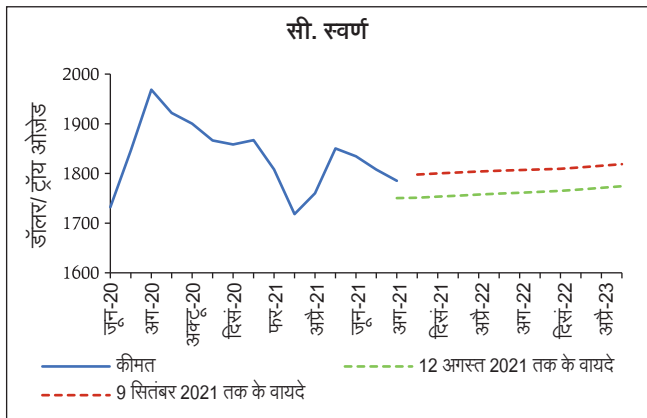
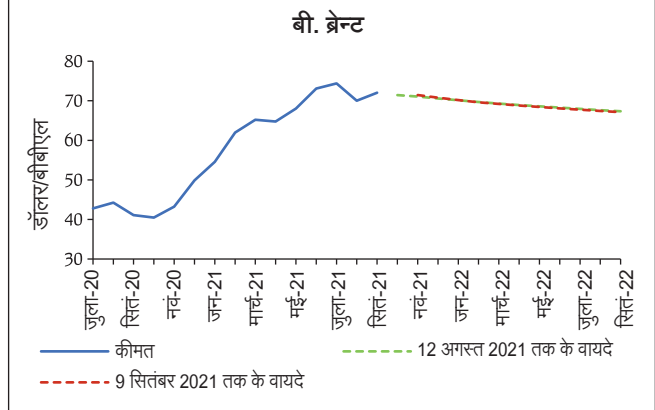
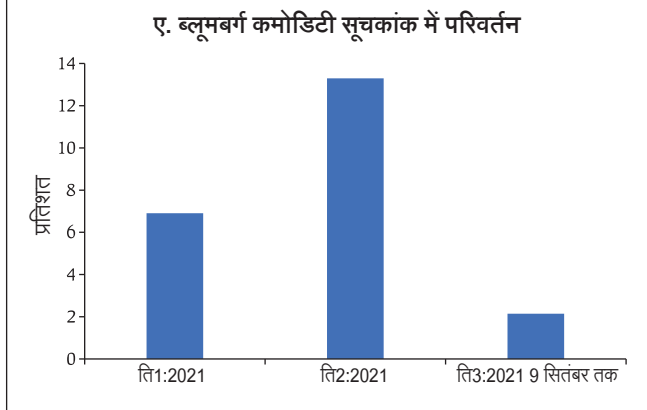
अगस्त में, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा संकलित माल व्यापार बैरोमीटर पिछले पांच वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ओईसीडी के अनुसार, ति2:2021 में, जी20 क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पण्य वस्तु व्यापार (नाममात्र शब्दों में) पिछली तिमाही में मापे गए रिकॉर्ड को पार कर गया (चार्ट 6ए)। मासिक आधार पर, प्रतिकूल आधार के बावजूद, पण्य वस्तु व्यापार में वर्ष-दर-वर्ष दो अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट 6बी)। एशिया के प्रमुख केंद्रों में नई आपूर्ति व्यवधानों के साथ शिपिंग शुल्क लगातार बढ़ रहा है (चार्ट 6सी)। पीएमआई से पता चलता है कि अगस्त में आठ महत्वपूर्ण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं का वितरण समय उप-सूचकांक नकारात्मकता में चला गया, जबकि औसत विक्रेता प्रमुख समय में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन में गिरावट आई। इस संबंध में, वियतनाम में संक्रमण का बेरोकटोक प्रसार - जिसने 2020 में महामारी के सबसे गंभीर चरण के दौरान एक वैश्विक व्यापार महाशक्ति के रूप में काम किया और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक संभावित धुरी के रूप में उभरा - जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के कामकाज का गला घोट रहा है।

डेल्टा वैरिएंट की चिंताओं के कारण अगस्त में कमोडिटी बाजार ठंडा हो गया। अगस्त के अंतिम सप्ताह में और सितंबर की शुरुआत में, हालांकि, जैसे ही चीन में नए संक्रमण कम हुए,

कमोडिटी बाजार में वापस से उछाल आने लगा। ब्लूमबर्ग कमोडिटी सूचकांक जुलाई में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया (चार्ट 7ए)। अगस्त में कच्चे तेल की कीमतों में 5.9 प्रतिशत की कमी आई, अप्रैल के बाद पहली मासिक गिरावट और सितंबर 2020 के बाद से सबसे तेज, कोविड-19 के प्रकोप के कारण निकट अवधि में मांग में बढ़ोतरी के बारे में चिंता बढ़ गई (चार्ट 7 बी)। साथ ही, सोने में मुद्रास्फीति हेज और सुरक्षित आश्रय दोनों के रूप में नए सिरे से ब्याज देखा गया, जिससे सितंबर की शुरुआत में कीमतें 1,828 अमेरिकी डॉलर प्रति ट्रॉय औंस तक बढ़ गईं (चार्ट 7सी)। लगातार दो महीनों की नरमी के बाद, अगस्त में चीनी, वनस्पति तेल और अनाज के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई (चार्ट 7डी)।

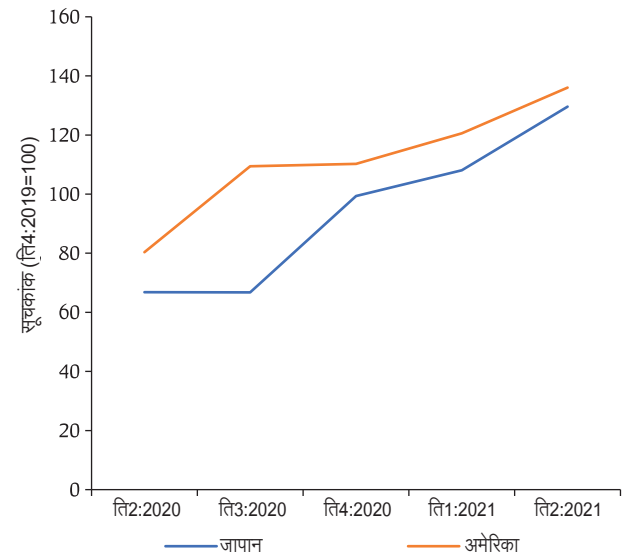
फ्रेडरल रिजर्व के 2021 में सिकुड़ने के संकेत को अपनी ध्यान में लेते हुए वित्तीय बाजार मजबूत बने रहे। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में शेयर बाजार मजबूत कॉर्पोरेट आय के कारण और जापान में आसन्न चुनावों से उत्पन्न आशावाद के कारण भी आगे बढ़ रहे हैं (चार्ट 8)। यूएस एसएंडपी सूचकांक ने सितंबर तक हर महीने एक नया शिखर छुआ है। दूसरी ओर, ईएमई शेयर बाजार, चीन की नियामक कार्रवाइयों के साथ-साथ रिकवरी के लिए डेल्टा वैरिएंट के खतरे को दर्शाते हुए पिछड़ गए

चार्ट 7: क्मोडिटी और ख़ाद्य कीमतें



स्रोत : वर्ल्ड बैंक; ब्लूमबर्ग; और ख़ाद्य और कृषि संस्था।

चार्ट 8: कॉर्पोरेट लाभ

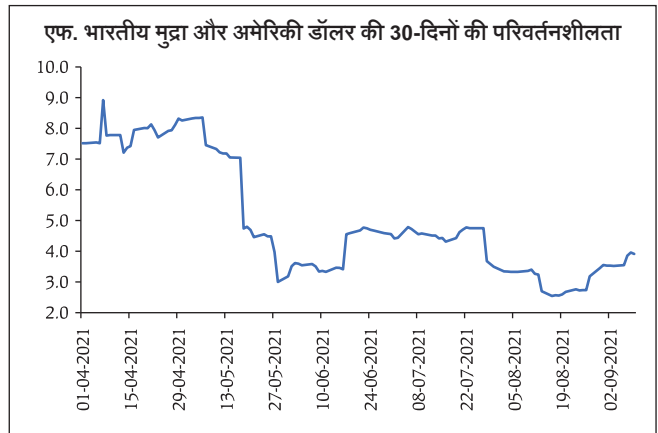
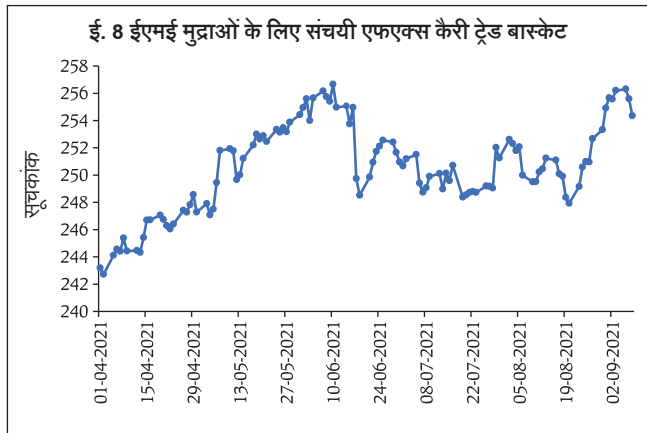
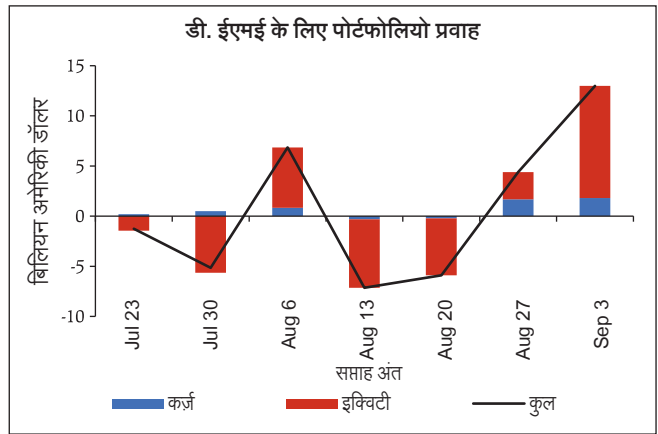
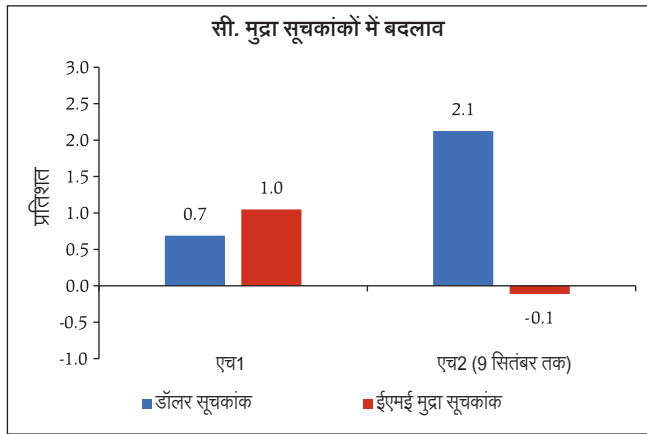
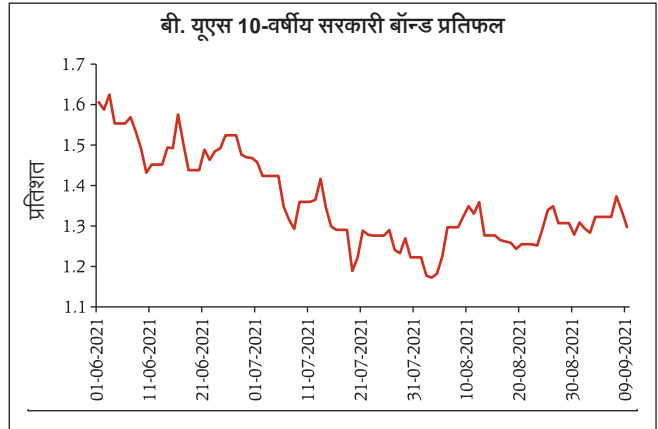
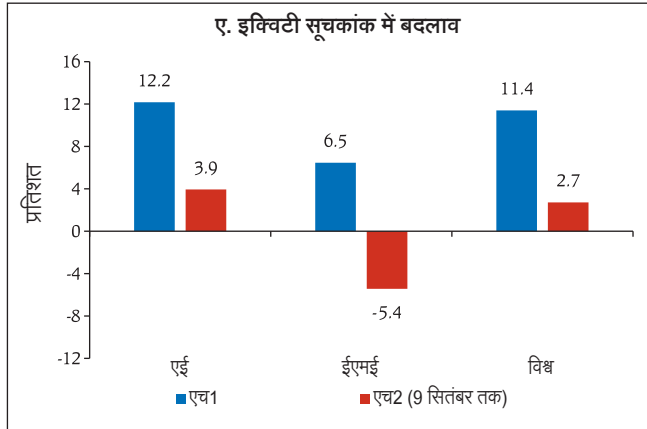


स्रोत : ब्लूमबर्ग

हैं (चार्ट 9ए)। यूएस 10-वर्षीय ख़ज़ाना प्रतिफल सीमाबद्ध रहा, कुछ हाल ही में सख्त हुए (चार्ट 9बी)। कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद, अमेरिकी डॉलर अगस्त में मजबूत रहा, लेकिन उसके बाद कमजोर पेट्रोल डेटा के साथ कमजोर हुआ (चार्ट 9सी)।

ईएमई मुद्राएं एक अनुकूल जगह पर हैं, नए सिरे से पूंजी प्रवाह के कारण अगस्त के उत्तरार्ध के बाद से मजबूत हुई हैं (चार्ट 9डी)। अमेरिकी डॉलर के हाल में कमजोर पड़ने के कारण, केंद्रीय बैंकों के अलग-अलग नीति पथों ने ईएमई मुद्रा बाजारों में व्यापार के अवसरों को आगे बढ़ाया है। आठ ईएमई मुद्राओं के लिए ब्लूमबर्ग संचयी विदेशी मुद्रा कैरी ट्रेड बास्केट, कैरी ट्रेड विवरणियों को दर्शाता है, अगस्त के अंतिम सप्ताह से बढ़ गया है (चार्ट 9ई)। यह भारतीय रुपये (आईएनआर) के लिए भी है, और आईएनआर पर सकारात्मक भावनाओं ने अमेरिकी डॉलर-

चार्ट 9 : वित्तीय बाज़ार

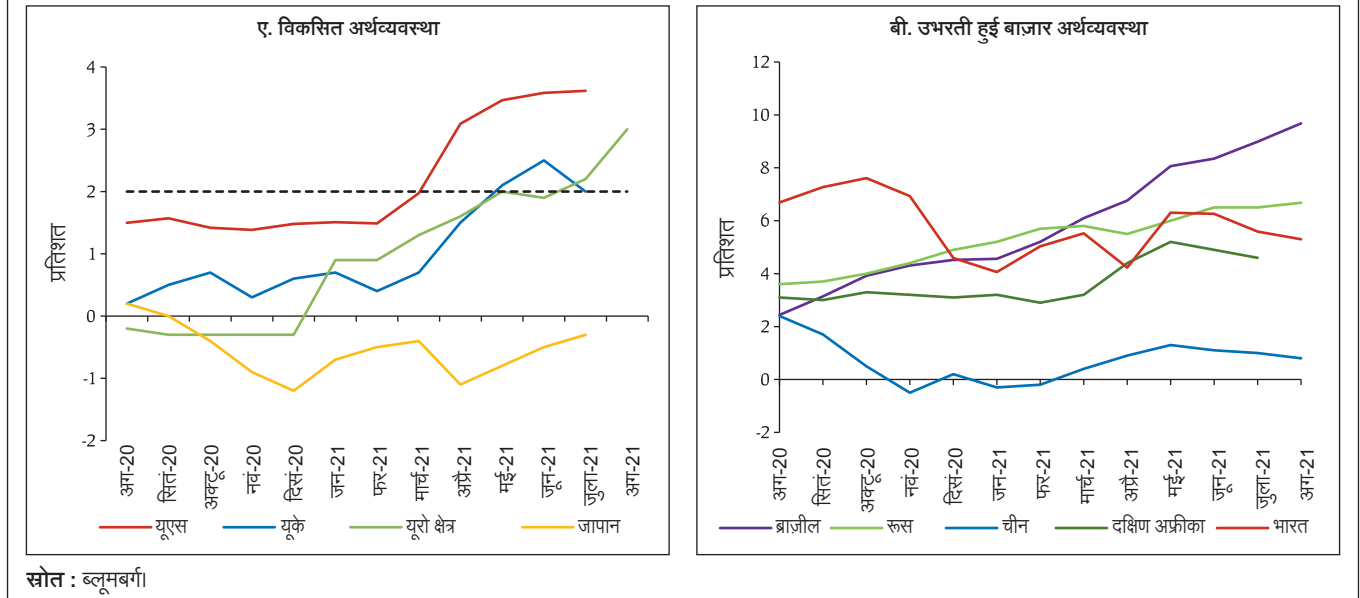


स्रोत : ब्लूमबर्ग; एफबीआईएल; और आईआईएफए

आईएनआर फॉरवर्ड प्रीमियम में गिरावट को भी कैरी-ट्रेड कार्यनीतियों के लिए इसके आकर्षण में जोड़ा है। अमेरिकी डॉलर-आईएनआर-30दिन की अंतर्निहित अस्थिरता में भी गिरावट आयी है (चार्ट 9एफ)।

यूरो क्षेत्र में, मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गई, जो अक्टूबर 2008 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है, जो आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं, चल रहे आर्थिक प्रतिकेप और जर्मनी में मूल्य वर्धित कर में पिछले वर्ष की कटौती के उलटने

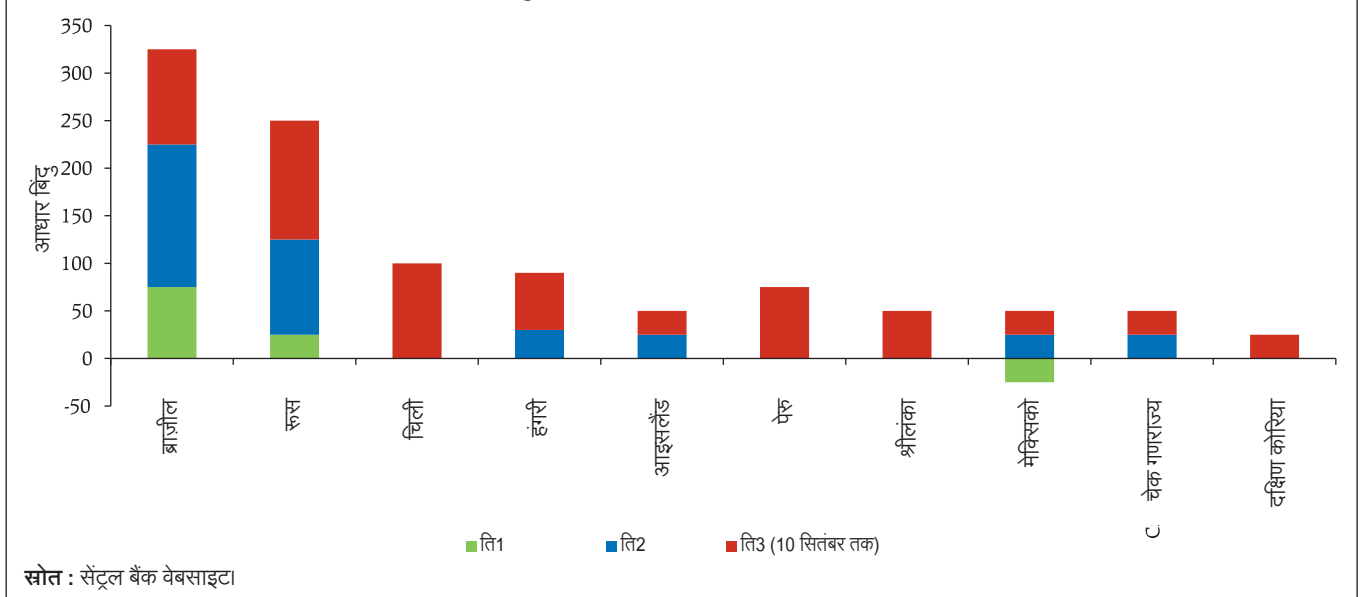
चार्ट 10: मुद्रास्फीति



द्वारा चालित हैं (चार्ट 10ए)। मार्च में 16 देशों की तुलना में केवल चार यूरो क्षेत्र के देशों में मुद्रास्फीति के चिन्ह 2 प्रतिशत से कम थे। यूएस प्रमुख व्यक्तिगत खपत व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति जुलाई में 30 साल के उच्च स्तर 3.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, अगस्त में ब्राजील में मुद्रास्फीति बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई, जो फरवरी 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है (चार्ट 10बी)। अगस्त में रूस में महंगाई दर 6.7 फीसदी थी जो 5 साल के उच्चतम स्तर पर थी।

अगस्त में, दक्षिण कोरिया दरों में वृद्धि करने वाला पहला और समग्र रूप से तीसरा प्रमुख एई बन गया। यहां तक कि कोविड-19 संक्रमण में पुनरुत्थान की स्थिति में भी इसने लक्ष्य मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता जोखिमों के जवाब में प्रमुख दर में 25 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी को प्रभावित किया (चार्ट 11)। दो अन्य एई - चेक गणराज्य और आइसलैंड - ने अगस्त में अपनी दूसरी 25 बीपीएस बढ़ोतरी को प्रभावित किया। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, ब्राजील ने अगस्त में

चार्ट 11: 2021 में चुनिंदा देशों के केंद्रीय बैंकों की दर संबंधी कार्रवाई



नीतिगत दर में 100 आधार अंकों की वृद्धि को प्रभावी करते हुए अपनी नीति को सख्त बनाया, जबकि मेक्सिको ने लगातार उच्च मुद्रास्फीति के जवाब में अपनी नीतिगत दर में लगातार दूसरी वृद्धि का सहारा लिया। हंगरी ने लगातार तीसरे महीने दरों में 30 बीपीएस की वृद्धि की, जबकि चिली ने सख्ती का पालन किया जो जुलाई में शुरू हुई और अगस्त में 75 बीपीएस की अधिक आक्रामक वृद्धि दर्ज की। पेरू, उरुग्वे और पराग्वे जैसी अन्य लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं ने भी नीतिगत दरों में वृद्धि की। रूस ने सितंबर में 25 बीपीएस की वृद्धि के साथ 2021 की अपनी पांचवीं दर वृद्धि को प्रभावित किया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम के तहत खरीद की कुल मात्रा में बदलाव नहीं करते हुए पिछली दो तिमाहियों की तुलना में बांड खरीद की गति को कम करने की घोषणा की है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बांड-खरीद कार्यक्रम की समीक्षा को सितंबर 2021 के मध्य से फरवरी 2022 के मध्य तक कोविड-19 के पुनरुत्थान के कारण पांच महीने के लिए स्थगित कर दिया। यह तब तक 4 बिलियन अमरीकी डालर की साप्ताहिक गति से बांड खरीदना जारी रखेगा।

कुल मिलाकर, निकट अवधि के दृष्टिकोण में गिरावट बनी हुई है क्योंकि संक्रामक डेल्टा वैरिएंट आर्थिक गतिविधियों को

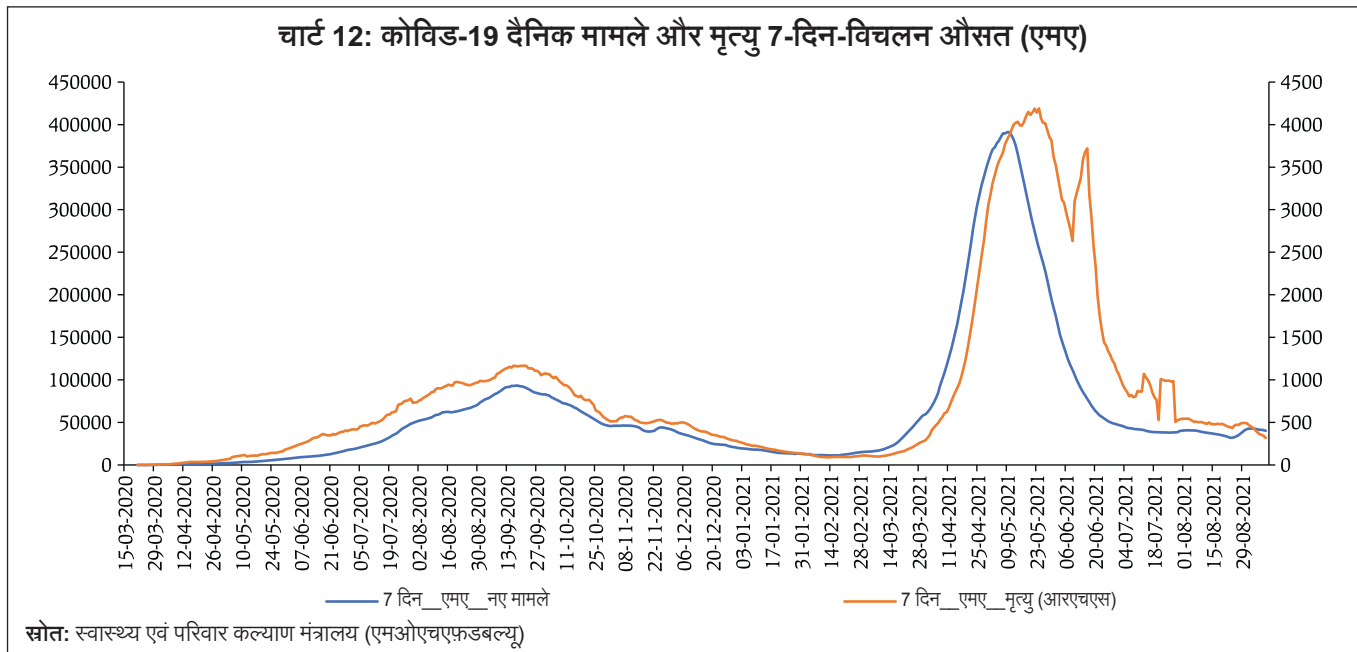
धीमा कर रहा है और विश्व व्यापार के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा कर रहा है। मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों और रुखों को पूरी तरह से अलग करने से वित्तीय स्थितियों में जल्दबाजी हो सकती है, जो अपरिपक्व रिकवरी में अवरोध डाल सकती है।

III. घरेलू विकास

अगस्त में घरेलू आर्थिक स्थितियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्रगतिशील उद्घाटन और टीकाकरण अभियान के विस्तार के साथ वृद्धि आवेगों ने गति पकड़ी। महामारी से बचने की गति प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं उज्ज्वल हो रही हैं क्योंकि दूसरी लहर खत्म हो गई है और भविष्य के लिए तैयारी युद्ध के लिए सचेत होने जैसी है।

दैनिक नए मामलों की 7-दिवसीय औसत गति 8 मई, 2021 के 3,92,322 शिखर से 12 सितंबर, 2021 को 35,464 हो गई (चार्ट 12)। 27 अगस्त, 2021 से 8 सितंबर, 2021 तक तीसरी बार, भारत ने एक दिन में कोविड-19 वैक्सिन की एक करोड़ से अधिक खुराकें दीं। प्रशासित खुराक की कुल संख्या 72 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है (9 सितंबर, 2021 तक)। नतीजतन, 12 सितंबर, 2021 तक दोहरी खुराक टीकाकरण ने 12.8 प्रतिशत आबादी को कवर किया।

चार्ट 12: कोविड-19 दैनिक मामले और मृत्यु 7-दिन-विचलन औसत (एमए)

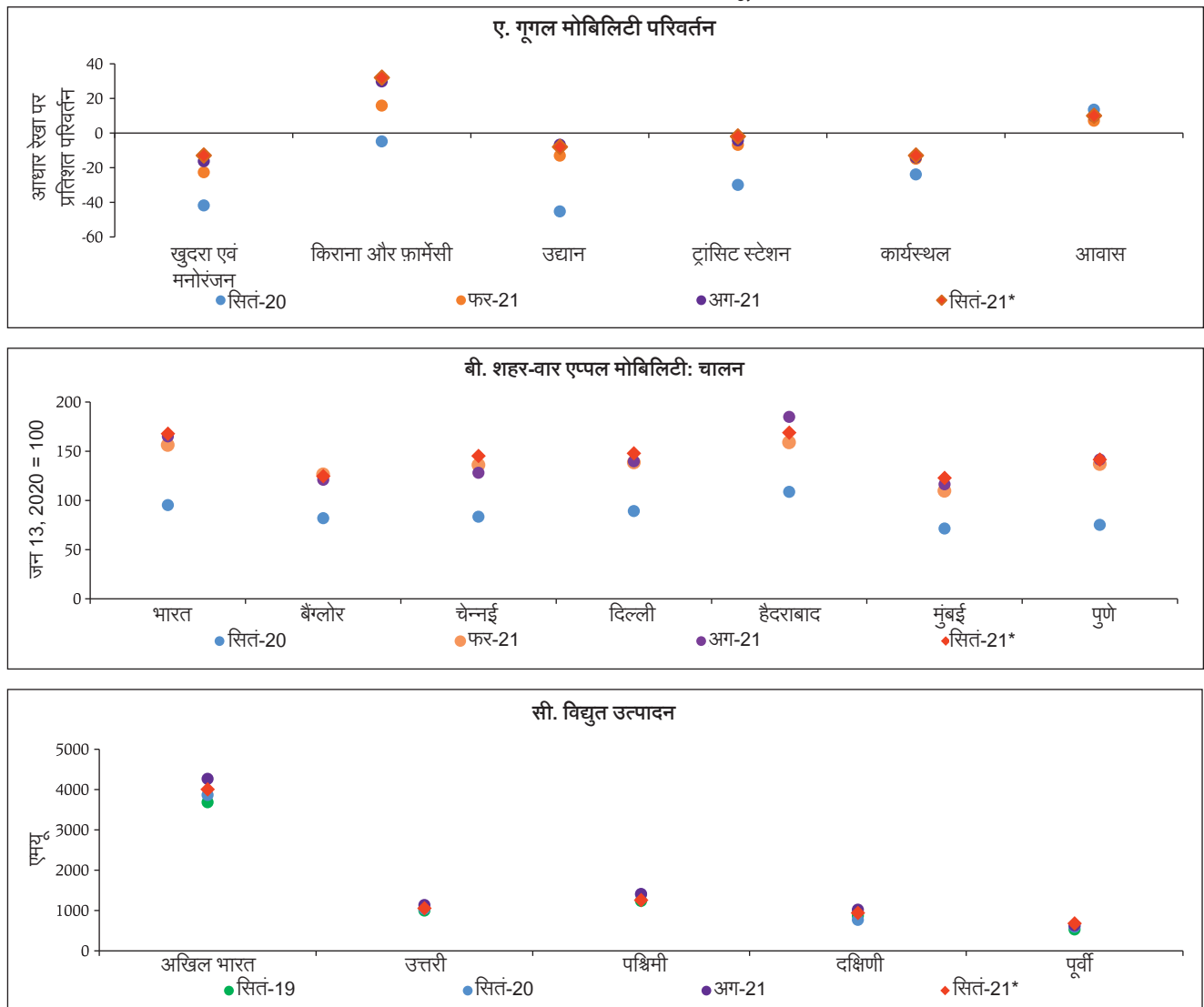


राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 31 अगस्त को 2021-22 की पहली तिमाही के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी को 20.1 प्रतिशत पर जारी किया, जो कि मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव के कारण था, क्योंकि जीडीपी में ति1: 2020-21 के दौरान गिरावट आयी थी। वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद की मौसमी रूप से समायोजित तिमाही-दर-तिमाही वार्षिक दर गिर गई, जो पहली तिमाही में अंतर्निहित गतिविधि की कमजोर गति का संकेत है। ति1: 2021-22 में जीडीपी का स्तर अभी भी ति1: 2019-20 की तुलना में कम है, जो अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कमी को दर्शाता है। बहरहाल, अस्वस्थता और मृत्यु दर की

अपेक्षाकृत उच्च दर के बावजूद, वास्तविक अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर की तुलना में सीमित रहा है।

आत्मविश्वास के पुनरुत्थान के साथ, महामारी की शुरुआत के बाद से मोबिलिटी (9 सितंबर, 2021 तक) अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ी (चार्ट 13ए और 13बी)। बिजली उत्पादन दो साल पहले यानी सितंबर 2019 के महामारी-पूर्व स्तर पर पहुंच गया (चार्ट 13सी)। नए बिजली संशोधन विधेयक 2021 का उद्देश्य बिजली वितरण से लाइसेंस हटाना और निजी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति देना है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और वितरण में दक्षता बढ़ा देगा।

चार्ट 13: आर्थिक गतिविधि पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव



*: 7 सितंबर 2021 तक
 स्रोत: गूगल; सीएमआईई; सीईआईसी; और पीओएसओसीओ।

कुल मांग

कुल मांग मजबूत हो रही है। अगस्त 2021 में पेट्रोल की खपत में वृद्धि दर्ज की गई, भले ही विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) में कमी जारी रही। ईंधन की कुल खपत में कमी आई क्योंकि मानसून की बारिश के कारण ट्रकों की अंतर-राज्यीय आवाजाही ठप होने के कारण डीजल की खपत में क्रमिक रूप से गिरावट आई (चार्ट 15ए)।

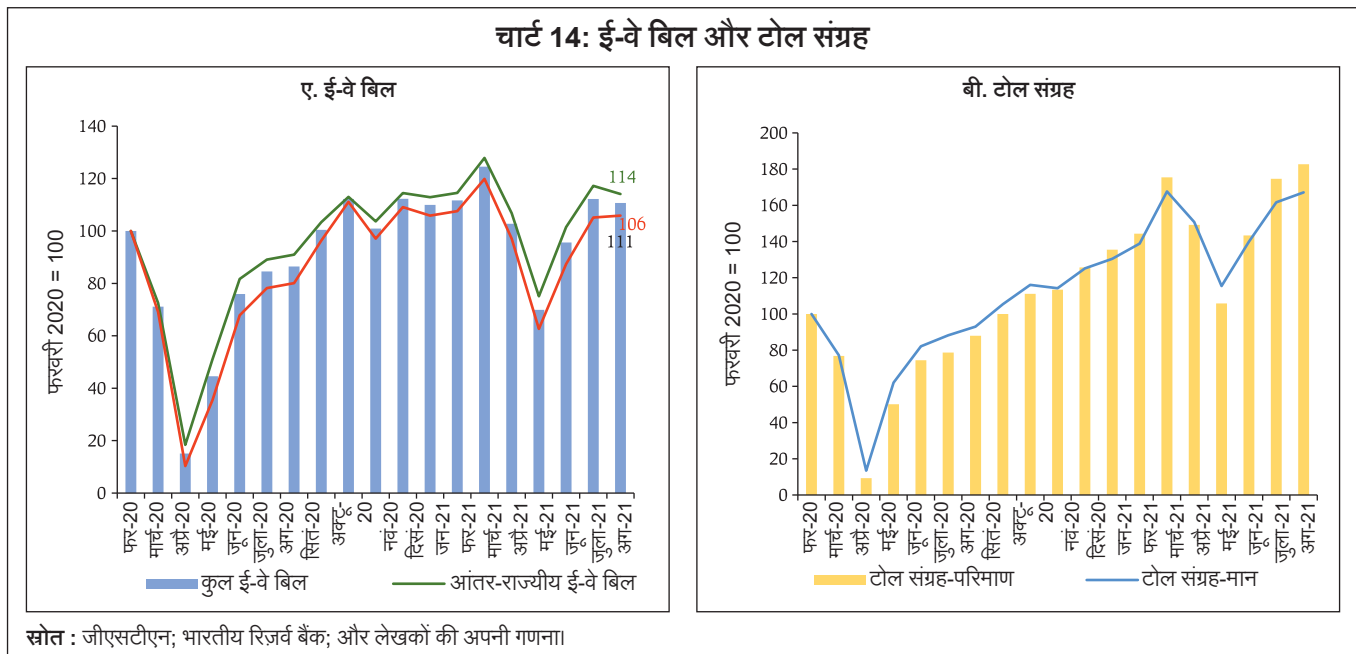
अगस्त में, ई-वे बिल – अंतर-राज्यीय और आंतर-राज्यीय दोनों – फरवरी 2020 के पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर रहे (चार्ट 14 ए), जो उच्च माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह को आगे बढ़ने का संकेत देता है (अनुबंध)। सितंबर (9 सितंबर तक) के लिए ई-वे बिल संग्रह ने साल-दर-साल और 2019 के इसी स्तर की तुलना में मजबूत वृद्धि दर्ज की। अगस्त में टोल संग्रह में तेजी से वृद्धि हुई, जो वर्ष-दर-वर्ष 107.8 प्रतिशत और पिछले महीने के स्तर से 4.6 प्रतिशत अधिक है। (चार्ट 14बी)।

अगस्त में ऑटोमोबाइल थोक विक्रेताओं ने यात्री वाहनों को छोड़कर सभी श्रेणियों में वृद्धि में सकारात्मक गति के साथ वृद्धि

दर्ज की, जहां अर्धचालक चिप की तीव्र आपूर्ति की कमी ने उत्पादन को प्रभावित किया³। 32 दिनों के त्योहारी मौसम से पहले, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अड़चनें पैदा होती हैं।

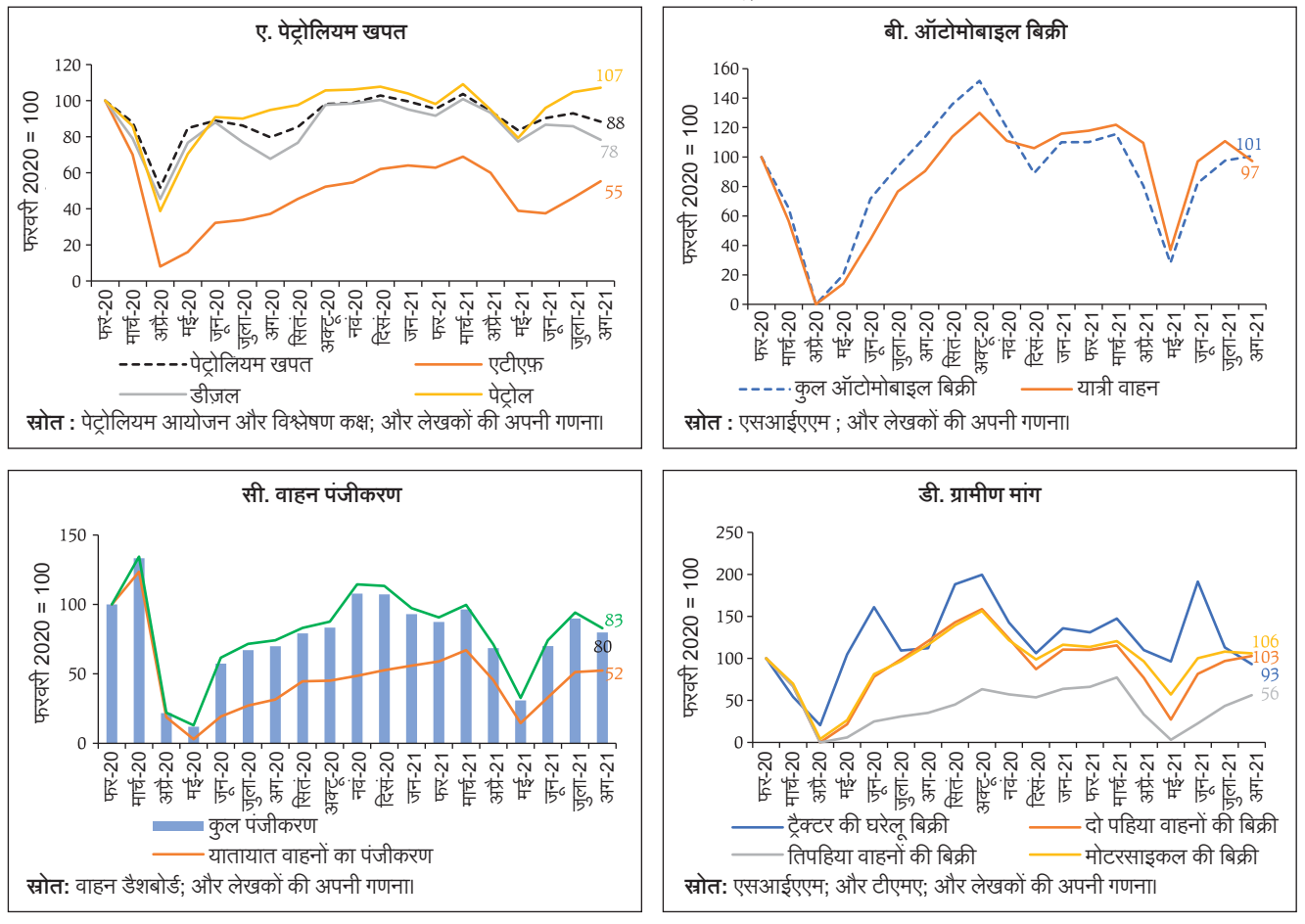
मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री ने पिछले साल अगस्त में कम आधार पर वृद्धि दर्ज की, लेकिन गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में संकुचन के कारण जुलाई 2021 के संबंध में क्रमिक रूप से गिरावट आयी क्योंकि मांग में कमी आई और ग्राहकों ने त्योहारी छूट का इंतजार किया। सितंबर के पहले सप्ताह में और सुधार हुआ (चार्ट 15बी और सी)। महामारी की दूसरी लहर के दौरान दर्ज किए गए ब्लिप के बाद दोपहिया वाहनों के पूर्व-महामारी के स्तर पर लौटने के साथ, ग्रामीण मांग उत्साहित रही। खरीफ के मौसम समाप्त होने के साथ ही ट्रैक्टर की घरेलू बिक्री में मौसमी गिरावट दर्ज की गई। मोटरसाइकिलों की बिक्री मजबूत रही, जबकि तीन पहिया वाहनों की बिक्री पूर्व-महामारी के स्तर के लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ गई (चार्ट 15डी)। मॉनसून के सामान्य रहने और बुवाई में तेजी आने के साथ, उद्योग के विशेषज्ञ आने वाले महीनों में अच्छी बिक्री की उम्मीद करते हुए, इस भाग पर आशावादी बने हुए हैं।

चार्ट 14: ई-वे बिल और टोल संग्रह



³ अगस्त 2021 में अर्धचालकों की कमी के कारण मारुति सुजुकी के कुल उत्पादन में 8 प्रतिशत की गिरावट आई (टाइम्स ऑफ इंडिया, 8 सितंबर, 2021)।

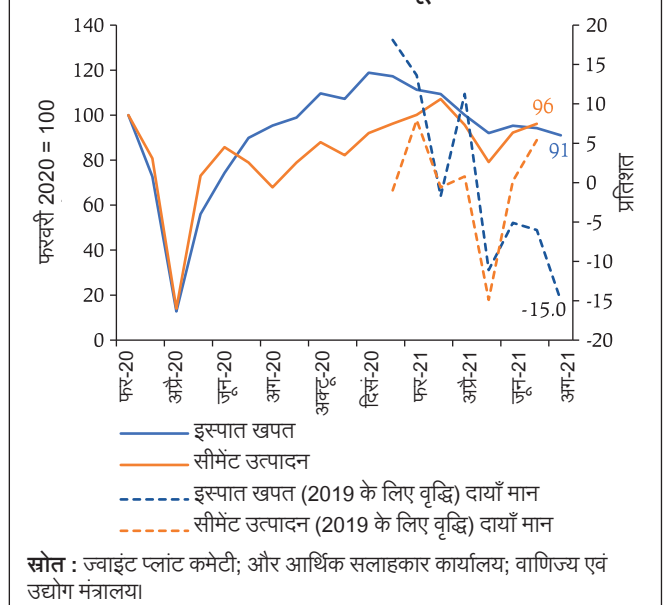
चार्ट 15: परिवहन क्षेत्र सूचकांक



सेवा क्षेत्र में, भारतीय रेलवे का माल भाड़ा प्रभावशाली बना रहा, जो एक साल पहले के अपने स्तर से अगस्त (110 मिलियन टन) में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भले ही इसने माह-दर-माह के आधार पर गिरावट दर्ज की, लेकिन अगस्त 2019 के पूर्व-महामारी स्तर की तुलना में इसमें 21.5 प्रतिशत का सुधार हुआ। प्रमुख वस्तुओं में से, सीमेंट माल ढुलाई में अगस्त में क्रमिक सुधार दर्ज किया गया (चार्ट 17)। फरवरी 2020 के स्तर पर सामान्यीकृत, निर्माण गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक - स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन - आधार रेखा से नीचे रहे: हालांकि, सीमेंट उत्पादन ने पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर वृद्धि दर्ज की (चार्ट 16)।

विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में, सड़कों को जनवरी-जुलाई 2021 में ₹ 22,200 करोड़ की उच्चतम सरकारी

चार्ट 16: निर्माण क्षेत्र सूचकांक

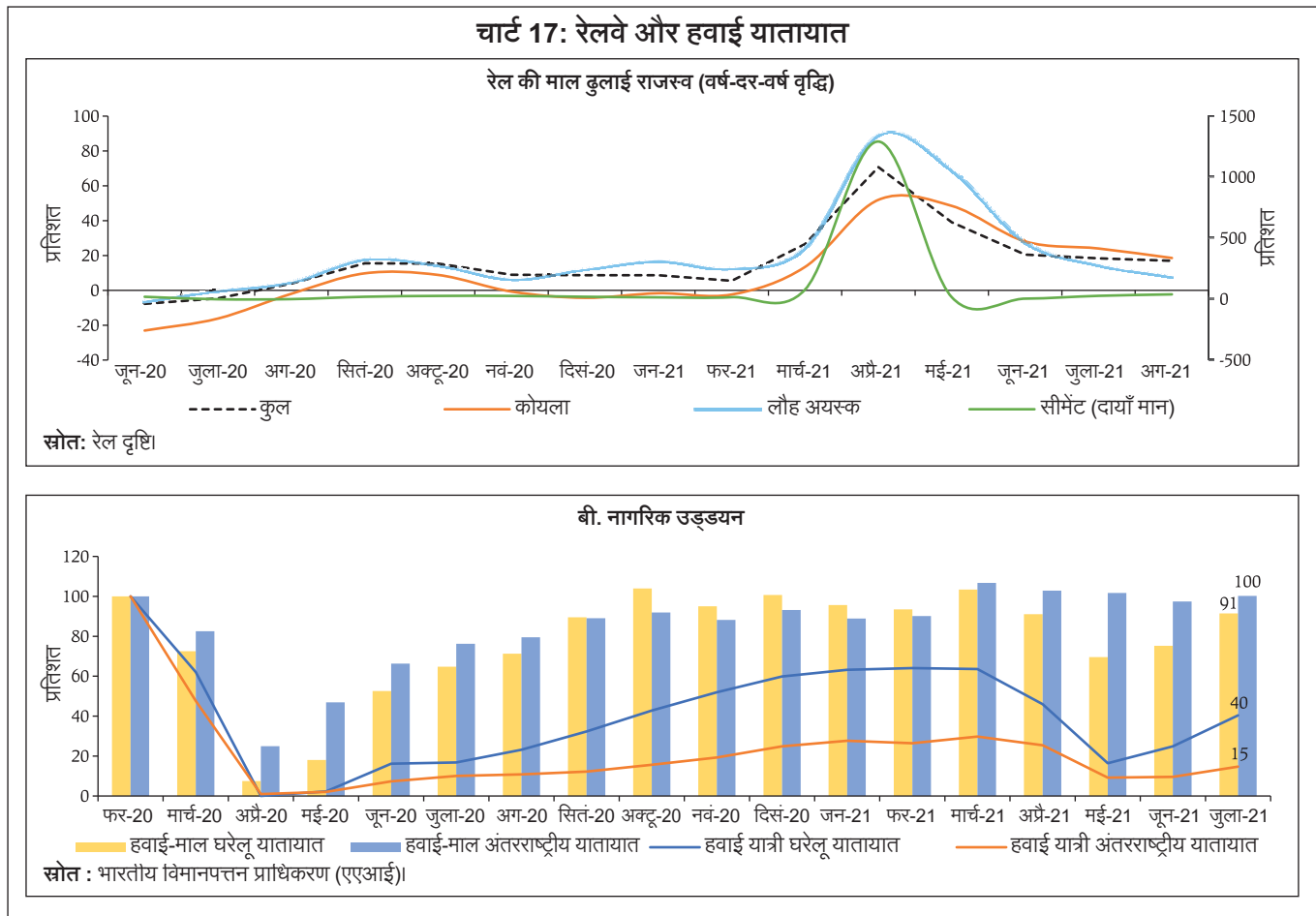


परियोजनाएं प्राप्त हुईं – जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तीन गुना है। यह, निष्पादन में सुधार, श्रम उपलब्धता में वृद्धि और सरकार द्वारा समय पर भुगतान जारी करने के साथ, सड़क निर्माण कंपनियों के आगे बढ़ने के लिए शुभ संकेत है।⁴

विमानन क्षेत्र में, माल भाग ने अगस्त में यात्री खंड से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखा। जबकि घरेलू यात्री भाग में कुछ वृद्धि दर्ज की गई थी, फरवरी 2020 में यातायात में पूर्व-महामारी स्तर की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अंतरराष्ट्रीय यात्री का भाग पूर्व-महामारी के केवल 15 प्रतिशत यातायात पर निराशाजनक बना रहा (चार्ट 17 बी)।

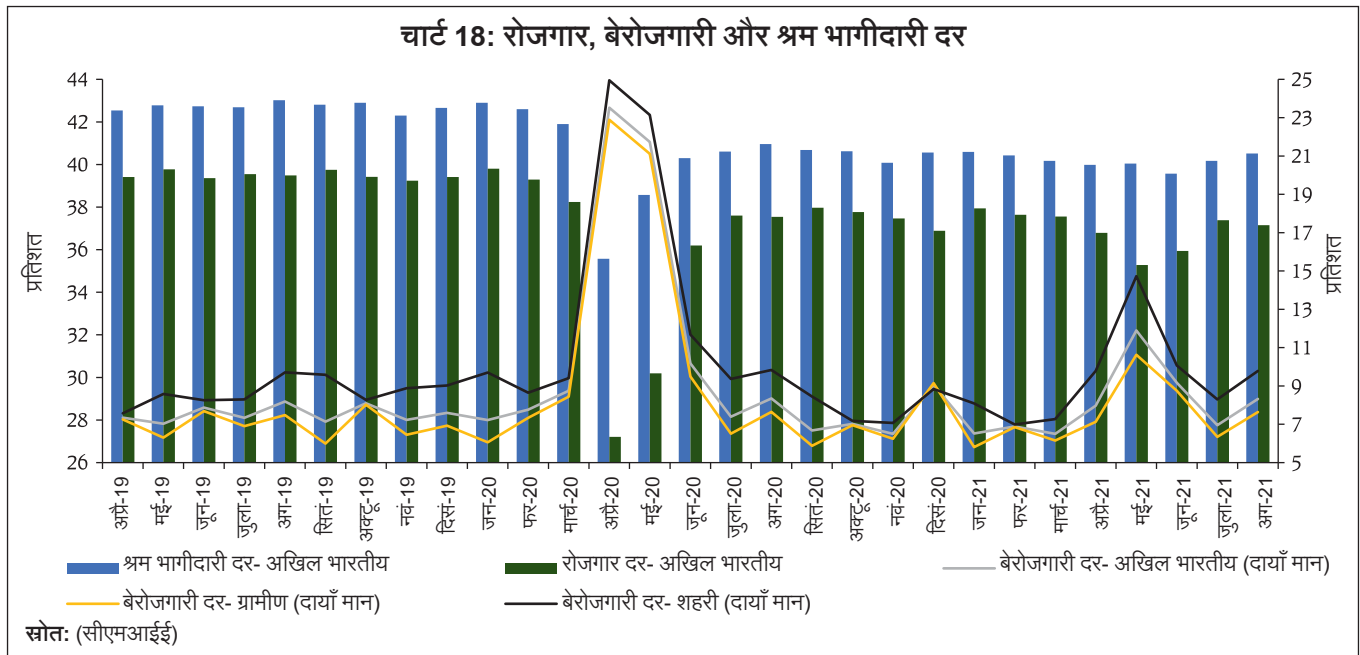
अगस्त 2021 में तीव्र-चालित उपभोक्ता वस्तु (एफएमसीजी) भाग में उछाल आया, जिसमें पूरे क्षेत्रों में व्यापक-आधार वाले सामानों की मांग बनी रही। आपूर्ति बाधाओं के बावजूद, अधिकांश एफएमसीजी कंपनियों ने अगस्त के दूसरे और तीसरे सप्ताह में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की। त्योहारी मौसम नजदीक आने के साथ, कंपनियों को सितंबर 2021 में बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है जो महामारी से पहले के स्तर से काफी आगे निकल जाएगी।⁵

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, अगस्त 2021 में श्रम भागीदारी दर 40.5 प्रतिशत थी, जो जनवरी 2021 के स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन जुलाई 2021 में बेरोजगारी दर में 7 प्रतिशत और अगस्त



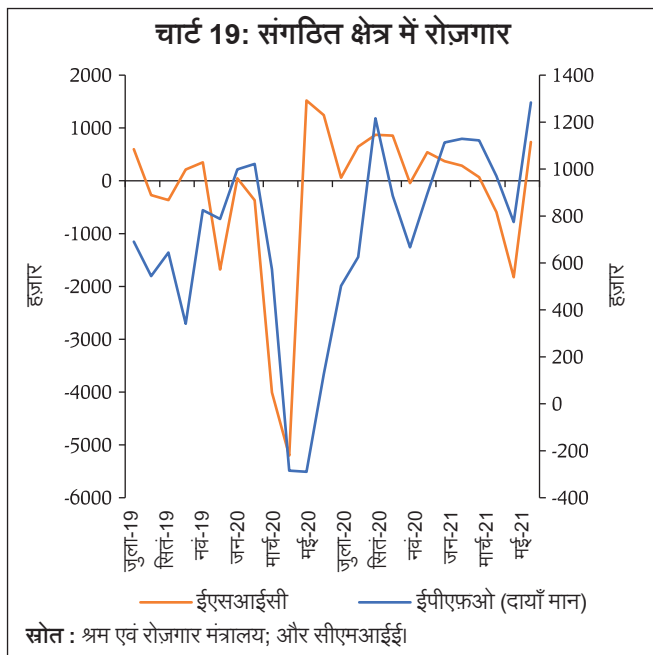
⁴ ईटी, 20 अगस्त 2021

⁵ मिनट, 27 अगस्त।



2021 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 18)। साप्ताहिक श्रम बाजार संकेतक बताते हैं कि सितंबर 2021 के दूसरे सप्ताह में बेरोजगारी दर काफी गिरकर 7.35 प्रतिशत और श्रम भागीदारी दर में मामूली सुधार होकर 40.87 प्रतिशत हो गई।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा लिए गए संगठित क्षेत्र के

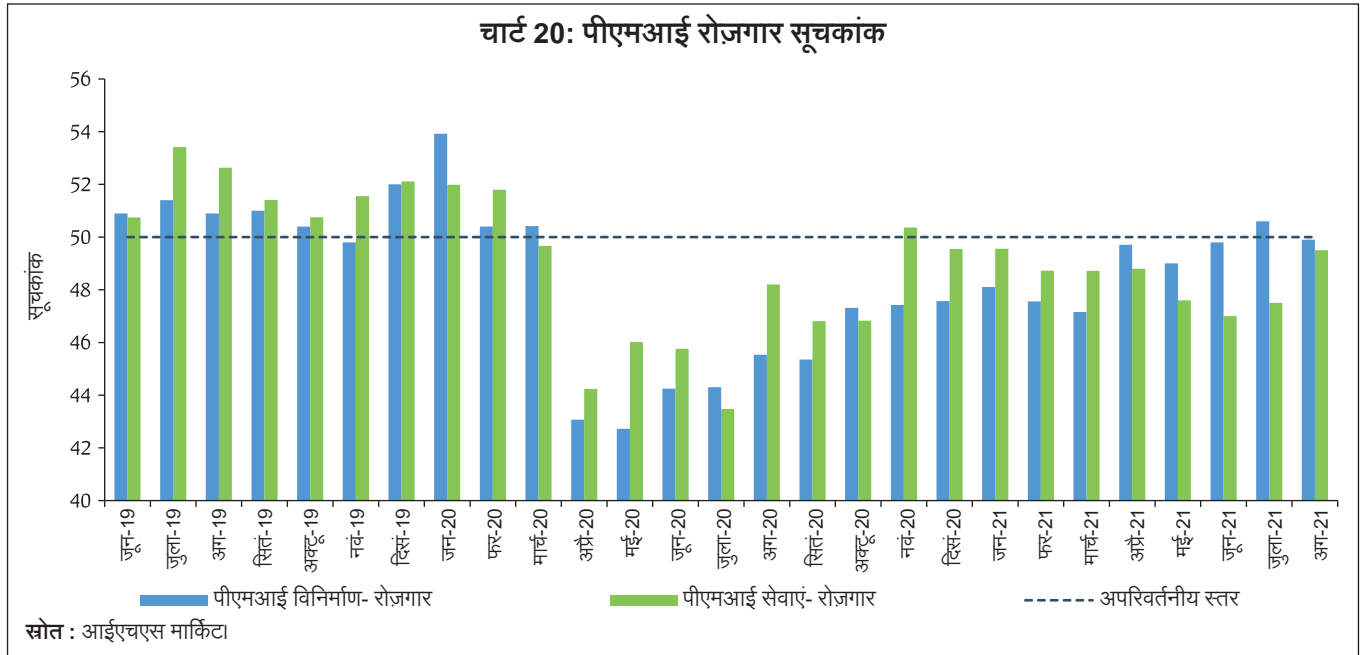


श्रम बाजार के आंकड़ों से पता चलता है कि दूसरी लहर का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा है (चार्ट 19)।

पीएमआई का रोजगार उप-सूचकांक एक मिश्रित तस्वीर दिखाता है। जबकि विनिर्माण के लिए उप-सूचकांक जुलाई 2021 में 50.6 पर मामूली विस्तार के बाद, अगस्त 2021 में 49.9 पर मामूली संकुचन पर वापस आ गया, सेवाओं में नौकरी छूटने की दर जुलाई 2021 में 47.5 से घटकर अगस्त 2021 में 49.5 हो गई (चार्ट 20)।

अप्रैल-जुलाई के दौरान, केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान (बीई) के 21.3 प्रतिशत पर रहा, जो कर राजस्व और कम राजस्व व्यय के पीछे था (चार्ट 21ए)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नेतृत्व में एक साल पहले इसी अवधि के मुकाबले पूंजीगत व्यय में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसने 2021-22 के लिए अपने बजटीय पूंजीगत व्यय का 44.7 प्रतिशत समाप्त कर दिया है (चार्ट 21 बी)।

राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के शुभारंभ के साथ पूंजी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा मिला है। संपत्ति मुद्राकरण, जिसमें एक सीमित अवधि के लिए एक निजी क्षेत्र की इकाई को सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति का लाइसेंस/पट्टा शामिल है, निजी क्षेत्र की पूंजी का दोहन करके इंफ्रास्ट्रक्चर

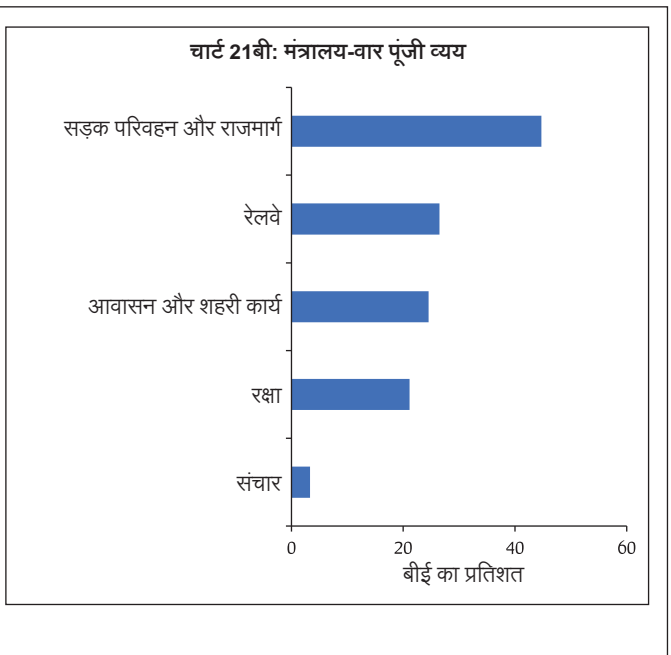
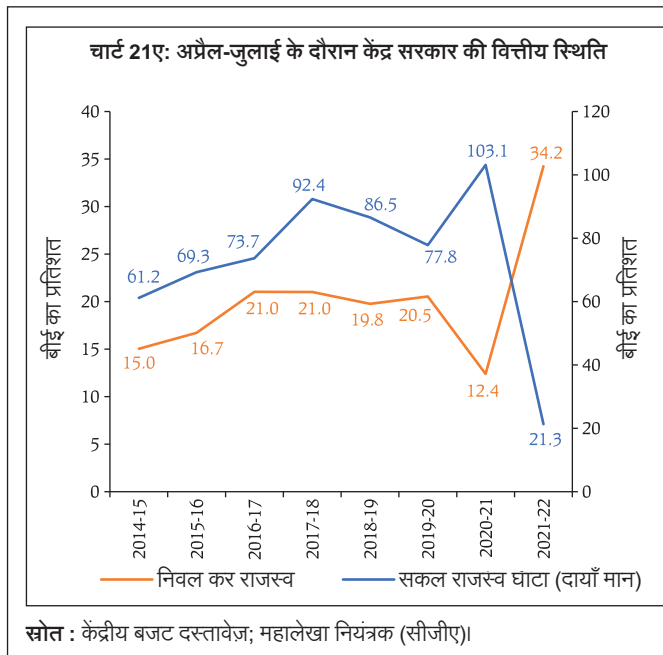


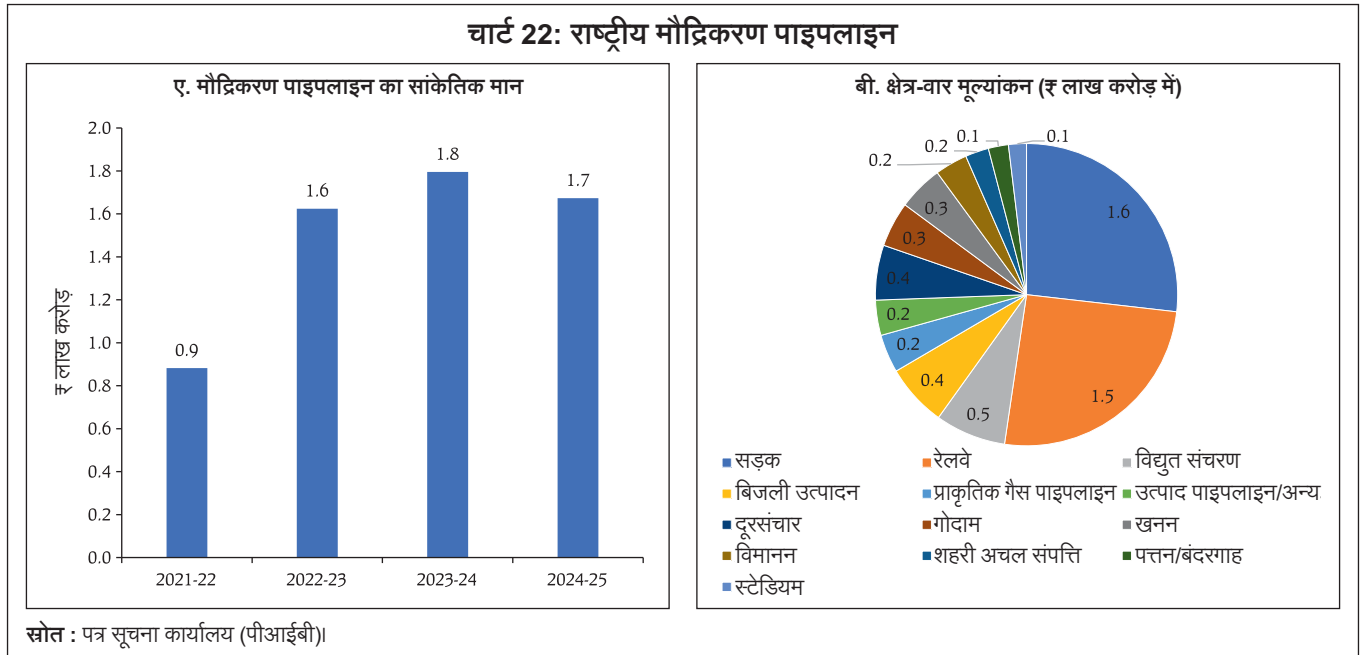
से सार्वजनिक निवेश के मूल्य के दरवाजे खोलता है। सरकार द्वारा प्राप्त धन को नए इंफ्रास्ट्रक्चर में पुनर्निवेश किया जा सकता है या अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए लगाया जा सकता है।

एनएमपी ने 2021-22 से 2024-25 तक की चार साल की अवधि में ₹ 6.0 लाख करोड़ की कुल मुद्राकरण क्षमता की परिकल्पना की है, जिसमें से चालू वित्त वर्ष में ₹0.88 लाख करोड़

जुटाने का अनुमान है। अधिकतम मूल्य उत्पन्न करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्रों में शामिल हैं: सड़कें (27 प्रतिशत); रेलवे (26 प्रतिशत); शक्ति (15 प्रतिशत); तेल और गैस पाइपलाइन (8 प्रतिशत); और दूरसंचार (6 प्रतिशत) [चार्ट 22]।

जीएसटी संग्रह (केंद्र एवं राज्य) अपने रास्ते पर बने रहे, जून में एक क्षणिक ब्लिप के बाद जुलाई और अगस्त में ₹ 1 लाख

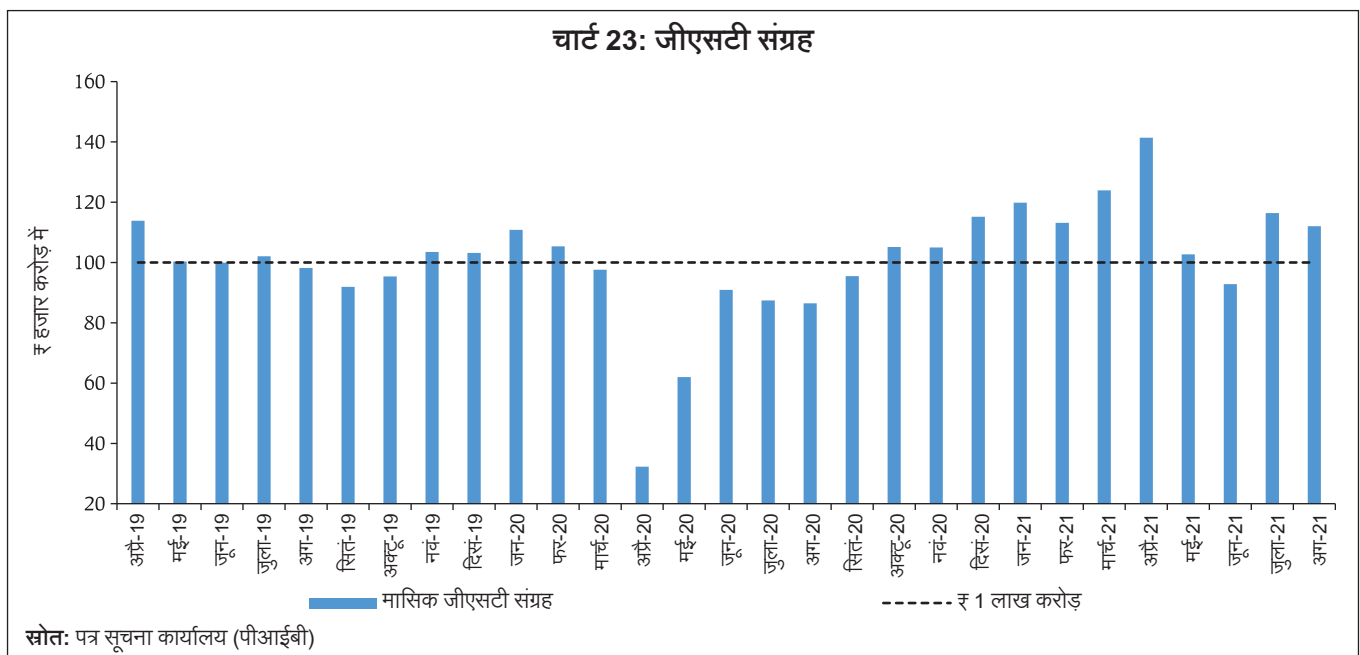


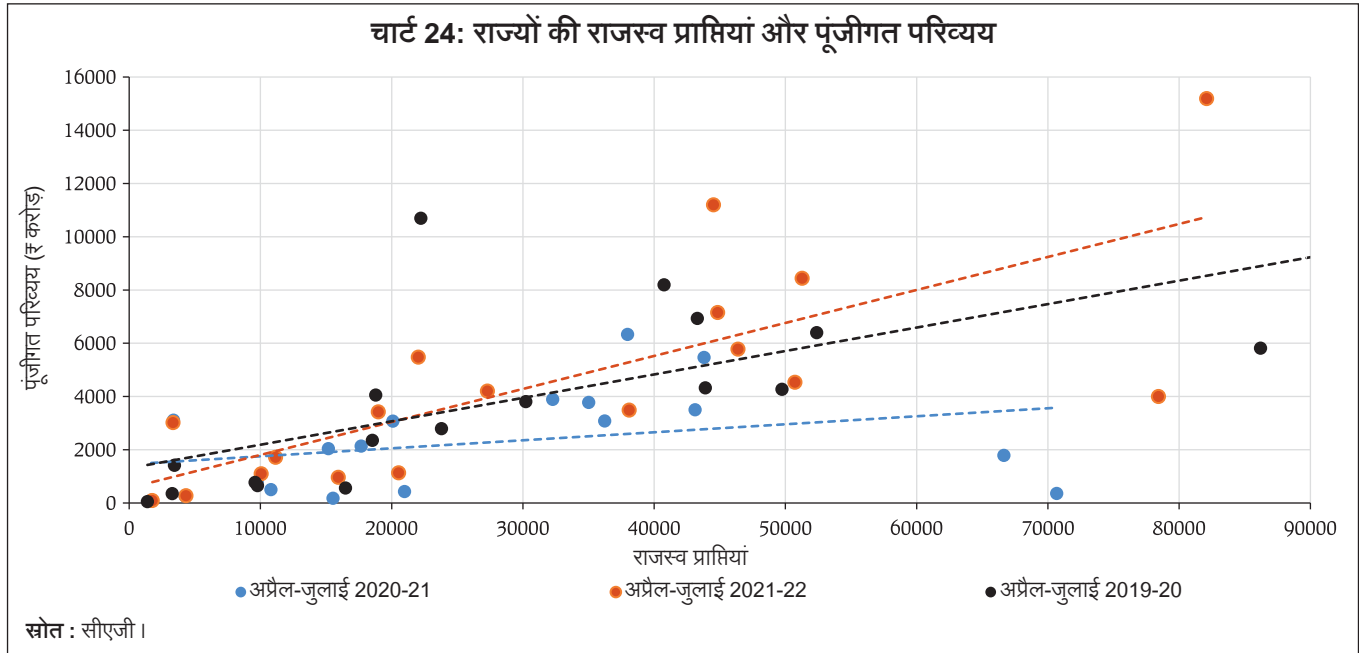


करोड़ की सीमा से ऊपर रहे, दूसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधि में पुनरुत्थान को दर्शाता है (चार्ट 23)।

18 राज्यों के लिए उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, उनके राजस्व संग्रह में अप्रैल-जुलाई 2021 में अप्रैल-जुलाई 2020 में संकुचन की तुलना में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर और स्वयं के गैर-कर राजस्व दोनों के तहत उच्च संग्रह हुआ, जो

राज्य-विशिष्ट लॉकडाउन में कमी होने के कारण था। यह, वर्ष के शेष भाग के लिए बेहतर संभावनाओं के साथ, राज्यों को अपने पूंजी परिव्यय का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान, पूंजी परिव्यय में 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 44.5 प्रतिशत की गिरावट आई थी। राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत परिव्यय दोनों के



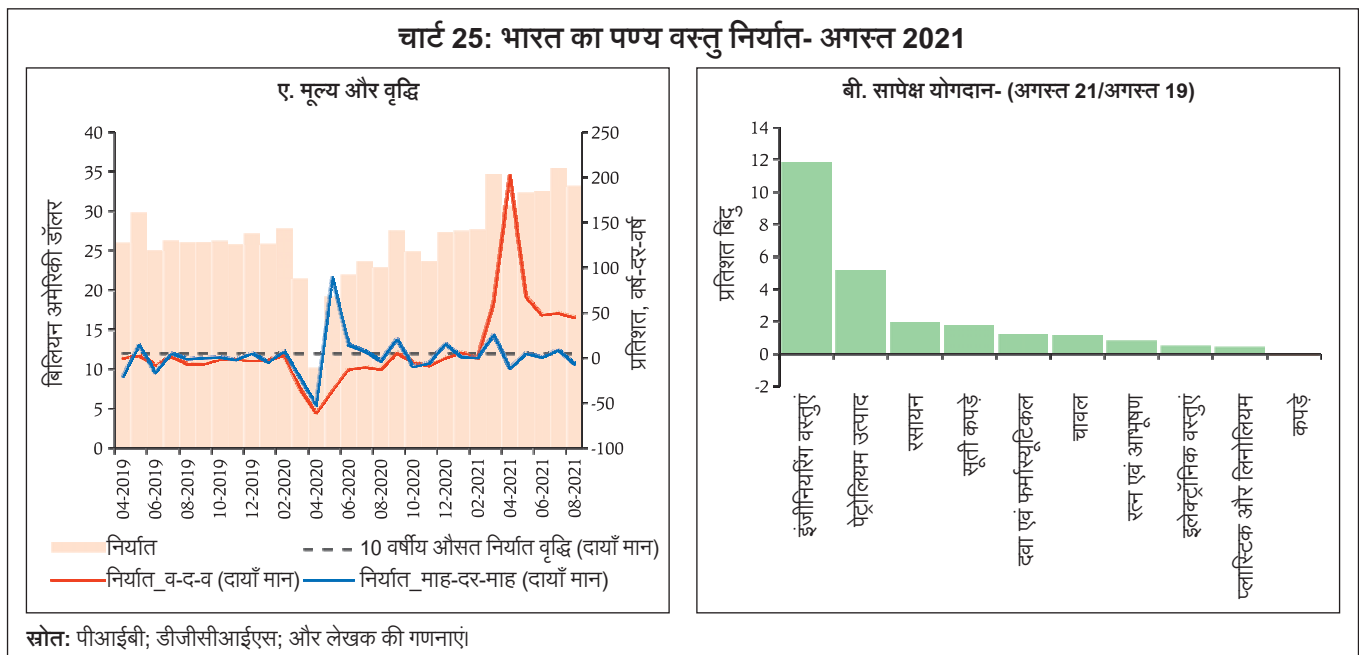


संदर्भ में, राज्यों ने अप्रैल-जुलाई 2019 की पूर्व-कोविड अवधि की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट 24)। इसी अवधि के दौरान, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा एक साल पहले के 29 प्रतिशत के मुकाबले बजट अनुमानों के 23 प्रतिशत पर था।

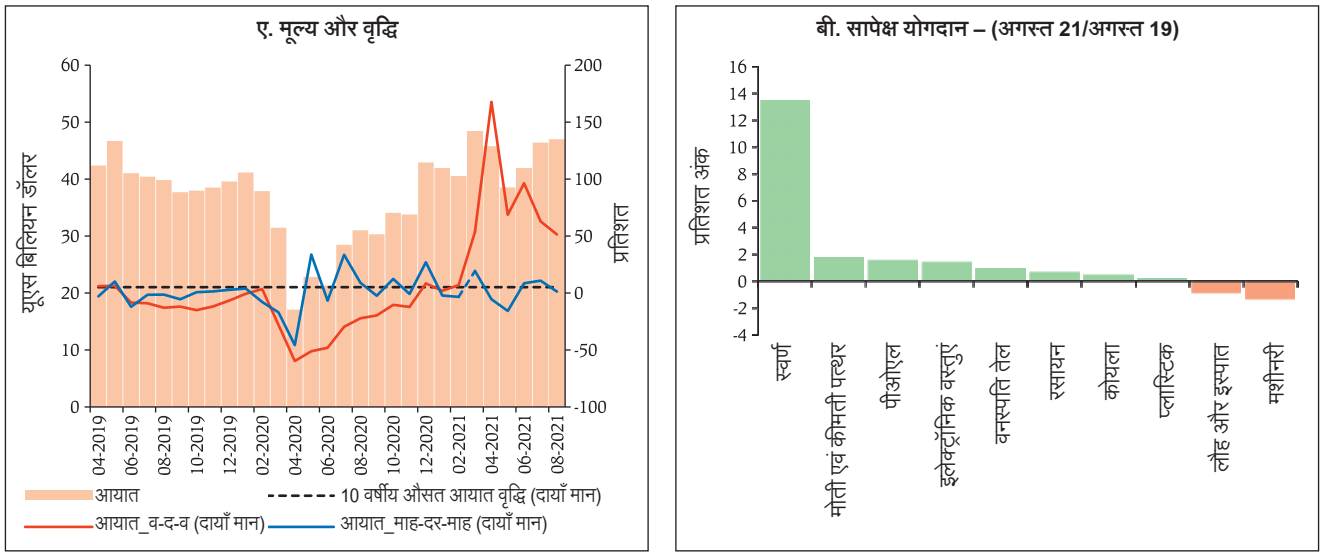
भारत का पण्य वस्तु निर्यात उनके शानदार प्रदर्शन के साथ जारी रहा (चार्ट 25)। इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों के लिए भागीदार देशों में मांग के कारण उच्च वृद्धि

हुई थी (चार्ट 25बी)। निर्यात वृद्धि 10 प्रमुख कमोडिटी समूहों में से 9 के रूप में व्यापक-आधारित रही - निर्यात टोकरी में 80 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार - एक साल पहले महीने के दौरान विस्तार दर्ज किया गया।

भारत का माल आयात पूर्व-कोविड-19 स्तरों की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा (चार्ट 26ए)। गैर-तेल-गैर-सोने का आयात लगातार नौवें महीने में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक



चार्ट 26: भारत का पण्य आयात- अगस्त 2021



स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; लेखकों की गणना

रहा है, जो अर्थव्यवस्था में जारी सुधार को दर्शाता है। आयात वृद्धि व्यापक रूप से 10 प्रमुख कमोडिटी समूहों में से 8 के रूप में बनी हुई है (जो कि आयात टोकरी का 80 प्रतिशत से अधिक है) पूर्व-महामारी के स्तर की तुलना में विस्तारित है (चार्ट 26 बी)।

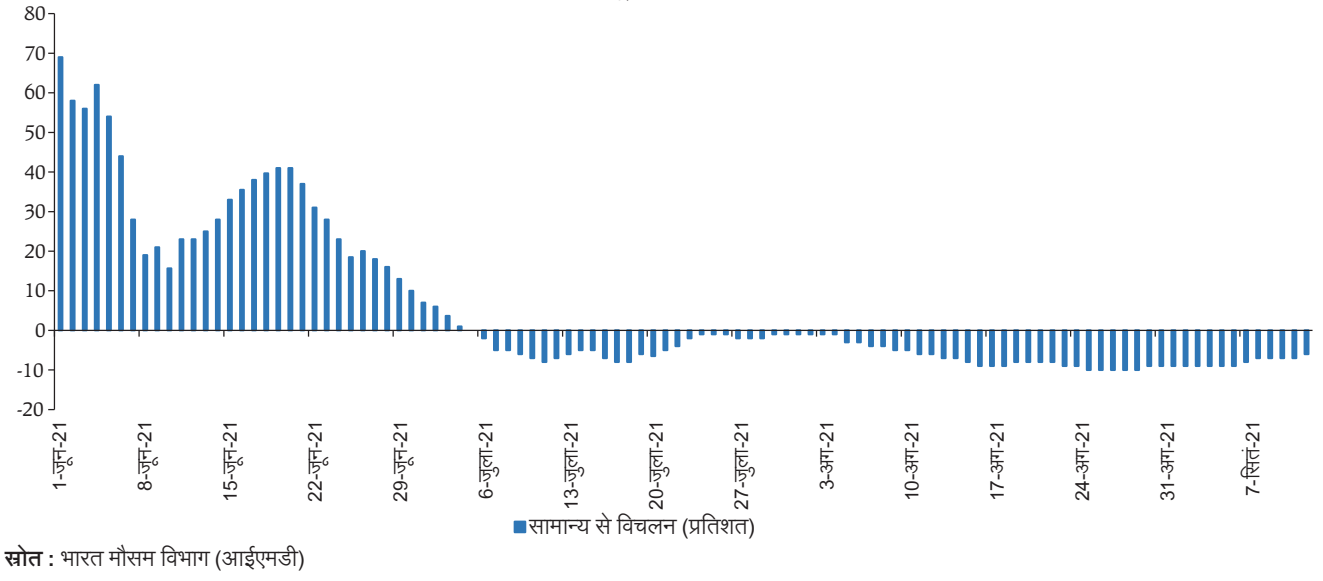
मई-जून 2021 तक तेजी से सिकुड़ने के बाद सोने का आयात जुलाई और अगस्त में बढ़ गया, जो उनके पूर्व-कोविड

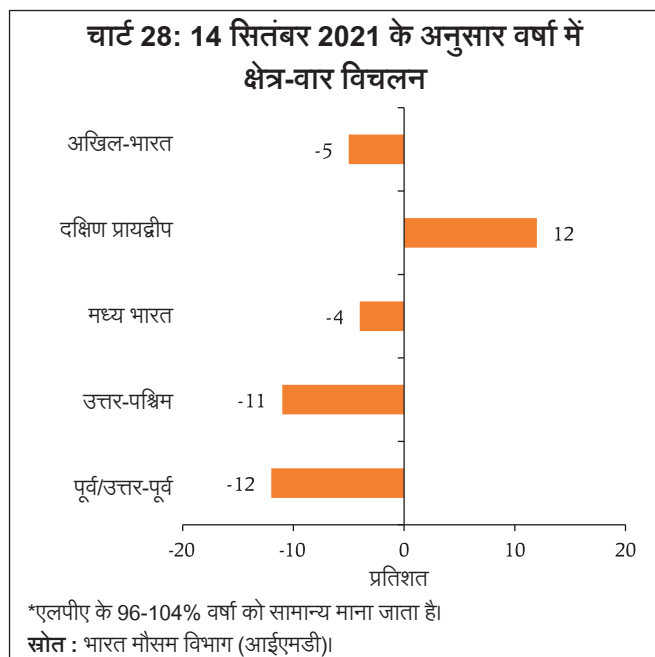
स्तर से कहीं अधिक है। यह रत्न एवं आभूषण उद्योग में शादियों के लिए रुकी हुई मांग और बेहतर कारोबारी धारणा के प्रभाव को दर्शाता है।

सकल आपूर्ति

1 जून - 14 सितंबर 2021 के दौरान संचयी बारिश (एसडब्ल्यू मानसून) दीर्घावधि के औसत (एलपीए) से 5 प्रतिशत

चार्ट 27 : दक्षिण पश्चिमी मानसून 2021- अखिल भारतीय संचयी वर्षा





कम थी (चार्ट 27)। दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में एलपीए से 12 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। हालांकि, पूर्व/उत्तर पूर्व भारत, मध्य

भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश हुई (चार्ट 28)। स्थानिक संवितरण से पता चलता है कि 1 जून से 14 सितंबर 2021 के दौरान 7 उप-मंडलों में भारी बारिश हुई थी, 22 उप-मंडलों में सामान्य और 36 उप-मंडलों में से 7 उप-मंडलों में कम/बहुत कम बारिश हुई थी।

कुल बुवाई क्षेत्र 1096.7 लाख हेक्टेयर था, जो एक साल पहले के रिकॉर्ड कवरेज से सिर्फ 0.9 प्रतिशत कम है, लेकिन सामान्य रकबे (5-वर्ष के औसत) से 3.5 प्रतिशत और पूर्ण सीजन रकबे (5-वर्ष औसत) से 2.2 प्रतिशत अधिक है (सारणी 3)।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सितंबर के लिए सामान्य से अधिक (एलपीए पर 10 प्रतिशत से अधिक) बारिश का अनुमान लगाया है। पूर्वानुमान से पता चलता है कि मध्य भारत के कई क्षेत्रों में सामान्य तथा सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश

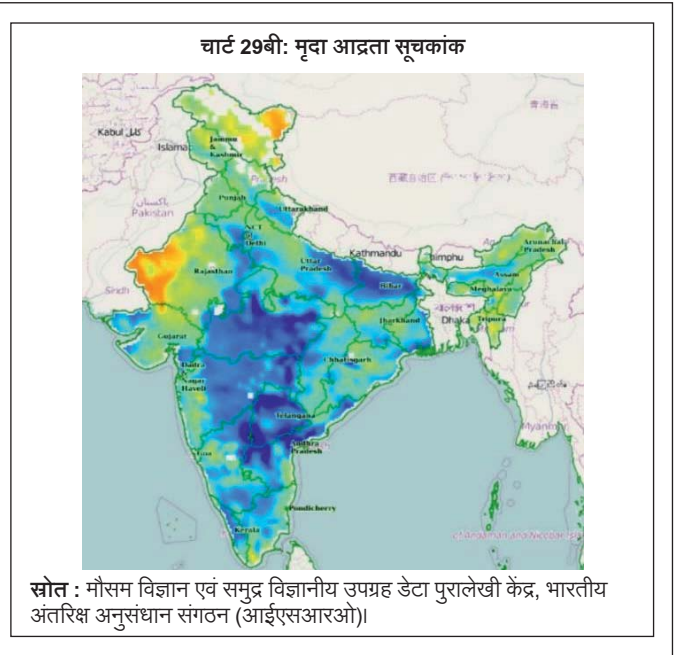
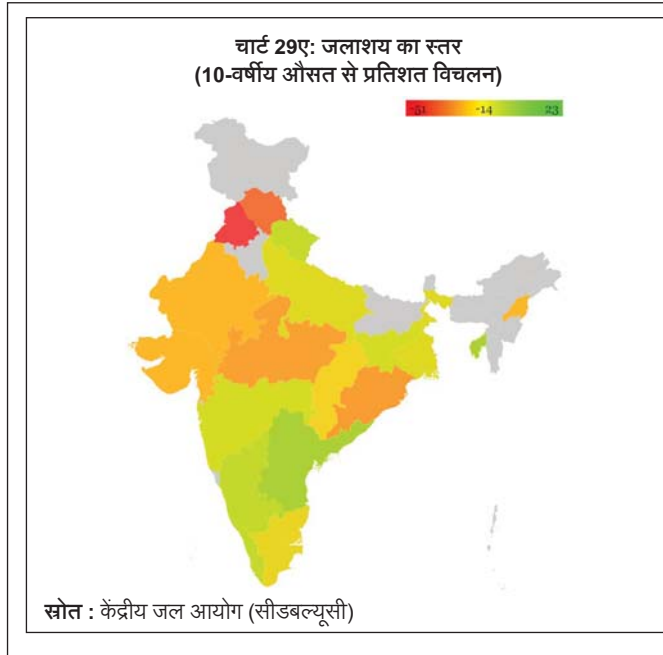
सारणी 3: अखिल भारतीय फसल स्थिति- खरीफ (2021-22) 10 सितंबर 2021 की स्थिति

फसल का नाम	संचयी औसत (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत उतार-चढ़ाव		अंतर्निहित क्षेत्र(संपूर्ण सामान्य सीजन का प्रतिशत*)
		Over normal* (as on date)	Over last Year	
1. चावल	409.6	6.5	0.4	103.5
2. मोटे अनाज	173.8	-2.7	-2.5	94.7
2ए. ज्वार	14.5	-16.2	-3.3	74.2
2बी. बाजरे	63.3	-6.4	-7.7	86.3
2सी. मक्का	81.1	1.9	1.6	108.6
3. कुल दालें	139.6	2.2	1.9	103.2
3ए. तूर	49.8	5.4	3.9	109.2
3बी. उड़द	38.9	0.1	1.5	104.3
3सी. मूंग	35.1	5.6	-0.3	104.8
3डी. कुलथी चने की दाल	0.5	-16.3	-3.6	23.5
3ई. अन्य	15.3	-8.2	2.4	91.6
I. कुल खाद्यान्न (1+2+3)	723.0	3.3	0.0	101.2
4. तिलहन	192.6	5.8	-1.6	107.0
4ए. मूंगफली	49.0	12.5	-3.8	117.5
4बी. सोया बीन	121.7	7.2	0.4	107.8
4सी. सूरजमुखी	1.5	20.6	26.1	105.9
4डी. तिल	13.2	-6.5	-4.2	100.2
5. कपास	119.5	0.1	-5.8	96.7
6. गन्ना	54.7	6.0	1.4	115.1
7. जूट और मेस्ता	7.0	-0.2	1.0	95.4
II. वाणिज्यिक फसलें (4+5+6+7)	373.7	3.8	-2.5	104.2
III. सभी फसलें (I+II)	1096.7	3.5	-0.9	102.2

*: सामान्य क्षेत्र: पिछले पांच वर्षों का औसत।

टिप्पणी: क्षेत्रफल के आंकड़े राज्य के कृषि विभागों के आकलन के अनुसार हैं।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएफडब्ल्यू)।



हिस्सों में सामान्य तथा सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।

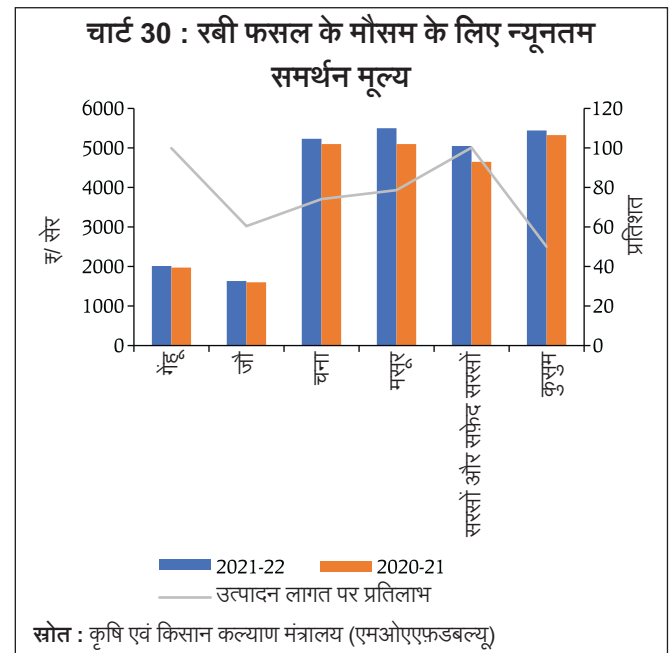
9 सितंबर 2021 तक जलाशय का स्तर दशक के औसत से केवल 6 प्रतिशत कम था, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा में कम स्तर था। पश्चिमी भागों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में मिट्टी का गीलापन सूचकांक सकारात्मक है (चार्ट 29)।

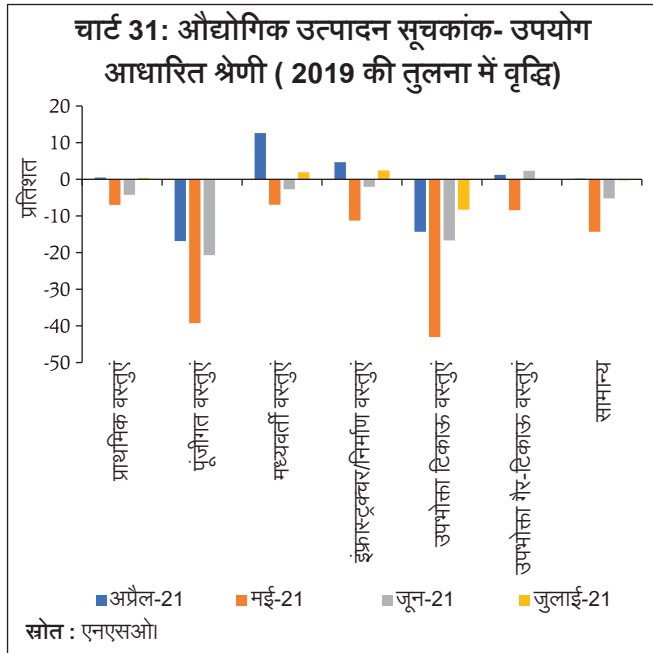
अगस्त 2021 के अंत तक, अनाज का स्टॉक स्तर चावल और गेहूं के बफर मानदंडों के क्रमशः 2.8 और 1.9 गुना पर्याप्त है।

8 सितंबर 2021 को आगामी रबी बुवाई सीजन (2021-22) के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की गई, जो एक साल पहले की तुलना में 2.0-8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (चार्ट 30)। रेपसीड और सरसों (8.6 प्रतिशत) के लिए एमएसपी में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद दाल (7.8 प्रतिशत) और चने (2.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। एमएसपी में मार्क-अप ने सभी फसलों के लिए उत्पादन लागत (जैसा कि ए2 प्लस एफएल[2] द्वारा मापा गया) से कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित किया है। बुवाई के मौसम से पहले उच्च एमएसपी की घोषणा कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। सरकार

ने 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए 307 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है।

जुलाई 2021 के महीने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने गतिविधि में सुधार का संकेत दिया क्योंकि इसमें 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जुलाई 2019 की तुलना में गिरावट की गति घटकर 0.3 प्रतिशत हो गई (2019 की तुलना में



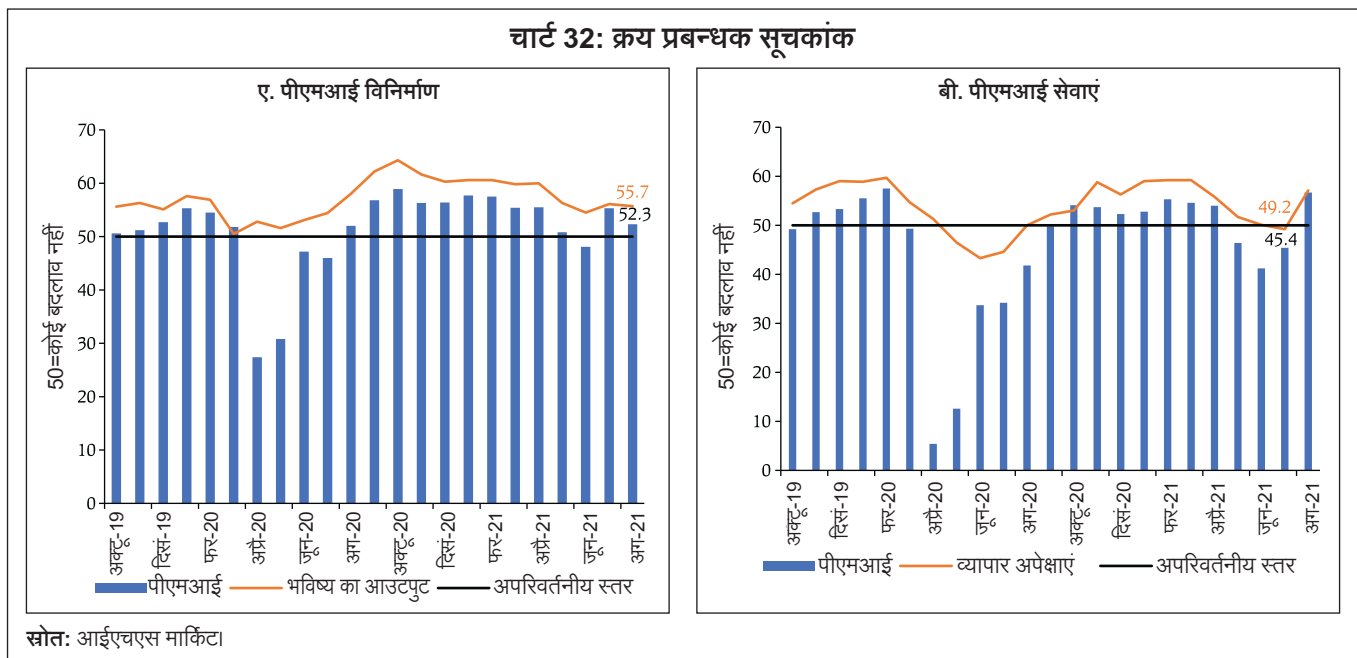


जून 2021 में -5.2 प्रतिशत)। 2019 की तुलना में सभी संकेतकों ने क्रमिक सुधार दिखाया। उपयोग-आधारित श्रेणियों में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के अलावा सभी ने जुलाई 2019 के पूर्व-महामारी स्तरों में सुधार दिखाया (चार्ट 31)।

अगस्त 2021 में हेडलाइन पीएमआई विनिर्माण 52.3 हुआ, जो जुलाई 2021 के 55.3 से कम था। महामारी की अनिश्चितताएं और बढ़ती निविष्टी लागत मामूली कम हुई। आउटपुट और नए ऑर्डर बढ़े लेकिन पिछले महीने की तुलना में कम थे। पिछले तीन महीनों के संकुचन के बाद, हेडलाइन पीएमआई सेवाएं, अगस्त 2021 में 56.7 तक बढ़ गईं। इसके अलावा, सेवाओं के लिए व्यापार प्रत्याशा सूचकांक, जो जुलाई 2021 में वर्ष में पहली बार संकुचित हुआ था, अगस्त 2021 में पांच महीनों के उच्चतम स्तर 57.1 पर पहुंच गया है। फर्मों को उम्मीद है कि कोविड-19 प्रतिबंध सहज होने के कारण मांग में सुधार होगा (चार्ट 32)।

सेवा क्षेत्र की मजबूत वृद्धि व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में सुधार से समर्थित है; हालांकि, 2019 के अनुरूपी स्तर के संबंध में, सेवा क्षेत्र के अधिकांश उच्च आवृत्ति संकेतकों के लिए विकास मजबूत रहा (सारणी 4)।

कुल मिलाकर, घरेलू आर्थिक गतिविधि दूसरी लहर में कमी के साथ उछाल के संकेत दे रही है। आईआईपी और आठ प्रमुख



सारणी 4: उच्च आवृत्ति सेवा संकेतक

उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवा वृद्धि (व-द-व प्रतिशत)						2019 की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)					
क्षेत्र	संकेतक	अप्रै-21	मई-21	अग-21	जुला-21	अग-21	अप्रै 21/ अप्रै 19	मई 21/ मई 19	जून 21/ जून 19	जुला 21/ जुला 19	अग 21/ अग 19
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री		162.5	119.3	44.7	7.6	5.7	-61.2	10.6	39.1	22.8
ग्रामीण मांग	दो पहिया बिक्री		26.1	4	-2.1	-11.4	-39.3	-79.6	-36	-17.1	-12.1
	तीन पहिया बिक्री	59587	-48.7	-8.8	40.5	59.7	-70.3	-97.6	-81.9	-67.9	-60.5
	ट्रैक्टर बिक्री	436.2	-8	18.9	3.3	-17	10.6	-4.3	45.5	43.1	45
	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	व्यावसायिक वाहनों की बिक्री	234.4					-49.2			
	रेल माल यातायात	70.7	39.1	20.5	18.4	16.9	10.5	9.5	11.2	13.0	21.5
	पोर्ट कार्गो यातायात	29.5	33.1	19.3	6.7	11.5	2.4	2.2	2.0	-7.2	-0.1
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	105896.5	608.7	53.8	136.4		-4.9	-34.2	-25.6	-17.2	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	2575.0	343.3	31.2	45.9		-4.3	-9.4	-5.6	-8.0	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	105896.5	608.7	53.8	136.4		-47.6	-82.9	-74.3	-58.1	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	2575.0	343.3	31.2	45.9		-75.2	-91.2	-90.8	-86.1	
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	582.5	56.8	25.9	32.7	33.3	11.9	-26.3	9.9	23.0	28.6
	जीएसटी ई-वे बिल (आंतरराज्यीय)	480.3	47.1	24.3	31.6	30.8	17.4	-20.6	14.5	26.5	32.7
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरराज्यीय)	840.6	76.5	28.8	34.4	37.2	4.3	-34.4	3.2	17.9	22.9
	पर्यटकों का आगमन	14674.9					-91.0				
विनिर्माण कार्य	स्टील की खपत	684.4	64.3	28.3	4.8	-4.2	11.3	-11.1	-4.6	-3.8	-15.0
	सिमेंट उत्पाद	582.7	7.5	21.8			0.8	-14.9	0.2	5.4	
पीएमआई सेवाएं	उत्पादन सूचकांक	54	46.4	41.2	45.4	56.7					
	कारोबार प्रत्याशा	55.8	51.7	50.1	49.2	57.1					

* 2021-22 की पहली तिमाही से संबंधित

उद्योग औद्योगिक गतिविधि में सुधार दर्शाते हैं जबकि अगस्त में सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक निरंतर सुधार की ओर इशारा करते हैं। ई-वे बिल, जीएसटी राजस्व, रेलवे भाड़ा, बिजली की मांग और श्रम बल भागीदारी दरों में मजबूत वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 प्रतिबंधों में सहजता और विपणन प्रयासों में वृद्धि के साथ पीएमआई भविष्य उत्पादन सूचकांक अगस्त के लिए उच्च बना हुआ है। मजबूत निर्यात वृद्धि से वैश्विक मांग में और सुधार प्रतिबिंबित होता है जो घरेलू सुधार का समर्थन करता है।

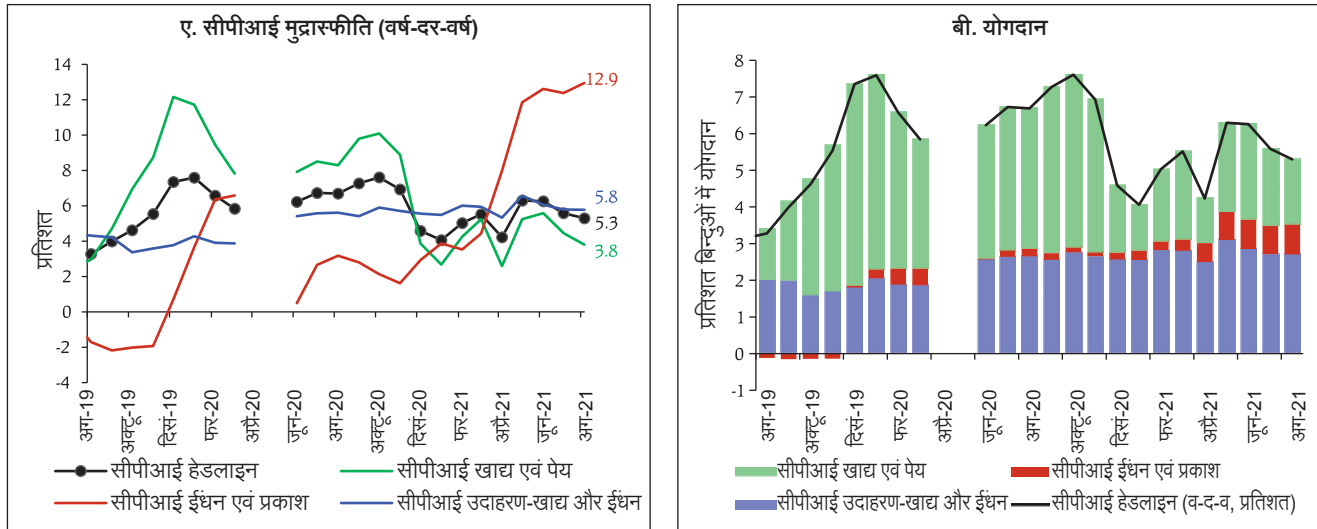
मुद्रास्फीति

13 सितंबर को एनएसओ द्वारा अगस्त 2021 के लिए हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति जारी की गई थी। इसने लगातार दूसरे महीने में राहत दी (चार्ट 33 ए)। एक अनुकूल आधार प्रभाव (एक साल पहले कीमतों में महीने-दर-महीने परिवर्तन) के साथ-साथ एक महीने पहले 70 बीपीएस से कीमतों (महीने-दर-महीने की कीमतों में वर्तमान महीने में परिवर्तन) में गिरावट के साथ

लगभग 20 बीपीएस हो गई। लगभग 50 बीपीएस, जिसने कीमतों की गति को पूरी तरह से ऑफसेट कर दिया, ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को एक महीने पहले के स्तर से 30 बीपीएस नीचे लाकर अगस्त में 5.3 प्रतिशत कर दिया, जो जुलाई 2021 में 5.6 प्रतिशत थी।

घटकों में, खाद्य और पेय पदार्थ मुद्रास्फीति जुलाई में 4.5 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 3.8 प्रतिशत हो गई। वास्तव में, खाद्य और पेय पदार्थ सूचकांक अगस्त और जुलाई के बीच अपरिवर्तित रहा। सब्जियों में अवस्फीति का गहराना, अनाज और चीनी में निरंतर अवस्फीति और अंडे, फलों, दालों और गैर-मादक पेय पदार्थों के मुद्रास्फीति में नरमी खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के मुख्य कारक थे। दूसरी ओर, तेल और वसा में मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी रही। हालांकि मांस और मछली और दूध में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, मांस और मछली की कीमतों में गिरावट आई और दूध की कीमत में गिरावट आई।

चार्ट 33: सीपीआई मुद्रास्फीति



टिप्पण: अप्रैल-मई 2021 की सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल-मई 2020 के लिए लगाए गए सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गयी थी।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ की गणना।

ईंधन मुद्रास्फीति लगभग 60 बीपीएस से बढ़कर 12.9 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई (2012=100 आधार वर्ष श्रृंखला में)। एलपीजी, केरोसिन, और जलाऊ लकड़ी और चिप्स इसके प्रमुख वाहक बने रहे। ईंधन (सीपीआई में 6.84 प्रतिशत का भार) ने अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 33 बी)।

खाद्य और ईंधन या मूल मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त 2021 में 5.8 प्रतिशत पर स्थिर रही। जबकि व्यक्तिगत देखभाल का सामान, परिवहन और संचार, और पान-तंबाकू और नशीले पदार्थों के उप-समूहों में मुद्रास्फीति दर्ज की गई, शिक्षा, कपड़े और जूते और घरेलू सामान और सेवाओं के उप-समूहों की मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गयी। अगस्त में आवास, मनोरंजन और स्वास्थ्य में मुद्रास्फीति कमोबेश स्थिर रही।

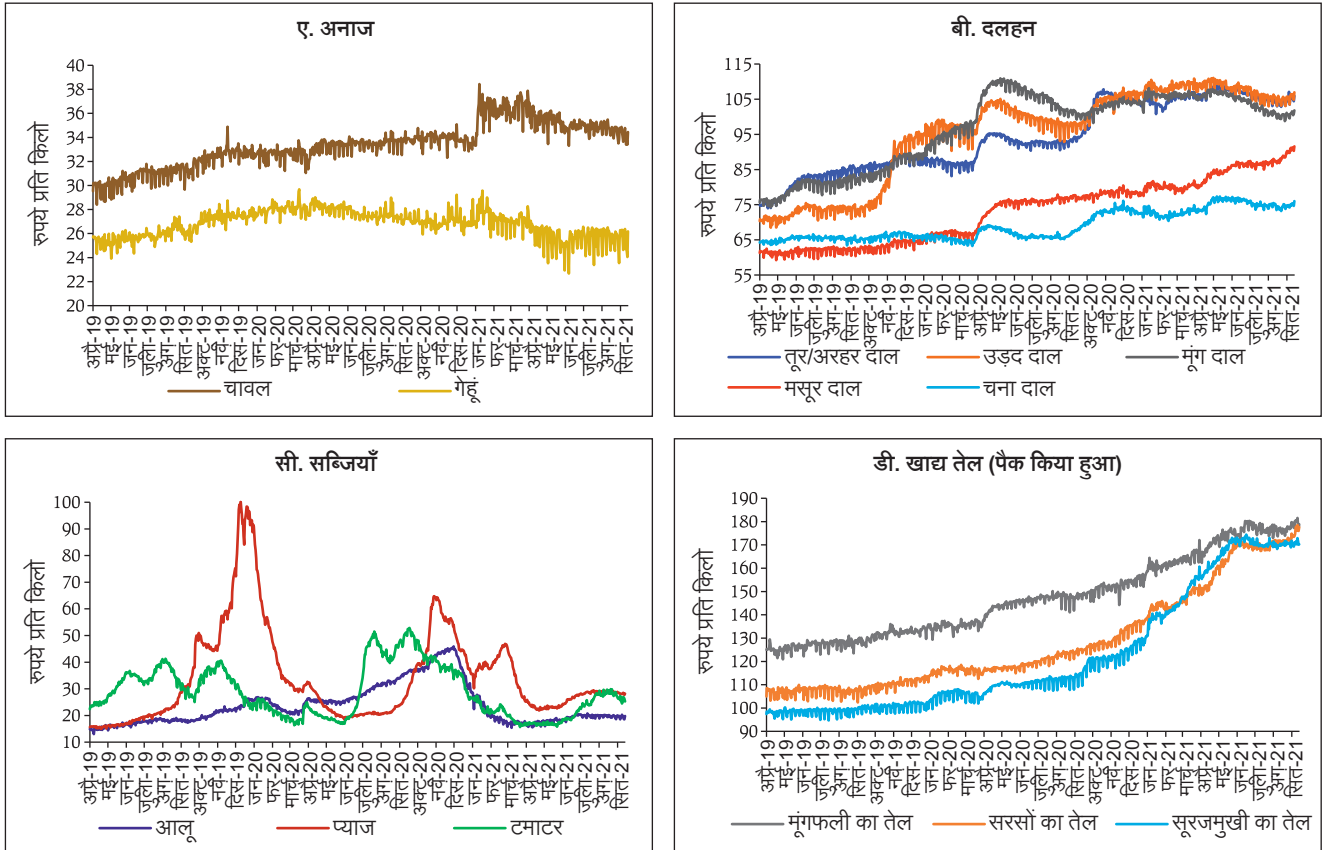
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से सितंबर के अब तक (13 तारीख तक) के उच्च आवृत्ति डेटा अनाज की कीमतों में और गिरावट दर्शाते हैं। दूसरी ओर, दालों की कीमतें, जो हाल के महीनों में कम

हो रही हैं, सितंबर में मसूर की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ उलट गई हैं। सितंबर में सभी प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में और तेजी आई है। प्रमुख सब्जियों - टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और यह वर्ष-दर-वर्ष में कम है (चार्ट 34)।

पंप की कीमतों (चार प्रमुख महानगरों में पंप की कीमतों का औसत) ने सितंबर में अब तक (सितंबर 1-13, 2021) कुछ नरमी दर्ज की, पेट्रोल के लिए ₹ 102.26 प्रति लीटर और डीजल के लिए ₹ 92.45 प्रति लीटर (13 सितंबर 2021 तक) जहां सितंबर पूर्वाध में मिट्टी के तेल की कीमतों में गिरावट आई, वहीं 17 अगस्त 2021 और 1 सितंबर 2021 को एलपीजी की कीमतों में ₹25 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई (सारणी 5)।

पीएमआई में परिलक्षित निविष्टि लागत, अगस्त में सभी विनिर्माण और सेवाओं में और बढ़ गयी। जबकि सेवाओं में निविष्टि लागत की दर तेजी से बढ़ी, इससे विनिर्माण में कुछ नरमी दिखाई बिक्री की कीमतों के लिए प्रभावी उच्च निविष्टि लागत से विनिर्माण

चार्ट 34 : डीसीए आवश्यक वस्तु की कीमतें



स्रोत: उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ का अनुमाना

और सेवाओं दोनों में पूर्व की तुलना में बाद में मूल्य निर्धारण शक्ति के कमजोर होने के साथ मंदी रही।

सारणी 5: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

मद	युनिट	घरेलू कीमतें			महीना-दर महीना (प्रतिशत)	
		सितं-20	अग-21	सितं-21 [^]	अग-21	सितं-21
पेट्रोल	₹/लीटर	84.36	103.03	102.29	0.2	-0.7
डीजल	₹/लीटर	76.10	93.32	92.48	-0.2	-0.9
केरोसीन	₹/लीटर	22.47	34.29	33.18	2.8	-3.2
एलपीजी (गैर सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	604.63	870.13	895.13	3.0	2.9

[^]: 1-13 सितंबर 2021 की अवधि के लिए

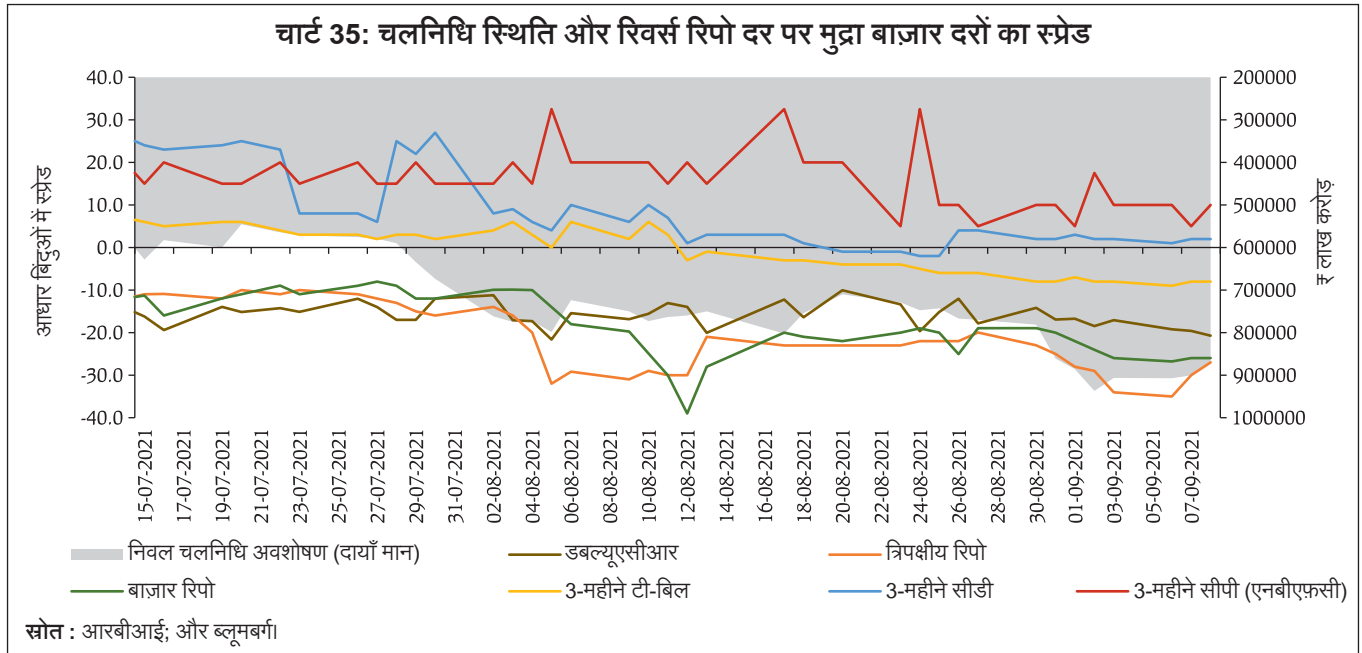
टिप्पणी: चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा लगाए जाने वाले कीमतों का औसत।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएससी); और लेखक का परिकलना

IV. वित्तीय स्थितियां

रिज़र्व बैंक परिचालन लचीलेपन और सहभागिता को बढ़ाकर, उचित प्रणालीगत चलनिधि सुनिश्चित करके, अनुचित अस्थिरता से युक्त और प्रतिफल वक्र के एक व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाकर वित्तीय बाजारों के संचालन और विकास में लगा रहा। नियमों को सुव्यवस्थित करने और ठोस और कुशल भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी फ्रेमवर्क के निर्माण के प्रयास चल रहे हैं।

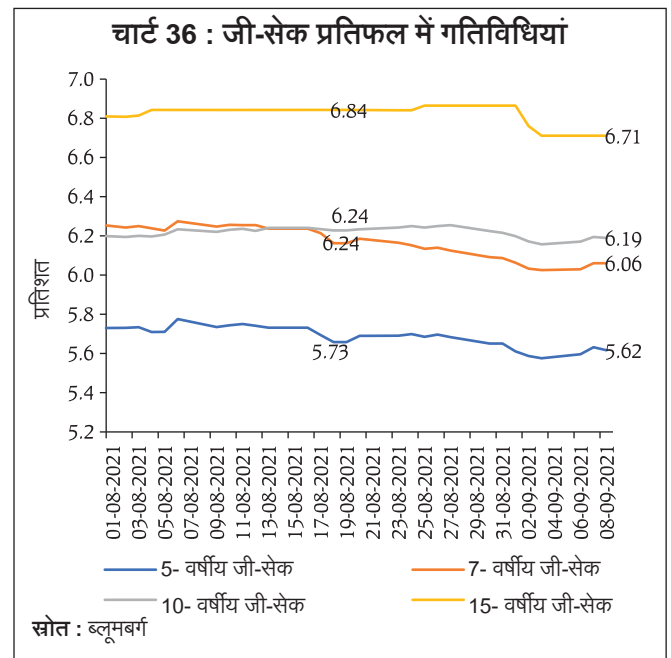
अगस्त और सितंबर के दौरान अब तक, घरेलू वित्तीय स्थिति सौम्य रही है, जिसमें सभी बाजार क्षेत्रों में पर्याप्त चलनिधि बनी हुई है। मुद्रा बाजारों में, अगस्त की शुरुआत से दरों में एक आरामदायक सहजता शुरू हो गई है, भले ही परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों के तहत अवशोषित

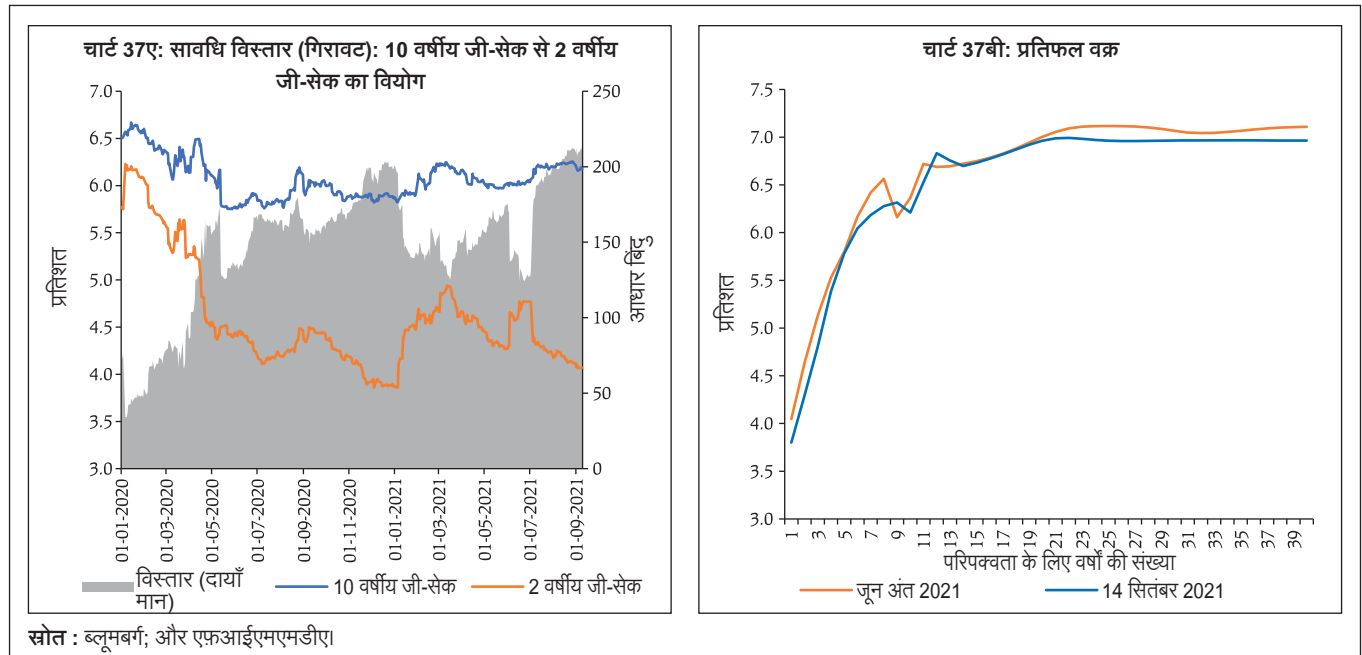


राशियों में वृद्धि हुई हो। इन परिचालनों ने 13 अगस्त, 27 अगस्त और 9 सितंबर को क्रमशः 1.8, 1.7 और 1.5 के बोली कवर अनुपात की मांग पर ज़ोर दिया। इसके अलावा, नीलामी कट-ऑफ 18 जून 2021 से लगातार कम हो गई है।

ओवरनाइट मुद्रा बाज़ार खंड में, भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) का रिवर्स रेपो दर से नीचे का स्प्रेड लगभग 16 बीपीएस पर काफी हद तक स्थिर रहा; हालांकि, अगस्त से सितंबर के दौरान (13 सितंबर तक) तृतीय पक्षकार रिपो और मार्केट रेपो दरों में औसतन 25 बीपीएस और रिवर्स रिपो दर से 21 बीपीएस नीचे कारोबार हुआ। अधिक चलनिधि ने टी-बिल और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दरों को रिवर्स रिपो दर से नीचे खींच लिया (चार्ट 35)। अगस्त-सितंबर (13 सितंबर तक) के दौरान, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत अवशोषित चलनिधि अधिक सरकारी खर्च के रूप में बढ़कर ₹8.0 लाख करोड़ हो गया। अब तक 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने द्वितीयक बाज़ार परिचालनों के माध्यम से ₹2.4 लाख करोड़ की स्थिर चलनिधि उपलब्ध करायी, जिसमें जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) (एसडीएल सहित) के माध्यम से ₹1.9 लाख करोड़ और एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर खुले बाज़ार में खरीद के माध्यम से शेष राशि शामिल हैं।

मुद्रा बाज़ार दरों में नरमी का पूर्वाग्रह भी ऋण बाज़ार में फैल गया और जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी मौद्रिक नीति सामान्यीकरण डोविश टिप्पणियों द्वारा वक्र के लॉग एंड में बढ़ाया गया था (चार्ट 36)। जुलाई 2021 के लिए अनुमानित सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट से कम, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में नरमी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बाज़ार की





भावनाओं का समर्थन करने के लिए संयुक्त रूप से जीएसटी की कमी को पाटने के लिए अतिरिक्त उधारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अगस्त 2021 के अंत में 6.22 प्रतिशत से 13 सितंबर, 2021 को 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल घटकर 6.19 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक बाजार में, अगस्त में आयोजित सभी नीलामी सुचारू रूप से संपन्न हुई, जिससे छ1:2021-22 के लिए निर्धारित बजटीय सरकारी उधारी का लगभग 89 प्रतिशत पूरा किया गया।

स्प्रेड शब्द, जिसे आमतौर पर 10-वर्ष और 2-वर्ष की जी-सेक यील्ड के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, बढ़ रहा है,

जो जुलाई 2021 के बाद से यील्ड कर्व में तेजी से परिलक्षित होता है (चार्ट 37ए और 37बी)।

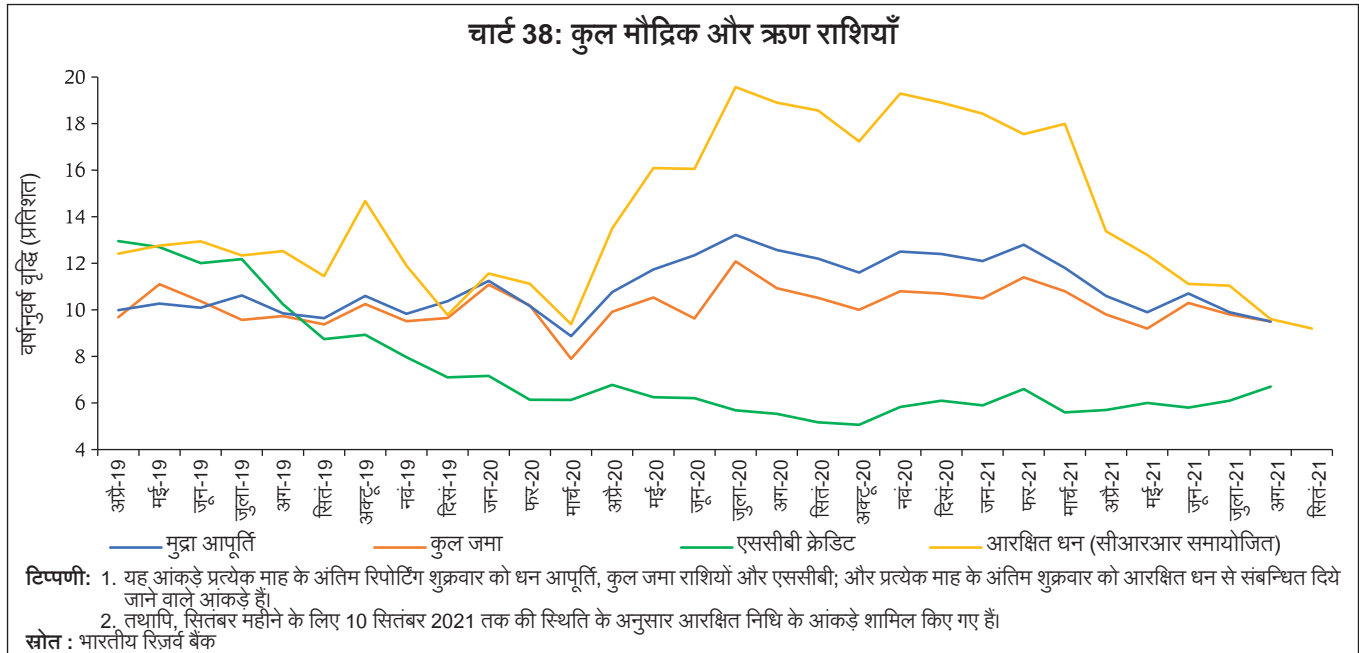
जी-सेक यील्ड के साथ अगस्त और सितंबर के दौरान अब तक (13 सितंबर तक) कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड में कमी आई है। पिछले महीनों की तुलना में कॉर्पोरेट बॉन्ड की अपेक्षाकृत कम आपूर्ति, अनुकूल वित्तीय स्थितियों के साथ, प्रतिफल के लिए सुलभ झुकाव प्रदान किया। हालांकि, संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों के स्प्रेड का पिछले महीने की तुलना में सितंबर (9 सितंबर तक) के दौरान जारीकर्ताओं और रेटिंग श्रेणियों में विस्तार हुआ (सारणी 6)।

सारणी 6: कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड

जारीकर्ता	प्रतिफल	प्रतिफल			स्प्रेड		
		अग-21	सितं-21	घट-बढ़ (अगस्त 21 की तुलना में सितंबर 21)	अग-21	सितं-21	घट-बढ़ (अगस्त 21 की तुलना में सितंबर 21)
पीएसयू, बैंक	एएए	5.40	5.25	-14	44	47	3
	एए	6.14	6.05	-9	118	127	9
	बीबीबी-	9.28	9.20	-8	433	442	9
कॉर्पोरेट	एएए	5.20	5.19	-1	24	40	16
	एए	6.04	6.02	-2	108	123	15
	बीबीबी-	9.99	9.96	-3	504	517	14
एनबीएफसी	एएए	5.35	5.29	-6	40	50	10
	एए	6.25	6.23	-2	130	144	14
	बीबीबी-	10.44	10.42	-2	549	563	14

टिप्पण: प्रतिफल तथा स्प्रेड तीन वर्षीय कॉर्पोरेट बॉण्ड के माह का औसत हैं।

स्रोत: एफआईएमएमडीए



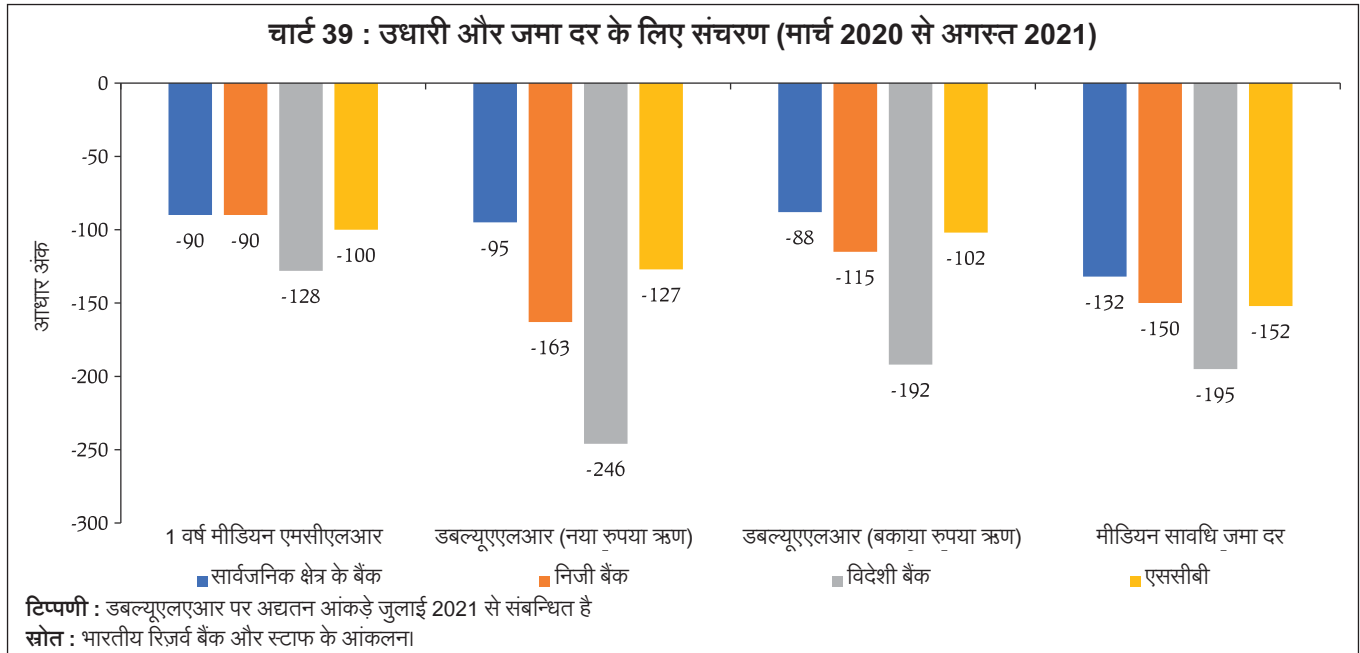
कुल मिलाकर मौद्रिक और ऋण स्थितियां आर्थिक सुधार में सहायक रहीं। आरक्षित मुद्रा (आरएम) वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष), आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, 10 सितंबर, 2021 को 9.2 प्रतिशत तक कम हो गया (एक साल पहले 19.0 प्रतिशत) [चार्ट 38]। प्रचलन में मुद्रा - आरएम का सबसे बड़ा घटक - नवंबर 2017 (एक साल पहले 22.4 प्रतिशत) के बाद से 9.4 प्रतिशत की सबसे धीमी गति से बढ़ा, जो पहली लहर के दौरान एक साल पहले दर्ज की गई वृद्धि के विपरीत कम एहतियाती मांग को दर्शाता है। 27 अगस्त, 2021 को मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 12.6 प्रतिशत), जो इसके 10.9 प्रतिशत के एक दशक औसत (2012-21) से कम है।

बैंकों की कुल जमाराशि - एम3 का सबसे बड़ा घटक - मजबूत बना रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 9.5 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 10.8 प्रतिशत)। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का ऋण, जो जुलाई 2021 से एक साल पहले की तुलना में तेजी से बढ़ा है, 27 अगस्त 2021 को 6.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई (एक साल पहले 5.5 प्रतिशत)।

रिजर्व बैंक द्वारा भावी मार्गदर्शन के साथ, अधिक चलनिधि ने मौद्रिक संचरण को आसान बनाया। मार्च 2020 के बाद से एससीबी की भारित औसत उधार दर (नए रुपया ऋण) और सावधि जमा दरों के लिए प्रभावी नीतिगत दरों में कटौती रही है (चार्ट 39)। मार्च 2020 से अगस्त 2021 तक औसत सावधि जमा दर में 152 बीपीएस की कमी आई। एक वर्ष तक की परिपक्वता की अल्पावधि जमाराशियों में 181 बीपीएस की बड़ी गिरावट देखी गयी है।

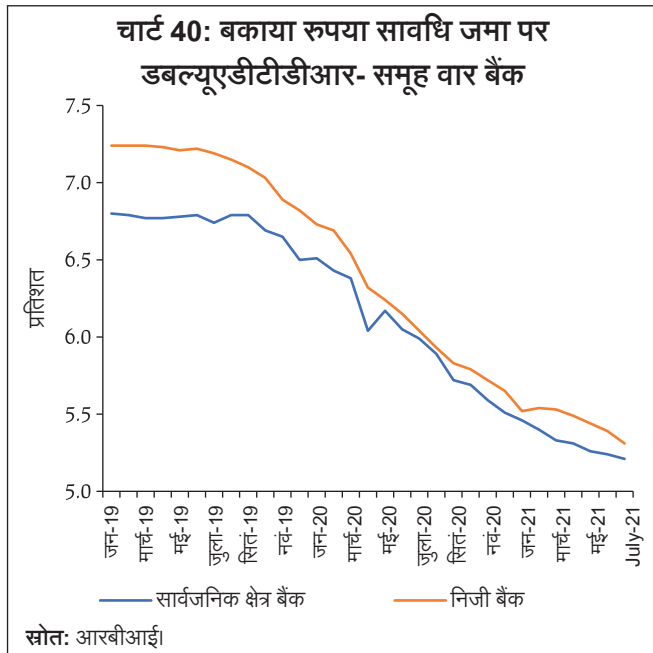
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की तुलना में निजी बैंक उच्च प्रभावी सावधि जमा दरों से प्रभावित रही, जो पूर्व में उच्च जमा वृद्धि के कारण है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) का अभिसरण हुआ है (चार्ट 40)। मार्च 2020 के बाद से, एससीबी की फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत में संचयी रूप से 100 बीपीएस की कमी आई है।

अगस्त और सितंबर की पहली छमाही में, भारतीय इक्विटी बाजार सहायक वैश्विक संकेतों, मजबूत जीएसटी संग्रह, ति1:



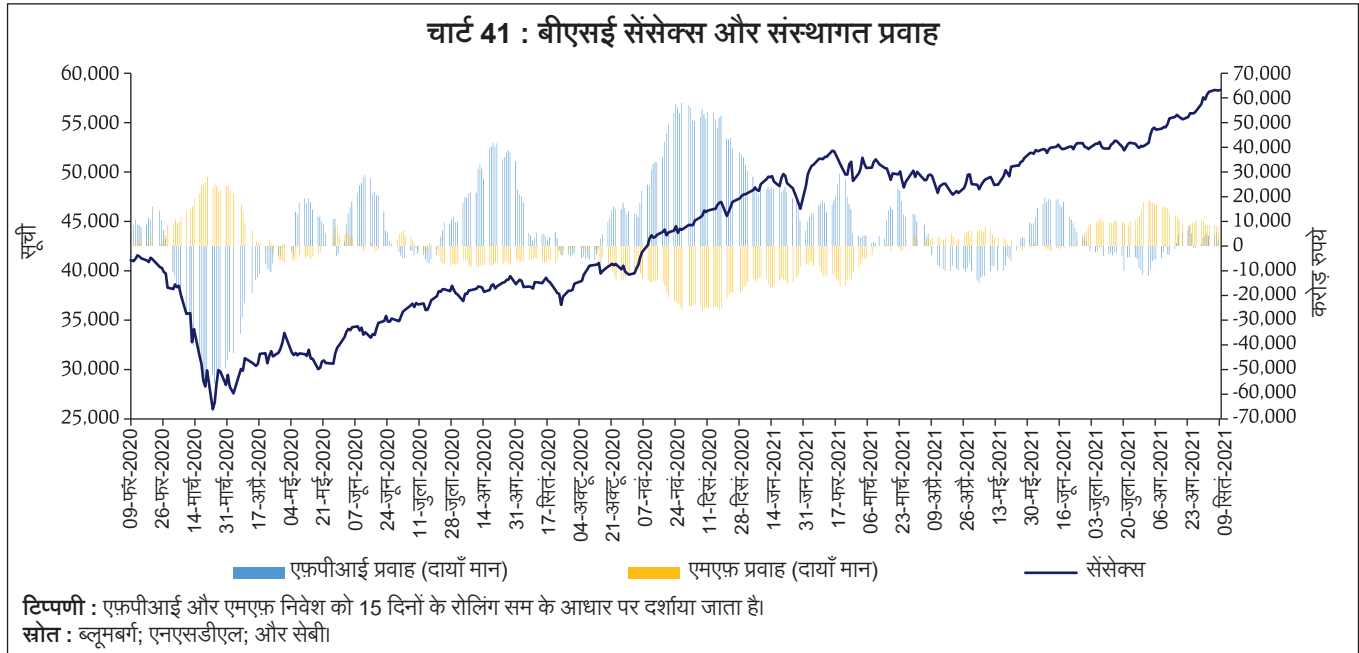
2021-22 के लिए मजबूत कॉर्पोरेट आय परिणाम और टीकाकरण अभियान में तेजी से उत्साहित रहा। अगस्त 2021 में बीएसई बेंचमार्क 9.4 प्रतिशत और सितंबर में 1.2 प्रतिशत बढ़कर (14 सितंबर तक) 58,247 पर बंद हुआ (चार्ट 41)। बेंचमार्क सूचकांकों ने कई रिकॉर्ड स्तरों को पार किया और

सितंबर में अब तक मिड-कैप और स्मॉल-कैप सूचकांकों में क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत और क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ बाजार मध्यम बढ़त के साथ बंद हुआ।



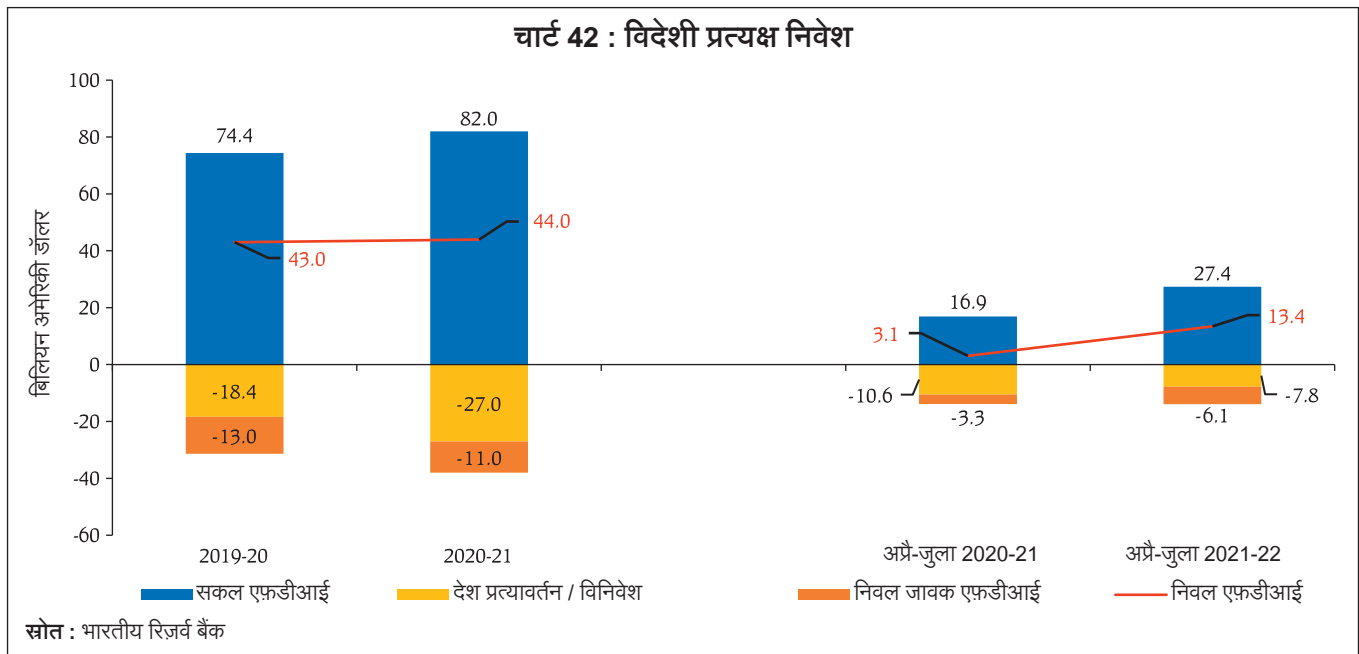
एक साल का फॉरवर्ड वैल्यूएशन 25 गुना है, जबकि अन्य तुलनायोग्य देशों के लिए 7-17 गुना है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने महीने के अंतिम सप्ताह में स्टॉक उतारने के बावजूद अगस्त में ₹7,454 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। 2021-22 में अब तक, एफपीआई प्राथमिक बाजार में शुद्ध खरीदार होने के दौरान द्वितीयक बाजार खंड में विक्रेता - आईपीओ और अन्य प्राथमिक निर्गमों में निवेशक रहे हैं।

घरेलू म्यूचुअल फंड ने अगस्त और सितंबर में भारतीय इक्विटी बाजार में अपने निवेश का विस्तार किया, जो विभिन्न नए फंड ऑफर की सफलता से प्रेरित था। अगस्त में इक्विटी फंडों ने ₹8,057 करोड़ का निवेश प्राप्त किया। म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजारों में नए खुदरा निवेशकों की रिकॉर्ड एंट्री हुई है। मासिक एसआईपी का योगदान, जो खुदरा निवेशकों को दीर्घवधि में छोटी मात्रा में निवेश करने की अनुमति देता है, अगस्त में

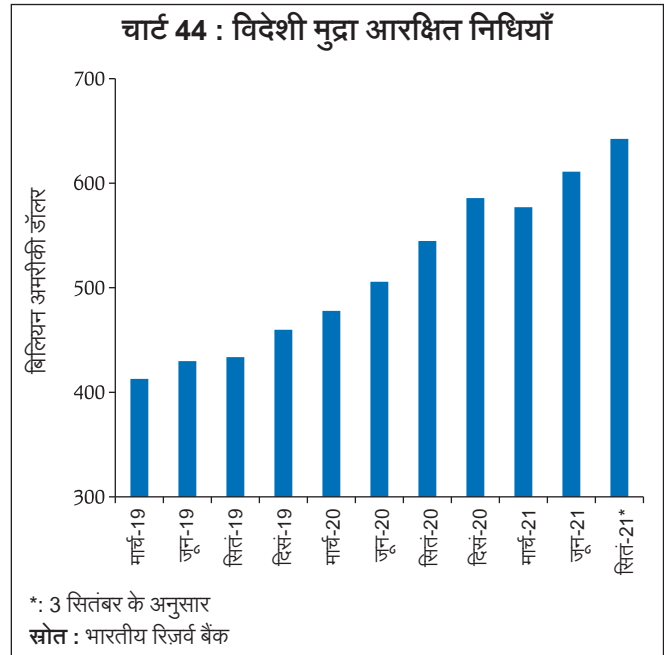
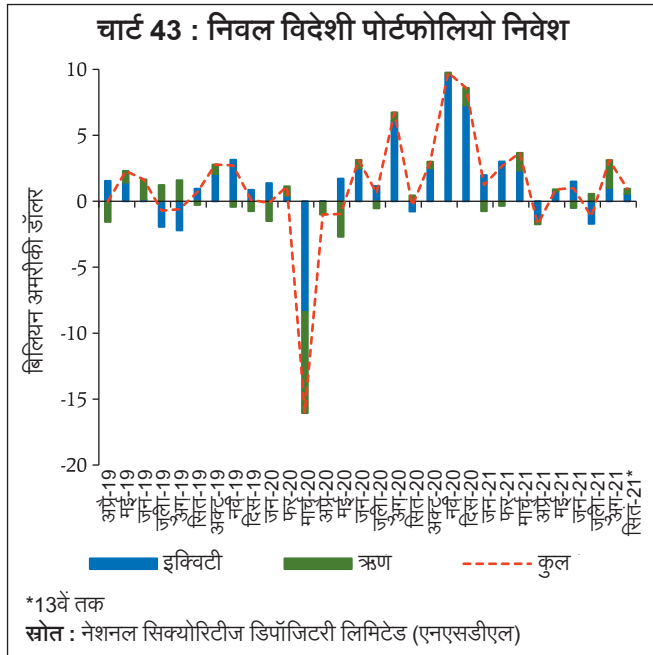


₹9,923 करोड़ का एक नया स्तर दर्ज किया गया (मार्च 2021 में 9,182 करोड़ रुपये से 8.1 प्रतिशत अधिक)। केवल अगस्त में मात्र 24.92 लाख नए पंजीकरण के साथ खुदरा एसआईपी खातों की संख्या बढ़कर 4.32 करोड़ हो गई⁶

संचयी रूप से, निवल एफडीआई एक साल पहले के 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जुलाई 2021 में 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट 42)।



⁶ <https://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/equity-inflows-dip-as-etfs-marginally-surge-shows-amfi-monthly-data-release-7444581.html>



घरेलू कर्ज बाजार में, वैश्विक प्रतिफल की तुलना में घरेलू प्रतिफल में वृद्धि के कारण एफपीआई अगस्त 2021 में लगातार दूसरे महीने शुद्ध खरीदार बने रहे। 2021-22 में (13 सितंबर तक), स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत शुद्ध निवेश एक साल पहले 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट 43)।

भारत के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की मंजूरी और वितरण में जुलाई 2021 में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो घरेलू कारोबारी माहौल में सुधार दर्शाती है। संचयी रूप से, भारत में ईसीबी अंतर्वाह (इंटरकंपनी उधार सहित) अप्रैल-जुलाई 2021 में बढ़कर 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 6.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

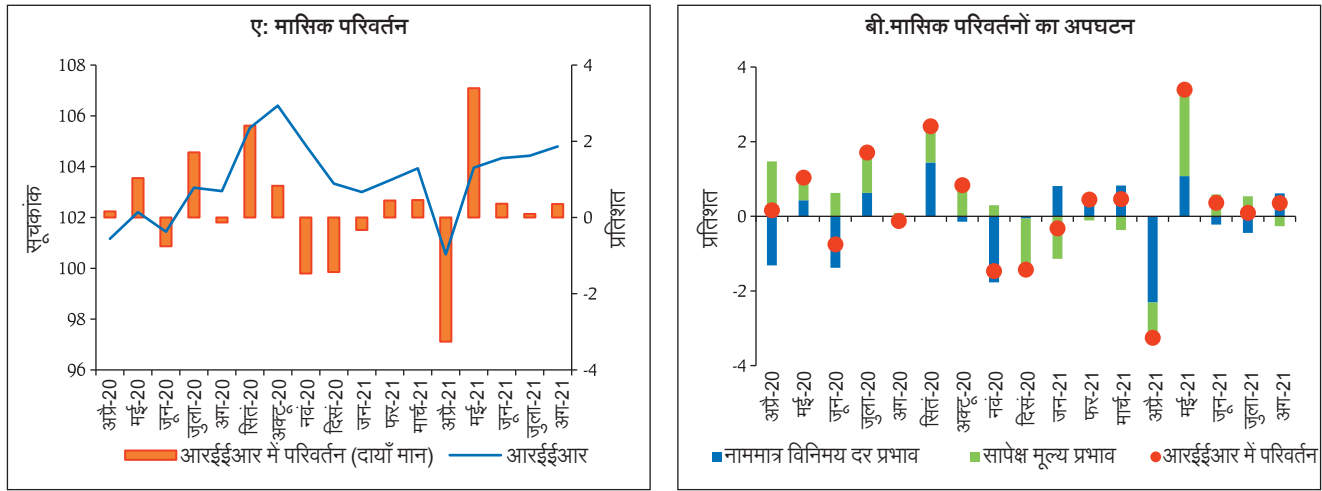
3 सितंबर 2021 को विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 642.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के सामान्य

आवंटन को दर्शाता है, जिसमें से भारत को यूएस \$ 17.9 प्राप्त हुआ (चार्ट 44)।⁷ आरक्षित निधियों का स्तर 2021-22 के लिए अनुमानित 15 महीने के आयात के करीब है।

विदेशी मुद्रा बाजार में, एफपीआई प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बीच, अगस्त 2021 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आईएनआर में 0.5 प्रतिशत (म-द-म) की वृद्धि हुई। यह विकास 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक के संदर्भ में आईएनआर के उतार-चढ़ाव में परिलक्षित होता है, जो एक महीने पहले अपने स्तर से 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 45 ए और 45 बी)।

⁷ 2 अगस्त, 2021 को, आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कोविड-19 संकट के प्रभाव से निपटने के लिए विशेष रूप से अधिक कमजोर सदस्य देशों की मदद करने के उद्देश्य से अपने सदस्यों के लिए 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग एसडीआर 456 बिलियन) के बराबर एसडीआर के सामान्य आबंटन को मंजूरी दी। यह आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा आबंटन है जो 23 अगस्त, 2021 को प्रभावी हुआ। नए बनाए गए एसडीआर को सदस्य देशों में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में जमा किया गया था।

चाट 45 : 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) में मासिक गतिविधियां (आधार : 2015-16=100)



टिप्पणी : अगस्त 2021 के आंकड़े अनंतिम हैं
 स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

भुगतान प्रणाली

भुगतान क्षेत्र में, प्रमुख भुगतान लिखतों के माध्यम से डिजिटल लेनदेन अगस्त और सितंबर (9 सितंबर तक) में मूल्य और मात्रा दोनों के लिहाज से निरंतर वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई (सारणी 7)। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) लेनदेन, समग्र व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक, लगातार तीसरे महीने तेज रहा। खुदरा क्षेत्र में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के माध्यम से भुगतान में और

तेजी आई 9 अगस्त 2021को लाभार्थियों को ₹19,500 करोड़ से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत संवितरण के कारण नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) लेनदेन मूल्यों में वृद्धि हुई थी।⁸ यह आने वाले दिनों में ग्रामीण खुदरा व्यय के लिए बेहतर है। ई-रुपी की क्षमता के प्रमाण के रूप में, जारीकर्ता बैंकों की संख्या 11 (लॉन्च होने पर) से बढ़कर 16 हो गई है।⁹

17 अगस्त, 2021 को रिज़र्व बैंक ने अपना वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रस्तुत किया, एक व्यापक सूचकांक जिसमें 97 संकेतक शामिल हैं, जिन्हें तीन व्यापक शीर्षों में - पहुंच (35 प्रतिशत भार),

सारणी 7: चयनित भुगतान प्रणालियों का वृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेनदेन की मात्रा में वृद्धि (व-द-व प्रतिशत)				लेनदेन के मूल्य में वृद्धि (व-द-व प्रतिशत)			
	जुलाई-2020	जुलाई-2021	अग-2020	अग-2021	जुलाई-2020	जुलाई-2021	अग-2020	अग-2021
आरटीजीएस	-2.1	34.4	-1.7	42.6	-33.7	28.9	-36.7	39.4
एनईएफटी	9.4	32.0	6.0	37.2	10.0	12.3	7.5	14.5
यूपीआई	82.1	116.7	76.3	119.6	98.5	108.5	93.1	114.2
आईएमपीएस	17.3	58.7	22.9	54.3	24.0	37.9	24.3	36.2
एनएसीएच	8.6	1.9	22.2	-2.3	19.9	1.8	6.0	21.0
एनईटीसी	217.7	122.0	248.6	107.8	166.8	83.4	180.5	79.6
बीबीपीएस	97.0	153.7	100.8	177.6	113.1	159.3	106.9	172.5

स्रोत: आरबीआई

⁸ <https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=1744050>

⁹ <https://www.npci.org.in/what-we-do/erupi/erupi-live-partners>, accessed on September 9, 2021.

उपयोग (45 प्रतिशत), और गुणवत्ता (20 प्रतिशत) के तहत एकत्रित किया गया है। वित्तीय समावेशन की दिशा में विभिन्न हितधारकों के संचयी प्रयासों से सूचकांक 2016-17 के 43.4 से 2020-21 में 53.9 तक बढ़ा।¹⁰ डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने टियर -1 में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के हिस्से के रूप में चयनित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अपनी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) योजना ¹¹ टियर -3 से टियर -6 केंद्रों जो पहले से ही पीआईडीएफ योजना के लिए पात्र थे के अलावा टियर 1 और टियर 2 केंद्र ¹² को प्रदान करने का निर्णय किया है।

रिज़र्व बैंक ने लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने और ग्राहक डेटा गोपनीयता को मजबूत करने के लिए कार्ड टोकननाइज़ेशन फ्रेमवर्क में कई बदलावों की भी घोषणा की। मोबाइल फोन और टैबलेट के अलावा, उपभोक्ता उपकरणों - लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेअरेबल, और अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों के लिए डिवाइस-आधारित टोकननाइज़ेशन की सुविधा बढ़ायी है।¹³ 1 जनवरी 2022 से, कार्ड लेनदेन/भुगतान श्रृंखला (कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क को छोड़कर) में किसी भी संस्था को ग्राहक डेटा सुरक्षा के हित में वास्तविक कार्ड डेटा¹⁴ स्टोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, यह भी निर्णय लिया गया है कि डिवाइस-आधारित टोकननाइज़ेशन फ्रेमवर्क को कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकननाइज़ेशन के साथ-साथ दिया जाए, जिससे ग्राहकों को उनके टोकन कार्ड का उपयोग करके प्रत्येक लेनदेन के लिए कार्ड विवरण दर्ज करने की परेशानी से बचाएगा। ऐसा करते हुए, बैंक ने ग्राहकों की सुविधा और डेटा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है।

¹⁰ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=52068

¹¹ योजना का उद्देश्य टियर -3 से टियर -6 के केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक और डिजिटल दोनों) की तैनाती को प्रोत्साहित करना है।

¹² https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=52112

¹³ <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12152&Mode=0>

¹⁴ <https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12159&Mode=0>

एकाउंट एग्रीगेटर (एए) के मोर्चे पर रोमांचक घटनाक्रम जारी हैं।¹⁵ एए रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त एनबीएफसी हैं जो ग्राहक की सहमति प्राप्त करते हैं, वित्तीय सूचना प्रदाताओं (जैसे, बैंकों) से अपना डेटा एकत्र करते हैं और इसे वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ताओं (जैसे, डिजिटल ऋणदाताओं) के साथ साझा करते हैं जो ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय डेटा तक पहुंच सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल तरीके से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के वितरण का विस्तार करने की क्षमता है। एए पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने और डेटा साइलो को तोड़कर फिनटेक नवाचार के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की अपेक्षा है।

निष्कर्ष

अगस्त के अंक में, हमने पतझड़ के संगीत में वसंत के गीतों को डूबते हुए लिखा था। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम मानते हैं कि वर्तमान मोड़ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था उस गुरुत्वाकर्षण गुलेल के लिए समान रूप से तैयार है जो इसे अपने आकांक्षी विकास पथ पर लॉन्च करेगी। जैसे-जैसे महामारी के प्रभाव कम होते जाएंगे, निष्क्रिय विकास आवेगों को दिशा देते हुए, कार्यनीति का चयन महत्वपूर्ण होगा।

स्थिरीकरण नीति –मौद्रिक नीति जिसका एक अभिन्न तत्व है - व्यापार चक्र की चोटियों और गर्त में अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए निवेश किया जाता है; और केंद्रीय बैंकिंग समुदाय ने प्रभावशाली रूप में कहा कि - अस्थायी उतार-चढ़ाव होने की संभावना को ऑफसेट करने का प्रयास न करें; यह 'अच्छा करने के बजाय अधिक नुकसान ही कर सकता है। इसके अलावा, स्थिरीकरण नीतियां लंबे और परिवर्तनशील अंतरालों के साथ काम करती हैं और इसलिए, समय-संगत नीतिगत कार्य जो प्रचलित परिस्थितियों में उचित है जब वे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं तो महत्वपूर्ण होता हैं।

महामारी जैसा आघात कोई हो ही नहीं सकता है। इसके अल्पावधि प्रभाव स्पष्ट हैं और नीतिगत प्रतिक्रियाएं उनका निरंतर

¹⁵ <https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/eight-major-banks-join-the-account-aggregator-network/article36256274.ece>

आधार पर समाधान कर रही हैं। स्थिरता के साथ सतत और समावेशी विकास की नीतियां महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जागरूकता के आधार पर होनी चाहिए।

मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र अपेक्षा से अधिक अनुकूल रूप से नीचे जा रहा है। अगस्त के मुद्रास्फीति परिणाम ने मई के कीमत आघात को क्षणिक मानकर देखने के एमपीसी के निर्णय को सही ठहराया है। विभिन्न खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट तीसरी तिमाही तक बढ़ने की संभावना है और हेडलाइन मुद्रास्फीति पर ईंधन और मूल कीमतों का दबाव शामिल है। अब कार्य इन लाभों को समेकित करना और उन्हें चौथी तिमाही में भी आगे ले जाना है। भारत ईंधन की कीमतों के संबंध में एक मूल्य लेने वाला देश है, जो समय के साथ अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप बना है।

मुख्य मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के भाग्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि महामारी के निशान ठीक हो जाते हैं और आपूर्ति की स्थिति को उत्पादकता लाभ के साथ बहाल किया जाता है जो आमतौर पर एक बड़े झटके के बाद अर्जित होता है, कोर मुद्रास्फीति की निरंतर सहजता की उम्मीद की जा सकती है और यह मौद्रिक नीति के विकास-सहायक रुख को सुदृढ़ करेगा।

हम मानते हैं कि अगस्त में, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ से गुजरा है जो सितंबर में फलेगा-फूलेगा।

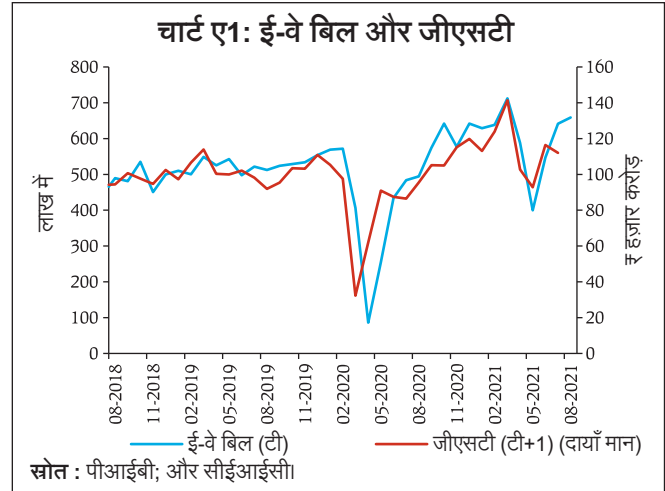
संदर्भ

Kumar P., "An Economic Activity Index for India", *RBI monthly bulletin*, November 2020.

अनुबंध: जीएसटी के प्रमुख संकेतक के रूप में ई-वे बिल

जुलाई 2017 में शुरू किए गए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत, पिछले वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ से अधिक के कुल कारोबार वाले सभी व्यवसायों को अगले महीने की 20 तारीख तक मासिक जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) दाखिल करना आवश्यक है। ₹5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यवसायों को एक तिमाही के अगले महीने की 22 या 24 तारीख तक तिमाही रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है। पिछले ग्यारह महीनों (अक्टूबर 2020 से अगस्त 2021) में, जीएसटी संग्रहण जून 2021 को छोड़कर हर महीने ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इसका श्रेय चल रहे आर्थिक सुधार, नकली बिलिंग के खिलाफ करीब से निगरानी, जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी सिस्टम और प्रभावी कर प्रशासन सहित कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करके गहन डेटा विश्लेषण को दिया गया है।

जीएसटी प्रणाली के तहत, माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल तैयार करना आवश्यक है, जिसका मूल्य ₹50,000 रुपये से अधिक है। जबकि ई-वे बिल किसी विशेष महीने (टी) में किए गए लेनदेन को कैप्चर करते हैं, इन लेनदेनों के लिए रिटर्न अगले महीने (टी+1) में दाखिल करना आवश्यक है। इस प्रकार, महीने 'टी' में उत्पन्न ई-वे बिल 'टी + 1' महीने में जीएसटी संग्रह का एक अग्रिम संकेतक हो सकता है। अवधि 'टी+1' में जीएसटी राजस्व का एक प्लॉट और



अवधि 'टी' में ई-वे बिल दोनों के बीच घनिष्ठ सह-संबंध दर्शाता है (सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण लीड सहसंबंध लगभग 70 प्रतिशत) [चार्ट ए 1]। हालांकि, यह ध्यान में रखना है कि ई-वे बिल माल के व्यापार का एक संकेतक हैं; उनके पास सेवा व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अगस्त में, ई-वे बिल ने वर्ष-दर-वर्ष 33.3 प्रतिशत¹ की वृद्धि दर्ज की, यह दर्शाता है कि सितंबर 2021 में ₹ 1.1 लाख करोड़ जीएसटी संग्रहण होने का अनुमान लगाया जा सकता है।²

¹ महीने-दर-महीने 2.7 प्रतिशत की वृद्धि।

² जीएसटी राजस्व का पूर्वानुमान एक साधारण प्रतिगमन फ्रेमवर्क के आधार पर बनाया गया था: जीएसटी=सी+ सी1 ई-वे बिल (टी-1)+€टी अप्रैल और मई 2020 के लिए प्रतिरूपी चर के साथ पेश किया गया था ताकि इन महीनों के दौरान कोविड से संबंधित प्रतिबंधों से संबन्धित जीएसटी राजस्व में गिरावट को ध्यान में रखा जा सके। विनिर्देश स्वतःसहसंबंध से मुक्त पाया गया (ब्रूश-गॉडफ्रे सीरियल सहसंबंध एलएम टेस्ट के स्वतः सहसंबंध की शून्य परिकल्पना को 0.3 के पी-मान के साथ खारिज नहीं किया जा सकता था) और विषमरूपता (ब्रूश-पागन की समरूपता की शून्य परिकल्पना) -गॉडफ्रे टेस्ट को 0.6 के पी-वैल्यू के साथ खारिज नहीं किया जा सकता था), और त्रुटियों को सामान्य रूप से वितरित पाया गया था (जार्के बेरा टेस्ट के सामान्य वितरण की शून्य परिकल्पना को 0.13 के पी-वैल्यू के साथ खारिज नहीं किया जा सकता था)।

क्षेत्रवार बैंक ऋण आबंटन में परिवर्तन : 2007-08 से हुई प्रगति*

वर्ष 2007-08 से 2013-14 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक ऋण में उछाल देखा गया। हालांकि, बाद के वर्षों में, औद्योगिक क्षेत्र में निराशाजनक ऋण उठाव के कारण बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन में एक उल्लेखनीय गुणात्मक बदलाव के साथ ऋण चक्र उलट गया, जिसमें ऋण वृद्धि लगभग पूरी तरह से गैर-औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋणद्वारा संचालित थी। तैंतीस चुनिंदा बैंकों के विश्लेषण से पता चलता है कि गैर-खाद्य ऋण में अपने हिस्से के आधार पर छह प्रमुख बैंकों वाले प्रमुख-समूह ने गैर-औद्योगिक क्षेत्रों को उधार देना जारी रखा लेकिन औद्योगिक क्षेत्र को इसका ऋण कम था। बाकी बैंकों के दूसरे समूह ने औद्योगिक ऋण में गिरावट दर्ज की, खासकर महामारी की अवधि के दौरान। फिक्स्ड इन्फेक्ट पैनल रिग्रेशन का उपयोग करते हुए एक अनुभवजन्य प्रयोग से पता चला कि महामारी की अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था।

I. भूमिका

आर्थिक विकास के लिए ऋण की पर्याप्तता और समय पर उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है। भारत में, हाल के वर्षों में बाजार आधारित स्रोतों को महत्व मिलने के बावजूद, बैंक ऋण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्त का प्रमुख स्रोत रहा है। वित्तीय वृद्धि के अलावा, बैंक ऋण में भिन्नता केंद्रीय बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल है, जो अपने नीतिगत रुख को व्यक्त करने के लिए ब्याज दरों पर भरोसा करते हैं (आरबीआई, 2005)।

मूल रूप से, बैंक ऋण व्यक्तियों, कारोबारी संगठनों, उद्योगों के साथ-साथ सरकार के लिए भी महत्व रखता है¹

* यह आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के पवन कुमार, मंजूषा सेनापति और आनंद प्रकाश द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

¹ व्यक्ति उपभोग और निवेश दोनों उद्देश्यों के लिए ऋण लेते हैं, कारोबारी संगठन और उद्योग संयंत्र एवं मशीनरी और कार्यशील पूंजी में निवेश करने के लिए ऋण लेते हैं, जबकि सरकार आवर्ती और पूंजीगत उद्देश्यों के लिए खर्च करने हेतु उधार लेती है (टिम्सिना, 2014)।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में बैंक ऋण प्रवाह के महत्व को देखते हुए, रिज़र्व बैंक बैंक ऋण डेटा के मासिक क्षेत्रवार विनियोजन का संकलन और प्रकाशन कर रहा है। डेटा को खाद्य और गैर-खाद्य ऋण (एनएफसी) श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों को खाद्यान्न की खरीद के लिए खाद्य ऋण प्रदान किया जा रहा है।

चूंकि खाद्य ऋण बड़े पैमाने पर बाहरी ताकतों जैसे कि मानसून, विपणन अधिशेष के आकार और सरकारी खरीद द्वारा संचालित होता है, गैर-खाद्य ऋण को आम तौर पर बैंक ऋण के मापक के रूप में उपयोग किया जाता है (बनर्जी, 2011)। गैर-खाद्य ऋण को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है - (i) कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, (ii) उद्योग, (iii) सेवाएँ, और (iv) व्यक्तिगत ऋण। इन चार में से, व्यक्तिगत ऋण खंड के लिए ऋण उठाव पिछले कुछ वर्षों में समग्र गैर-खाद्य ऋण वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभरा है, जिसमें गैर-खाद्य ऋण में लगभग 29.0 प्रतिशत की हिस्सेदारी और मार्च 2021 में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) है।

सभी क्षेत्रों में ऋण आबंटन में विकसित पैटर्न अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि बैंकों की ऋण आबंटन कार्यनीतियों का अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के मामले में, जहां आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए पूंजी की कमी है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि समय के साथ ऋण की क्षेत्रवार संरचना कैसे बदल गई है, क्योंकि इसका आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ सकता है। परिणामस्वरूप, लक्षित क्षेत्रों, जैसे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देना, जिनके आगे और पीछे, और उच्च रोजगार क्षमता दोनों अधिक संबंध हैं, हमेशा रिज़र्व बैंक की नियोजित नीतिगत पहलों का हिस्सा रहा है।

हाल के दिनों में, एंथनी एवं अन्य (2019) ने अपनी क्षेत्रवार गतिशीलता के साथ-साथ समग्र गैर-खाद्य ऋण की गतिविधियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया और व्यक्तिगत ऋणों के रूप

में खुदरा क्षेत्र को आक्रामक ऋण देने के साथ बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन में गुणात्मक बदलाव का उल्लेख किया। प्रकाश और कुमार (2021) ने आगे कोविड-19 महामारी से पहले की अवधि के दौरान बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन में हुई प्रगति का अध्ययन किया और उनकी तुलना भारत में कोविड-19 की पहली लहर की अवधि के दौरान की और निष्कर्ष निकाला कि महामारी के मद्देनजर 2020-21 में पहले से ही ठंडी ऋण वृद्धि को एक और झटका लगा। हालांकि, इन अध्ययनों ने गैर-खाद्य ऋण और इसके क्षेत्रवार घटकों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। विभिन्न क्षेत्रों में बैंक-वार उधार व्यवहार की अभी तक किसी भी अध्ययन द्वारा जांच नहीं की गई है।

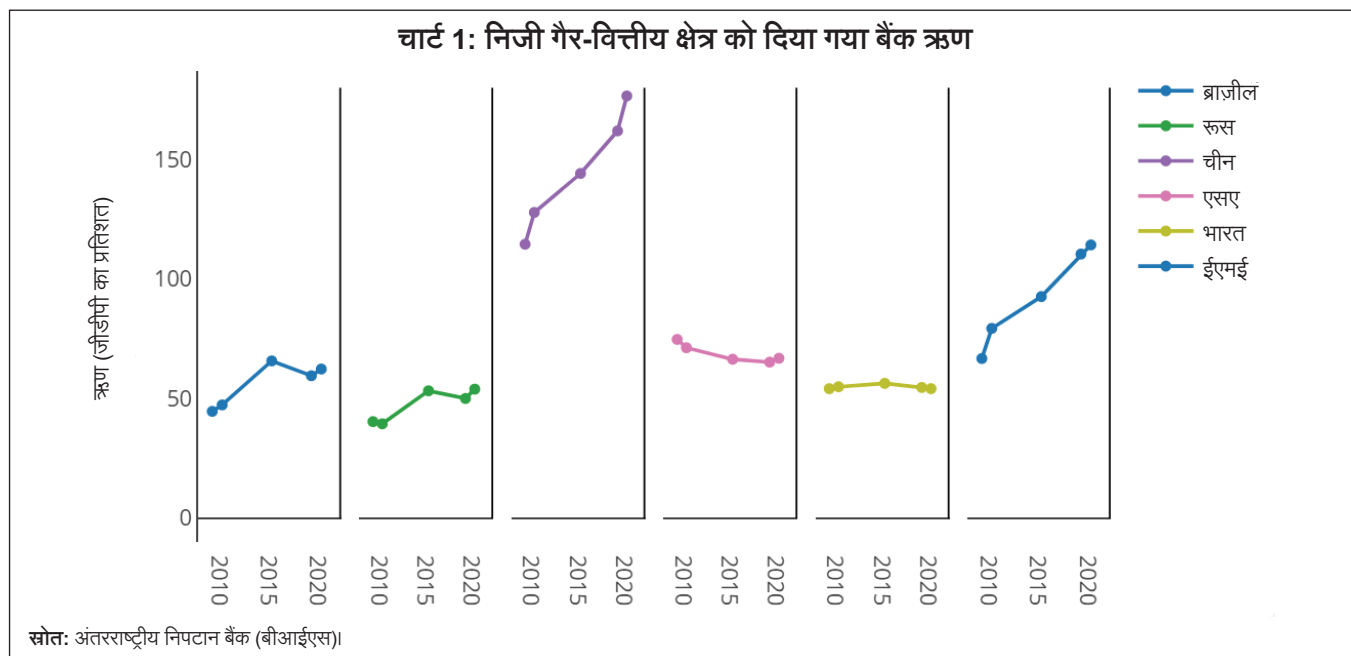
इस पृष्ठभूमि के आलोक में, इस आलेख में वर्ष 2007-08 के बाद से औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों के बीच ऋण आवंटन में परिवर्तन के साथ-साथ बैंकों के उधार व्यवहार की जांच की गयी है। यह अध्ययन अनुभवजन्य रूप से (ए) ऋण सुपुर्दगी और (बी) क्षेत्रवार ऋण उठाव पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करता है। मौजूदा मंद ऋण वृद्धि को देखते हुए विश्लेषण प्रासंगिक है और ऋण उठाव और इसके आबंटन में सुधार के लिए

भविष्य की नीति को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

शेष आलेख को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। खंड II में क्षेत्रवार ऋण में रुझान प्रस्तुत किया गया है। खंड III में विश्लेषण किया गया है कि क्या औद्योगिक क्षेत्र में ऋण उठाव कुछ बैंकों द्वारा संचालित है। खंड IV में विभिन्न औद्योगिक उप-क्षेत्रों को ऋण देने में बैंक समूहों के प्रदर्शन और उधार व्यवहार को दर्शाया गया है। खंड V में गैर-औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण देने में बैंक समूहों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। खंड VI में कोविड-19 से पहले की अवधि और कोविड-19 अवधि के लिए बैंकों के प्रमुख-समूह और अन्य-समूह के रूप में परिभाषित किए गए अनुभवजन्य अनुमान प्रदान किया गया है और अंत में, खंड VII में समापन टिप्पणियाँ दी गयी हैं।

II. क्षेत्रवार ऋण में रुझान

भारत में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र को बैंक ऋण वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का 57.4 प्रतिशत था। कुछ ईएमई की तुलना में, भारत में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र में बैंक ऋण ने हाल के दिनों में लगभग सपाट प्रवृत्ति दिखाई है (चार्ट 1)।



² गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ, सेवाएँ और व्यक्तिगत ऋण खंड शामिल हैं।

³ इस अध्ययन के लिए, बैंकों को प्रमुख-समूह और अन्य-समूह में वर्गीकृत किया गया है। आलेख में इन दो समूहों के उधार व्यवहार की जांच की गई है।

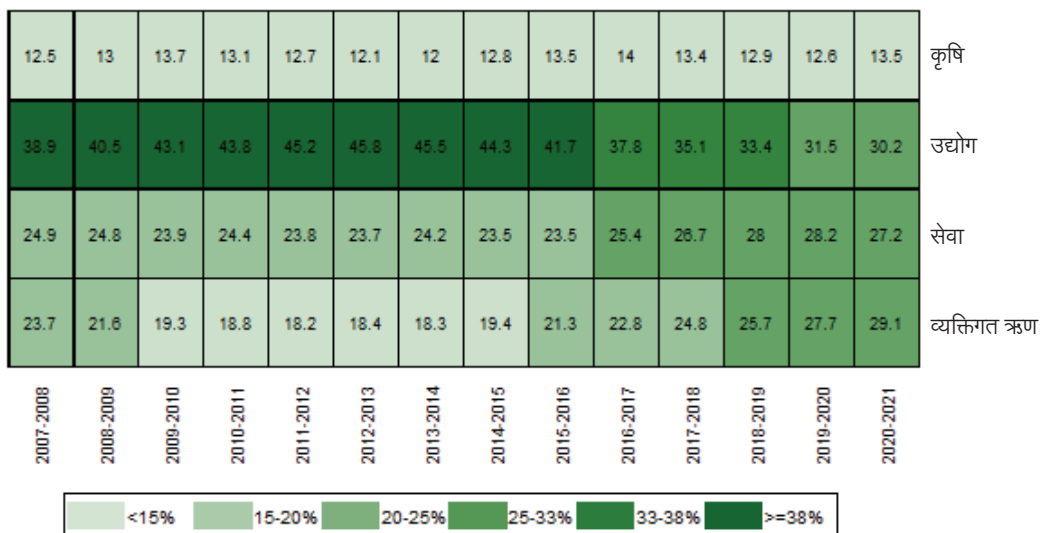
गैर-खाद्य ऋण की क्षेत्रवार संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि समग्र गैर-खाद्य ऋण उठाव में औद्योगिक क्षेत्र को ऋण का हिस्सा, जो वर्ष 2013-14 में 45.0 प्रतिशत से अधिक था, वर्ष 2020-21 तक घटकर लगभग 30.0 प्रतिशत हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में ऋण का हिस्सा अभी भी सबसे अधिक है, इसके बाद व्यक्तिगत ऋण, सेवाएं और कृषि का स्थान है (चार्ट 2)। पिछले कुछ वर्षों में, व्यक्तिगत ऋण खंड और सेवा क्षेत्र के ऋण ने अधिक प्रमुखता प्राप्त की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2007-08 से वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान गैर-खाद्य ऋण के साथ 16.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज करने के साथ बैंक ऋण में उछाल देखा गया, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत ऋण वृद्धि के साथ-साथ गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में त्वरित ऋण प्रवाह से प्रेरित था। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के ऋण में 19.6 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई, जबकि गैर-औद्योगिक क्षेत्रों के ऋण में 14.6 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई। समग्र गैर-खाद्य ऋण वृद्धि में औद्योगिक क्षेत्र में ऋण का सापेक्ष योगदान लगभग 50.0 प्रतिशत था, जो इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में ऋण के महत्वपूर्ण विस्तार से जुड़ी मजबूत ऋण वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट 3)। मजबूत ऋण प्रवाह के परिणामस्वरूप, कुल गैर-खाद्य ऋण में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2007-

08 के 38.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 45.5 प्रतिशत हो गई (चार्ट 2)।

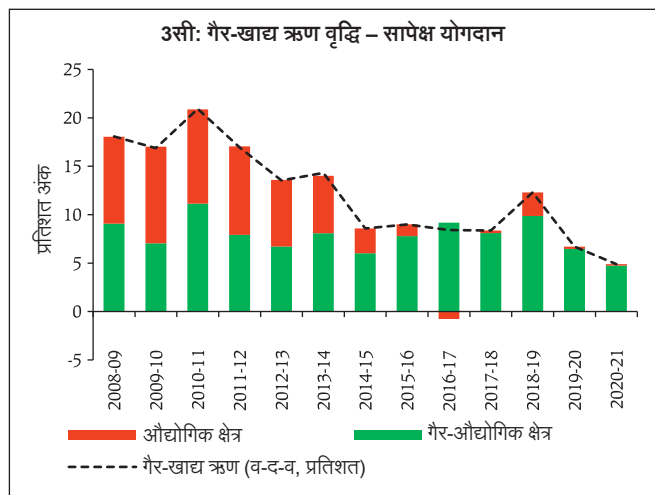
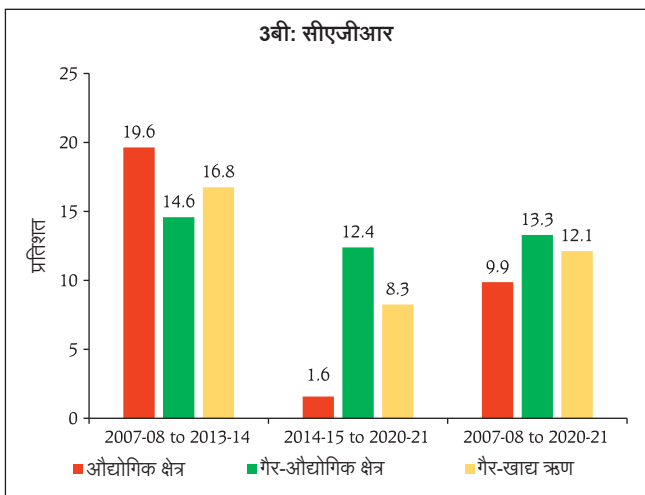
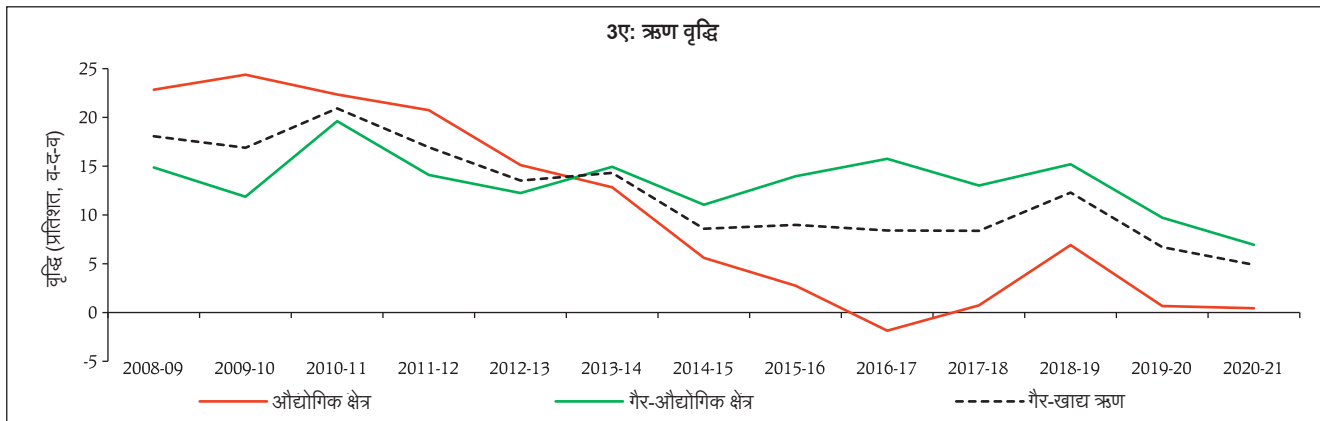
हालांकि, बाद के वर्षों में, बैंक ऋण के क्षेत्रीय परिणियोजन में एक उल्लेखनीय गुणात्मक बदलाव के साथ-साथ क्रेडिट चक्र उलट गया। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान, मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में उलटफेर के कारण, 8.3 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज करते हुए, ऋण वृद्धि में गिरावट आई। वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान गैर-औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण दर्ज द्वारा की गयी 12.4 प्रतिशत के सीएजीआर के मुकाबले औद्योगिक क्षेत्र को ऋण में 1.6 प्रतिशत का मंद सीएजीआर दर्ज किया गया। समग्र गैर-खाद्य ऋण वृद्धि लगभग पूरी तरह से गैर-औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र को व्यक्तिगत ऋण के रूप में, अवधि के दौरान ऋण के विस्तार द्वारा संचालित थी (चार्ट 3)। औद्योगिक क्षेत्र को ऋण का मंद प्रदर्शन औद्योगिक बैंक ऋण की कम मांग, वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत, जैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), इक्विटी, बांड, डिबेंचर इत्यादि जैसे कारकों के कारण था, जो कुछ जोखिम से बचने के साथ कुछ बड़े उद्योगों में दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या के कारण बैंकों की ओर से जोखिम विमुखता से भी जुड़ा था। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद ऋण वृद्धि में मंदी और बढ़ गई।

चार्ट 2: गैर-खाद्य ऋण में प्रमुख क्षेत्रों की हिस्सेदारी



स्रोत: आरबीआई एवं लेखकों का अनुमान।

चार्ट 3: ऋण उठाव – औद्योगिक बनाम गैर-औद्योगिक क्षेत्र



स्रोत: आरबीआई एवं लेखकों का अनुमान

महामारी के फलस्वरूप और अधिकांश आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के परिणामस्वरूप, न केवल वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई, बल्कि ऋण मांग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में और गिरावट आई और साथ ही गैर-औद्योगिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण वृद्धि में नरमी आई।

वर्ष 2014-15 के बाद से औद्योगिक क्षेत्र में धीमी ऋण वृद्धि के कारणों की जांच की आवश्यकता है जिसके कारण समग्र ऋण वृद्धि में भी कमी आई है; क्या औद्योगिक क्षेत्र को ऋण देने में मंदी सभी बैंकों के लिए समान है या सभी बैंकों के व्यवहार में अंतर रहा है।

III. क्या औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऋण उठाव कुछ बैंकों द्वारा संचालित है?

बैंकों के उधार व्यवहार का अध्ययन करने की दृष्टि से, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में, रिजर्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डेटा, कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के लिए 33 चुनिंदा बैंकों को कवर करता है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए खाद्य ऋण का उपयोग किया गया है। डेटा के बैंक-वार विश्लेषण के आधार पर, यह देखा गया है कि कुछ बैंक समग्र गैर-खाद्य ऋण उठाव में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए, बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - (i) बैंकों का प्रमुख समूह,

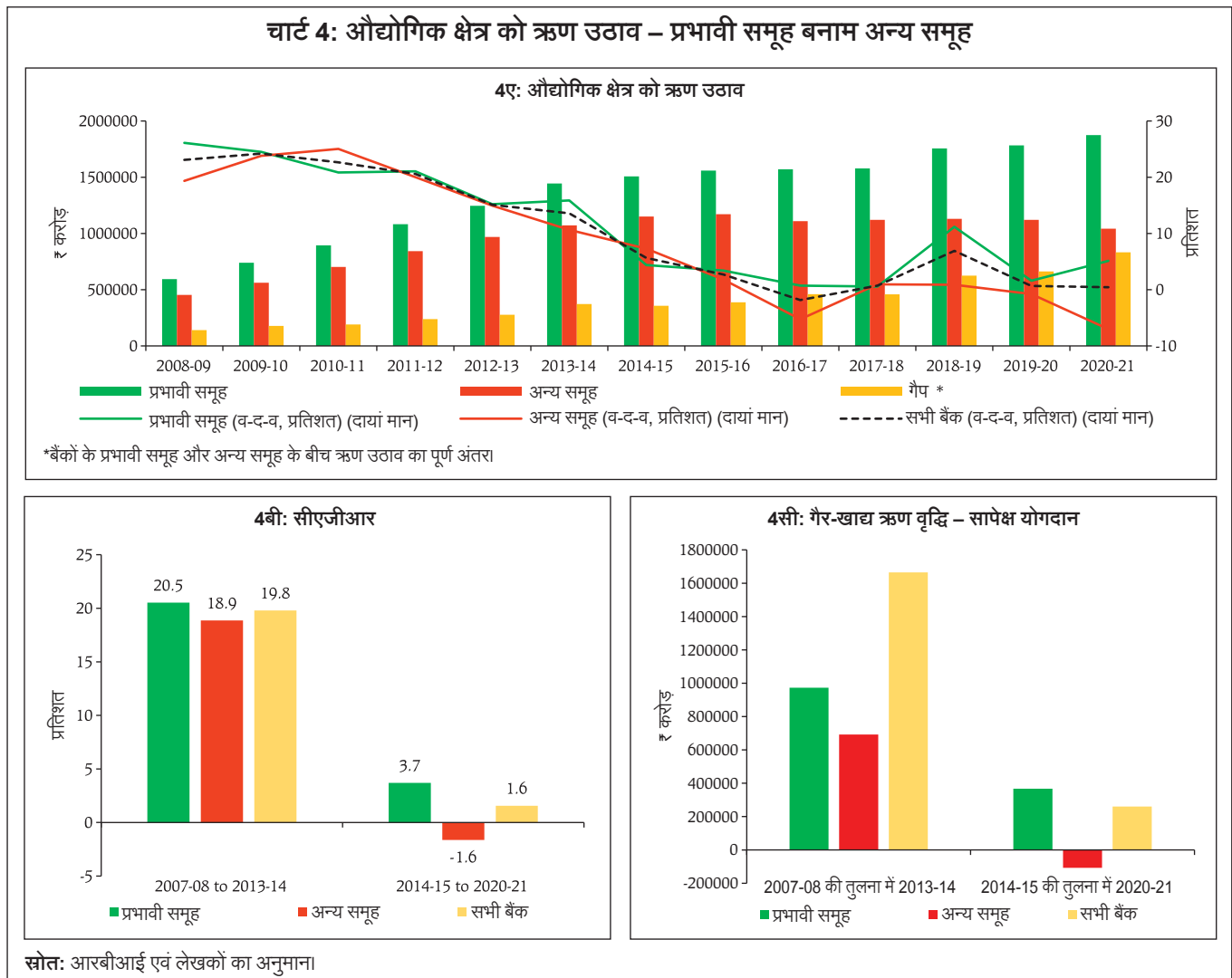
जिसमें कुल गैर-खाद्य ऋण⁴ में उनके हिस्से के आधार पर छह अग्रणी बैंक शामिल हैं, और (ii) बैंकों का अन्य समूह, जिसमें शेष 27 बैंक शामिल हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि, जो वर्ष 2013-14 तक दोहरे अंकों में रही, में बाद में तेज गिरावट देखी गई, जो मुख्य रूप से इसके सबसे बड़े घटक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ऋण उठाव में तेज संकुचन के कारण वर्ष 2016-17 में ऋणात्मक क्षेत्र में चली गई। इसने वर्ष 2018-19 में एक रिकवरी दर्ज की लेकिन बाद के वर्षों में मंद रहा। वर्ष 2007-08 से 2013-14 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत ऋण वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र को उधार देने में बैंकों

के प्रमुख-समूह और अन्य-समूह दोनों की आक्रामक भागीदारी के कारण थी। इस अवधि के दौरान क्रमशः औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए बैंकों के प्रमुख समूह और अन्य-समूह के ऋण के 20.5 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत के सीएजीआर में भी परिलक्षित होता है। हालांकि, प्रमुख-समूह का ऋण उठाव, कुल और वृद्धिशील दोनों मामलों में, उच्च स्तर पर रहा, तथापि प्रमुख-समूह और अन्य-समूह द्वारा ऋण उठाव के बीच का अंतर इस अवधि के दौरान बहुत अधिक नहीं बदला (चार्ट 4)।

इस ऋण उछाल अवधि के बाद, औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में तेजी से उलटफेर हुआ और वर्ष 2014-15 से

चार्ट 4: औद्योगिक क्षेत्र को ऋण उठाव – प्रभावी समूह बनाम अन्य समूह



⁴ मार्च 2021 में 33 बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण में बैंकों के प्रमुख समूह की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत थी।

2020-21 की अवधि के दौरान 1.6 प्रतिशत की मंद सीएजीआर दर्ज की गई। ऋण वृद्धि में यह गिरावट मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान प्रमुख समूह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए ऋण में मामूली वृद्धि के साथ-साथ दूसरे समूह द्वारा वितरित ऋण में संकुचन के कारण हुई थी। दूसरे समूह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए ऋण में 1.6 प्रतिशत का ऋणात्मक सीएजीआर दर्ज किया गया, जबकि प्रमुख समूह द्वारा इस अवधि के दौरान 3.7 प्रतिशत का मामूली सीएजीआर दर्ज किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि को वर्ष 2020-21 में एक और झटका लगा और कोविड-19 के प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मुश्किल से 0.4 प्रतिशत की घनात्मक वृद्धि हुई। महामारी वर्ष में, प्रमुख-समूह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए ऋण में 5.1 प्रतिशत की त्वरित वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि दूसरे-समूह द्वारा वितरित 7.0 प्रतिशत से अधिक संकुचित हो गए। इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कुछ बैंक औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि अधिकांश अन्य बैंक औद्योगिक क्षेत्र को ऋण देने में पिछड़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर बैंकों के दो समूहों के उधार व्यवहार का विश्लेषण अगले दो खंडों में किया गया है।

IV. औद्योगिक क्षेत्र के भीतर प्रमुख-समूह और बैंकों के अन्य-समूह का उधार व्यवहार

संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आकार के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र को मोटे तौर पर सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र को कुल ऋण उठाव में बड़े उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत रही

है। वर्ष 2014-15 के बाद से औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में गिरावट मुख्य रूप से बड़े उद्योगों को ऋण वृद्धि में गिरावट के कारण है।

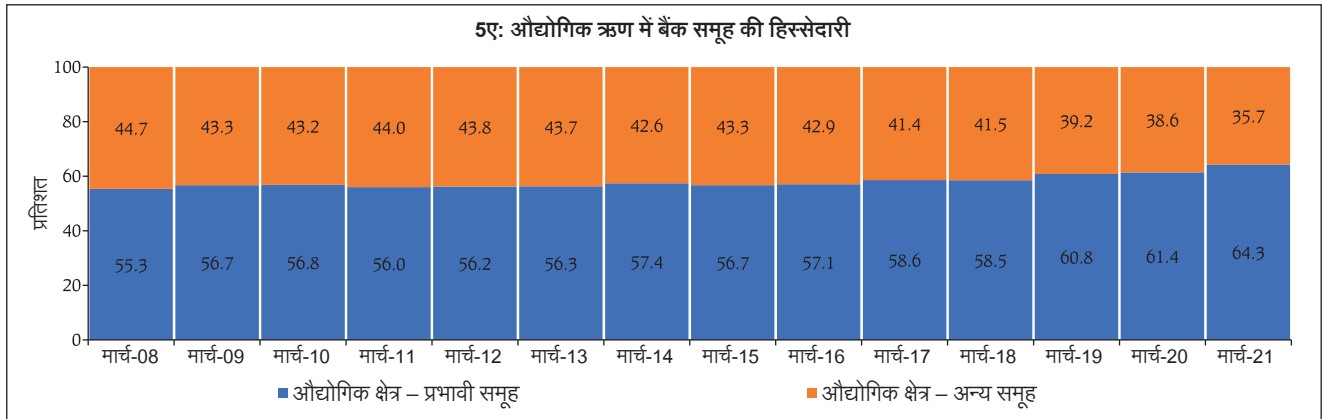
उप-क्षेत्रों⁵ में, बुनियादी धातु और धातु उत्पाद, कपड़ा, रसायन और रासायनिक उत्पाद, और खाद्य प्रसंस्करण के बाद औद्योगिक क्षेत्र में ऋण उठाव का करीब दो-पाँचवाँ हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर का है।

प्रमुख समूह और बैंकों के अन्य समूह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए ऋण के वितरण के संदर्भ में, प्रमुख समूह की तुलना में अन्य समूह लगातार बाजार हिस्सेदारी खो रहा है, वर्ष 2017-18 के बाद गिरावट में अधिक तेजी आई है। मार्च 2021 के अंत में औद्योगिक क्षेत्र को ऋण में दूसरे समूह की हिस्सेदारी घटकर लगभग 36 प्रतिशत हो गई (चार्ट 5)।

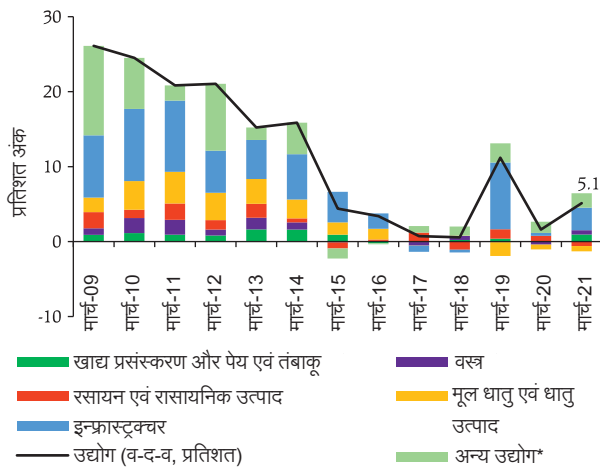
वर्ष 2007-08 से 2013-14 की अवधि के दौरान औद्योगिक ऋण में उछाल मुख्य रूप से दोनों समूहों द्वारा बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण ऋण विस्तार के कारण था। प्रमुख-समूह और अन्य-समूह द्वारा दर्ज की गई औद्योगिक ऋण वृद्धि में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण की हिस्सेदारी औसतन लगभग 36 प्रतिशत और 40 प्रतिशत थी। बुनियादी धातु और धातु उत्पाद उद्योगों के ऋण ने प्रत्येक समूह द्वारा पंजीकृत औद्योगिक ऋण की वृद्धि में 13 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। वर्ष 2014-15 के बाद से औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में तीव्र उलटफेर प्रमुख उद्योगों में ऋण वृद्धि में मंदी/संकुचन द्वारा चिह्नित किया गया था। इस औद्योगिक ऋण वृद्धि में प्रत्येक समूह के सापेक्ष योगदान में गिरावट में भी परिलक्षित हुआ, विशेष रूप से दूसरे समूह के मामले में।

⁵ बैंक-क्रेडिट डेटा के क्षेत्रवार विनियोजन में आरबीआई/राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) के मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) के वर्गीकरण के अनुरूप 5 उद्योगों को 18 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

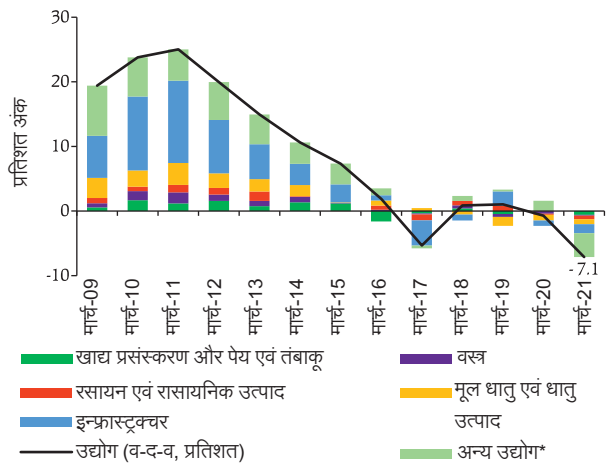
चार्ट 5: औद्योगिक क्षेत्र के भीतर उधारी प्रवृत्ति – प्रभावी समूह बनाम अन्य समूह



5बी: प्रभावी समूह का औद्योगिक ऋण वृद्धि: प्रमुख उद्योगों में योगदान



5सी: अन्य समूह का औद्योगिक ऋण वृद्धि: प्रमुख उद्योगों में योगदान



*अन्य उद्योगों में खनन एवं उत्खनन, चमड़ा व चमड़ा उत्पाद, लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, कागज एवं कागज उत्पाद, पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद, व परमाणु ईंधन, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, सभी इंजीनियरिंग, वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण, निर्माण आदि।

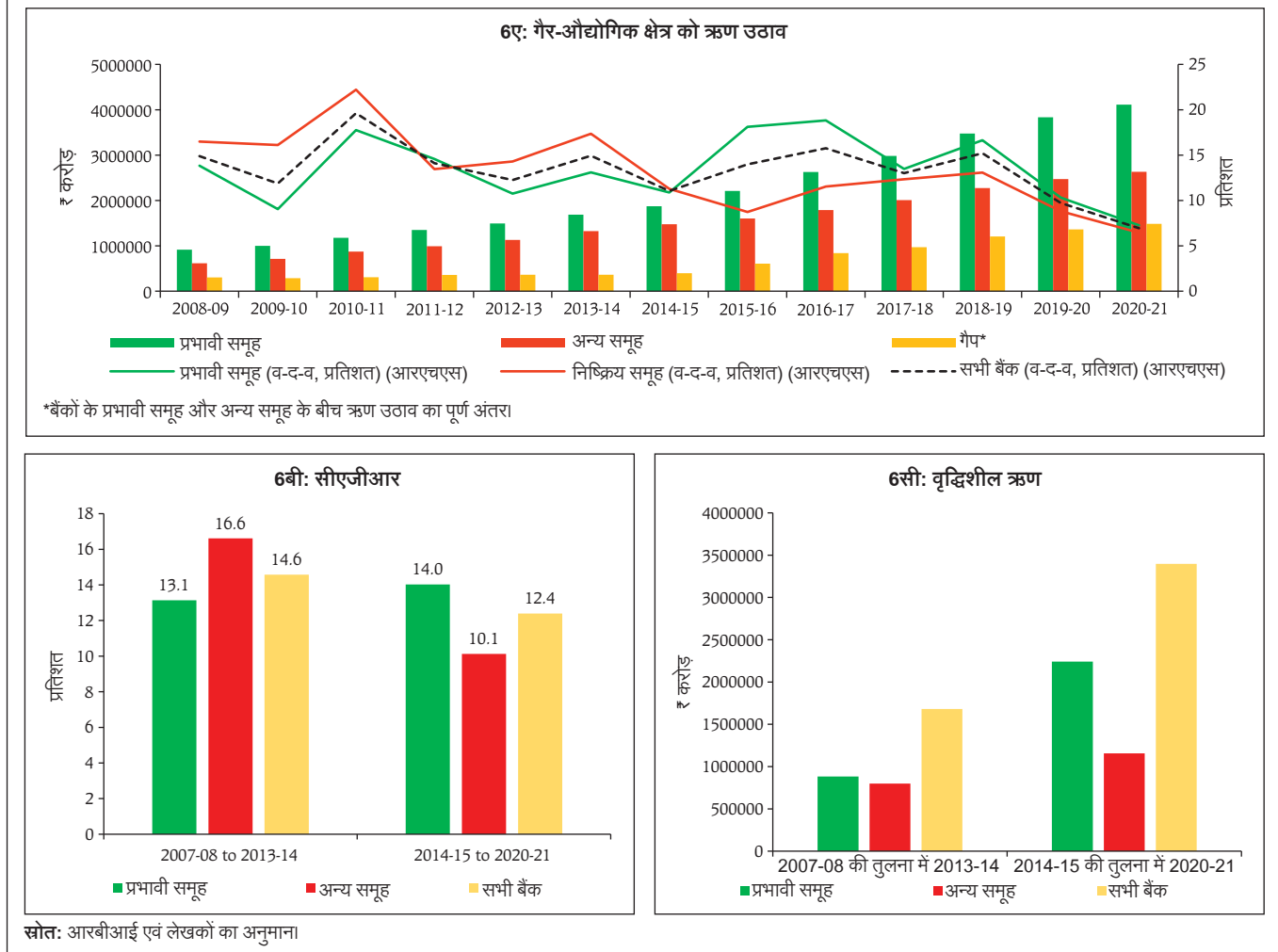
V. गैर-औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में बैंक समूहों का प्रदर्शन

जहां वर्ष 2014-15 के बाद से औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है, वहीं दोनों प्रमुख-समूह और अन्य-समूह के बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को उधार देने के कारण, गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण वृद्धि वर्ष 2018-19 तक दोहरे अंकों में बनी रही, जो यह दर्शाता है कि शेष अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह पिछले कुछ वर्षों के दौरान धीमा होने से पहले मजबूत बना रहा (चार्ट 6)। यह वर्ष 2014-15 के बाद से गैर-औद्योगिक क्षेत्रों की

तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में बढ़ते विचलन की ओर भी इशारा करता है।

गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में मजबूत ऋण वृद्धि, मुख्य रूप से व्यक्तिगत ऋण खंड द्वारा संचालित, बैंकों के दोनों समूहों द्वारा इन क्षेत्रों को लगातार ऋण वितरण के कारण थी। वर्ष 2007-08 से 2013-14 के दौरान प्रमुख समूह और अन्य समूह द्वारा गैर-औद्योगिक क्षेत्रों को दिए गए ऋण में क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 16.6 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान यह क्रमशः 14.0 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत थी।

चार्ट 6: गैर-औद्योगिक क्षेत्र को ऋण उठाव – प्रभावी समूह बनाम अन्य समूह



VI. प्रमुख-समूह और बैंकों के अन्य-समूह से संबंधित अनुभवजन्य अनुमान: कोविड-19 से पहले और उसके बाद की अवधि दौरान

इस खंड में, फ़िक्स्ड इफ़ेक्ट्स पैनल रिग्रेशन विधि का उपयोग करके अनुभवजन्य रूप से यह अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है कि क्या प्रमुख-समूह और अन्य-समूह के क्षेत्रवार ऋण के अनुपात में गैर-खाद्य ऋण के अनुपात में कोविड-19 से पहले और कोविड-19 अवधि के दौरान निश्चित प्रभाव लागू करने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। अनुभवजन्य अनुमान के लिए, मार्च 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि के मासिक डेटा का उपयोग किया गया है। परिणाम सारणी 1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

कोविड-19 एक डमी है जिसका मान मार्च 2020 तक 0 और उसके बाद के महीनों के लिए 1 है। यह पता लगाने के लिए कि क्या अन्य समूह कोविड-19 से अधिक प्रभावित हुआ था, एक अन्योन्यक्रिया पद भी शामिल है। यह देखा गया कि सभी बैंकों को एक साथ मिलकर देखें तो यह औद्योगिक क्षेत्र था जो कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित था। व्यक्तिगत ऋण खंड महामारी से ज्यादा प्रभावित नहीं था। प्रमुख-समूह और अन्य-समूह की तुलना करते समय, कोविड-19 के कारण दूसरे समूह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए ऋण पर काफी प्रभाव पड़ा। अन्य समूह ने कृषि और सेवा क्षेत्रों को दिए गए ऋण में प्रमुख समूह की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

सारणी 1: नियत प्रभाव पैनेल रिग्रेसन

चर	एनएफसी- कृषि ऋण का अनुपात	एनएफसी- औद्योगिक ऋण का अनुपात	एनएफसी- सेवा क्षेत्र ऋण का अनुपात	एनएफसी- व्यक्तिगत ऋण का अनुपात
कोविड-19	-0.316* (0.163)	-3.237*** (0.6)	1.259** (0.585)	2.295*** (0.341)
बैंक प्रकार x कोविड-19 डम्मी	1.408*** (0.18)	-2.407*** (0.665)	1.198* (0.649)	-0.198 (0.378)
स्थिर	11.65*** (0.0309)	38.71*** (0.114)	30.58*** (0.111)	19.07*** (0.065)
निरूपण	1980	1980	1980	1980
आर-स्क्वायर	0.093	0.175	0.04	0.097
बैंकों की संख्या	33	33	33	33

कोष्ठक में मानक आंकड़े

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; NFC: Non-food credit

औद्योगिक क्षेत्र के भीतर, यह बड़े उद्योग थे जहाँ अन्य-समूह द्वारा दिए गए ऋण पर प्रमुख समूह की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ा। मध्यम और छोटे उद्योगों के लिए, बैंकों का अन्य समूह कुछ सहायता दे सकता है (सारणी 2)।

सारणी 2: औद्योगिक क्षेत्र के भीतर नियत प्रभाव पैनेल रिग्रेसन

चर	औद्योगिक ऋण की तुलना में बड़े उद्योगों में ऋण का अनुपात	औद्योगिक ऋण की तुलना में मध्यम उद्योगों में ऋण का अनुपात	औद्योगिक ऋण की तुलना में सूक्ष्म और लघु उद्योगों में ऋण का अनुपात
कोविड-19	0.424 (0.518)	-0.179 (0.27)	-1.335*** (0.391)
बैंक प्रकार x कोविड- 19 डम्मी	-3.799*** (0.555)	0.496* (0.299)	3.303*** (0.434)
स्थिर	80.840*** (0.095)	4.541*** (0.0514)	14.62*** (0.0744)
निरूपण	1980	1980	1980
आर-स्क्वायर	0.078	0.003	0.059
बैंकों की संख्या	33	33	33

कोष्ठक में मानक आंकड़े

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

VII. निष्कर्ष

पिछले डेढ़ दशकों में बैंक ऋण वृद्धि में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2007-08 से 2013-14 के बीच की अवधि को भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक ऋण उछाल अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि गैर-खाद्य ऋण में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत ऋण वृद्धि से प्रेरित है। दोनों प्रमुख-समूह और बैंकों के अन्य-समूह ने औद्योगिक और साथ ही अन्य क्षेत्रों को आक्रामक रूप से उधार दिया। उद्योगों के भीतर, बुनियादी ढांचे, और बुनियादी धातु एवं धातु उत्पाद उद्योगों ने ऋण उछाल अवधि के दौरान दोनों बैंक समूहों से ऋण उठाव का एक बड़ा हिस्सा लिया।

इसके बाद, हालांकि, बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन में बदलाव के साथ-साथ ऋण चक्र उलट गया। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान, समग्र ऋण वृद्धि में गिरावट आई, मुख्य रूप से गैर-वित्तीय प्रतिष्ठानों द्वारा कर्जभार कम करने, वित्तीय संसाधनों के लिए गैर-बैंक स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता और बैंकों की ओर से कुछ जोखिम से बचने के कारण, विशेष रूप से बैंकों के दूसरे समूह द्वारा उद्योगों को उधार देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में उलटफेर से प्रेरित था, जो कोविड -19 महामारी के प्रकोप के बाद और अधिक जटिल हो गया।

कोविड-19 से पहले की अवधि में और कोविड-19 अवधि के दौरान गैर-खाद्य ऋण के लिए क्षेत्रवार ऋण के अन्य-समूह और प्रमुख समूह अनुपात के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद होने पर एक अनुभवजन्य प्रयोग से पता चला कि कोविड-19 अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। कोविड-19 के कारण दूसरे समूह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दिया गया ऋण काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन जहां तक कृषि और सेवा क्षेत्रों को ऋण का संबंध है, दूसरे समूह का प्रदर्शन प्रमुख समूह की तुलना में बेहतर है।

वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र गैर-खाद्य ऋण वृद्धि लगभग पूरी तरह से गैर-औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण के विस्तार से प्रेरित थी, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण के रूप में खुदरा क्षेत्र को उधार देने से। प्रमुख समूह और बैंकों के दूसरे समूह दोनों की सक्रिय भागीदारी गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण वृद्धि को बढ़ावा दे रही है।

औद्योगिक ऋण में तीव्र मंदी, विशेष रूप से बैंकों के अन्य समूह द्वारा, की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और उचित जोखिम लेने के अनुरूप ऋण उठाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें से सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा पहले ही कदम उठा लिए गए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऋण बाजार को मुक्त कर सकते हैं और कोविड -19 महामारी की वजह से पटरी से उतरी आर्थिक वृद्धि की गति को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान ऋण उठाव में उल्लेखनीय कमी देखने के बाद, हाल के महीनों में दूसरी कोविड लहर के बावजूद ऋण वृद्धि में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।

संदर्भ

Anthony, J.M., Shankar, S., and Sahoo, S. (2019), "Sectoral Deployment of Bank Credit in India", RBI Monthly Bulletin, February.

Banerjee, K. (2011), "Credit and Growth Cycles in India: An Empirical Assessment of the Lead and Lag Behaviour", RBI WORKING PAPER SERIES NO. 22, January.

Prakash, A., and Kumar, S. (2021), "Sectoral Deployment of Bank Credit in India: Recent Developments", RBI Monthly Bulletin, February.

Timsina, N. (2014), "Bank credit and economic growth in Nepal: An empirical analysis", *NRB Economic Review*, 26(2), 1-24.

The Reserve Bank of India (2005), Report on currency and finance 2003-04.

निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2020-21 में वृद्धि और 2021-22 के लिए दृष्टिकोण*

यह आलेख परियोजना प्रस्तावों द्वारा इंगित निवेश चरणबद्ध योजना के अनुसार निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश प्रयोजन से संबंधित आंकड़ों के आधार पर भारत में निजी निवेश गतिविधि के लिए निकट-अवधि के दृष्टिकोण की जांच करता है। 2020-21 में कोविड के प्रभाव को दर्शाते हुए, स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई और पहले से ही प्रक्रियाधीन परियोजनाओं पर धीमी प्रगति हुई। निवेश के दृष्टिकोण से प्रक्रियाधीन परियोजनाओं से संबंधित 2021-22 के लिए चरणबद्ध योजनाओं पर डेटा निकट-अवधि के जोखिमों को बनाए रखने की ओर इशारा करता है।

भूमिका

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अर्थव्यवस्था में निवेश के वातावरण का एक प्रमुख संकेतक है। निजी निवेश उच्च वृद्धि को गति प्रदान कर सकता है और उसे रोक सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए, वृद्धि की संभावनाओं का आकलन करने के लिए निजी निवेश दृष्टिकोण का आकलन महत्वपूर्ण है। हालांकि, निवेश संबंधित विवरण रखने वाली कंपनियों के वार्षिक लेखे काफी समय अंतराल के बाद प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे उनकी उपयोगिता अल्पकालिक दूरदेशी विश्लेषण तक सीमित हो जाती है।

साहित्यिक समीक्षा से पता चलता है कि देश अक्सर परिकल्पित कॉर्पोरेट निवेश योजनाओं और निवेश प्रयोजन पर जानकारी उत्पन्न करने के लिए सर्वेक्षण आधारित विधियों का उपयोग करते हैं। इस तरह के सर्वेक्षणों के परिणाम वर्तमान निवेश माहौल और निवेश के इरादे दोनों के आकलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिनकी लघु से मध्यम अवधि में अमल में आने की

* इस आलेख को सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) के कॉर्पोरेट अध्ययन प्रभाग में राजेंद्र एन चव्हाण, प्रोनिता पी सैकिया और आर के सिन्हा द्वारा तैयार किया गया है। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। पिछला अध्ययन "वर्ष 2019-20 में निजी कॉर्पोरेट निवेश: सुधार के आसार" भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के फरवरी 2020 अंक में प्रकाशित हुआ था।

संभावना है। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से निजी निवेश के आकलन और पूर्वानुमान/ तात्कालिक अनुमान के लिए भारत में भी सर्वेक्षण करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

रिजर्व बैंक लंबे समय से उन परियोजनाओं के माध्यम से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की पूंजीगत व्यय योजनाओं पर नजर रखता रहा है, जिन्हें रंगराजन (1970)¹ द्वारा कैपेक्स के समय पर चरणबद्ध तरीके से अपनाई गई कार्यप्रणाली पर आधारित निवेश पर एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इस तरह के आलेख शुरुआत में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में और बाद में 1989 से बुलेटिन में प्रकाशित हुए थे।

निवेश के प्रयोजन पर डेटा का प्राथमिक स्रोत कैपेक्स परियोजनाओं के पित्तपोषक हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्था (एफआई)² के साथ-साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)³, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी), रुपया मूल्यवर्ग के बॉन्ड (आरडीबी) और एक वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और अधिकार निर्गम।

इसके अतिरिक्त, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के कैपेक्स डेटाबेस से पूंजीगत व्यय परियोजनाओं पर विस्तृत स्तर का डेटा, जो उनकी प्रगति से, घोषणा से लेकर पूरा होने तक (पूरी हुई परियोजनाओं के लिए), समाप्ति (परित्यक्त/ स्थगित परियोजनाओं के लिए) और मध्यवर्ती घटनाओं (लाइव परियोजनाओं के लिए) से संबंधित है, का उपयोग परियोजनाओं के जीवन चक्र का आकलन करने के लिए भी किया गया है (बॉक्स 1)।

¹ यह कार्य-प्रणाली 19 दिसंबर, 1970 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू), खंड संख्या 5, अंक संख्या 51, पृष्ठ 2049-2051 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा लिखित आलेख "कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का पूर्वानुमान" में प्रकाशित हुआ था।

² सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक, और वित्तीय संस्थाएं जो परियोजना के वित्तपोषण में सक्रिय रूप से शामिल हैं, अर्थात्, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) शामिल हैं। भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम)।

³ ईसीबी में रुपये में मूल्यवर्गीत बॉन्ड (आरडीबी) शामिल हैं।

बॉक्स 1: पूंजीगत व्यय परियोजनाओं का जीवन चक्र

पूंजीगत व्यय परियोजना का जीवन चक्र⁴ आमतौर पर इसकी घोषणा के साथ शुरू होता है और उसके बाद विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है, जैसे कि विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करना, वित्तीय पूर्णता प्राप्त करना, ऋण की मंजूरी, कार्यान्वयन की शुरुआत आदि। इस चक्र की परिणति या तो सफलता में हो सकती है, अर्थात् परियोजना का पूर्ण होना, या एक असफल घटना के रूप में इसके पूरा होने से पहले समाप्ति⁵ के माध्यम से। ऐसी परियोजनाएं, जो समाप्त नहीं हुई हैं (सभी चरणों के पूरा होने के माध्यम से), को लाइव प्रोजेक्ट के रूप में माना जाता है। कुछ परियोजनाएँ जो घोषणा और पूर्ण होने के बीच कुछ समय के लिए रुक जाती हैं, उन्हें "अवरुद्ध" परियोजनाओं की संज्ञा दी जाती है।

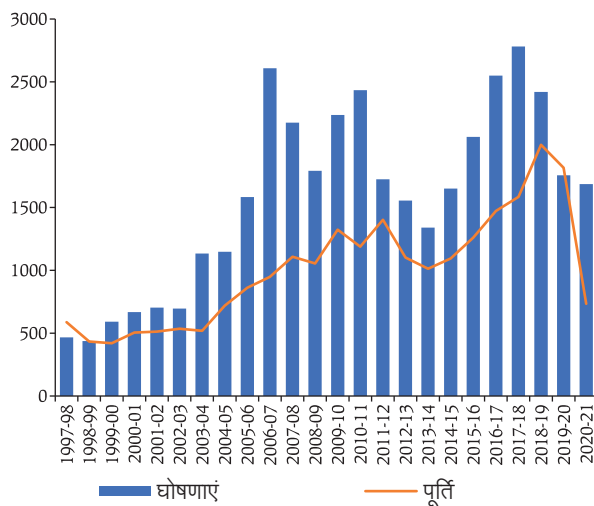
घोषणाएं और उनकी पूर्णता

2020-21 के दौरान पूर्ण की गई निजी परियोजनाओं की संख्या में काफी गिरावट आयी है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह केवल 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के वर्ष के दौरान मामूली गिरावट आयी थी, और बाद में कुछ अस्थिरता के साथ 2011-12 तक

बढ़ी। इसमें 2013-14 से 2018-19 तक लगातार इजाफा हुआ और 2019-20 में गिरावट आई जो कि महामारी-पूर्व प्रचलित मंद दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह 2020-21 में महामारी की गंभीरता को दर्शाता है। नई घोषणाओं की संख्या में भी 2020-21 में और गिरावट आयी। घोषणाओं और पूर्ण होने की घटती प्रवृत्तियां आगे चल रहे पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा को प्रभावित कर सकती हैं (चार्ट 1)।

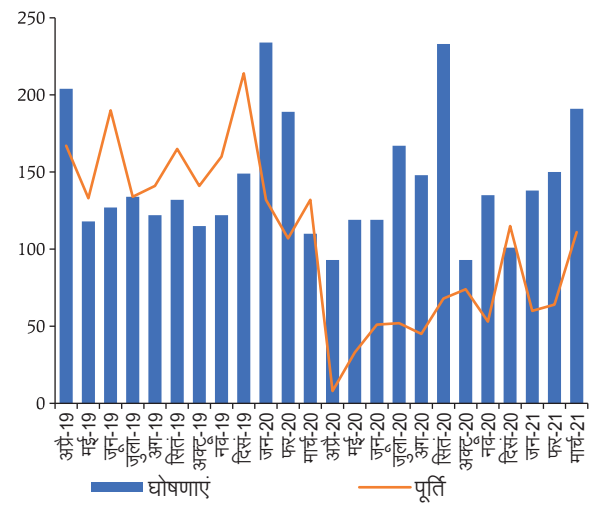
मासिक डेटा से पता चलता है कि अप्रैल 2020 में केवल आठ निजी परियोजनाएं पूरी हुईं, जिसमें देशव्यापी तालाबंदी देखी गई। इस स्थिति में तब से कुछ सुधार हुआ है, हालांकि ये संख्या सामान्य वर्ष की औसत मासिक संख्या से काफी कम प्रतीत होती है। 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान अपेक्षाकृत अधिक संख्या में निजी परियोजनाओं की घोषणाएं बैकलॉग को कवर कर सकती हैं, अर्थात् लंबित/अतिदेय घोषणाओं को, जो तिमाही में प्रबल लॉकडाउन के कारण 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान पूर्ण नहीं हो सकीं (चार्ट 2)।

चार्ट 1: नई घोषणाओं और उनकी पूर्ति की संख्या - वार्षिक



स्रोत: सीएमआईई और लेखकों द्वारा की गई गणना

चार्ट 2: नई घोषणाओं और उनकी पूर्ति की संख्या - मासिक



स्रोत: सीएमआईई और लेखकों द्वारा की गई गणना

(जारी...)

⁴ एक पूंजीगत व्यय परियोजना के जीवन चक्र से तात्पर्य परियोजना के पूर्ण होने से पहले के विभिन्न चरणों को कवर करने वाले चक्र से है। एक अन्य जीवन चक्र के बारे में सोचा जा सकता है कि परियोजना के पूरा होने/ चालू होने से लेकर उसके ध्वस्त होने या अप्रयुक्त होने से पहले तक चालू रहने तक के चरण को कवर करने के बारे में सोचा जा सकता है।

⁵ परियोजनाओं का अंत किसी भी चरण में हो सकता है। सबसे पहली संभावना घोषणा के बाद ही परियोजना का परित्याग है (किसी और चरण में बिना आगे बढ़े)। यह विभिन्न अनुमोदन चरणों (घोषणा के बाद लेकिन कार्यान्वयन की शुरुआत से पहले) के दौरान हो सकता है। की तीसरी संभावना कार्यान्वयन की शुरुआत के बाद है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के कैपेक्स डेटाबेस में बहिर्गमन के इन तीन प्रकारों को क्रमशः "घोषित और परित्यक्त", "शेल्ड" और "परित्यक्त" के रूप में परिभाषित किया गया है।

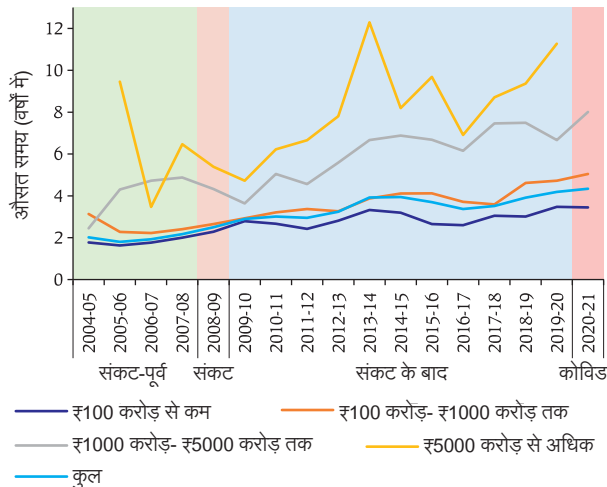
परियोजनाओं को पूर्ण करने का औसत समय

पूर्ण की गई परियोजनाओं का डेटा समूह पुष्टि करता है कि घोषणा की तारीख से किसी परियोजना के पूरा होने का औसत समय उसकी लागत के आकार के साथ धनात्मक संबंध रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्विक वित्तीय संकट की अवधि के दौरान और उसके आसपास वृद्धि हुई है और तब से 2014-15 तक उच्च बनी हुई है। 2016-17 के ट्रफ से 2020-21 तक औसत समय फिर से बढ़ गया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोविड जनित वर्ष 2020-21 में परियोजनाओं के पूरा होने के औसत समय में वृद्धि काफी हद तक बड़ी परियोजनाओं के समूह के समय में (लागत आकार ₹1,000 करोड़-₹5,000 करोड़) उसी वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित है। सभी लागत-आकार समूहों में परियोजनाओं के पूर्ण होने की संख्या में गिरावट के अनुरूप, पूर्ण हो गई परियोजनाओं की संख्या 2020-21 में उल्लेखनीय रूप से कम हो गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष में कोई बृहद् परियोजना (लागत आकार ₹5,000 करोड़ और अधिक) नहीं है (चार्ट 3)।

परित्याग/ शेल्व्ड / प्रगति को अवरुद्ध करने का औसत समय

ऐसी निजी परियोजनाओं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता था और जिसे या तो छोड़ दिया गया था या समाप्त हो गया था, उनका औसत समय वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर 2017-18 (परित्यक्त परियोजनाओं के लिए) और 2015-16 (शेल्व्ड परियोजनाओं के लिए) के वर्षों में काफी बढ़ गया है। संकलित औसत समय से उनकी संबंधित घोषणाओं के बाद परियोजनाओं को छोड़ने या ठंडे बस्ते में डालने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कई परियोजनाएं, जिन्हें वित्तीय संकट (एक तीव्र वृद्धि की अवधि) से पहले घोषित किया गया था, को छोड़ दिया गया था या स्थगित कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 2017-18 के बाद, इन आंकड़ों में कमी आयी है जो यह दर्शाती है कि या तो ऐसी परियोजनाओं की घोषणा में कमी आयी है या निष्पादन योजना में सुधार हुआ है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद परियोजनाओं में विलंब का औसत समय भी धीरे-धीरे बढ़ा, लेकिन 2017-18 से इसमें कमी आयी है (चार्ट 4)।

चार्ट 3: परियोजनाओं को पूर्ण करने का औसत समय

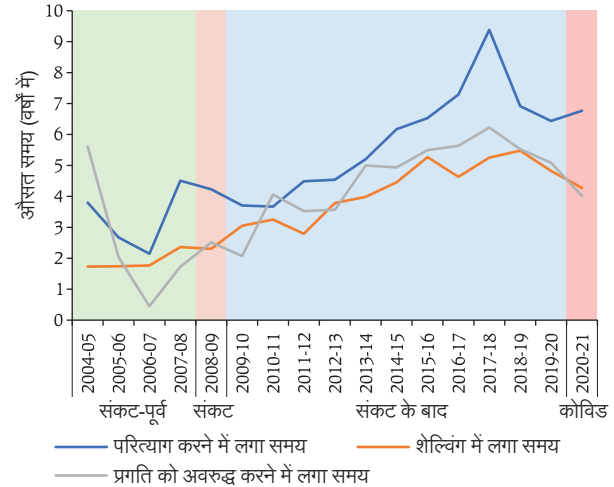


टिप्पणियाँ:

1. परियोजनाओं की लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं देने वाली परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया था।
2. 2019-20 की अवधि भारतीय संदर्भ में केवल कुछ दिनों की कोविड-19 महामारी को कवर करती है। तदनुसार, केवल 2020-21 को महामारी प्रभावित वर्ष के रूप में माना है।
3. पूर्ति/ परित्याग/ शेल्विंग / प्रगति को अवरुद्ध करने का औसत समय, साधारण औसत पर आधारित है।

स्रोत: सीएमआईआई और लेखकों द्वारा की गई गणना

चार्ट 3: परियोजनाओं की पूर्ति/ परित्याग/ शेल्विंग / प्रगति को अवरुद्ध करने का औसत समय



यह आलेख छह खंडों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। खंड II कार्य पद्धति और इसकी सीमाओं को निर्धारित करता है। खंड III समीक्षा की अवधि के दौरान स्वीकृत या अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताओं, उसके वित्त पोषण, और क्षेत्रों और उद्योगों के संदर्भ में वितरण संबंधी पहलुओं को संबोधित करता

है। खंड IV स्वीकृत/ अनुबंधित ऋणों/ वित्तपोषण की चरणबद्ध रूपरेखा से संबंधित है और कॉर्पोरेट निवेश की वृद्धि का अनुमान लगाता है। खंड V वर्ष के दौरान किए गए निजी स्थानन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड VI में अध्ययन का समापन हुआ है।

II. कार्य पद्धति और सीमाएं

पूर्व में दिये गए संकेत के अनुसार, वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट परियोजनाओं के चरणबद्ध विवरण के आधार पर पूंजीगत व्यय के अल्पकालिक (एक वर्ष आगे का) पूर्वानुमान का मार्ग 1970 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा प्रशस्त किया गया था। इस कार्य पद्धति के तहत पूंजीगत व्यय के अनुमान के लिए निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में परियोजनाओं पर डेटा को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जाता है, जो अन्य स्रोतों जैसे ईसीबी/ एफसीसीबी/ आईपीओ/ एफपीओ/ अधिकार निर्गम के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए जुटाए गए वित्त पर डेटा के पूरक हैं। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन के समय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशित चरणबद्ध योजनाओं के आधार पर, वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय के संभावित स्तर का अनुमान प्राप्त किया जाता है।

इस विश्लेषण में रिजर्व बैंक के आंतरिक डेटाबेस के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि प्रत्येक परियोजना केवल एक ही बार सूचना समूह में प्रवेश करे, भले ही इसे एक से अधिक स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया हो। जिन परियोजनाओं को उपर्युक्त स्रोतों में से किसी के माध्यम से वित्तपोषित नहीं किया गया है या जिनका आकार ₹10 करोड़ से कम है, वे इसमें शामिल नहीं हैं। 51 प्रतिशत से कम निजी स्वामित्व वाली या ट्रस्टों, केंद्र और राज्य सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को भी शामिल नहीं किया गया है।

ये अनुमान इस धारणा के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं कि कंपनियां अपनी प्रत्याशित व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। हालांकि, ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) में उपलब्ध कॉर्पोरेट स्थिर निवेश के वास्तविक अनुमानों से हट सकते हैं। यह इस संभावना के मद्देनजर है कि कुछ प्रत्याशित प्रयोजन उनकी राशि और निवेश के समय के संदर्भ में वास्तविक निवेश में फलित नहीं हो सकते हैं और कुछ परियोजनाएं स्व-वित्तपोषित हो सकती हैं।

III. स्वीकृत/ अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएं

निवेश का माहौल 2019-20 में सुस्त रहा था, उसे महामारी के मद्देनजर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 2020-21 की शुरुआत से ही यह मंद रहा है। नई घोषणाओं की कम संख्या के साथ मौजूदा परियोजनाओं की समय-सीमा बढ़ गई

(बॉक्स 1)। 2020-21 के दौरान बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता के आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है।

2020-21 की पहली छमाही में नई मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या घटकर 68 पर आ गई, जो 2019-20 की पहली छमाही के दौरान स्वीकृत 137 परियोजनाओं की तुलना में कम है, जो स्पष्ट रूप से कोविड-19 महामारी की भूमिका का संकेत देती है। अधिकांश बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं ने 2020-21 की पहली छमाही के दौरान 'शून्य' परियोजनाओं की सूचना दी, जो महामारी-जनित अनिश्चितताओं के कारण निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के बहुत ही मंद निवेश वातावरण की ओर इशारा करती है। 2020-21 की दूसरी छमाही में परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दिए, जिन्हें बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता मिली, हालांकि इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत के संदर्भ में निवेश का माहौल कमजोर बना रहा।

कुल मिलाकर, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने 2020-21 के दौरान निजी कंपनियों के केवल 220 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो हाल के वर्षों में रिकॉर्ड कमी⁶ है। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत भी 2020-21 में तेजी से घटकर ₹75,558 करोड़ हो गई, जो 2019-20 में ₹1,75,830 करोड़ थी (अनुबंध: सारणी ए1)।

कुल 344 कंपनियों ने ईसीबी/ एफसीसीबी के माध्यम से ₹40,382 करोड़ की राशि जुटाई और बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से किसी भी तरह के वित्तपोषण का लाभ नहीं उठाया। इसके अलावा, 12 कंपनियों ने किसी भी बैंक वित्त या ईसीबी/ एफसीसीबी का लाभ नहीं उठाया, लेकिन घरेलू इक्विटी निर्गमों के माध्यम से अपनी पूंजीगत जरूरतों के लिए ₹663 करोड़ जुटाए। कुल मिलाकर, 2020-21 के दौरान 576 परियोजनाओं की निवेश योजनाएं कुल ₹1,16,603 करोड़ की थीं, जबकि 2019-20 में 827 परियोजनाओं में कुल 2,71,374 करोड़ रुपये के निवेश प्रयोजन थे (अनुबंध: सारणी ए1-ए4)।

आकार, उद्देश्य, उद्योग और स्थान के अनुसार स्वीकृत/ अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएं नीचे वर्णित हैं:

⁶ एक वित्तीय वर्ष में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या लगभग 400 (लगभग 100 प्रति तिमाही) रही है, हालांकि गिरावट की प्रवृत्ति (2017-18 में 485, 2018-19 में 409 और 2019-20 में 320) देखी गई है। महामारी-जनित वर्ष 2020-21 में स्वीकृत परियोजनाओं की अंतिम संख्या 220 (पहली छमाही में 68 और दूसरी छमाही में 152) है। इनमें से कुछ परियोजनाओं को आगे जाकर संशोधित/ निरस्त किया जा सकता है।

(ए) आकार-वार

परियोजनाओं के आकार-वार संवितरण ने कुल परियोजना लागत में इसके संयुक्त हिस्से में कमी के साथ-साथ बृहद् परियोजनाओं (₹ 5,000 करोड़ और अधिक) की संख्या 2019-20 में पांच से कम हो गई और 2020-21 में उल्लेखनीय कमी आयी। इसी तरह, 2020-21 में ₹1000 करोड़-₹5000 करोड़ आकार की बड़ी परियोजनाओं की संख्या 36 (2019-20 में) से घटकर 24 हो गई। हालांकि ऐसी परियोजनाओं की सापेक्ष हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर 53.5 प्रतिशत हो गई, जो 2019-20 में 37.4 प्रतिशत थी, जो 2020-21 में स्वीकृत परियोजनाओं के छोटे समूह में उच्च सापेक्ष उपस्थिति का संकेत देती है। जैसा कि इस आलेख में पहले देखा गया था, परियोजनाओं के जीवन चक्र की घोषणा से लेकर पूर्ण होने तक की अवधि आम तौर पर बड़ी परियोजनाओं के लिए लंबी होती है (बॉक्स 1)। तदनुसार, बृहद्/ बड़ी परियोजनाओं की चरणबद्ध योजना का दीर्घावधि में पूंजीगत व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है (अनुबंध: सारणी ए5)।

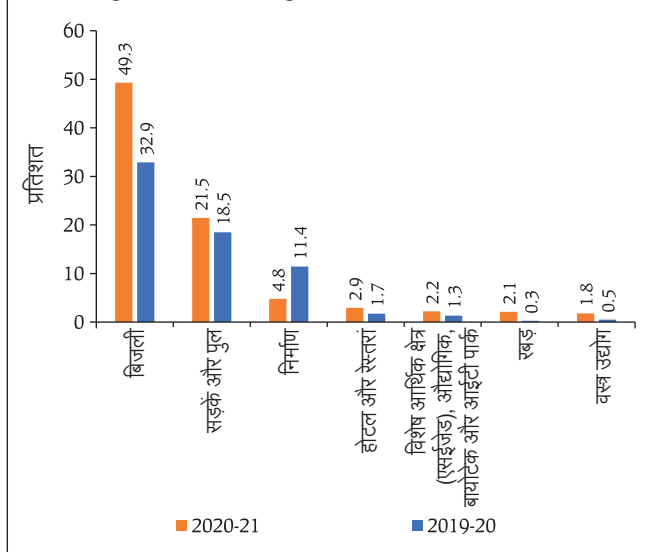
(बी) उद्देश्य-वार

परियोजनाओं के उद्देश्य-वार स्वरूप से पता चलता है कि 2020-21 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत में ग्रीन फील्ड (नई) परियोजनाओं में निवेश का प्रमुख हिस्सा (94.1 प्रतिशत) था। यह हाल के वर्षों में संरूपी हिस्सेदारी (2018-19 में 76.8 प्रतिशत और 2019-20 में 79.8 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था। मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का कुल परियोजना लागत में लगभग 5.9 प्रतिशत का योगदान है (अनुबंध: सारणी ए6)।

(सी) उद्योग-वार

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (iv) भंडारण और जल प्रबंधन, (v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क, और (vi) सड़कें और पुल शामिल हैं। 2019-20 में इनकी हिस्सेदारी 61.5 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 74.3 प्रतिशत हो गई है। इसका श्रेय इसके दो सबसे बड़े घटकों, अर्थात् 'बिजली क्षेत्र' और 'सड़कों और पुलों' में तेज वृद्धि को दिया जा सकता है। हालांकि, कई उद्योगों में अच्छी-खासी गिरावट दर्ज होने के कारण 2020-21 में कुल परियोजना लागत में 2019-20 की तुलना में कमी आयी। उदाहरण के लिए, 'बिजली क्षेत्र' में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत

चार्ट 5: बैंकों/ एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख उद्योगों की हिस्सेदारी



2019-20 में ₹57,855 करोड़ से घटकर ₹37,253 करोड़ हो गई, हालांकि 2020-21 में इसकी सापेक्ष हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। इसी तरह 'सड़कों और पुलों' के मामले में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत भी 2019-20 में ₹32,522 करोड़ से घटकर ₹16,224 करोड़ हो गई। यह स्मरण किया जा सकता है कि समग्र तौर पर, परियोजनाओं की कुल लागत में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में आधे से अधिक (57 प्रतिशत) की गिरावट आयी है (चार्ट 5 और अनुबंध: सारणी ए7)।

चूंकि देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की अगुवाई में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश की महती भूमिका है, इसलिए इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी गई है और आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करने हेतु समय-समय पर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा भी की गई है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) ने 2020-25 की अवधि के दौरान ₹111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के साथ पांच साल का रोडमैप निर्धारित किया है, जिसमें परियोजनाओं को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा।

महामारी के कारण समग्र रूप से कमजोर निवेश माहौल के बावजूद उद्योग विवरण, स्वीकृत परियोजनाओं में परिलक्षित जानकारी की पुष्टि करते हैं। आगे बढ़ते हुए, इन नई इन्फ्रास्ट्रक्चर

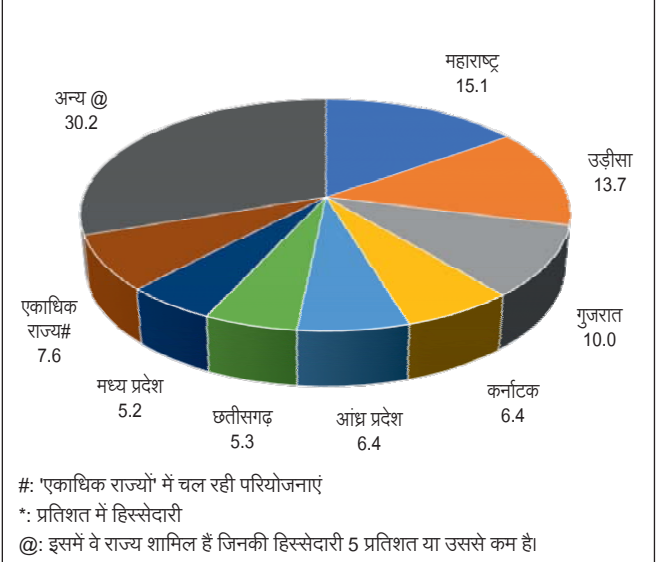
परियोजनाओं (सड़कों और पुलों और निर्माण) के सफल कार्यान्वयन में वृद्धि बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि, महामारी ने अल्पावधि में इन परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की होगी, जो अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे गति पकड़ने के साथ कम होनी चाहिए।

(डी) राज्य-वार

एक परियोजना का स्थान चुनने के निर्णायक कारक निम्न हैं: कच्चे माल तक पहुंच, श्रम की उपलब्धता, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, बाजार का आकार और वृद्धि की संभावनाएं। पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के आंकड़ों से पता चला है कि आधे से अधिक (52.3 प्रतिशत) परियोजनाएं का आरंभ पांच राज्यों में शुरू किया गया था, अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 2020-21 में इसके हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आने के बावजूद, 2016-21 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान 2011-16 की पंचवर्षीय अवधि की तुलना में एक से अधिक राज्यों में परियोजनाओं के प्रसार में वृद्धि हुई है (चार्ट 6 और चार्ट 7)।

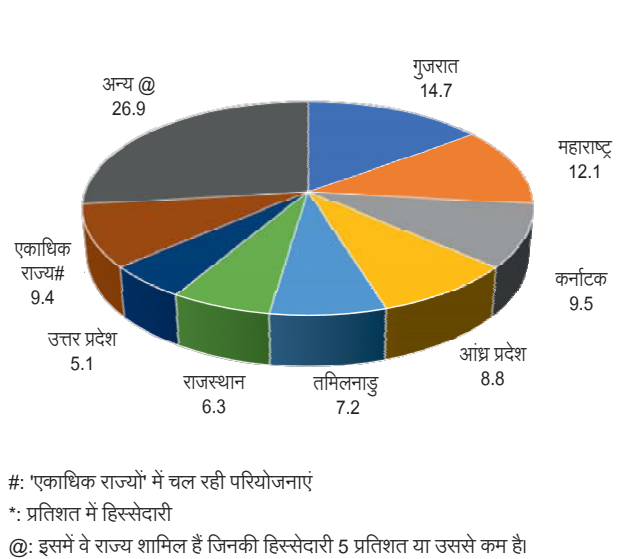
2020-21 में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में राजस्थान और गुजरात की सबसे अधिक (17.1 प्रतिशत) हिस्सेदारी थी, इसके बाद आंध्र प्रदेश (15 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (13.7 प्रतिशत), महाराष्ट्र (8.5 प्रतिशत), हरियाणा (7.8 प्रतिशत), कर्नाटक (6.1 प्रतिशत) की

चार्ट 7: 2011-12 से 2015-16* तक की अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण*

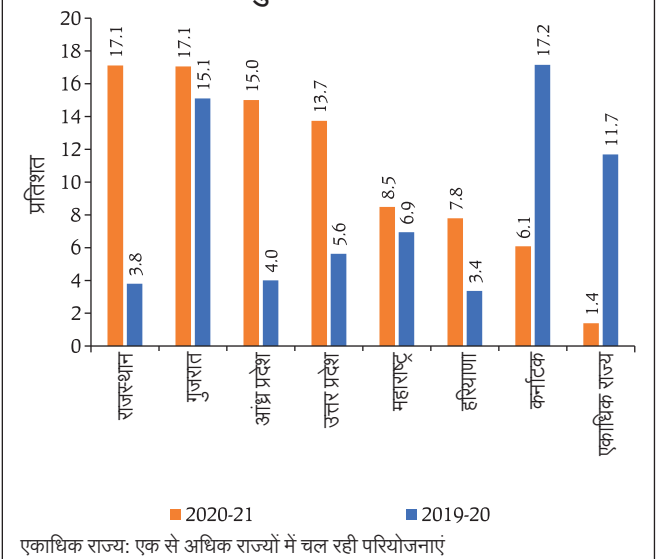


हिस्सेदारी थी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण लाभ (10 से अधिक प्रतिशत अंक) दर्ज करने के साथ पंचवर्षीय अवधि के दौरान भी बढ़ोतरी की है। दूसरी ओर, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने हिस्से में गिरावट दर्ज की (चार्ट 8 और अनुबंध: सारणी ए8)।

चार्ट 6: 2016-17 से 2020-21* तक की अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण*



चार्ट 8: बैंकों/ एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख राज्यों की हिस्सेदारी



IV. निवेश के प्रयोजन की चरणबद्ध रूपरेखा

विभिन्न वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा की जानकारी से पूंजीगत व्यय का अल्पकालिक (एक वर्ष आगे का) पूर्वानुमान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 2020-21 में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से चरणबद्ध तरीके से संकेत मिलता है कि 2020-21 में कुल प्रस्तावित व्यय का 38.4 प्रतिशत (₹29,013 करोड़), 2021-22 में 34.6 प्रतिशत (₹26,166 करोड़) और 2021-22 के बाद के वर्षों में 18.8 प्रतिशत (₹14,179 करोड़) निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा उपगत किया गया होगा। 2020-21 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत का लगभग 8.2 प्रतिशत 2020-21 से पहले ही खर्च कर दिया गया था। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 2020-21 में नियोजित व्यय से परिकल्पित पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.9 प्रतिशत (₹1,38,288 करोड़ से ₹1,23,240 करोड़) की गिरावट देखी गई (अनुबंध: सारणी ए1)।

अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों से किए जाने वाले पूंजीगत व्यय में भी लगभग 59 प्रतिशत की कमी आई, जो लगातार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक रहा। पूंजी बाजार (इक्विटी माध्यम) ने 2020-21 में ₹159 करोड़ के परिकल्पित पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण को समर्थित किया, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम था (अनुबंध: सारणी ए2, ए3)।

संक्षेप में, यह आंकलन किया गया है कि 2020-21 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा ₹1,60,407 करोड़ का कुल पूंजीगत व्यय (सभी माध्यमों से) किया जाएगा, जो कि नियोजित चरणबद्धता से 30 प्रतिशत की कम होगा। पिछला साल। इस तीव्र गिरावट का कारण वित्तपोषण के सभी माध्यम हैं (अनुबंध: सारणी ए4)।

पिछले वर्षों में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहले से स्वीकृत प्रक्रियाधीन परियोजनाओं⁷ पर आधारित परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा यह दर्शाती है कि यह 2020-21 में ₹94,227 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹68,469 करोड़ होने का संकेत देती है। यह वित्तपोषण के सभी माध्यमों पर ध्यान में रखते हुए भी 2021-22 में ₹1,07,535 करोड़ (2020-21 में

⁷ प्रक्रियाधीन परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं, जिनका कार्यान्वयन पहले ही आरंभ चुका है। किसी प्रक्रियाधीन परियोजना से पूंजीगत व्यय किसी वर्ष के लिए वे परिकल्पित राशियां हैं, जो उस वर्ष से पहले वाले वर्ष में मंजूर हो चुकी हैं।

₹1,13,171 करोड़) पर भी कम है। हालाँकि, यह बहुत संभव है कि 2020-21 के दौरान इनमें से कई की प्राप्ति नहीं की गई हो और 2021-22 में कुछ अन्य को आकस्मिक महामारी संबंधी अनिश्चितताओं के कारण प्राप्त नहीं जा सके (अनुबंध: सारणी ए1 और ए4)।

V. निजी स्थानन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट निवेश

हाल के वर्षों में, कॉर्पोरेट क्षेत्र ने पूंजीगत व्यय वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में बॉन्ड और ऋण-पत्र (डिबेंचर) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जैसे कर्ज लिखतों पर आश्रित हुआ है। कर्ज के निजी स्थानन के आंकड़ों से पता चलता है कि 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कर्ज (बॉन्ड और डिबेंचर) के निजी स्थानन के माध्यम से निधि जुटाना काफी हद तक बढ़ा, लेकिन इसके बाद 2016-17 में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के बाद इसमें काफी कमी आयी। 2019-20 में गिरावट के बाद 2020-21 में इसमें इजाफा हुआ। पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में एफडीआई की प्राथमिकता भी देखी गई है, जिसमें 2017-18 को छोड़कर 2012-13 से लगातार एफडीआई राशि में वृद्धि हुई है। तदनुसार, एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2020-21 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा (सारणी 1)।

सारणी 1: निजी स्थानन और एफडीआई

(₹ करोड़ में)

अवधि	कर्ज-निजी स्थानन*	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**
2011-12	27,040	165,146
2012-13	59,188	121,907
2013-14	56,042	147,518
2014-15	97,358	181,682
2015-16	118,317	262,322
2016-17	153,356	291,696
2017-18	136,599	288,889
2018-19#	129,971	309,867
2019-20#	105,699	353,558
2020-21#	128,930	442,569

*: केवल निजी क्षेत्र की विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए

** : आवक एफडीआई में केवल इक्विटी पूंजी शामिल है

: अनंतिम आंकड़े

स्रोत: प्राइम डेटाबेस और भारत सरकार

VI. निष्कर्ष

यह आलेख समग्र निवेश प्रयोजन पर पहुंचने और निकट अवधि में निवेश गतिविधि के दृष्टिकोण का आंकलन करने के लिए अपने परियोजना प्रस्तावों की चरणबद्ध योजनाओं (प्रत्याशित) के आधार पर निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश के प्रयोजन पर डेटा का उपयोग करता है।

कोविड-19 से पहले भी अर्थव्यवस्था मंद निवेश की भावना से सराबोर थी, जैसा कि कम संख्या में परियोजनाओं की नई घोषणाओं के साथ-साथ मौजूदा परियोजनाओं के जीवन चक्र के विस्तार से परिलक्षित होता है। महामारी ने 2020-21 के दौरान नई परियोजनाओं की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और

प्रक्रियाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में भी बाधा उत्पन्न की। प्रक्रियाधीन परियोजनाओं से संबंधित समय-सीमा की निगरानी करना - इसके विस्तार की सीमा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से संभावित परिणाम की रेंज (पूर्णता/ परित्याग/ आस्थगन आदि) - इसलिए महत्वपूर्ण होगी। परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा 2021-22 में निजी निवेश दृष्टिकोण के लिए निकट-अवधि के जोखिमों को दर्शाता है, जबकि 2021-22 में नई परियोजनाएं निजी निवेश के दृष्टिकोण को आकार देंगी; प्रक्रियाधीन परियोजनाएं 2020-21 से 2021-22 तक आस्थगित प्रक्रियाधीन निवेश से सामान्य को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे निजी निवेश पर समग्र जोर सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है।

अनुबंध

सारणी ए1: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण

मंजूरी देने का वर्ष ↓	परियो-जनाओं की संख्या	मंजूरी के वर्ष में परियोजना लागत (₹ करोड़)	संशोधन/ निरसन* के कारण परियोजना लागत & (₹ करोड़)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2011-12 तक				2,90,613	1,78,643	86,858	21,408	3,044	869						
2012-13	414	1,96,345	1,89,483 (3.5)	36,664	56,725	48,976	27,325	11,219	6,447	2,045					
2013-14	472	1,34,019	1,27,328 (5.0)	1,332	15,139	34,769	44,925	19,909	7,105	2,677	1,472				
2014-15	326	87,601	87,253 (0.4)		98	14,822	34,589	25,765	9,535	1,246	162	1,036			
2015-16	346	95,371	91,781 (3.8)			3,787	7,434	37,517	28,628	8,079	4,964	1,152	220		
2016-17	541	1,82,807	1,79,249 (2.0)			1,352	3,952	25,388	71,186	41,075	21,643	8,566	4,001	2,086	
2017-18	485	1,72,831	1,68,239 (2.6)				620	15,184	12,445	63,001	41,436	22,767	10,202	2,342	242
2018-19	409	1,76,581	1,59,189 (9.8)					569	6,862	11,000	59,973	47,080	21,248	9,759	2,698
2019-20	320	2,00,038	1,75,830 (12.1)							4,049	14,524	53,978	58,556	28,116	16,607
2020-21	220	75,558									2,491	3,709	29,013	26,166	14,179
कुल#				3,28,609	2,50,605	1,90,564	1,40,253	1,38,595	1,43,077	1,33,172	1,46,665	1,38,288	1,23,240	68,469	33,726
प्रतिशत परिवर्तन					-23.7	-24.0	-26.4	-1.2	3.2	-6.9	10.1	-5.7	-10.9	*	

: कॉलम के योग किसी वर्ष विशेष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं जिसमें उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें विभिन्न वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ये प्रत्याशित अनुमान हैं जिनमें केवल परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। वे वास्तव में प्राप्त/ प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

*: 2021-22 के लिए प्रतिशत परिवर्तन पर काम नहीं किया गया है क्योंकि 2021-22 में स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव से पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधन/ निरस्तीकरण का प्रतिशत हैं।

सारणी ए2: ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी** के माध्यम से वित्तपोषित कैपेक्स परियोजनाओं* की चरणबद्धता

मंजूरी देने का वर्ष ↓	परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुबंधित ऋण (₹ करोड़)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011-12 तक			38,342	15,673	2,400	100								
2012-13	519	65,692		37,792	20,267	6,300	1,333							
2013-14	563	80,736			56,197	20,976	3,563							
2014-15	478	57,327				36,791	16,806	3,151	575	2	2			
2015-16	314	38,885					28,998	7,311	2,572	4				
2016-17	346	22,154						14,953	6,005	1,192	2	2		
2017-18	419	37,896							17,822	13,054	6,484	529	7	
2018-19	515	72,490								46,221	17,725	1,236	5,398	1,910
2019-20	495	95,491									65,367	17,157	11,717	1,250
2020-21	344	40,382										18,084	21,523	775
कुल&			38,342	53,465	78,864	64,167	50,700	25,415	26,974	60,473	89,580	37,008	38,645	3,935
प्रतिशत परिवर्तन				39.4	47.5	-18.6	-21.0	-49.9	6.1	124.2	48.1	-58.7	#	

*: जिन परियोजनाओं को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

** : रुपये में अंकित बांड (आरडीबी) 2016-17 से शामिल किए गए हैं।

: 2021-22 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की है क्योंकि 2021-22 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है, वे पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है।

& : अनुमान प्रत्याशित हैं, इनमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/ प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों* के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

इक्विटी निर्गम की अवधि ↓	कंपनियों की संख्या	परिकल्पित कैपेक्स (₹ करोड़ में)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011-12 तक			1,186	455										
2012-13	25	1,135		533	494	108								
2013-14	21	454				384	70							
2014-15	24	1,078				189	557	332						
2015-16	40	4,511				11	644	2,753	849	183	71			
2016-17	29	1,159					14	471	368	163	143			
2017-18	51	1,538							419	327	787	5		
2018-19	39	609								506	90	13		
2019-20	12	53								2	49	2		
2020-21	12	663										139	421	103
कुल*			1,186	988	494	692	1,285	3,556	1,636	1,181	1,140	159	421	103
प्रतिशत परिवर्तन				-16.7	-50.0	40.1	85.7	176.7	-54.0	-27.8	-3.5	-86.1	#	

*: जिन परियोजनाओं को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

#: 2021-22 के लिए प्रतिशत परिवर्तन पर काम नहीं किया गया है क्योंकि 2021-22 में लागू होने वाले प्रस्तावों से पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान प्रत्याशित हैं, इनमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/ प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी ए4: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ आईपीओ/ ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी* / आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

कंपनियों की संख्या ↓	कंपनियों की संख्या	परियोजना लागत (₹ करोड़)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 के बाद
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011-12 तक			3,30,141	1,94,771	89,258	21,508	3,044	869						
2012-13	958	2,56,310	36,664	95,050	69,737	33,733	12,552	6,447	2,045					
2013-14	1,056	2,08,518	1,332	15,139	90,966	66,285	23,542	7,105	2,677	1,472				
2014-15	828	1,45,658		98	14,822	71,569	43,128	13,018	1,821	164	1,038			
2015-16	700	1,35,177			3,787	7,445	67,159	38,692	11,500	5,151	1,223	220		
2016-17	916	2,02,562			1,352	3,952	25,402	86,610	47,448	22,998	8,711	4,003	2,086	
2017-18	955	2,07,673				620	15,184	12,445	81,242	54,817	30,038	10,736	2,349	242
2018-19	963	2,32,288					569	6,862	11,000	1,06,700	64,895	22,497	15,157	4,608
2019-20	827	2,71,374							4,049	14,526	1,19,394	75,715	39,833	17,857
2020-21	576	1,16,603								2,491	3,709	47,236	48,110	15,057
कुल*			3,68,137	3,05,058	2,69,922	2,05,112	1,90,580	1,72,048	1,61,782	2,08,319	2,29,008	1,60,407	1,07,535	37,764
प्रतिशत परिवर्तन				-17.1	-11.5	-24.0	-7.1	-9.7	-6.0	28.8	9.9	-30.0	#	

*: रुपये में अंकित बॉन्ड (आरडीबी) 2016-17 से शामिल किए गए हैं।

#: 2021-22 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2021-22 तक स्वीकृति की संभावनाओं वाली परियोजनाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

&: आकलन प्रत्याशित हैं, जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/ प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी ए5: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2011-12 से 2020-21

अवधि		₹100 करोड़ से कम	₹100 करोड़ से ₹500 करोड़ तक	₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़ तक	₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़ तक	₹5000 करोड़ और उससे अधिक	कुल
2011-12	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	420 8.3	145 17.0	36 13.7	26 27.6	9 33.4	636 100 (1,91,592)
2012-13	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	245 4.8	119 14.6	20 7.3	23 26.8	7 46.4	414 100 (1,89,483)
2013-14	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	306 8.3	115 20.0	25 13.9	21 29.1	5 28.7	472 100 (1,27,328)
2014-15	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	223 9.0	65 16.6	18 14.6	19 47.8	1 12.0	326 100 (87,253)
2015-16	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	214 8.6	76 20.9	34 26.0	21 38.5	1 5.9	346 100 (91,781)
2016-17	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	287 5.8	180 23.3	29 11.9	40 41.7	5 17.4	541 100 (1,79,249)
2017-18	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	263 5.2	149 21.0	28 10.8	42 43.8	3 19.1	485 100 (1,68,239)
2018-19	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	220 4.8	110 17.0	39 17.0	36 39.6	4 21.6	409 100 (1,59,189)
2019-20	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	150 3.3	84 11.9	45 18.6	36 37.4	5 28.8	320 100 (1,75,830)
2020-21	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	128 5.5	52 16.8	15 14.2	24 53.5	1 10.0	220 100 (75,558)

टिप्पणी : i. कोष्ठक में दिये गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत को दर्शाते हैं।
ii. प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजनाओं की कुल लागत का प्रतिशत है। पूर्णांकन किए जाने के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का योग सौ ना हो।

सारणी ए6: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य-वार वितरण: 2011-12 से 2020-21

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी	नई	विस्तार और आधुनिकीकरण	विविधीकरण	अन्य	कुल
2011-12	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	449 70.6	172 23.1	5 0.1	10 6.3	636 100 (1,91,592)
2012-13	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	303 84.2	107 14.7	- -	4 1.1	414 100 (1,89,483)
2013-14	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	361 65.2	95 20.1	2 -	14 14.7	472 100 (1,27,328)
2014-15	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	203 39.4	92 14.7	2 0.2	29 45.7	326 100 (87,253)
2015-16	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	260 73.6	64 14.3	3 0.1	19 12.0	346 100 (91,781)
2016-17	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	429 78.6	97 9.9	4 0.1	11 11.3	541 100 (1,79,249)
2017-18	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	396 89.0	80 9.5	2 0.1	7 1.5	485 100 (1,68,239)
2018-19	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	309 76.8	80 19.3	- -	20 3.9	409 100 (1,59,189)
2019-20	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	262 79.8	37 13.7	1 -	20 6.4	320 100 (1,75,830)
2020-21	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	181 94.1	38 5.9	1 -	- -	220 100 (75,558)

टिप्पणी: i. कोष्ठक में दिये गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत को दर्शाते हैं।
ii. प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजनाओं की कुल लागत का प्रतिशत है। पूर्णांकन किए जाने के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का योग सौ ना हो।
iii.-: शून्य/ नगण्य।

सारणी ए7: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योग-वार वितरण: 2011-12 से 2020-21

उद्योग	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी
इन्फ्रास्ट्रक्चर	107	47.4	82	47.9	87	39.8	74	48.8	108	72.0	204	62.6	150	51.8	122	60.4	99	61.5	63	74.3
i) बिजली	82	42.4	71	39.4	70	35.1	65	42.2	92	57.1	170	45.4	117	36.5	78	26.8	47	32.9	35	49.3
ii) दूरसंचार	1	0.0	2	5.6	1	0.0	1	4.9	1	0.3	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे	1	1.3	1	1.9	1	0.8	-	-	3	2.4	8	5.7	6	3.1	4	14.2	4	8.4	1	0.1
iv) भंडारण और जल प्रबंधन	12	0.5	-	-	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.4	13	5.7	4	0.4	5	1.2
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क	11	3.2	8	0.9	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	9	1.6	11	3.2	8	1.3	5	2.2
vi) सड़कें और पुल	-	-	-	-	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	10.1	16	10.4	36	18.5	17	21.5
निर्माण	23	1.8	20	2.8	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12.0	39	5.3	26	2.3	44	11.4	27	4.8
होटल और रेस्तरां	51	4.6	31	3.1	29	2.7	15	1.1	16	1.1	12	0.8	29	2.9	26	1.9	16	1.7	4	2.9
रबड़ उत्पाद	18	0.9	7	0.5	9	0.3	8	0.8	4	0.5	8	0.2	10	2.5	5	0.5	5	0.3	17	2.1
वस्त्र	94	7.0	31	1.9	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.7	27	3.4	11	0.5	15	1.8
रसायन और उर्वरक	17	3.5	19	1.1	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.4	19	2.9	12	1.3	9	1.6
खाद्य पदार्थ	41	1.5	36	0.9	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.8	28	1.4	32	1.9	20	1.5
सीमेंट	9	2.0	11	3.9	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6	10	5.1	2	0.1	5	1.3
धातु और धातु के उत्पाद	73	16.3	51	28.9	44	17.0	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.7	16	3.0	14	0.8	6	0.8
फार्मास्युटिकल्स	20	0.8	10	0.4	19	1.3	9	1.5	11	0.3	12	1.1	15	0.6	23	1.6	9	0.6	7	0.5
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं	9	0.3	17	1.4	10	0.7	2	0.1	1	0.0	22	1.1	18	1.8	15	2.6	12	0.7	7	0.3
परिवहन उपकरण	26	2.6	17	0.9	16	1.2	7	5.3	4	2.5	9	3.6	10	0.3	5	0.8	5	0.4	2	0.3
खनन और उत्खनन	4	0.2	2	0.1	1	0.6	2	0.1	10	2.7	4	0.4	1	0.0	7	5.6	6	5.3	2	0.2
अन्य*	144	11.0	80	5.8	102	14.1	65	7.5	61	7.4	77	3.9	65	6.7	80	8.5	53	13.4	36	7.7
कुल	636	100	414	100	472	100	326	100	346	100	541	100	485	100	409	100	320	100	220	100
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़)	1,91,592		1,89,483		1,27,328		87,253		91,781		1,79,249		1,68,239		1,59,189		1,75,830		75,558	

*: कृषि और संबंधित गतिविधियों, कागज और कागज से बने उत्पाद, मुद्रण और प्रकाशन, रबड़ के उत्पाद, आईटी सॉफ्टवेयर, संचार, व्यापार सेवाएं, कागज और कागज उत्पाद, मनोरंजन, अन्य विनिर्माण, अन्य सेवाओं आदि जैसे उद्योगों शामिल हैं।

- : शून्य / नगण्य।

टिप्पणी: प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजनाओं की कुल लागत का प्रतिशत है। पूर्णांकन किए जाने के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का योग सौ ना हो।

सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण: 2011-12 से 2020-21

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी
राजस्थान	49	4.9	41	5.3	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.3	21	7.7	23	3.8	21	17.1
गुजरात	75	9.0	58	5.6	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	8.0	56	11.1	47	15.1	54	17.1
आंध्र प्रदेश	52	5.1	35	5.7	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.9	29	11.1	12	4.0	7	15.0
उत्तर प्रदेश	42	7.8	26	4.4	21	1.1	20	5.4	15	2.5	22	3.7	30	2.4	28	4.8	24	5.6	30	13.7
महाराष्ट्र	86	19.1	67	10.7	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	23.3	34	11.5	41	6.9	13	8.5
हरियाणा	45	1.4	18	1.2	15	1.1	11	1.9	16	3.6	13	1.6	21	0.5	18	1.7	20	3.4	15	7.8
कर्नाटक	39	12.0	20	1.6	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	64	9.6	34	5.7	33	17.2	11	6.1
असम	3	0.2	1	0.5	4	0.3	2	0.2	4	0.4	10	0.6	5	0.8	4	0.2	1	0.3	3	4.4
मध्य प्रदेश	16	5.6	13	3.9	30	6.1	14	3.9	21	7.0	18	7.5	10	0.7	12	1.6	10	1.2	19	2.8
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.8	51	5.5	17	1.9	26	9.1	12	4.0	9	1.9
छत्तीसगढ़	11	2.4	9	4.1	16	10.7	8	7.4	8	4.6	15	4.0	7	4.8	6	0.9	6	0.2	3	1.2
तमिलनाडु	58	5.7	22	1.8	33	5.4	27	2.9	26	9.3	23	4.4	28	6.6	32	12.8	28	8.3	7	0.7
पंजाब	37	1.7	12	10.9	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	31	2.2	15	1.9	9	0.8	4	0.7
पुदुचेरी	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.5
पश्चिम बंगाल	19	4.9	13	1.0	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8	13	1.1	7	0.9	3	0.4
झारखंड	12	1.3	8	1.2	4	0.3	2	0.7	5	0.3	1	0.0	3	0.3	2	0.5	4	9.4	1	0.2
जम्मू और कश्मीर	5	0.2	10	0.2	10	5.2	2	0.1	9	0.2	3	0.1	8	2.0	11	0.4	3	0.1	5	0.2
हिमाचल प्रदेश	7	0.5	5	0.3	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	0.0	8	2.3	7	0.3	6	0.1	4	0.2
एकाधिक राज्य#	34	4.5	15	7.7	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	16	7.5	15	9.8	8	11.7	2	1.4
अन्य*	46	14.0	41	34.1	32	12.5	23	17.3	25	4.6	38	7.5	32	9.0	46	8.2	26	7.1	8	0.2
कुल	636	100	414	100	472	100	326	100	346	100	541	100	485	100	409	100	320	100	220	100
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़)	1,91,592		1,89,483		1,27,328		87,253		91,781		1,79,249		1,68,239		1,59,189		1,75,830		75,558	

#: इसमें एकाधिक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही परियोजनाएं शामिल हैं।

*: इसमें शेष राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

‘-’: शून्य/ नगण्य अथवा सूचना उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी: प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजनाओं की कुल लागत का प्रतिशत है। पूर्णांकन किए जाने के कारण हो सकता है कि प्रतिशत का योग सौ ना हो।

वृद्धि पथ को दर्शाती वित्तीय समावेशन योजनाएं*

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा 2016 से 2020 तक प्रस्तुत वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) के आंकड़ों की समीक्षा वित्तीय समावेशन क्षेत्र में पीएसबी के प्रभुत्व को दर्शाती है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पहुंच संकेतकों में वृद्धि धीमी रही है, जबकि पीवीबी के लिए, पहुंच और उपयोग संकेतक दोनों में वृद्धि उच्च रही है। वैकल्पिक वितरण मॉडल होने से, कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल प्रमुख वितरण मॉडल के रूप में उभर रहा है। उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्य क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से वक्र के पीछे रहे हैं, ने समीक्षा अवधि के दौरान वित्तीय समावेशन के पहुंच संकेतक में बेहतर प्रदर्शन किया है।

1. भूमिका

भारत में, वित्तीय समावेशन के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल और विषम बैंकिंग संरचना की दिशा में प्रयास कर रहे रिजर्व बैंक के साथ मिलकर बैंक वित्तीय समावेशन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय संदर्भ में, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हुई प्रगति को मापने का महत्वपूर्ण पैमाना वर्ष 2010 से रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) का आकलन रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य वित्तीय समावेशन के लिए एक नियोजित और संरचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना है। इन योजनाओं के माध्यम से, प्रत्येक बैंक समूह से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी विशिष्ट दक्षताओं का लाभ उठाने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) नागरिकों के बीच पहुंच और कथित विश्वास में अपने प्रभुत्व के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की शुरुआत कर सकते हैं, वहीं निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) प्रौद्योगिकी को जल्दी अपनाकर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) अपनी

* यह लेख वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) के वित्तीय समावेशन प्रभाग के सुष्मिता फुकन, साजू थॉमस पुन्नूस, अभिषेक कुमार, दिनेशकुमार एस और अभिषेक कुमार द्वारा तैयार किया गया है। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त करते हों।

स्थानीय और क्षेत्रीय उपस्थिति के माध्यम से समावेशन सुनिश्चित कर सकते हैं।

इन बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए एफआईपी विवरणियों का उपयोग करते हुए, वित्तीय समावेशन की पहुंच और उपयोग संबंधी आयामों के तहत प्रगति का प्रभावी ढंग से आकलन किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की प्रगति वैश्विक मंच पर अत्यधिक प्रासंगिकता रखती है, क्योंकि देश जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के मामले में सातवां सबसे बड़ा देश है।

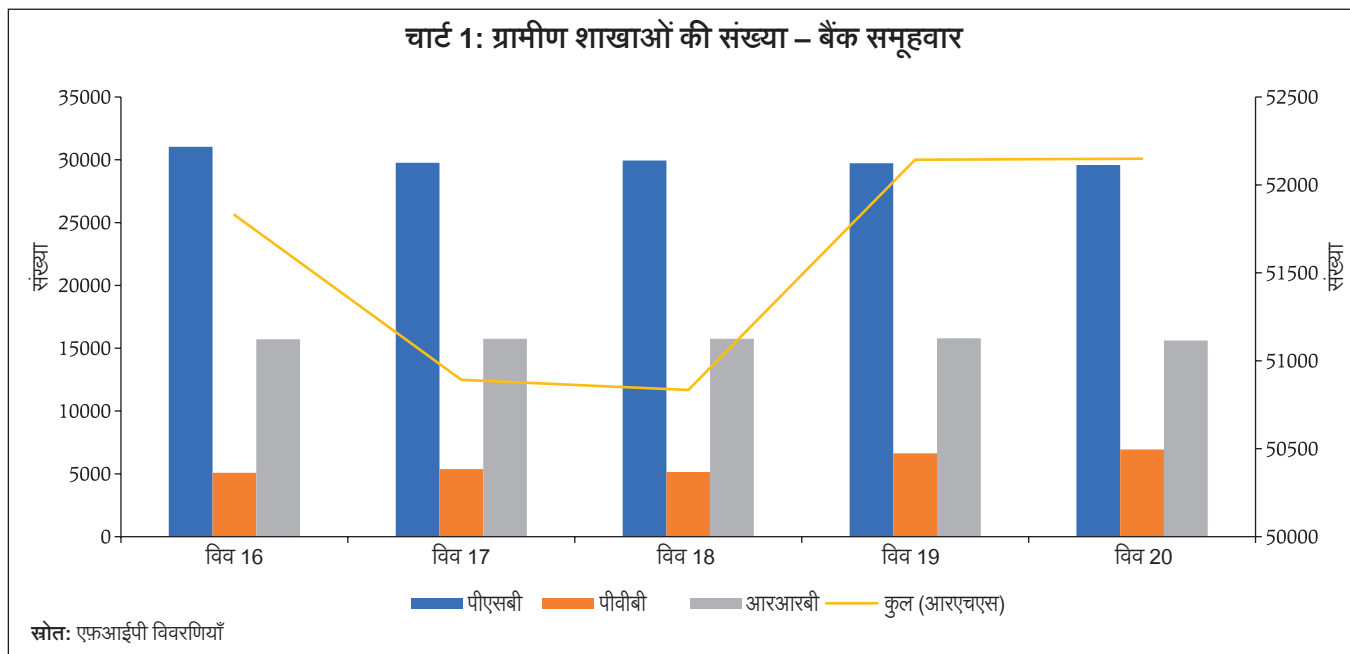
इस आलेख में भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 2016 से 2020 तक पांच साल की अवधि के दौरान एफआईपी के हिस्से के रूप में हासिल की गई प्रगति को समझने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में विभिन्न बैंक समूहों की ताकत और सीमाओं के क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया गया है। आलेख को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में पहुंच संबंधी विषय की चर्चा की गयी है जबकि खंड 3 में उपयोग के मुद्दे को दर्शाया गया है। बीसी मॉडल की चर्चा खंड 4 में की गयी है जबकि खंड 5 में निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. पहुंच

पहुंच वित्तीय समावेशन के आयामों में से एक है, जो ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों की श्रेणी को संदर्भित करता है। इस खंड में, वित्तीय समावेशन के दो प्रमुख पहुंच मानकों के अंतर्गत वृद्धि अर्थात् ग्रामीण बैंक शाखाओं और बीसी का विश्लेषण किया गया है।

ए. ग्रामीण शाखाओं में वृद्धि

समीक्षा अवधि के दौरान, पारंपरिक भौतिक शाखाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच का विस्तार उत्साहहीन रहा है; इसने केवल 0.15 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की। पीएसबी और आरआरबी में, इस अवधि के दौरान उनकी ग्रामीण शाखाओं की संख्या में कमी के कारण समेकन की ओर रुझान था। दूसरी ओर, समीक्षाधीन अवधि के दौरान पीवीबी की ग्रामीण शाखाओं ने 8.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है (चार्ट 1)।

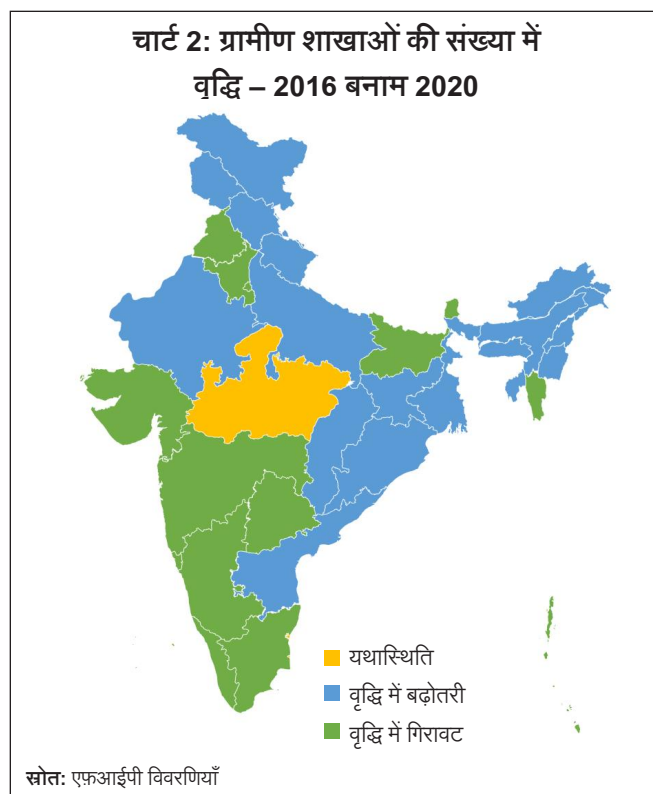


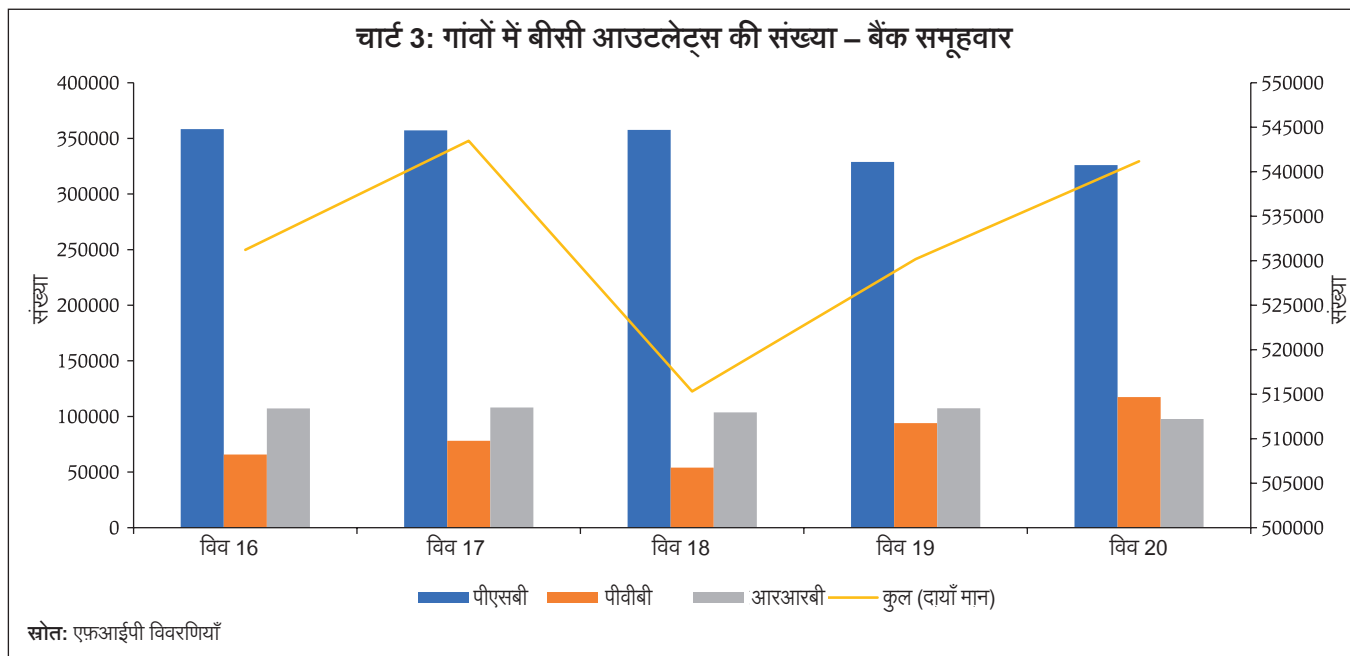
उत्तर-पूर्वी (एनई) क्षेत्र में ग्रामीण शाखाओं की संख्या में वृद्धि सबसे अधिक 3.70 प्रतिशत थी, इसके बाद पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में क्रमशः 1.35 प्रतिशत और 0.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों ने इस अवधि में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी (चार्ट 2)।

बी. गांवों में बीसी आउटलेट में वृद्धि

अधिकाधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, बीसी मॉडल ने पारंपरिक भौतिक शाखाओं की तुलना में अधिक प्रमुखता पायी है। आगे चलकर, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, विशेष रूप से वंचित / कम सेवा वाले हिस्सों में बीसी आउटलेट्स के माध्यम से प्रावधान किया जा रहा है। पीएसबी गांवों में बीसी आउटलेट्स की संख्या पर हावी थे, जिसकी चर्चा बाद में उप-खंड सी में की गई है, लेकिन समीक्षा अवधि के दौरान, समेकन के कारण, उनके बीसी आउटलेट्स ने ऋणात्मक वृद्धि दिखाई। गांवों में बीसी

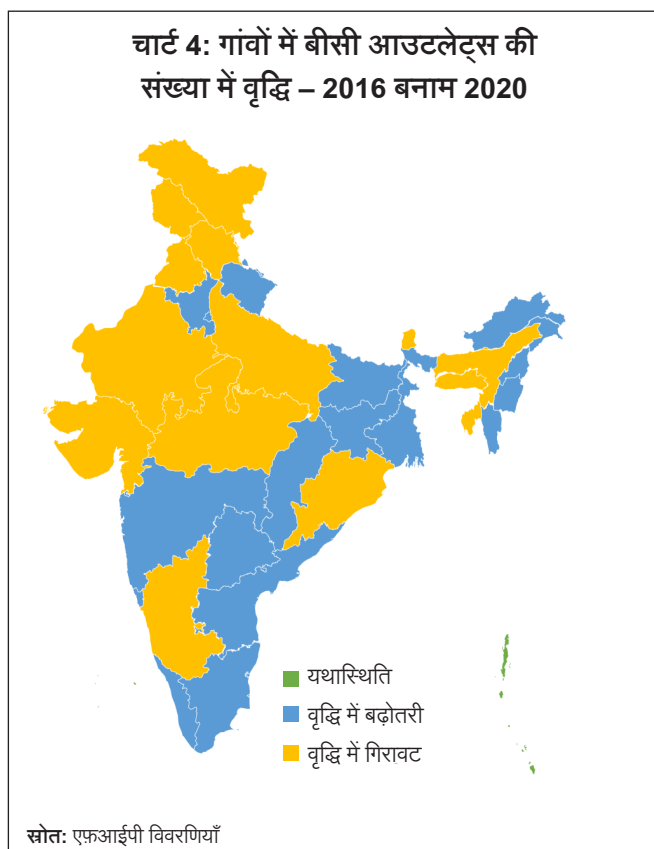
आउटलेट की वृद्धि भी आरआरबी के लिए ऋणात्मक थी। इसके विपरीत, पीवीबी ने 2016 और 2020 के बीच आउटलेट्स में धनात्मक वृद्धि दर्ज की (चार्ट 3)।





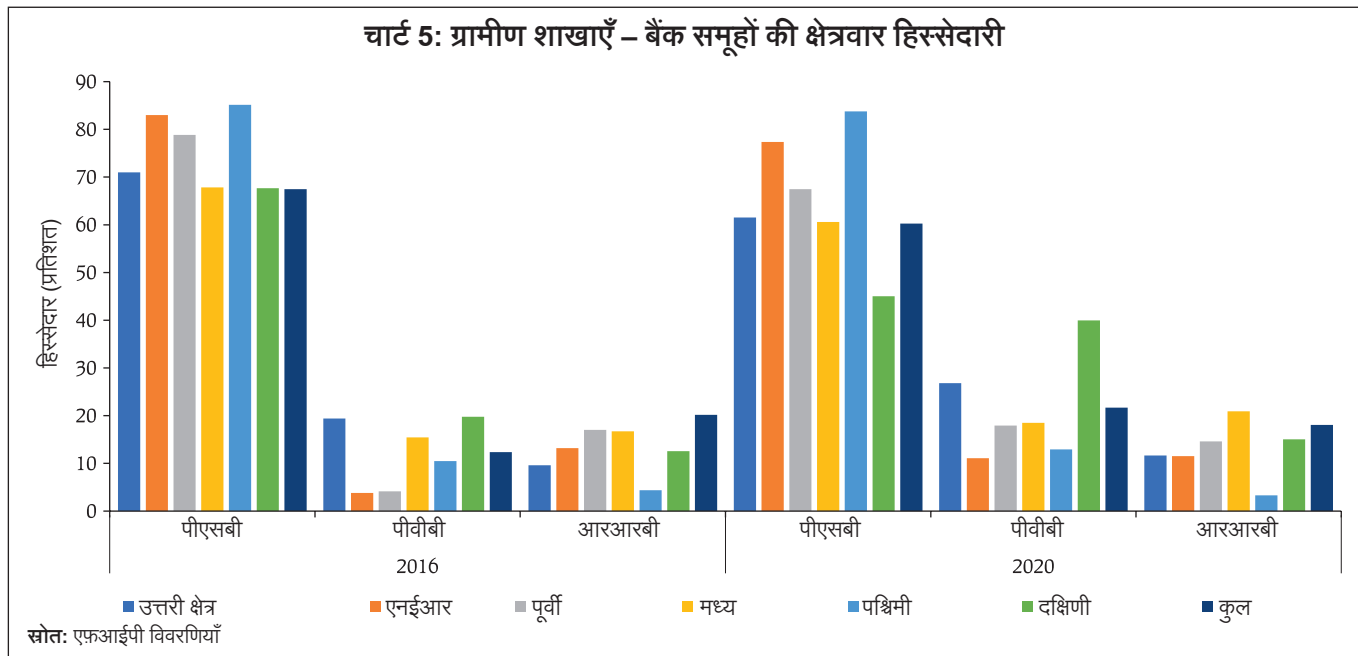
हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी आउटलेट्स में पीएसबी की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार 60% से अधिक रही है, जो बैंक समूहों में सबसे अधिक है।

समीक्षा अवधि के दौरान 22,998 आउटलेट के साथ पूर्वी क्षेत्र में गांवों में बीसी आउटलेट्स की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 4)।



सी. बीसी ग्राम आउटलेट और ग्रामीण शाखाओं की हिस्सेदारी

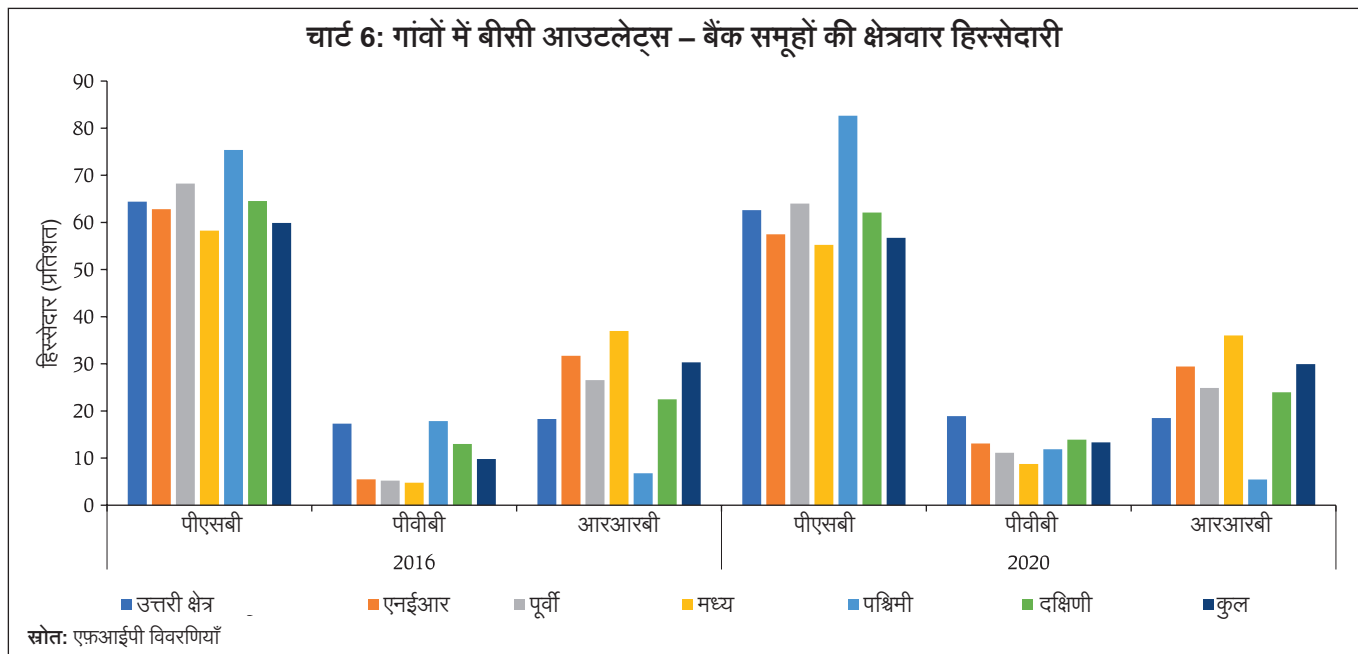
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पीएसबी ने गांव में बीसी आउटलेट में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है, लेकिन इन आउटलेट्स पर उनका दबदबा बना हुआ है। इसी तरह, वे देश में ग्रामीण शाखाओं की संख्या पर भी भारी थे। इस अवधि के दौरान ग्रामीण शाखाओं में उनकी हिस्सेदारी 60% से अधिक रही (चार्ट 5)। हालांकि, सभी क्षेत्रों में गांव में बीसी आउटलेट्स में उनकी हिस्सेदारी 2020 में मामूली रूप से घटकर 57 प्रतिशत रह गई है, जो 2016 में 60 प्रतिशत थी (चार्ट 6)। ग्रामीण शाखाओं और गांवों में बीसी आउटलेट दोनों के लिए, पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतम हिस्सेदारी पीएसबी की है। हालांकि, गांवों में बीसी आउटलेट्स के लिए, पीएसबी की हिस्सेदारी 2016 में 68% से गिरकर 2020 में 45% हो गई है। साथ ही, पीवीबी ने अपने हिस्से में उत्तरोत्तर वृद्धि की है, एनईआर, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्रों के गांवों में बीसी आउटलेट्स में कई गुना वृद्धि हुई है।

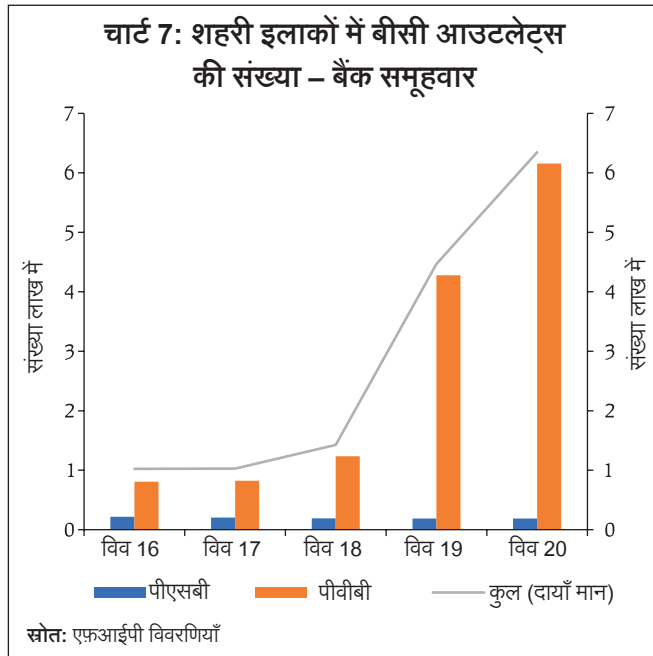


डी. शहरी इलाकों में बीसी आउटलेट

परंपरागत रूप से, यह समझा जाता था कि एक बीसी, जो एक बैंक की विस्तारित शाखा है, जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, गांवों में परिचालनगत रहेगा। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, बैंकों ने शहरी

स्थानों में भी बीसी मॉडल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। शहरी बीसी मॉडल मुख्य रूप से पीवीबी द्वारा अपनाया गया है, जिसमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान 66.23 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई (चार्ट 7)।





समीक्षा अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों ने शहरी बीसी आउटलेट में घनात्मक वृद्धि दर्ज की, जिसमें पूर्वी क्षेत्र लगभग 124.67 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ आगे रहा, इसके बाद क्रमशः मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 97.59 प्रतिशत और 76.27 प्रतिशत की वृद्धि दर रही (चार्ट 8¹)।

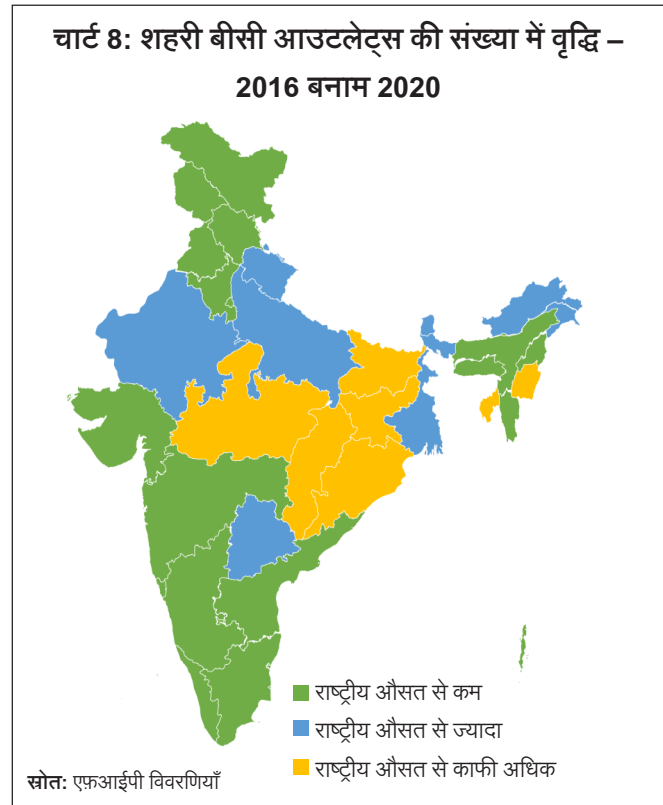
3. उपयोग

उपयोग का आयाम यह दर्शाता है कि वित्तीय सेवाओं के ग्राहक कैसे उपलब्ध पहुंच अवसरचना का उपयोग करते हैं। इस खंड में, एक जमा और एक ऋण उत्पाद का आकलन किया गया है, जो वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

ए. जमा - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)

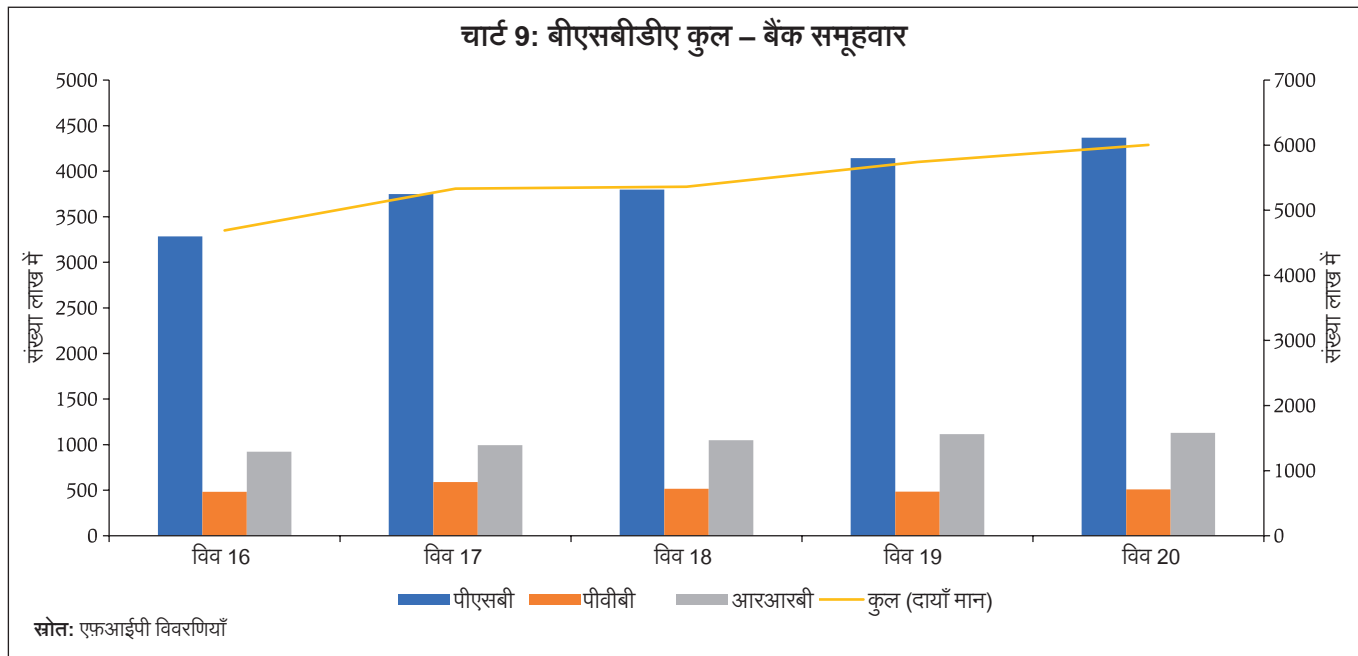
वित्तीय समावेशन का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को किफायती तरीके से उन वर्गों तक पहुंचाना है जो परंपरागत रूप से बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की लागत सहित कई बाधाओं के कारण वंचित

¹ उल्लेखनीय रूप से अधिक 75 प्रतिशत से ज्यादा के सीएजीआर को संदर्भित करता है, जिसमें राष्ट्रीय सीएजीआर 44 प्रतिशत है।



हैं। बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडी) को एक बचत खाते के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो ऐसे खाता के धारकों को कुछ न्यूनतम सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करेगा, इस प्रकार, गैर-बैंकिंग/अंडर-बैंकिंग सेगमेंट के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करेगा।

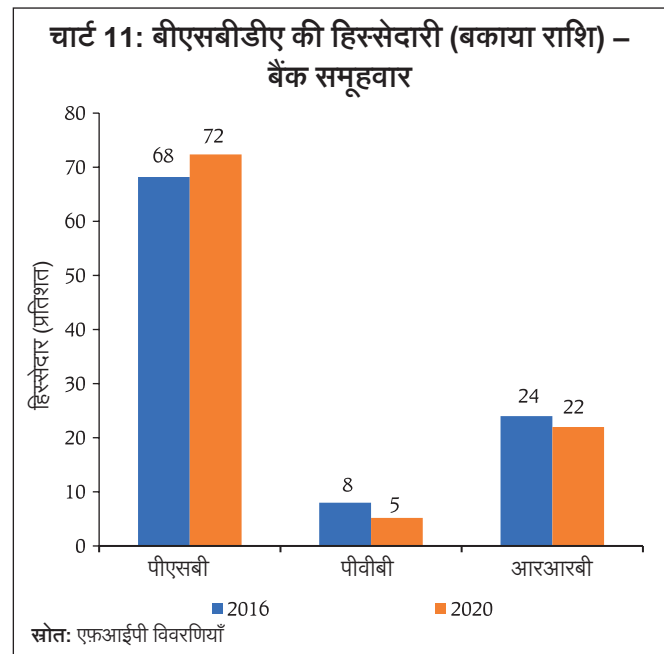
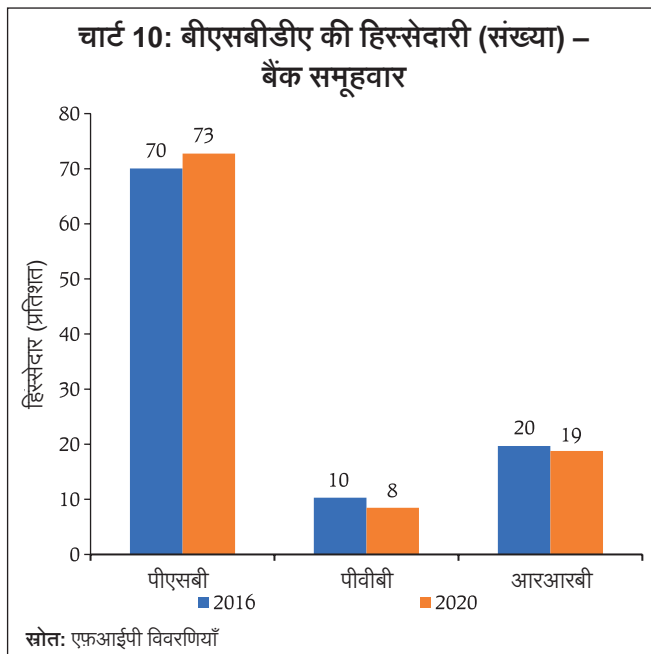
मार्च 2020 के अंत तक बीएसबीडीए की कुल संख्या 6004.2 लाख थी, जबकि मार्च 2016 के अंत में यह 4690.04 लाख थी, जिसमें 6.37 प्रतिशत की वृद्धि (सीएजीआर) दर्ज की गई थी। बकाया शेष राशि में वृद्धि (सीएजीआर) 27.46 प्रतिशत रही। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के बाद समीक्षा अवधि में लगभग 1314 लाख बीएसबीडी खातों की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसे सभी बैंक समूहों में अलग-अलग अनुपात में संवितरित किया गया था (चार्ट 9)।

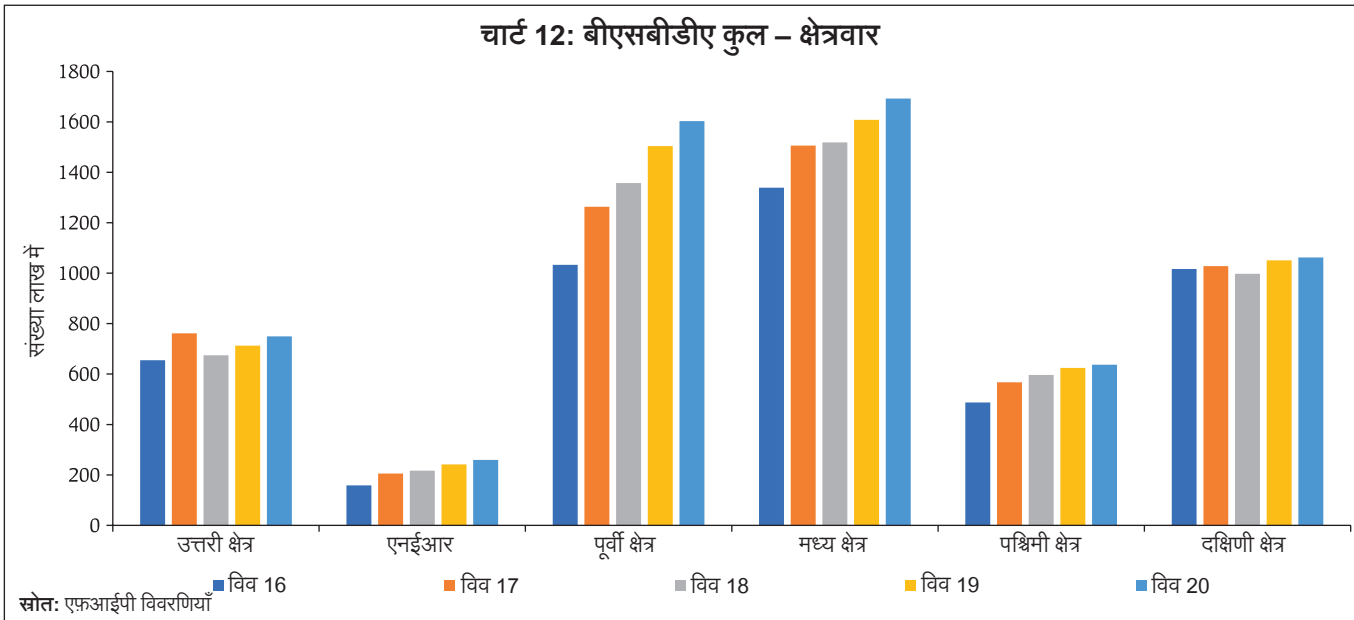


पीएसबी ने बीएसबीडीए के तहत संख्या और बकाया राशि दोनों में वृद्धि दिखाई। हालांकि, पीवीबी और आरआरबी ने इन दोनों मामलों में अपनी हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की (चार्ट 10 और 11)।

बीएसबीडीए में वृद्धि पूरे भारत में बांटी गई, जिसमें सभी क्षेत्रों में खातों की संख्या के साथ-साथ बकाया

राशि के मामले में धनात्मक वृद्धि देखने को मिली। समीक्षा अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र में बीएसबीडीए की वास्तविक संख्या (569.62 लाख) में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र ने बीएसबीडीए (13.09 प्रतिशत) की संख्या में उच्चतम वृद्धि दर्ज की (चार्ट 12)।

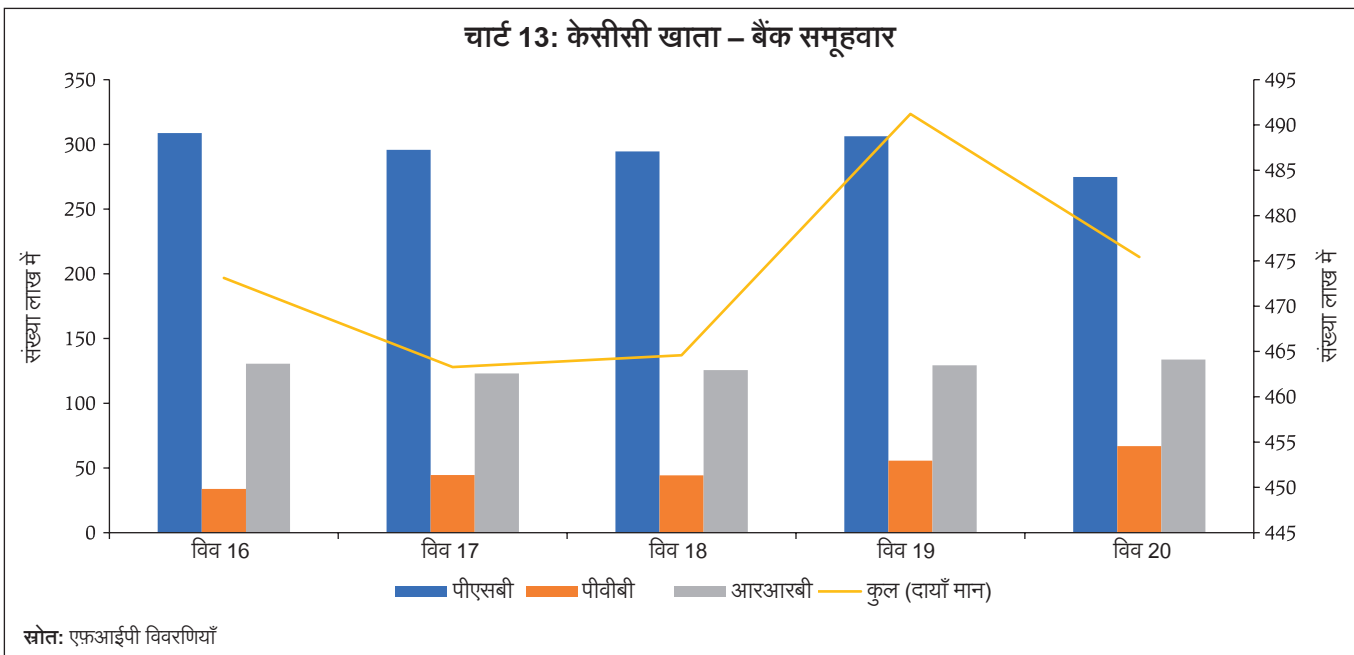


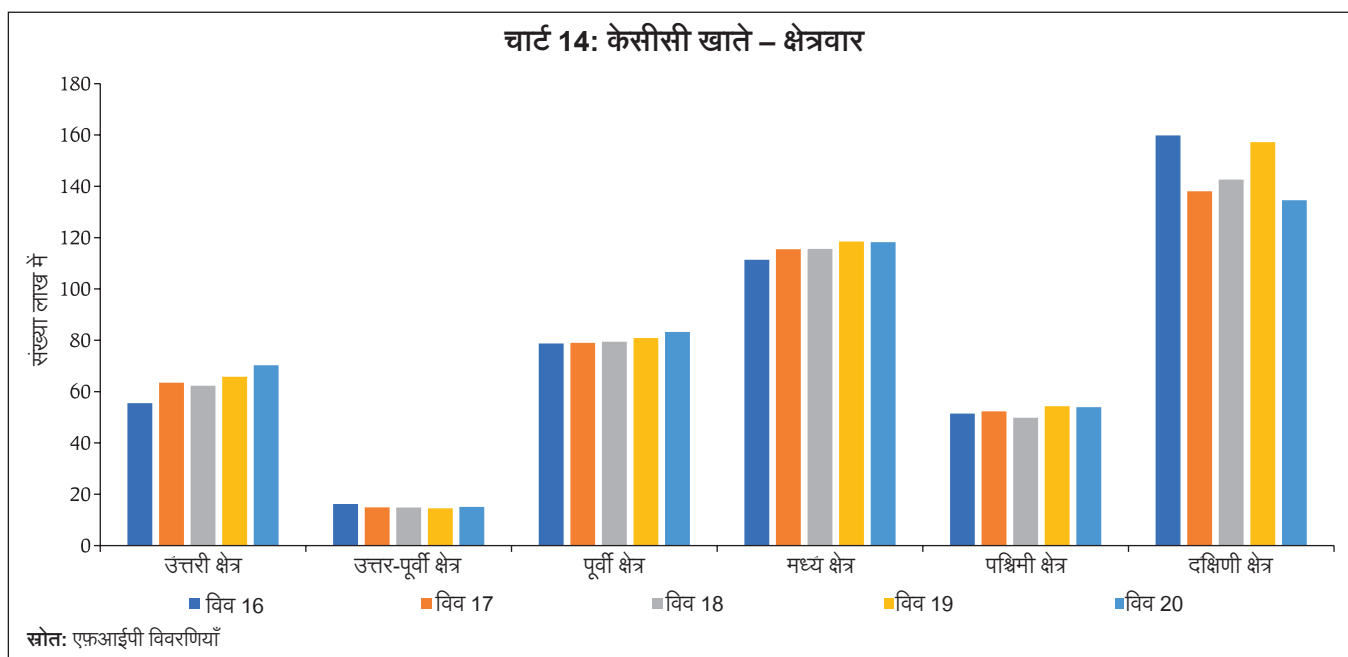


बी. कृषि ऋण - किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

मार्च 2020 के अंत में, 475.42 लाख केसीसी थे, जिनकी कुल राशि ₹6,39,069 करोड़ थी। जहां केसीसी की संख्या में 0.12 प्रतिशत की मामूली वृद्धि

दर्ज की गई, वहीं इस खातों के अंतर्गत बकाया राशि 5.64 प्रतिशत (सीएजीआर) की दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी (चार्ट 13)।





निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के लिए केसीसी की संख्या में धनात्मक वृद्धि देखी जा सकती है, जिसमें पीवीबी ने बढ़त बना ली है। हालांकि समीक्षा अवधि के दौरान केसीसी की कुल संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत से घटकर 58 प्रतिशत हो गई, तब भी सभी बैंक समूहों के बीच उनकी हिस्सेदारी उच्चतम बनी रही।

पूर्वोत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों ने केसीसी की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की (चार्ट 14)। जहां तक केसीसी के तहत कुल बकाया राशि का संबंध है, सभी क्षेत्रों में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

4. कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल

ए. कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) की संख्या

बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कारोबार प्रतिनिधियों की संख्या में 35.35 प्रतिशत से अधिक के सीएजीआर के साथ काफी वृद्धि हुई है। बैंक समूहों में, पीवीबी ने लगभग 65.30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। आगे, आरआरबी ने भी इस अवधि के दौरान बीसी की संख्या में धनात्मक वृद्धि दिखाई। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के

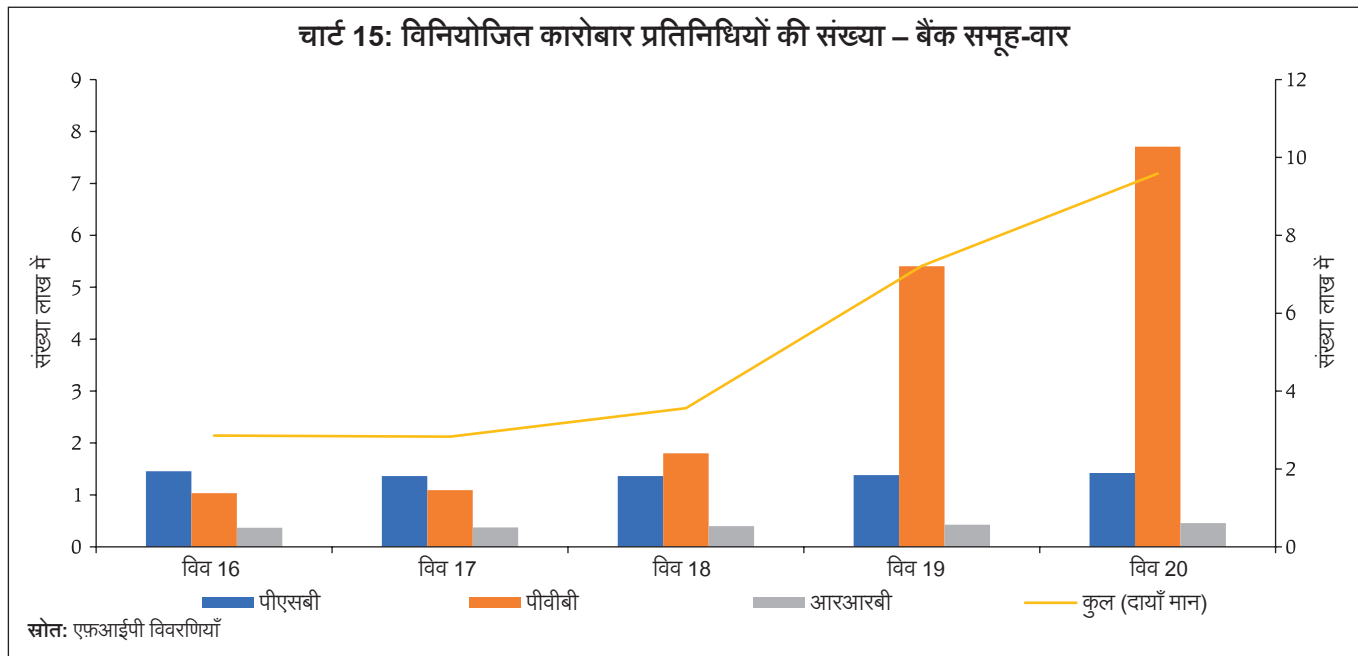
कारोबार प्रतिनिधियों की संख्या में मुख्य रूप से इस बैंक समूह में समेकन के कारण मामूली कमी आई।

बीसी की कुल संख्या में पीवीबी की हिस्सेदारी मार्च 2016 में 36.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 में 80 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से दो निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई, जबकि पीएसबी की हिस्सेदारी मार्च, 2016 में 51 प्रतिशत से घट कर 2020 में 15 प्रतिशत हो गई (चार्ट 15)।

देश के सभी क्षेत्रों में बीसी की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें अकेले पूर्वी क्षेत्र में 54.19 प्रतिशत (सीएजीआर) की दर से 2,48,315 कारोबार प्रतिनिधियों की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्रों का स्थान रहा (चार्ट 16)।

बी. लेनदेन

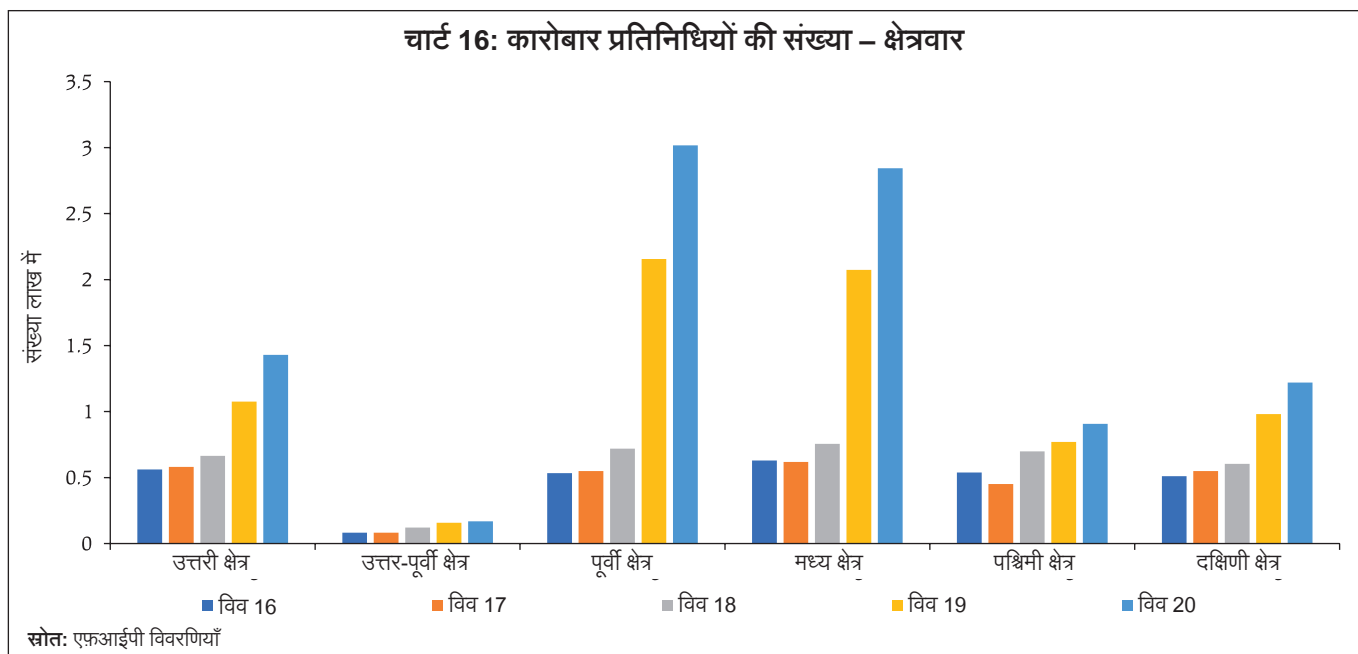
परंपरागत रूप से, एक बीसी बैंक की एक विस्तारित शाखा है, जो बैंक के ग्राहकों (बीसी के बैंक) को जमा, निकासी, हस्तांतरण, खाता खोलने और शेष राशि की पूछताछ की मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि पारस्परिकता का विनियामक प्रावधान, भुगतान प्रणालियों में विकास, बायोमेट्रिक-आधारित



पहचान और लेनदेन के उद्भव, और जमा राशि स्वीकार न करने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) को बीसी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जा रही है- ऐसी कई नीति स्तर की पहलों के माध्यम से बीसी के विभिन्न नए रूपों की शुरुआत हुई। इन नए बीसी में विप्रेषण बीसी शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर देशी मुद्रा अंतरण (डीएमटी) एजेंट और ऋण आधारित

बीसी (ज्यादातर एनबीएफसी-एमएफआई को बैंकों द्वारा ऐसे बीसी के रूप में कार्य करने के लिए शामिल किया गया है) के रूप में जाना जाता है।

इस भाग में, बैंक समूह-वार/ क्षेत्र-वार कार्य-निष्पादन को समझने के लिए बीसी आउटलेट्स पर किए गए ऋण संबंधी लेनदेन और विप्रेषण लेनदेन के डेटा का विश्लेषण किया गया है।

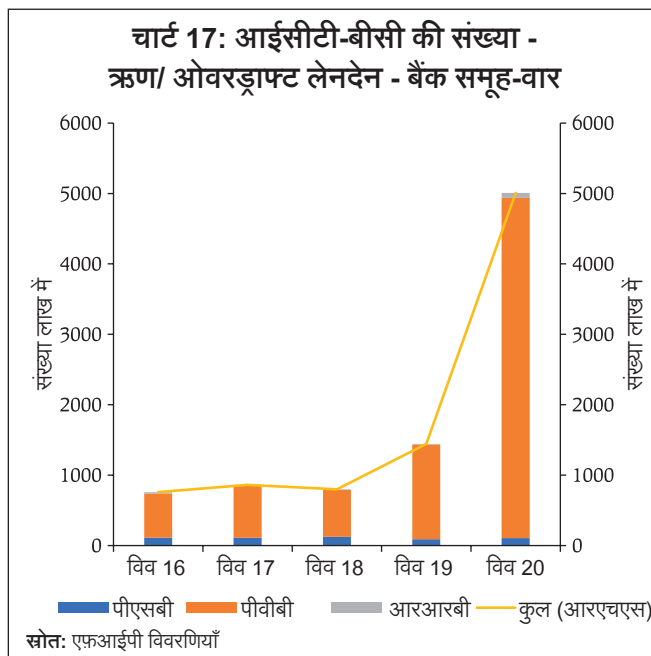


I. ऋण संबंधी लेनदेन - आईसीटी-बीसी क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) लेनदेन

बीसी आउटलेट्स पर 2016-20 के दौरान, क्रेडिट से संबंधित लेनदेन पीवीबी और आरआरबी के लिए क्रमशः 66.91 प्रतिशत और 31.81 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़े। यह पांच साल की अवधि में पीवीबी के लिए बीसी एजेंटों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति के अनुरूप था (चार्ट 17)। तथापि इसी अवधि के दौरान, पीएसबी के लिए आईसीटी-बीसी क्रेडिट/ ओडी लेनदेन में 1.86 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई।

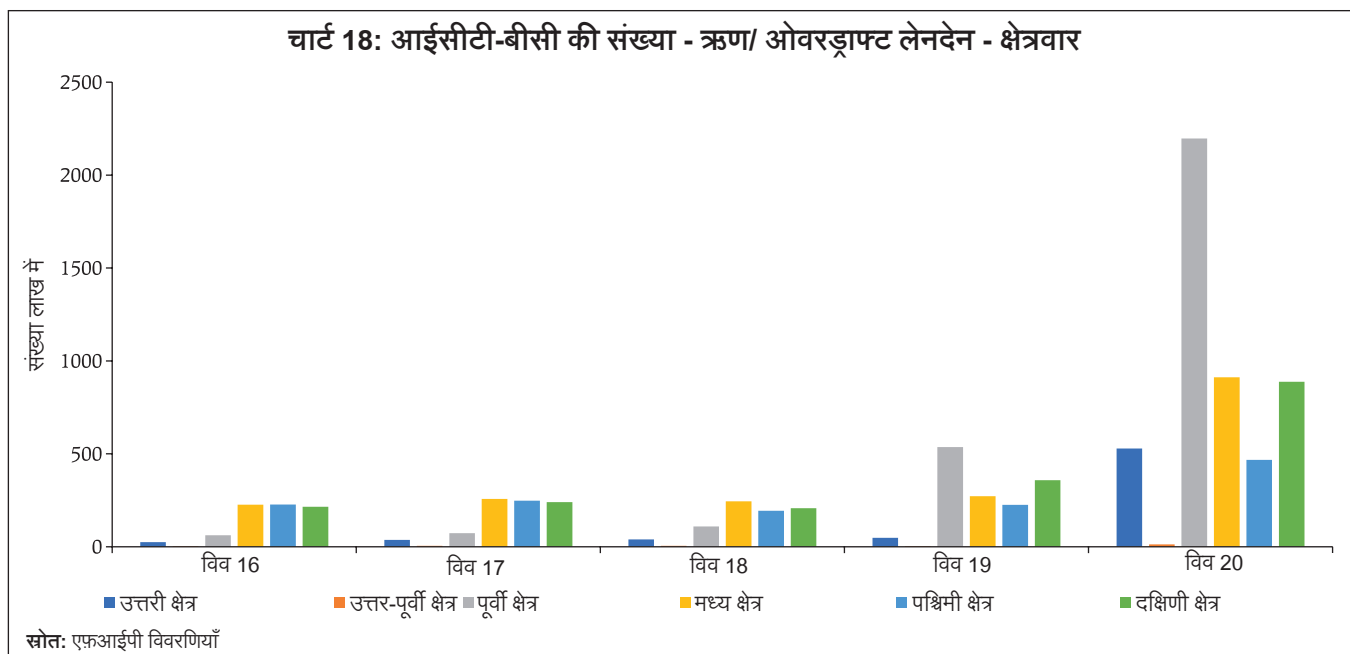
इसी प्रकार, बीसी आउटलेट्स पर क्रेडिट/ ओडी लेनदेन में पीवीबी की हिस्सेदारी 2016 में 82 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 97 प्रतिशत हो गई, जबकि पीएसबी और आरआरबी की हिस्सेदारी में काफी कमी आई।

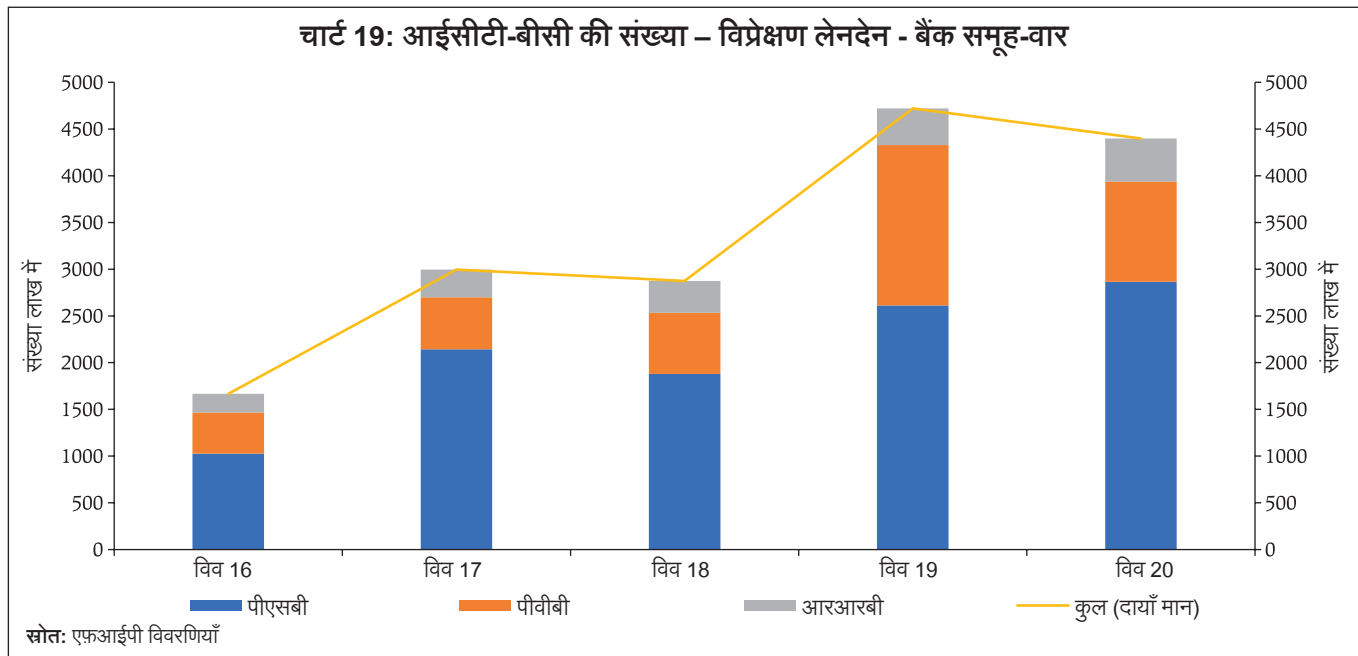
बीसी के माध्यम से आईसीटी-बीसी क्रेडिट/ ओडी लेनदेन की संख्या में समीक्षा अवधि के दौरान 60.27 प्रतिशत का समग्र सीएजीआर दर्ज किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रों में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पूर्वी क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई जिसमें महत्वपूर्ण रूप से चुनिंदा पीवीबी द्वारा काफी अधिक संख्या में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 18)।



II. विप्रेषण - आईसीटी-बीसी - विप्रेषण लेनदेन

सभी बैंक समूहों के लिए विप्रेषण लेनदेन की संख्या में वृद्धि हुई, जिसमें पीएसबी ने 29.30 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की (चार्ट 19)। इस अवधि के दौरान, पीवीबी और आरआरबी की वृद्धि क्रमशः 24.82 प्रतिशत और 23.31 प्रतिशत थी। जबकि आईसीटी-बीसी क्रेडिट/ ओडी लेनदेन

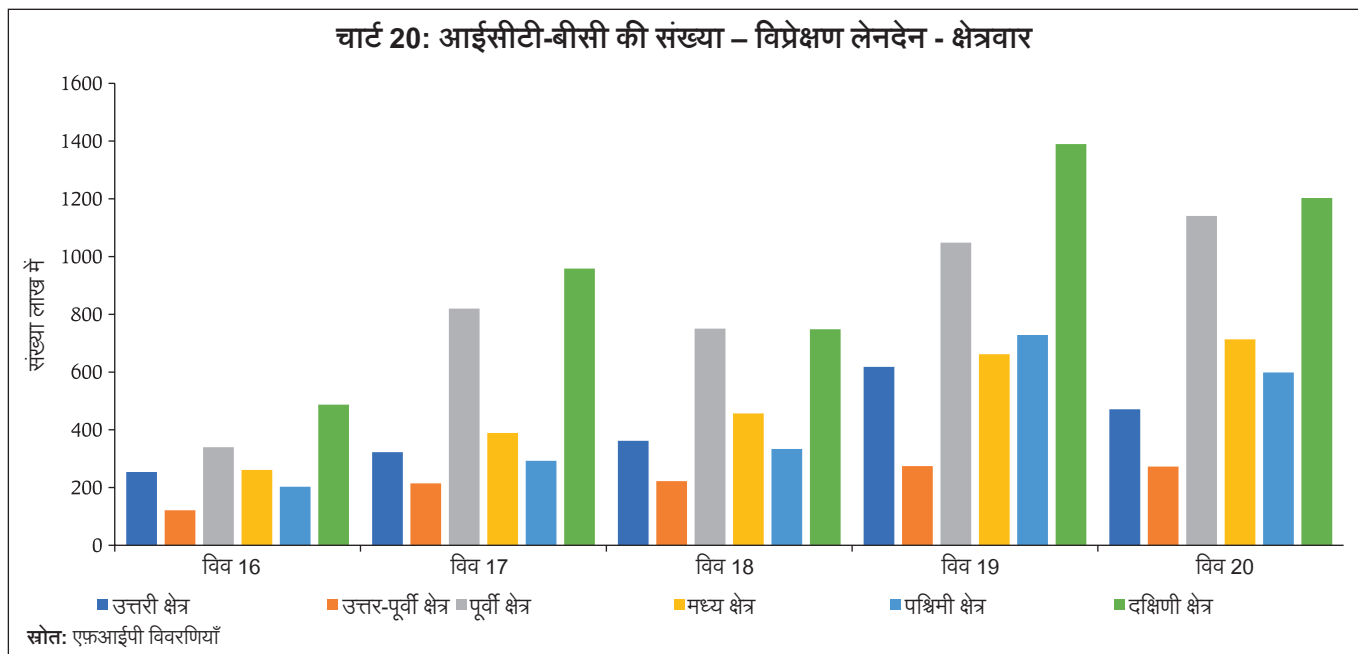




में पीवीबी का बड़ा हिस्सा था, वहीं आईसीटी-बीसी विप्रेक्षण लेनदेन में कुल विप्रेक्षण लेनदेन के 65 प्रतिशत से अधिक हिस्से के रूप में पीएसबी का वर्चस्व था। हालांकि शहरी बीसी खंड में, जिसे मुख्य रूप से विप्रेक्षण चैनल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पर पीवीबी का दबदबा रहा है, लेकिन समीक्षा अवधि के दौरान लेनदेन में उनकी

हिस्सेदारी 2016 में 26.47 प्रतिशत से घटकर 2020 में 24.34 प्रतिशत हो गई।

सभी क्षेत्रों ने विप्रेक्षण लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों में धनात्मक वृद्धि दर्ज की, जो क्रमशः 16 प्रतिशत से 35 प्रतिशत और 26 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक थी (चार्ट 20)।



पूर्वी क्षेत्र में लेनदेन की संख्या के साथ-साथ इन लेनदेन में शामिल राशि में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, विप्रेषण लेनदेन के क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र का वर्चस्व था। पूर्वी क्षेत्र ने समीक्षा अवधि के दौरान आईसीटी-बीसी विप्रेषण लेनदेन के कुल मूल्य में हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई।

सी. बीसी मॉडल के माध्यम से जमा और क्रेडिट उत्पाद

बीसी मॉडल दो महत्वपूर्ण पहलुओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है i) उपयोगिता और ii) व्यवहार्यता। बीसी नेटवर्क में विस्तार से यह स्थापित होता है कि सभी हितधारक अब इस मॉडल की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त हैं। आलेख के पिछले खंडों में बीसी मॉडल की पहुंच के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई, जिसने वित्तीय समावेशन के लिए मॉडल की उपयोगिता को सुदृढ़ किया।

मॉडल की व्यवहार्यता बीसी नेटवर्क के गहन होने (वंचिता/ कम सेवा प्राप्त ग्रामीण और शहरी इलाकों में विस्तार) और बीसी परिचालनों के विस्तार (उत्पादों और सेवाओं के समूह की डिलीवरी) पर निर्भर है। खाता खोलने के लिए बीसी की नियुक्ति (बीएसबीडीए), ऋण को मंगाना और ऋण से संबंधित लेनदेन को सुगम बनाना मॉडल को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

I. बीसी के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)

मार्च 2020 तक, बीएसबीडीए की कुल संख्या का 56.43 प्रतिशत बीसी नेटवर्क के माध्यम से खोला गया था, जिसमें पीएसबी की हिस्सेदारी कुल 75 प्रतिशत से अधिक थी। हालांकि बीसी आउटलेट्स (ग्रामीण + शहरी) की संख्या (7.3 लाख) थी, साथ ही बीसी एजेंट (7.7 लाख) पीवीबी के लिए सबसे ज्यादा थे, बीएसबीडीए में उनका हिस्सा सबसे कम था, जो दर्शाता है कि

इनमें से अधिकांश बीसी आउटलेट/ बीसी ऐसी सेवाओं के संवितरण में शामिल नहीं थे।

II. बीसी के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

2020 में कुल केसीसी का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा बीसी के माध्यम से सोर्स/ खोला गया था। पीवीबी ने बीसी के माध्यम से केसीसी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (81 प्रतिशत) रखी, इसके बाद पीएसबी (15 प्रतिशत) और आरआरबी (4 प्रतिशत) का स्थान रहा। हालांकि बीसी आउटलेट्स की संख्या में पीएसबी की प्रमुख उपस्थिति है, लेकिन बीसी के माध्यम से केसीसी को दिशा देने में पीएसबी का योगदान नगण्य था, जिसके परिणामस्वरूप केसीसी के लिए बीसी मॉडल का बहुत कम उपयोग हुआ।

III. बीसी के माध्यम से सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी)

मार्च 2020 के अंत में बीसी के माध्यम से सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) की कुल संख्या 132.61 लाख थी, जिसमें पीवीबी की कुल में हिस्सेदारी लगभग 98 प्रतिशत थी। बीसी के माध्यम से जीसीसी की हिस्सेदारी 2016 में 34.60 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 65.58 प्रतिशत हो गई, जिसमें पीवीबी जीसीसी के लिए बड़े पैमाने पर बीसी मॉडल का उपयोग कर रहे थे। इसका श्रेय पीवीबी द्वारा बीसी के रूप में एनबीएफसी-एमएफआई को जाता है और उनके नेटवर्क का उपयोग संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) की सोर्सिंग और वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

5. निष्कर्ष

पांच वर्षों (2016-2020) में बैंकों (पीएसबी, पीवीबी और आरआरबी) द्वारा प्रस्तुत एफआईपी डेटा की समीक्षा के माध्यम से यह देखा गया है कि वित्तीय समावेशन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का दबदबा बना हुआ है। 2020 में कुल ग्रामीण शाखाओं का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा पीएसबी में था। पीएसबी भी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद थे, जिनका 2020 में गांवों में कुल

बीसी आउटलेट में से 60 प्रतिशत हिस्सा था। इसी तरह, कुल बीएसबीडीए में, पीएसबी का योगदान समीक्षा अवधि के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक रहा। इसके अलावा, ऋण उत्पादों के बीच, केसीसी मुख्य रूप से पीएसबी के माध्यम से जारी किए गए थे, जो 2020 में केसीसी की कुल संख्या का 58 प्रतिशत था।

जैसे-जैसे पीएसबी ने अपनी पकड़ बनाए रखी, पीवीबी ने भी समीक्षा अवधि के दौरान अभिगम और उपयोग, दोनों संकेतकों में उच्च वृद्धि दर्ज की। पीवीबी के लिए गांवों में बीसी आउटलेट्स में वृद्धि हुई थी, साथ ही उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में काफी अधिक विकास हुआ जिससे पीएसबी और आरआरबी की मिली-जुली वृद्धि को पार कर लिया। पीवीबी ने पांच वर्षों के दौरान शहरी बीसी आउटलेट्स की संख्या में भी उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी 2016 में 77 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 97 प्रतिशत हो गई है। इसी तर्ज पर, बीसी एजेंटों की कुल संख्या में पीवीबी का योगदान भी 2016 में 37 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 80 प्रतिशत हो गया।

एक वैकल्पिक डिलीवरी मॉडल होने के साथ-साथ, बीसी मॉडल प्रमुख डिलीवरी मॉडल के रूप में उभर रहा है। जबकि समीक्षा अवधि के दौरान ग्रामीण शाखाओं की संख्या में वृद्धि द्रुत रही, बड़ी संख्या में वंचित/ कम सेवा प्राप्त आबादी की दहलीज पर औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले गांवों और शहरी इलाकों, दोनों में, बीसी आउटलेट्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल बीएसबीडीए खातों का लगभग 56 प्रतिशत और जीसीसी का 65 प्रतिशत हिस्सा बीसी के माध्यम से खोले गए थे। जबकि पीएसबी के कारोबार प्रतिनिधियों का जमा खंड में वर्चस्व बना रहा, बीसी के माध्यम से पीवीबी का जीसीसी में एक बड़ा हिस्सा रहा। समीक्षा अवधि के दौरान, बीसी आउटलेट के माध्यम से किए गए कुल लेनदेन मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में काफी बढ़ गए।

अंत में उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्य क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से वक्र के पीछे रहे हैं, ने समीक्षा अवधि के दौरान वित्तीय समावेशन के अभिगम संकेतक में बेहतर प्रदर्शन किया।

भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक*

व्यापक, समावेशी और धारणीय वृद्धि के लिए बृहत्तर वित्तीय समावेशन (एफआई) महत्वपूर्ण है। इसलिए, एफआई को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई नीतिगत पहल की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए एफआई का एक महत्वपूर्ण कदम आवश्यक है। 97 संकेतकों पर आधारित एक बहुआयामी समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) का निर्माण किया गया है जो वित्तीय समावेशन को परिमाणित करता है और उपलब्धता, पहुंच में आसानी, उपयोग, असमान वितरण और सेवाओं में कमी, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। 0 से 100 के पैमाने में, 2021 के लिए गणना किए गए तीन उप-सूचकांक जैसे 'अभिगम', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' के साथ वार्षिक एफआई-इंडेक्स 53.9 पर रहा, जिसमें अभिगम उप-सूचकांक का 73.3 का मुख्य योगदान था। यह देश में वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अब तक संतोषजनक प्रगति को दर्शाता है जिसमें सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयास रहे हैं।

"हमें सभी के लिए धारणीय भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बृहत्तर वित्तीय समावेशन के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए"

श्री शक्तिकांत दास, जुलाई 2021¹

I. भूमिका

वित्तीय अभिगम पहुंच को हमेशा आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक माना गया है, और इसलिए, एक समावेशी वित्तीय प्रणाली का संवर्धन नीतिगत वृद्धि और प्राथमिकता का एक क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, देश की मुख्यधारा की वित्तीय समावेशन यात्रा को 1950 के दशक में सहकारी समितियों

* यह आलेख अनिल कुमार शर्मा, कार्यपालक निदेशक; सोनाली सेनगुप्ता, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक; इंद्रजीत रॉय, निदेशक; और सुष्मिता फुकन, महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

¹ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा 15 जुलाई, 2021 को इकोनॉमिक टाइम्स फ्राइनेशियल समिट में उद्घाटन भाषण दिया गया।

के संवर्धन, 1960 के दशक में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों और आबादी के पिछड़े वर्गों को क्रेडिट देने के बारे में पता लगाया जा सकता है। अनेक वर्षों में शाखाओं के नेटवर्क का विस्तार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल), अग्रणी बैंक योजना का शुभारंभ, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) का संवर्धन, कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के कार्यान्वयन जैसी विभिन्न पहलों के साथ-साथ किया गया था। बीसी मॉडल द्वारा पूरित पारंपरिक भौतिक शाखाओं ने देश के कोने-कोने में बैंकिंग प्रणाली की पहुंच का विस्तार किया है। हालांकि, एफआई की दिशा में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के शुभारंभ के साथ अपने विभक्ति बिंदु तक पहुंच गया था, जिसके तहत अब तक अपवर्जित आबादी के खाते बढ़ी संख्या में समयबद्ध तरीके से खोले गए थे, और समय के साथ हालिया वर्षों में डिजिटल माध्यम को बढ़ावा दिया गया और अपनाया गया।

जन-धन, आधार और मोबाइल (जेएम) पारिस्थितिकी तंत्र ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है और सुविधाजनक, संरक्षित और सुरक्षित, पारदर्शी और किफायती तरीके से डिजिटल भुगतान को सार्वभौमिक बनाने के लिए कई पहल की गई हैं। पिरामिड के निचले भाग में मूल्य के दोहन की अव्यक्त संभाव्यता को देखते हुए, बड़ी संख्या में भागीदार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं जैसे भुगतान बैंक, छोटे वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) और फिनटेक कंपनियां शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान देते हुए और वित्तीय सेवाओं के जिम्मेदार और धारणीय उपयोग करने के लिए ग्राहकों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था और आबादी के पिछड़े वर्गों की जरूरतों को पूरा करने पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति 2019-2024 (एनएसएफआई) और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 (एनएसएफई) वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक समन्वित दृष्टिकोण के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समेकित प्रयासों के साथ, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नीतिगत पहलों की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय समावेशन का एक समेकित उपाय आवश्यक है। इसलिए, एक वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) का निर्माण करना उचित है जो वित्तीय समावेशन को परिमाणित करता है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में उपलब्धता, पहुंच में आसानी, उपयोग की सीमा, सेवाओं में असमानता और कमी, वित्तीय साक्षरता का प्रसार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्तरदायी है; सुरक्षा; और बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के विस्तार पर प्रकाश डालता है।

अक्टूबर 2017 में भारत सरकार द्वारा एक कार्य बल (टीएफ) का गठन किया गया था, जिसमें वित्तीय समावेशन के सूचकांक के निर्माण के लिए विभिन्न आयामों और पहलुओं का सुझाव देने के लिए सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व किया गया था। इस कार्य बल ने अगस्त 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जबकि कार्य बल द्वारा सुझाई गई कार्यप्रणाली को बरकरार रखा गया था, *अन्य बातों के साथ*, विभिन्न उप-सूचकांकों के तहत कई संकेतक जोड़े गए थे और भार वितरण, लक्ष्य मूल्य, आदि का निर्धारण करने के अलावा, 'गुणवत्ता' का एक आयाम पेश किया गया था।

तदनुसार, यह आलेख एफआई-सूचकांक के निर्माण में 'अभिगम', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' आयामों, भार वितरण, चयनित संकेतकों के लिए वांछित लक्ष्य, और इन संकेतकों को एक समग्र सूचकांक में संयोजित करने की पद्धति पर जोर देता है। इस प्रकार निर्मित एफआई-सूचकांक 0 और 100 के बीच एक ही संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों पर जानकारी प्राप्त करता है - जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण का प्रतिनिधित्व करता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को इंगित करता है।

आलेख को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II वित्तीय समावेशन पर कुछ मौजूदा अध्ययनों की समीक्षा करता है। खंड III एफआई-सूचकांक के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पर चर्चा करता है। खंड IV डेटा और परिणामों का वर्णन है; और खंड V आगे चलकर क्या क्रियाविधि होगी- इस पर ध्यान केन्द्रित करता है।

II. साहित्यिक समीक्षा

अधिकांश अध्ययनों ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण का पालन किया जिसमें प्रति व्यक्ति बैंक खाते, बैंक शाखाएं, एटीएम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, घरेलू जमाकर्ताओं/ उधारकर्ताओं की संख्या शामिल थी (सरमा 2012; डबला-नोरिस और अन्य, 2015; मियालौ और अन्य, 2017)। एकल संकेतक दृष्टिकोण वित्तीय समावेशन की सही सीमा का सही वर्णन नहीं कर सकता है, उदाहरण के लिए, केवल एक बैंक खाता होने का मतलब यह नहीं हो सकता है कि भौतिक या मनोवैज्ञानिक बाधाओं के कारण खाते का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। इसके अलावा बैंक खाता होने के बावजूद "सीमांत बैंकिंग सुविधायुक्त" लोग औपचारिक वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहे हैं और अनौपचारिक गैर-बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं (डिनिज और अन्य, 2011; केम्पसन, 2004; सीडमैन और अन्य, 2005)।

संस्थागत स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का वित्तीय अभिगम सर्वेक्षण (एफएएस) दुनिया भर में आधारभूत वित्तीय सेवाओं के उपयोग और उपयोग पर वार्षिक समय श्रृंखला डेटा एकत्र करता है। वित्तीय समावेशन के तहत प्रमुख अभिगम और उपयोग संकेतकों पर आपूर्ति पक्ष डेटा को समेटने के लिए एफएएस को 2009 में लॉन्च किया गया था। एफएएस, *अन्य बातों के साथ-साथ*, प्रति 100,000 व्यक्तियों पर एटीएम, प्रति 100,000 व्यक्तियों पर बैंक शाखाओं, प्रति 1000 वयस्कों पर जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं की संख्या, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जमा और क्रेडिट आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह बीमा और डिजिटल लेनदेन पर डेटा भी प्राप्त करता है। एफएएस दुनिया के अधिकांश देशों के लिए वित्तीय समावेशन डेटा के व्यापक स्रोत के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग क्रॉस रेफरेंस के लिए किया जा सकता है। क्रिसिल का इनक्लूसिक्स, पहली बार 2013 में प्रकाशित होने के बाद अगली तीन बार 2014, 2015 और 2018 में प्रकाशित हुआ, एक समग्र सूचकांक है जो शाखा व्यापन (बीपी), ऋण व्यापन (सीपी), जमा व्यापन (डीपी) और बीमा व्यापन (आईपी) के चार आयामों में कुल छह मानकों के रूप में वित्तीय समावेशन को मापता है। 'इनक्लूसिक्स' जिले-वार आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर वित्तीय समावेशन का विस्तार करता

है। 2011 से विश्व बैंक प्रत्येक तीन साल में फाइंडेक्स डेटाबेस (डेमिगुक-कूंट और क्लैपर, 2012) प्रकाशित करता है जो 140 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 150,000 से अधिक वयस्कों के सर्वेक्षण पर आधारित है कि वयस्क कैसे बचत करते हैं, उधार लेते हैं, भुगतान करते हैं, और जोखिम का प्रबंधन करते हैं।

III. क्रियाविधि

एफआई-इंडेक्स के निर्माण में तीन प्रमुख चुनौतियां हैं, *अर्थात्*, उपयुक्त संकेतक या चर का चयन, लक्ष्य निर्धारित करना (वांछित स्तर), और भार वितरण का निर्धारण करना।

एफआई-सूचकांक पर अधिकांश मौजूदा अध्ययन वित्तीय समावेशन की पहुंच और उपयोग आयाम का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर सामान्यीकृत संकेतकों के भारित औसत (या समान भार) के आधार पर एक समग्र सूचकांक का निर्माण करते हैं। हालांकि, ये अध्ययन वित्तीय समावेशन के 'गुणवत्ता' आयाम को छोड़ देते हैं, जो वित्तीय समावेशन को कारगर बनाने के उद्देश्य की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चूंकि चयनित संकेतकों को संयोजित करने से पहले उन्हें समान पैमाने पर लाने के लिए सामान्यीकृत करने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक संकेतक की तुलना उसके वांछित लक्ष्य के संबंध में की जाती है; जब कोई संकेतक अपने वांछित लक्ष्य या 'इष्टतम मूल्य' को प्राप्त करता है; यह माना जाता है कि संकेतक द्वारा अनुमानित वित्तीय समावेशन पूरा हो गया है। चूंकि सैद्धांतिक रूप से वित्तीय समावेशन के एक संकेतक के लिए उपलब्ध के इष्टतम स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, लक्ष्य मूल्य को तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

इसके अलावा, सभी चयनित संकेतकों का वित्तीय समावेशन लक्ष्य के प्रति समान महत्व नहीं हो सकता है। इसलिए, चयनित संकेतकों के बीच भार वितरण असमान हो सकता है और बहिर्जात रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित एफआई-सूचकांक वित्तीय समावेशन के तीन आयामों पर आधारित है, *अर्थात्* 'पहुंच', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' जिनका भार क्रमशः 35, 45 और 20 प्रतिशत है। वित्तीय

समावेशन ('उपयोग' और 'गुणवत्ता') के गहन पहलू के लिए उच्च भार के साथ सूचकांक को दूरदेशी बनाने के लिए भार निर्धारित किए गए थे।

एफआई को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सूचकांक के तीन आयामों के संकेतक, उनके इष्टतम मूल्य और उनके संबंधित भार संबंधित क्षेत्रवार विनियामकों और सरकार के परामर्श से तय किए गए थे।

मोटे तौर पर, कुल भार का एक तिहाई भाग 'पहुंच' को निर्दिष्ट किया गया है जिसमें पूर्व में अधिकांश पहलें की गई हैं और जो उपलब्ध कराए गए आपूर्ति पक्ष के वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर की सीमा को दर्शाता है। दो-तिहाई भार वित्तीय समावेशन के गहन पहलू *अर्थात्* 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' को सौंपा गया है। इन तीन उप-सूचकांकों में से प्रत्येक संकेतक, गैर-अतिव्यापी समूह के आधार पर गणना किए गए आयामों के अलग-अलग समूहों से बना है।

'अभिगम' उप-सूचकांक, जिसे आगे चार आयामों में विभाजित किया गया है, जैसे, 'बैंकिंग', 'डिजिटल', 'पेंशन' और 'बीमा', वित्तीय समावेशन के आपूर्ति पक्ष पर किए गए प्रयासों को दर्शाता है, जैसे कि भौतिक और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और अपवर्जित वर्गों के लिए आधारभूत उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने के तरीके। चार आयामों में 26 संकेतकों को बीसी, एनबीएफसी, और डाकघर *आदि* सहित बैंकिंग आउटलेट की संख्या, अल्प बचत सहित कुल बचत खातों की संख्या, सभी प्रकार के कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर, जेएएम पारिस्थितिकी तंत्र, विभिन्न पेंशन योजनाओं और कार्यालयों और जीवन और गैर-जीवन बीमा *आदि* के एजेंटों का सदस्यता आधार प्राप्त करने के लिए चुना गया है।

'उपयोग' उप-सूचकांक पांच आयामों में विभाजित है, *अर्थात्*, 'बचत और निवेश', 'क्रेडिट', 'डिजिटल', 'बीमा' और 'पेंशन'। यह मांग पक्ष का उपाय 52 संकेतकों से मिलकर बना है और बचत, निवेश, बीमा, ऋण और विप्रेषण सुविधाओं *आदि* के माध्यम से वित्तीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के सक्रिय उपयोग के विस्तार को दर्शाता है। संकेतक बचत और निवेश स्वभाव को प्रतिबिंबित करने, बैंकों और गैर-बैंकों से ऋण प्राप्त करने, खुदरा डिजिटल भुगतानों का उपयोग, जीवन और गैर-जीवन दोनों बीमा की पहुँच, और विभिन्न पेंशन योजनाओं में योगदान के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

'गुणवत्ता' उप-सूचकांक के तीन आयाम हैं, अर्थात्, 'वित्तीय साक्षरता', 'उपभोक्ता संरक्षण', और 19 संकेतकों के साथ वित्तीय वितरण फ्रेमवर्क में 'असमानता'। ये संकेतक नागरिकों को उपलब्ध उचित वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए, उनका उपयोग करने के सुरक्षित तरीके, और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जैसे मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूक बनाने के हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों का पता लगाते हैं। वे शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को भी दर्शाते हैं और वित्तीय पहुँच और उपयोग के कुछ संकेतकों के असमान वितरण का हिसाब भी रखते हैं। असमानता को मापने के लिए जिला स्तरीय डेटा कणिकता के साथ लोरेज वक्र पर आधारित गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है।

सूचकांक में 97 संकेतकों में से 90 प्राथमिक संकेतक हैं और शेष 7 संकेतक संबंधित सात प्राथमिक संकेतक की असमानता के उपाय हैं अर्थात् बैंक शाखाओं का वितरण, निश्चित-बिंदु व्यापार आढ़तियों का वितरण (एफबीसी) आउटलेट, एटीएम का वितरण, बचत खाते की संख्या और बचत राशियों का वितरण, क्रेडिट खातों की संख्या का वितरण और बकाया ऋण। लोरेज वक्र और असमानता के उपाय इन सातों के गिनी गुणांक के संदर्भ में मापे गए संकेतक अनुबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। सभी संकेतक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति के लिए जहां भी आवश्यक हो समायोजित किया जाता है।

समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक बनाने के लिए, कई शोध अध्ययनों ने इसी तरह की पद्धति का इस्तेमाल किया है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में (एचडीआई) और मानव गरीबी सूचकांक (एचपीआई) में उपयोग किया जाता है। दृष्टिकोण एकाधिक संकेतकों को एक ही संख्या में संयोजित करने के लिए सरमा (2008) द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि के समान है जिसने यूएनडीपी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का अनुसरण किया था।

चयनित संकेतकों को सम्मान के साथ सामान्यीकृत किया गया उस मामले में जब कोई वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए, एफआई-सूचकांक का कोई 'आधार वर्ष' नहीं होता है। न्यूनतम मूल्य एक सामान्यीकृत पैरामीटर का '0' है और उच्चतम मान '100' है। सभी संकेतक वाईआई सामान्यीकृत हैं एनआई, उन्हें इकाई मुक्त करने के लिए और उन्हें उसी पैमाने पर लाने के

लिए, उन्हें संबंधित वांछित लक्ष्य से विभाजित किया जाता है। सभी संकेतकों के इच्छित लक्ष्य (टी_{आई}) और संकेतकों के वितरण के (डबल्यू_{आई}), आयाम, और उप-सूचकांक हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद पहुंचे थे। कुछ संकेतक अलग से जोड़े जाते हैं (जैसे, बीएसबीडीए, पीएमजेडीवाई खाते) कुल या समग्र व्यापक संकेतकों में एक समूह के रूप में उनकी निहित उपस्थिति के अलावा (कुल बचत खाते), वित्तीय समावेशन के लिए उनके महत्व को दर्शाने के लिए उन्हें भी चयनित संकेतकों में से एक के रूप में लिया जाता है। सभी आयामों के लिए वित्तीय समावेशन को भारत सामान्यीकृत संकेतक (डबल्यू_{एन}₁, डबल्यू_{एन}₂, डबल्यू_{एन}_क) की सामान्यीकृत 'यूक्लिडियन दूरी' के औसत द्वारा मापा जाता है एन-आयामी क्षेत्र में उनके सबसे खराब बिन्दु (0,0,.....0) से उनके सबसे अच्छे बिन्दु (डबल्यू₁, डबल्यू₂, डबल्यू_न) से दूरी के व्युत्क्रम में। एफआई उप-सूचकांक की गणना संबंधित आयाम के आधार पर की जाती है और एफआई-सूचकांक की गणना तीन उप-सूचकांकों के आधार पर की जाती है उसी पद्धति का अनुसरण करते हैं जैसा कि उपयोग किया जाता है आयामों की गणना करने के लिए।

मानो वाई_{आई} जहां_{आई} = 1,2,...के, आई वाला सूचकांक, और डबल्यू_{आई} संबंधित भार है_{आई} सूचकांक के लिए और टी_{आई} इच्छित लक्ष्य है या निर्धारित लक्ष्य है_{आई} सूचकांक के लिए। मानो एन_{आई} एक सामान्यीकृत मान है आई वाले संकेतक के लिए वाई_{आई} के समतुल्य।

$$\text{एन}_{आई} = \text{सामान्यीकृत मान (वाई}_{आई}\text{)} = \frac{\text{वाई}_{आई} - \text{जब कोई वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं}}{\text{इच्छित लक्ष्य (टी}_{आई}\text{)}}$$

$$N_i = \frac{Y_i - 0}{T_i} = \frac{Y_i}{T_i}$$

$$\text{Let } d_i = w_i * N_i; d_i^2 = d_i * d_i;$$

$$\text{Let } D^2 = d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_k^2 = \sum_{i=1}^k d_i^2;$$

$$\text{Let } W^2 = w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_k^2 = \sum_{i=1}^k w_i^2 \text{ and}$$

$$(W - D)^2 = \sum_{i=1}^k (w_i - d_i)^2$$

$$\text{Let } X_1 = \frac{\sqrt{D^2}}{\sqrt{W^2}} \text{ and } X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(W-D)^2}}{\sqrt{W^2}}$$

$$\text{आयाम का एफआई सूचकांक} = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

IV. डेटा और परिणाम

2017-2021 की अवधि के लिए सभी संकेतकों के लिए वार्षिक आवृत्ति पर आवश्यक डेटा संबंधित क्षेत्रीय नियामकों से प्राप्त किया गया है।

2017 के लिए 43.4 के मुकाबले 2021 के लिए परिकल्पित वार्षिक एफआई-सूचकांक 53.9, संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 5.5 प्रतिशत दर्ज की गयी।

तीन उप-सूचकांकों में से, एफआई-अभिगम सूचकांक 73.3 के मान पर, अपेक्षित रूप से, दोनों एफआई-उपयोग (43.0) और एफआई-गुणवत्ता (50.7) की तुलना में अधिक है जो इंगित करता है अधिक वित्तीय समावेशन के लिए जो मूलभूत अंग वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप वर्षों में स्थापित किया गया है उसे वित्तीय संस्थान को गहरा करके 'उपयोग' को बढ़ावा देने और 'गुणवत्ता' में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से आगे बढ़ाने की जरूरत है।

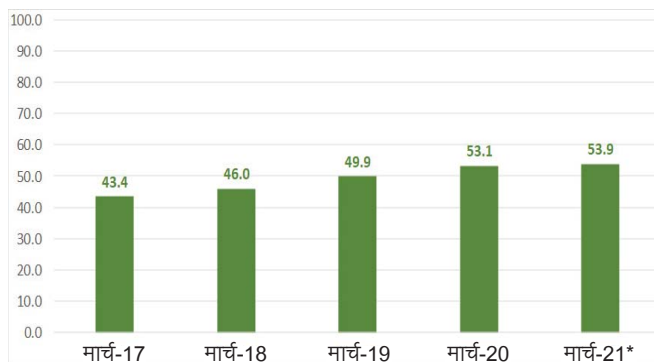
अभिगम उप-सूचकांक: 1950 के दशक से और हाल ही में बड़ी संख्या में उपाय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्तीय सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करने में किया गया। तदनुसार, 26 में से 16 संकेतकों के 'अभिगम' के अंतर्गत सूचकांक मान 53.9 के समग्र सूचकांक मान से भी अधिक हैं, जिसके परिणामस्वरूप अभिगम उप सूचकांक मान 73.3 है, जो भारत के आकार के देश के लिए है और विविधता, सराहनीय प्रगति का संकेत देती है। इस मान काफी हद तक वर्षों में वृद्धि से प्रेरित है, और हाल ही में, मानवयुक्त बैंक आउटलेट्स की संख्या में स्वयं के कर्मचारियों द्वारा, एफबीसीएस, बचत खातों की कुल संख्या, डाकघर, म्यूचुअल फंड में ग्राहकों की संख्या (एमएफ), जेएएम पारिस्थितिकी तंत्र, कार्यालयों की संख्या, बीमा, प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता, और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल आदि की संख्या में वृद्धि के कारण हैं।

सारणी 1: एफआई-सूचकांक और उप-सूचकांक

वर्ष	अभिगम	उपयोग	गुणवत्ता	एफआई-सूचकांक
मार्च-17	61.7	30.8	48.5	43.4
मार्च-18	63.9	33.7	51.4	46
मार्च-19	67.5	38.7	52.6	49.9
मार्च-20	71.6	42	53.8	53.1
मार्च-21*	73.3	43	50.7	53.9

*कुछ डेटा बिंदु अनंतिम हैं।

चार्ट 1: 2017-21 के लिए 0-100 के पैमाने पर एफआई-सूचकांक



उपयोग उप-सूचकांक: उपयोग ने उच्चतम वृद्धि दिखाई है अन्य उप-सूचकांकों की तुलना में, मुख्य रूप से 'बीमा', 'क्रेडिट' और 'बचत और निवेश' द्वारा संचालित है। इन आयामों के तहत कुछ संकेतकों की पर्याप्त वृद्धि दर्शाई गई जिसमें कुल क्रेडिट खाते, क्रेडिट में बकाया राशि एकीकृत भुगतान के खाते इंटरफेस (यूपीआई) के मात्र और मूल्य लेनदेन शामिल हैं। विभिन्न सरकारों के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के बढ़े हुए उपयोग का भी बैंक के बचत खाते में अधिक बकाया राशि के माध्यम से सूचकांक मान पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

जबकि कुछ वर्षों में 'अभिगम' के तहत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है और यह अच्छा सूचकांक मान दिखा रहा है, इसकी संभवता कोविड-19 से संबन्धित प्रतिबंध के कारण 2021 में 'उपयोग' में गिरावट आई है। बीसी मॉडल, जो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) चैनल का उपयोग करता है, इन प्रतिबंधों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत घोषित किए गए नकद लाभों की अंतिम छोर तक सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए सामने आया 94 करोड़ से अधिक लेनदेन के माध्यम से 2020-21 के दौरान ₹2.25 लाख करोड़ तक जो है।

गुणवत्ता उप-सूचकांक: क्रेडिट बकाया में क्षेत्रीय असमानता गिनी गुणांक के साथ 0.72 पर सबसे मुख्य है, इसके बाद जमा राशि में असमानता 0.58 के गिनी गुणांक के साथ। जमा खातों की संख्या के लिए गिनी गुणांक, एफबीसीएस, बैंक शाखाओं, क्रेडिट खातों, एटीएम की गणना क्रमशः 0.20, 0.25, 0.29, 0.43, 0.45 पर की जाती है (अनुबंध)।

V. आगे का रास्ता

एफआई-सूचकांक द्वारा मापी गई प्रगति, समावेशी प्रयास के मांग पक्ष पर अधिक से अधिक और केंद्रित हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। एनएसएफआई ने एक वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण निर्धारित किया है। इसमें वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 सी' दृष्टिकोण शामिल है जिसमें शिक्षा प्रासंगिक सामग्री (स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के पाठ्यक्रम में शामिल); वित्तीय सेवाएं और शिक्षा प्रदान करने वाले बिचौलियों की क्षमता में सुधार करना; समुदाय आधारित मॉडल अपनाने के माध्यम से वित्तीय साक्षरता उपयुक्त संचार रणनीति के साथ; विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और बढ़ाना।

पीएमजेडीवाई कार्यक्रम की सफलता पर पहुंच प्रदान करने में, प्रसुप्त/निष्क्रिय खातों से संबन्धित समस्याओं जैसे अंतर्निहित कारकों जैसे पर्याप्त/नियमित आय की कमी, उपयुक्त वित्तीय उत्पाद का सृजन और उनसे संबन्धित जागरूकता की कमी को दूर करना, प्रक्रियात्मक/संचालन संबंधी चुनौतियां और उपलब्ध स्वीकृति इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आदि को दूर करने की जरूरत है।

इस बात को समझना कि सतत वित्तीय समावेशन तक तभी पहुंचा जा सकता है जब वित्तीय सेवा प्रदाताओं तक पहुँच के साथ बीमा सहित वित्तीय उत्पादों का गुलदस्ता, पेंशन, निवेश और ऋण, एनएसएफआई, जैसी सुविधाएं दी जाएं, अर्थात्, प्रत्येक इच्छुक और पात्र ग्राहक इस तरह कि सुविधाएं दी जाएँ। इस वित्तीय समावेशन के पहलू को और बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा, एनएसएफआई जैसे मील के पत्थर के अनुसरण में वित्तीय साक्षरता केंद्रों की पहुंच का विस्तार करना (सीएफएल), चरण I में 1,199 सीएफएल को स्थापित करके सीएफएल की पायलट परियोजना को बढ़ाया जा रहा है।

वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में बीसी के प्रसार के अलग-अलग व्यवसाय मॉडल के साथ, वियोजित अंतिम मील को संबोधित करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बीसी एजेंटों की निरंतर उपलब्धता से संबंधित मुद्दे, उनकी क्षमता निर्माण, प्रमाणन आवश्यकताओं

और पारिश्रमिक से संबंधित मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करने की जरूरत है।

क्रेडिट अभिगम में आसानी, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), लघु और सीमांत किसान (एसएमएफ), महिलाएं और सूक्ष्म ऋण का खंड नीति निर्माताओं के लिए एक नीति प्राथमिकता बने हुए हैं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के दिशानिर्देश में हालिया संशोधन पूरे देश में चिन्हित ऋण की कमी वाले जिलों को ऋण को प्रोत्साहन देने के फ्रेमवर्क के साथ, स्टार्टअप्स को शामिल करना, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर आदि से ऋण के विनियोजन में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और लक्षित क्षेत्रों को अधिक से अधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने की उम्मीद की जा रही है।

अधिक वित्तीय संस्थाओं को बढ़ावा देने वाले डिजिटल लेनदेन के विस्तार और गहनता को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में 42 जिलों की पहचान की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये जिले आवश्यक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल साक्षरता के निर्माण के माध्यम से एक वर्ष में 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम हो जाएं। अन्य चिन्हित जिलों में पायलट के पैमाने पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

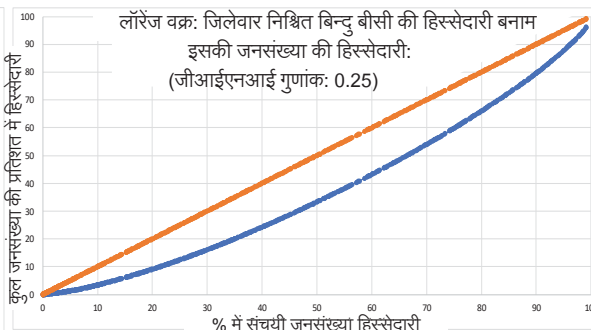
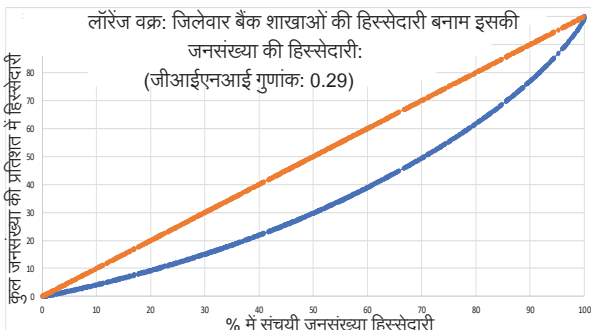
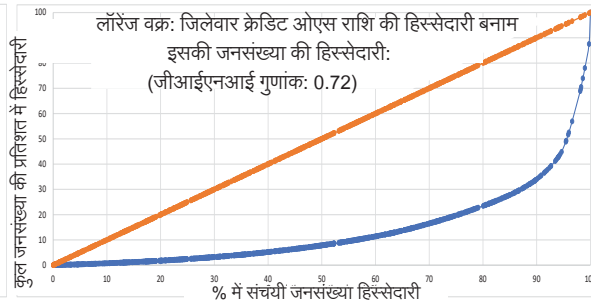
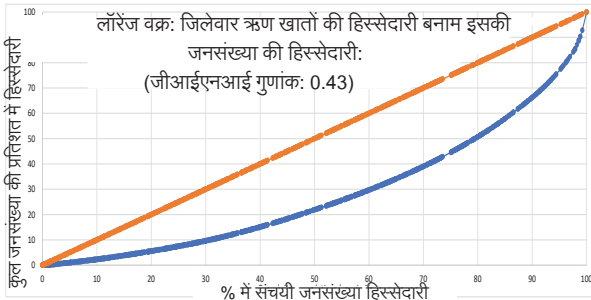
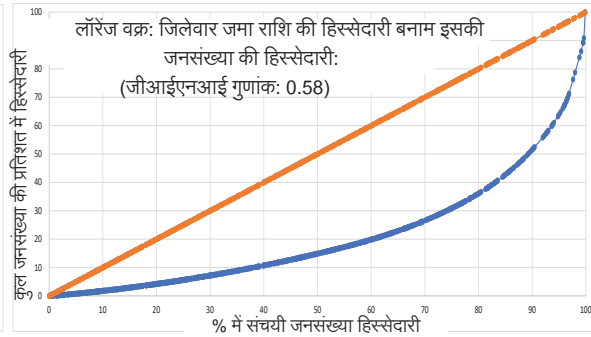
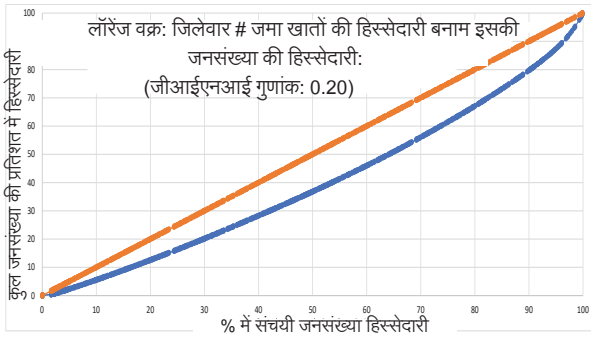
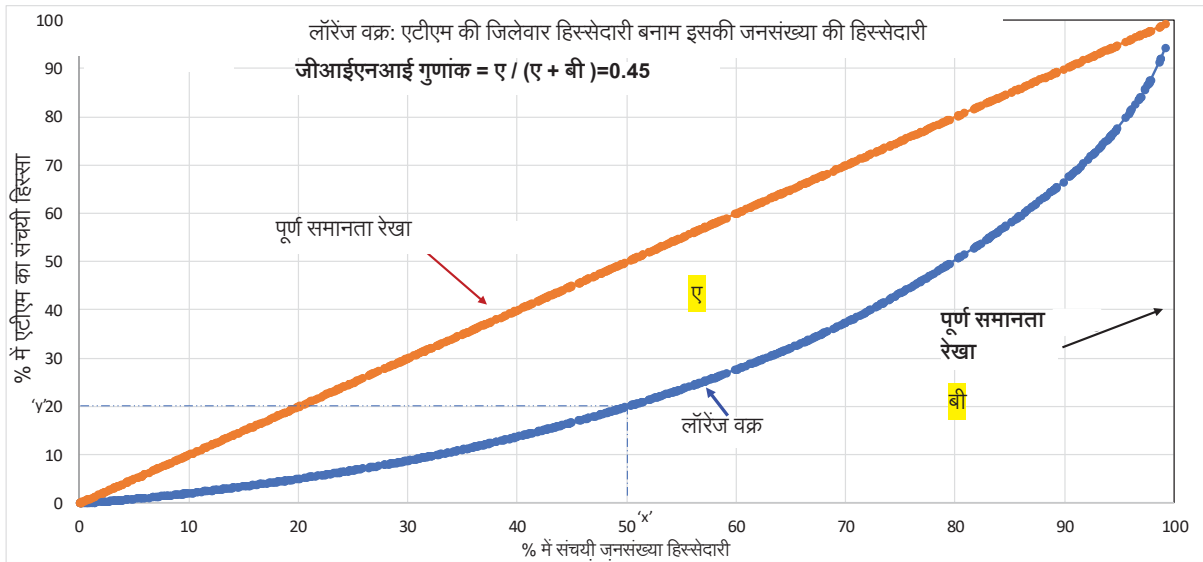
अधिक वित्तीय समावेशन और बढ़ते डिजिटल लेनदेन के साथ, सेवाओं में कमी और असफल लेनदेन आदि के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों का प्रभावी और शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। जबकि सभी नियामकों द्वारा इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, प्रयासों को बढ़ाने और समन्वित करने की आवश्यकता है।

यह आशा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष जुलाई में रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एफआई-सूचकांक न केवल विभिन्न हितधारकों द्वारा पहले से किए गए और किए जा रहे उपायों की सफलता को दर्शाएगा, बल्कि आगे किए जाने वाले उपायों के संबंध में एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा।

संदर्भ

- Dabla-Norris, E., Y. Deng, A. Ivanova, I. Karpowicz, F. Unsal, E. VanLeemput, and J. Wong (2015). "Financial Inclusion: Zooming in on Latin America," IMF Working Paper 15/206, International Monetary Fund, Washington, D.C.
- Demirguc-Kunt, A., and Klapper L. (2012). "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database". Policy Research Working Paper 6025, The World Bank.
- Diniz, E., Birochi, R. and Pozzebon, M. (2011). "Triggers and barriers to financial inclusion: The use of ICT-based branchless banking in an Amazon county". Electronic Commerce Research and Applications online at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.elerap.2011.07.006>
- Kempson E, Atkinson, A., and Pilley, O. (2004). "Policy level response to financial exclusion in developed economies: lessons for developing countries". Report of Personal Finance Research Centre, University of Bristol.
- Mialou, A., Amidzić, G., Massara, A. (2017), "Assessing Countries' Financial Inclusion Standing — A New Composite Index", Journal of Banking and Financial Economics, Central and Eastern European Online Library GmbH, Frankfurt, Germany.
- Sarma, M. (2012). "Index of Financial Inclusion—A measure of financial sector inclusiveness", Competence Centre on Money, Trade, Finance and Development Working Paper No. 07/2012, Berlin.
- Seidman, E., Hababou, M. and Kramer, J. (2005) "Getting to Know Underbanked Consumers: A Financial Services Analysis". Report of the Center for Financial Services Innovation, Chicago.

अनुबंध चुनिंदा संकेतकों के लिए मापी गई असमानता



वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषय -वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	99
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	100
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	101
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	102
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	103
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	103
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	104
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	105
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	106
9	कुल चलनिधि राशियां	106
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	107
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	107
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	108
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	108
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	109
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	110
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	111
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	112
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	113
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	113
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	113
21	थोक मूल्य सूचकांक	114
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	118
	सरकारी खाते और खजाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	118
24	खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	119
25	खजाना बिलों की नीलामी	119
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	120
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	121
28	वाणिज्यिक पत्र	121
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	121
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	122

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
बाह्य क्षेत्र		
31	विदेशी व्यापार	123
32	विदेशी मुद्रा भंडार	123
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	123
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	124
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	124
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	125
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	125
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	126
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	127
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	128
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	129
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	130
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ		
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	131
अवसरिक श्रृंखला		
44	लघु बचत	133
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	134
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	135
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	136
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	137
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	138

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2020-21	2019-20	2020-21		2021-22
		ति4	ति1	ति4	ति1
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	-6.2	3.7	-22.4	3.7	18.8
1.1.1 कृषि	3.6	6.8	3.5	3.1	4.5
1.1.2 उद्योग	-6.4	-3.2	-31.0	5.5	40.4
1.1.3 सेवाएं	-8.4	5.6	-24.9	3.2	16.1
1.1क अंतिम खपत व्यय	-7.3	3.3	-19.9	6.4	13.8
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-10.8	2.5	-46.6	10.9	55.3
	2020-21	2020		2021	
	1	जून	जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-8.4	-16.6	-10.5	13.6	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.4	9.6	11.1	9.8	9.8
2.1.2 ऋण	5.6	5.6	5.7	6.1	6.1
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.5	5.4	5.6	6.1	6.2
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	19.3	18.9	20.8	10.4	8.2
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	18.8	11.8	14.9	16.9	16.8
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	12.2	12.3	13.2	10.7	9.9
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.2	3.7	3.7	4.7	5.0
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.4	73.6	72.6	71.1	70.2
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	37.4	-37.6	-15.0	-56.5	-8.9
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	29.9	30.3	30.1	29.9
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	46.8	122.8	93.1	87.1	41.6
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.40/8.80	7.40/9.00	7.40/9.00	7.40/8.80	7.40/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.55/7.05	6.70/7.45	6.65/7.30	6.55/7.05	6.55/7.00
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	4.90/5.50	5.10/5.65	5.10/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.25	3.54	3.46	3.15	3.21
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.32	3.19	3.30	3.44	3.39
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.47	3.42	3.39	3.72	3.53
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.83	3.54	3.52	3.89	3.73
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.34	5.90	5.78	6.36	6.22
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.40	75.48	74.77	74.18	74.39
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.31	84.63	88.87	88.57	88.39
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	6.80	3.66	3.61	3.80	3.55
3-माह (%)	5.64	3.66	3.74	3.99	3.82
6-माह (%)	5.47	3.82	3.80	4.13	4.01
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.18	6.2	6.7	6.3	5.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.03	5.1	5.3	5.6	5.3
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.29	-1.8	-0.2	12.1	11.2
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.71	-0.1	1.6	7.7	5.7
6.3.2 ईंधन और पावर	-7.99	-16.2	-9.8	32.8	26.0
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.75	0.1	0.6	10.9	11.2
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-17.08	-48.0	-29.6	96.4	63.0
7.2 निर्यात	-7.08	-12.2	-9.9	47.9	49.8

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2020	2021				
			अग.	जुला. 30	अग. 6	अग. 13	अग. 20
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2831727	2654096	2919525	2926858	2933072	2926662	2916737
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	23	15	11	20	14	15
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2831738	2654119	2919541	2926870	2933092	2926676	2916752
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	106555	119425	115119	112985	109752	112108	111366
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2724437	2533943	2803636	2813114	2822587	2813829	2804667
1.2.3 रुपया सिक्का	746	751	786	771	753	739	719
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1504697	1373902	1959069	1966375	2001150	1993740	2011955
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	100	101	101	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	439411	674997	670411	672481	677256	641437
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6529	5183	7455	7624	7184	7287	6682
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3204	2416	3582	3586	3583	3594	3546
2.1.1.7 अन्य बैंक	31820	25785	37177	35695	38005	36012	37424
2.1.1.8 अन्य	895440	897611	1209139	1227275	1250915	1244638	1292462
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	24868	3354	26576	21640	28838	24810	30259
2.1.2 अन्य देयताएं	1343670	1419535	1383256	1361944	1349879	1349702	1318100
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2848367	2793437	3342325	3328319	3351029	3343442	3330055
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	23	15	11	20	14	15
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1204135	1151725	1511979	1500834	1485728	1476363	1435914
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1674	9033	836	7252	10175	9992	3080
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	90275	253645	91796	91620	91750	91804	91806
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	35
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	26422	24803	16731	16772	16772	16772	16772
2.2.3.7 एक्विजि बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	6678	9619	6609	6634	6634	6634	6634
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	24858	2626	26670	21672	28837	23019	28450
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1331671	1186206	1518026	1516983	1546006	1548814	1577196
2.2.6 अन्य आस्तियां	162643	155757	169662	166539	165106	170029	170152
2.2.6.1 सोना	146572	153600	164967	161909	160079	164948	164566

*: डेटा अर्न्तलिप्त है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घावधि रिपो परिचालन&	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालन	विशेष पुनः क्रय रिपो ₹	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12-2-4-7-8-13)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय					
जुला. 1, 2021	-	502074	-	-	2	1865	-	-	-	-	-	-	-	-
जुला. 2, 2021	-	466876	-	200018	121	9	-	-	-	-	-	-	1942	-500207
जुला. 3, 2021	-	39103	-	-	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-668706
जुला. 4, 2021	-	8623	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-37901
जुला. 5, 2021	-	482740	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-8618
जुला. 6, 2021	-	458434	-	-	16	-	-	-	170	-	-	-	-	-482734
जुला. 7, 2021	-	446750	-	-	0	-	-	-	2585	-	-	-	-	-458248
जुला. 8, 2021	-	446463	-	-	0	-	-	-	835	-	-	-	-	-444165
जुला. 9, 2021	-	459911	-	-	1	-	-	-	20775	-	-	-	-	-445628
जुला. 10, 2021	-	2954	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-439135
जुला. 11, 2021	-	1087	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-2914
जुला. 12, 2021	-	450452	-	-	3	-	-	-	950	-	-	-	-	-986
जुला. 13, 2021	-	461868	-	-	0	-9	-	-	340	-	-	-	-	-449499
जुला. 14, 2021	-	455612	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-461537
जुला. 15, 2021	-	510218	-	-	0	-	-	-	-	-	-	750	-	-455612
जुला. 16, 2021	-	463719	-	200022	0	-	-	-	695	-	-	-	3215	-509468
जुला. 17, 2021	-	33346	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-666261
जुला. 18, 2021	-	1504	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-33338
जुला. 19, 2021	-	480515	-	-	0	177	-	-	260	-	-	-	-	-1430
जुला. 20, 2021	-	426537	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-480078
जुला. 21, 2021	-	5774	-	-	5678	-	-	-	-	-	-	-	-	-426537
जुला. 22, 2021	-	445830	-	-	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-96
जुला. 23, 2021	-	451515	-	-	17	-900	-	-	20000	-	-	-	-	-445244
जुला. 24, 2021	-	2982	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-432398
जुला. 25, 2021	-	1293	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-2923
जुला. 26, 2021	-	456260	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-1259
जुला. 27, 2021	-	460374	-	-	0	-600	-	-	-	-	-	-	-	-456260
जुला. 28, 2021	-	470948	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-460974
जुला. 29, 2021	-	515171	-	-	0	5440	-	-	-	-	-	-	-	-470906
जुला. 30, 2021	-	554352	-	200033	254	-	-	-	310	-	-	-	3678	-509731
जुला. 31, 2021	-	80281	-	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-757499
														-79995

टिप्पणी: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), लक्षित दीर्घावधि रिपोपरिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) और मांग के अनुसार लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा लिए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।
 & ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतानकोदर्शाता है।
 ₹ 07 मई, 2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/177 के अनुसार 18 जून, 2021 से, 4 जून 2021 के प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/323 के अनुसार डाटा में राशि शामिल है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	68315	15973	18633	7205
1.1 क्रय (+)	162479	16903	21923	16160
1.2 विक्रय (-)	94164	930	3290	8955
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	510516	119677	138217	54618
3 संघयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	68315	29008	28687	35892
(करोड़ ₹)	510516	217659	213952	268570
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	72751	-379	49573	49010

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	12118	0	550	0
1.2 विक्रय (-)	12118	0	550	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	690	0	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	31 जुलाई 2021 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	7044	910	6134
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	15133	1340	13793
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	42723	13640	29083
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	64900	15890	49010

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2020-21	2020	2021					अग. 27
			अग. 28	मार्च 26	अप्रै. 23	मई 21	जून 18	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	182	300	182	149	494	59	254	2
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	0	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	0	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	-	0	0	0	0	0	0	0
4. अन्य								
4.1 सीमा	75000	65000	75000	75000	60000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	32387	34166	32387	27122	1662	5578	23296	23296
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32569	34466	32569	27271	2156	5637	23550	23298

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्जिम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2020-21	2020	2021		
		जुला. 31	जून 18	जुला. 16	जुला. 30
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2751828	2576293	2886015	2874742	2839340
1.1 संचलन में नोट	2826851	2646131	2961524	2950407	2919525
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	26170	25686	26252	26310	26381
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101935	96267	102504	102717	107309
2 जनता की जमाराशियां	2042471	1688504	1937501	2033890	2017171
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1995120	1648797	1887307	1983975	1971074
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	39707	50194	49915	46097
3 एम₁ (1 + 2)	4794299	4264797	4823516	4908632	4856511
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	150963	150963	150963	150963
5 एम₂ (3 + 4)	4945262	4415760	4974479	5059595	5007474
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	14050278	13361006	14343444	14466513	14515084
7 एम₃ (3 + 6)	18844578	17625803	19166960	19375145	19371595
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	433441	433441	433441	433441
9 एम₄ (7 + 8)	19278019	18059244	19600401	19808586	19805036

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		जुला. 31	जून 18	जुला. 16	जुला. 30
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5609914	5919507	6047015	6052724
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1099686	1078662	1049521	1097776	1116973
1.1.1 सरकार पर दावे	1337300	1184492	1487439	1501408	1517584
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1333917	1179635	1475641	1495581	1516748
1.1.1.2 राज्य सरकारें	3383	4857	11799	5827	836
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	237615	105830	437918	403632	400612
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	237572	105788	437875	403589	400569
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	4750689	4531252	4869986	4949239	4935751
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11668466	10941684	11551357	11591156	11623630
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	8709	11588	5749	9633	8573
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11659757	10930096	11545609	11581523	11615057
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10949509	10282057	10841755	10878497	10910567
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	694758	637599	686279	685393	686559
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	15490	10440	17574	17634	17931
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	4578846	4228164	4813999	4926871	4974997
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4199400	3983510	4434553	4547425	4595551
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4199637	3983748	4434789	4547670	4595795
3.1.2 विदेशी देयताएं	237	238	237	245	244
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	379446	244655	379446	379446	379446
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26429	26995	27053	27124
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3280021	3180389	3144899	3216950	3306880
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1356660	1547264	1349809	1384435	1382828
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1923362	1633125	1795090	1832515	1924052
एम₃ (1+2+3+4-5)	18844578	17625803	19166960	19375145	19371595

डेटा 26 मार्च, 2021 से संबंधित है

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		जुला. 31	जून 18	जुला. 16	जुला. 30
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4794300	4264798	4823516	4908632	4856511
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	11048277	10199512	11209463	11347186	11320264
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	18936051	17727030	19263589	19466298	19463460
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2751828	2576294	2886015	2874742	2839340
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	15892847	14837053	16078299	16291873	16334971
1.2.1 मांग जमाराशियां	1995121	1648797	1887307	1983975	1971074
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13897727	13188255	14190993	14307899	14363897
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6253977	5934715	6385947	6438554	6463754
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	106526	68603	64728	64620
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7643750	7253540	7805046	7869344	7900143
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	39707	50194	49915	46097
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	244025	273977	249080	249767	243052
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	18509287	17550995	18443322	18621703	18659302
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5609914	5919507	6047015	6052725
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1099686	1078662	1049521	1097776	1116973
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	4750689	4531252	4869986	4949239	4935752
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	12658912	11941081	12523815	12574687	12606577
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	34134	36601	7433	21187	25304
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12624778	11904480	12516383	12553500	12581273
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	951313	965520	954871	961213	954631
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26429	26995	27053	27124
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4438202	4087513	4691693	4842792	4818829
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	3983510	4434553	4547425	4595551
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	238802	104003	257140	295367	223278
2.4 पूंजी खाता	2775245	2826533	2972838	3022636	3025200
2.5 अन्य मदें (निवल)	1263105	1111375	925584	1002614	1016596

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2020-21	2020	2021		
	1	जुला.	मई	जून	जुला.
		2	3	4	5
1 एन एम₃	18936051	17727030	19105313	19263589	19463460
2 डाकघर जमाराशियां	433441	433441	433441	433441	433441
3 एल₁ (1 + 2)	19369492	18160471	19538754	19697030	19896901
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	33179	43663	28932	30104	29300
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2645	8425	3563	3563	3563
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	25550	31750	20275	21525	20525
4.3 सावधि जमाराशियां	4984	3489	5094	5016	5212
5 एल₂ (3 + 4)	19402671	18204134	19567685	19727134	19926201
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..
7 एल₃ (5 + 6)	19434576	19759039	..

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020		2021	
		जुला. 31	जून 18	जुला. 16	जुला. 30
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2672560	2988519	2977459	2946649
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	469087	715442	706277	723212
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	651748	435414	669032	660018	674997
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	39707	50194	49915	46097
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3599981	3181354	3754155	3733652	3715957
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	730328	718679	642416	543609	476110
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1099686	1078662	1049521	1097776	1116973
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1096345	1073847	1037765	1091992	1116179
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1333174	1178867	1474980	1494971	1515963
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1333174	1178867	1474980	1494971	1515963
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	743	768	661	610	786
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	237572	105788	437875	403589	400569
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	3340	4815	11756	5784	794
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-403492	-396584	-414538	-666167	-666167
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-378066	-371571	-412854	-563800	-649436
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	34134	36601	7433	21187	25304
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	1	30	1	1	1
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	25426	25013	1684	11554	16731
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26429	26995	27053	27124
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	3983510	4434553	4547425	4595551
2.3.1 सोना	247723	281463	265576	278573	280086
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3951694	3702064	4168994	4268870	4315482
2.4 पूंजी खाता	1173033	1248046	1250419	1286179	1282350
2.5 अन्य मदें (निवल)	183626	299218	99390	98256	100478

सं. 11: रिज़र्व बैंक - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया						
		2020		2021				
		जुला. 31	जून 25	जुला. 2	जुला. 9	जुला. 16	जुला. 23	जुला. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3599981	3181354	3698987	3726510	3702731	3733652	3689321	3715957
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2672560	2980029	2973280	2985406	2977459	2968067	2946649
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	469087	668838	704487	669036	706277	673989	723212
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	39707	50120	48742	48288	49915	47265	46097
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1099686	1078662	1017177	1108633	1070752	1097776	1048409	1116973
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-378066	-371571	-452721	-566299	-559464	-563800	-551457	-649436
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	8709	11588	6048	9632	9642	9633	8828	8573
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	3983510	4467940	4530861	4542137	4547425	4524878	4595551
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26429	27053	27053	27053	27053	27053	27124
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1356660	1547264	1366509	1383370	1387389	1384435	1368390	1382828

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुरुवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020		2021	
		जुला. 31	जून 18	जुला. 16	जुला. 30
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमा राशियां	14960961	13988519	15146092	15355693	15397908
1.1.1 मांग जमा राशियां	1861193	1528034	1751739	1848184	1834965
1.1.2 निवासियों की सावधि जमा राशियां	13099768	12460485	13394353	13507509	13562943
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमा राशियां	5894896	5607218	6027459	6078379	6103324
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	106526	68603	64728	64620
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमा राशियां	7204872	6853267	7366894	7429130	7459619
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	244025	273977	249080	249767	243052
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16368356	15541150	16385812	16499816	16512272
2.1.1 सरकार को ऋण	4461632	4291521	4580580	4656842	4642819
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11906724	11249629	11805232	11842974	11869453
2.1.2.1 बैंक ऋण	10949509	10282057	10841755	10878497	10910567
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10202769	10754843	10792826	10833089
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	13970	9126	16166	11027	11848
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	894	1888	1402	1199	1369
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	942351	956558	945909	952251	945669
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	238802	104003	257140	295367	223278
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	454866	355425	470587	515521	429636
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमा राशियां	152552	172750	152451	158614	151188
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	63512	78672	60996	61540	55170
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1010202	893214	1173216	1315368	1420586
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	542693	435414	669032	660018	674997
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90748	86229	91330	91550	96153
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-376761	-371571	-412854	-563800	-649436
2.4 पूंजी खाता	1578041	1554316	1698248	1712286	1718679
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	834333	721555	722748	792805	796497
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	593095	444792	514490	480712	518434
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	71018	74778	66063	60658	53300

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	26 मार्च 2021 की स्थिति	2020		2021	
		जुला. 31	जून 18	जुला. 16	जुला. 30
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4462526	4293409	4581982	4658042	4644188
2 वाणिज्यिक पत्र	82584	91396	81474	84972	80502
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	9840	11656	10554	10549	10701
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	64035	73007	68931	70250	70371
3.3 अन्य	5210	5201	5125	5168	5162
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	121008	127045	113821	114008	113832
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	308904	308784	321962	318728	315601
4.3 अन्य	149325	152655	153305	150747	149065
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	31142	45359	39269	45662	47220
5.2 वित्तीय संस्थाएं	167130	125695	151480	152166	153215

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2020-21	2020	2021		2020-21	2020	2021	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	209	210	210	210	133	134	134	134
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	259530	310011	240051	244295	254589	304773	235512	239820
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	200585	232324	181695	184989	195866	227270	177399	180794
1.2 बैंकों से उधार राशि	40886	61085	39462	40938	40880	61085	39456	40920
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	18059	16602	18893	18369	17843	16417	18656	18107
2 अन्य के प्रति देयताएं	16457782	15391502	16517473	16803856	16014145	14958717	16078860	16365752
2.1 कुल जमाराशियां	15540152	14576206	15692029	15970330	15113512	14161269	15272352	15549096
2.1.1 मांग	1899343	1563327	1788412	1875358	1861193	1528034	1748636	1834965
2.1.2 मीयादी	13640809	13012879	13903617	14094972	13252320	12633235	13523716	13714131
2.2 उधार	248271	278344	257970	248918	244025	273977	252064	243052
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	669359	536952	567473	584608	656607	523472	554444	573604
3 रिजर्व बैंक से उधार	90275	258425	90829	91796	90275	258425	90829	91796
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	90275	258425	90829	91796	90275	258425	90829	91796
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	650745	536304	732251	790642	633440	521643	713780	771150
4.1 उपलब्ध नकदी	92793	88242	93470	98126	90748	86229	91424	96153
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	557951	448062	638780	692516	542693	435414	622356	674997
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	265729	300944	245133	251829	197541	240022	188930	198368
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	179430	195372	169444	177465	143294	162911	134552	142739
5.1.1 चालू खाते में	16796	23597	16908	20982	14226	21275	14204	18316
5.1.2 अन्य खातों में	162634	171775	152536	156483	129068	141637	120347	124423
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36716	35509	26459	23233	10654	13592	9180	7856
5.3 बैंकों को अग्रिम	19908	25030	21525	23898	16764	24276	19910	23030
5.4 अन्य आस्तियां	29675	45033	27706	27233	26829	39243	25288	24743
6 निवेश	4598924	4421093	4739506	4784826	4462526	4293409	4601130	4644188
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4591896	4412593	4732584	4777342	4461632	4291521	4599956	4642819
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7029	8500	6922	7484	894	1888	1175	1369
7 बैंक ऋण	11297014	10614263	11197090	11248512	10949509	10282057	10859820	10910567
7क खाद्यान्न ऋण	91653	109692	121177	113296	61254	79287	85359	77478
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	11081668	10445518	10996327	11041167	10736491	10115236	10661149	10705239
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	30896	19744	29559	30468	30531	19465	29544	30452
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	128831	105755	116154	124753	127883	104766	114793	123424
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20762	17440	20268	19261	20394	17202	20057	19080
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	34857	25806	34783	32863	34210	25387	34277	32371

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	जून 26, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जुला. 31	जून 18		
	1	2	3	4	2021-22	2021
				%	%	
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	10949509	10282057	10841866	10910416	-0.4	6.1
II. खाद्यान्न ऋण	61254	79288	86912	77478	26.5	-2.3
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10202769	10754953	10832938	-0.5	6.2
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1304301	1172771	1284399	1318024	1.1	12.4
2. उद्योग	2895521	2795788	2867304	2824855	-2.4	1.0
2.1 सूक्ष्म और लघु ¹	383854	357711	375116	386092	0.6	7.9
2.2 मझौले	136054	95249	147875	163401	20.1	71.6
2.3 बड़े	2375613	2342828	2344313	2275362	-4.2	-2.9
3. सेवाएं	2603373	2529848	2600627	2597736	-0.2	2.7
3.1 परिवहन परिचालक	133936	127366	141169	132405	-1.1	4.0
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19179	18843	21006	19192	0.1	1.8
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	47875	45509	49640	48398	1.1	6.3
3.4 शिपिंग	7181	5138	6804	7142	-0.5	39.0
3.5 नौवहन	25643	25012	26440	30351	18.4	21.3
3.6 पेशेवर सेवाएं	104484	105819	112123	97174	-7.0	-8.2
3.7 व्यापार	588934	553332	614336	594351	0.9	7.4
3.7.1 थोक व्यापार	309097	275209	315376	313305	1.4	13.8
3.7.2 खुदरा व्यापार	279837	278123	298960	281046	0.4	1.1
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	270777	262291	232292	262655	-3.0	0.1
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	945383	887625	883851	892226	-5.6	0.5
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	187475	182256	166199	169722	-9.5	-6.9
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78442	33892	77528	78398	-0.1	131.3
3.10 अन्य सेवाएं ³	459983	498913	512966	513843	11.7	3.0
4. व्यक्तिगत ऋण	2856528	2570646	2786519	2858741	0.1	11.2
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8815	8078	7093	9526	8.1	17.9
4.2 आवास	1459346	1346742	1464645	1466762	0.5	8.9
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	62984	55275	65891	59191	-6.0	7.1
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	4454	6237	4430	4453	0.0	-28.6
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	116537	101391	102757	111323	-4.5	9.8
4.6 शिक्षा	64203	65455	62720	62531	-2.6	-4.5
4.7 वाहन ऋण	277748	247868	238214	265951	-4.2	7.3
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	59590	35189	62221	62412	4.7	77.4
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	802852	704412	778548	816592	1.7	15.9
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां ⁴	1264151	1155345	1253199	1260065	-0.3	9.1
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1107236	1096621	1036420	1099061	-0.7	0.2
5.3 मध्यम उद्यम ⁶	206122	122725	188251	209743	1.8	70.9
5.4 आवास	469863	464318	470908	471896	0.4	1.6
5.5 शिक्षा ऋण	48201	51434	47127	46754	-3.0	-9.1
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1171	1016	1321	1230	5.1	21.1
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2352	950	2467	2438	3.7	156.5
5.8 निर्यात ऋण ⁷	19028	15823	19852	21765	14.4	37.6
5.9 अन्य	19062	9277	23860	29024	52.3	212.8
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	813263	771359	832421	775238	-4.7	0.5

टिप्पणी 1: डाटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर-खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल गैर खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।
7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत निर्यात ऋण विदेशी बैंकों से संबंधित हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	26 अप्रै., 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जुला. 31	जून 18	जुला. 30		
	1	2	3	4	%	%
1 उद्योग (2.1 से 2.19)	2895521	2795788	2867304	2824855	-2.4	1.0
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	46050	43535	46544	46885	1.8	7.7
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	153262	148246	164730	151626	-1.1	2.3
1.2.1 चीनी	25519	22993	23210	21248	-16.7	-7.6
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18970	16988	19807	17490	-7.8	3.0
1.2.3 चाय	4273	3994	5692	4493	5.2	12.5
1.2.4 अन्य	104501	104270	116021	108395	3.7	4.0
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	15964	14475	15153	15036	-5.8	3.9
1.4 वस्त्र	200426	188233	202771	201145	0.4	6.9
1.4.1 सूती वस्त्र	90515	85438	88557	85916	-5.1	0.6
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2724	2057	2624	2735	0.4	33.0
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38834	34232	31216	41512	6.9	21.3
1.4.4 अन्य वस्त्र	68353	66505	80374	70982	3.8	6.7
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	10461	10801	11450	10534	0.7	-2.5
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	13179	12690	13543	13451	2.1	6.0
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	35445	32248	36339	36129	1.9	12.0
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन	66908	56471	73299	69299	3.6	22.7
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	192295	176199	179134	182266	-5.2	3.4
1.9.1 उर्वरक	32237	35642	31748	26330	-18.3	-26.1
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	51709	49864	49653	50310	-2.7	0.9
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	45621	35521	40172	41804	-8.4	17.7
1.9.4 अन्य	62727	55171	57561	63822	1.7	15.7
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	54299	49521	54578	57630	6.1	16.4
1.11 कांच और कांच के सामान	6319	6399	9234	6103	-3.4	-4.6
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	54192	60054	50255	47213	-12.9	-21.4
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	328844	338964	299116	293065	-10.9	-13.5
1.13.1 लोहा और स्टील	232928	256919	206361	201179	-13.6	-21.7
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	95916	82045	92755	91886	-4.2	12.0
1.14 सभी अभियांत्रिकी	147506	141655	145635	144818	-1.8	2.2
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	33869	29707	32351	33349	-1.5	12.3
1.14.2 अन्य	113637	111949	113284	111469	-1.9	-0.4
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	83175	87252	84258	87141	4.8	-0.1
1.16 रत्न और आभूषण	62983	55048	60158	61404	-2.5	11.5
1.17 निर्माण	94549	101196	97632	97834	3.5	-3.3
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1092203	1056232	1092381	1081228	-1.0	2.4
1.18.1 पावर	567579	567936	564092	568103	0.1	0.0
1.18.2 दूरसंचार	112119	132022	116239	114138	1.8	-13.5
1.18.3 सड़क	237061	183053	233219	237505	0.2	29.7
1.18.4 हवाई अड्डा	7327	4682	9467	7416	1.2	58.4
1.18.5 बंदरगाह	7363	11330	7700	8851	20.2	-21.9
1.18.6 रेलवे	11260	12197	12346	12909	14.6	5.8
1.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	149495	145012	149318	132305	-11.5	-8.8
1.19 अन्य उद्योग	237461	216569	231094	222047	-6.5	2.5

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2020		2021					
		जून 26	अप्रै. 30	मई 07	मई 21	मई 28	जून 04	जून 18	जून 25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	32	33	33	33	32	32	32
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	125859.6	127063.2	126362.8	125580.8	125356.3	124193.8	123877.1	124724.1	126197.5
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	23736.9	24080.4	24146.6	25794.2	25691.4	27145.3	27140.1	26341.5	26044.7
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	4100.6	5197.4	5245.1	4581.6	5137.8	5381.9	5372.9	4843.0
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	13958.2	14115.6	15351.2	16012.8	15774.7	15694.1	15633.4	16249.1
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	110.0	10.0	184.9	484.9	829.8	817.1	819.8	819.8
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	5911.7	4823.6	5013.1	4612.2	5403.1	5247.0	4515.4	4132.8
2.2 मीयादी देयताएं	179957.5	177717.6	178951.7	173892.5	172963.6	169907.2	168702.8	169090.5	169807.5
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	62430.6	64191.2	61126.2	61084.0	59567.6	58604.0	56839.2	56574.5
2.2.1.2 अन्य	111960.2	113105.0	112247.2	110229.6	109343.5	108419.1	108183.1	109090.7	109948.4
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	630.0	899.9	909.0	909.0	1118.9	1118.9	1308.9	909.2
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	1552.1	1613.3	1627.7	1627.1	801.6	796.8	1851.7	2375.3
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	56196.6	58908.7	49376.1	48100.8	49932.4	50548.8	52195.1	53705.9
4.1 मांग	15691.8	12464.4	11930.6	10425.1	10059.3	11059.3	9937.2	9969.4	10771.0
4.2 मीयादी	47868.0	43732.2	46978.1	38951.0	38041.5	38873.1	40611.6	42225.7	42934.9
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	8151.1	7433.5	8327.7	8073.1	8984.9	9274.1	9264.3	9227.3	8741.5
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	720.9	604.1	607.6	692.6	682.3	612.3	687.4	660.5
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	6712.6	7723.6	7465.5	8292.3	8591.8	8652.0	8539.9	8081.0
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1148.1	2085.3	951.6	1129.6	1170.2	1251.8	1302.7	1226.3	1198.4
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	64455.2	53708.4	65337.4	65921.0	66037.9	67366.8	67041.3	65848.8	67450.1
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	28835.7	29404.9	24534.3	18596.6	21085.4	21768.4	20817.9	20909.6	20762.6
9 बैंक ऋण (10.1+11)	114631.6	111677.9	118073.6	113134.2	126320.1	108118.7	109509.1	106569.9	106339.9
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	114612.1	111674.5	118054.5	113115.0	126301.2	108099.8	109499.7	106569.4	106339.3
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	80858.7	86692.3	81383.2	79921.7	84144.9	83060.6	85015.9	86149.5
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	3.4	19.2	19.3	18.9	18.9	9.4	0.6	0.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
			जुला.	मई	जून (अ)	जुला. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	128.7	127.9	131.6	131.8	134.8
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	121.6	120.6	124.4	124.6	126.0
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.4	108.3	109.6	110.1	114.8
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.1	77.0	76.7	76.4
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	128.0	125.7	128.4	130.1	128.3
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	121.9	121.9	126.2	124.8	123.3
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	128.7	126.9	132.8	134.0	136.2
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	65.2	64.6	66.5	66.2	66.0
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलरों और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण	4.969	117.8	117.3	119.5	119.6	120.5
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	119.4	118.7	119.6	119.6	120.8
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	116.1	115.9	119.4	119.7	120.2
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	126.2	125.6	130.0	129.9	131.1
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.9	158.8	158.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	105.0	105.7	104.1	103.8	103.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	124.7	124.0	129.0	128.9	130.5
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	130.3	128.7	135.9	136.3	136.4
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	128.5	127.4	133.5	132.4	132.3
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	133.2	127.7	146.3	147.5	145.9
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	133.2	127.7	146.3	147.5	145.9
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	132.4	134.1	139.7	138.4	137.0
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	130.5	132.4	138.1	136.7	135.1
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	173.7	166.5	200.4	195.3	203.3
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	132.0	130.9	136.0	136.9	137.8
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	142.4	143.9	148.5	146.8	148.7
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	167.4	167.3	170.7	170.7	171.3
2 खाद्य सूचकांक	24.378	153.4	152.5	158.8	158.6	159.3

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2019-20	2020-21	अप्रैल- जून		जून	
				2020-21	2021-22	2020	2021
				1	2	3	4
सामान्य सूचकांक	100.00	129.0	118.1	84.0	121.8	107.9	122.6
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	109.6	101.0	84.0	107.0	85.7	105.5
1.2 विनिर्माण	77.63	129.6	117.2	77.9	119.7	107.1	121.0
1.3 बिजली	7.99	158.4	157.6	144.1	168.3	156.2	169.1
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	127.0	118.1	102.6	123.8	109.3	122.4
2.2 पूंजीगत माल	8.22	93.3	75.9	35.4	74.4	63.8	80.2
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	137.7	124.7	78.8	133.7	108.2	132.6
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	136.6	124.7	74.5	135.6	114.9	136.8
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.0	101.2	41.1	95.6	78.2	101.7
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.3	142.1	118.5	139.9	147.5	140.8

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - जुलाई			
	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	बजट आकलनों का प्रतिशत	
				2021-22	2020-21
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	1788424	669149	227402	37.4	11.3
1.1 कर राजस्व (निवल)	1545396	529189	202788	34.2	12.4
1.2 करेतर राजस्व	243028	139960	24614	57.6	6.4
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	188000	14148	5458	7.5	2.4
2.1 ऋण की वसूली	13000	5777	5455	44.4	36.4
2.2 अन्य प्राप्तियां	175000	8371	3	4.8	0.0
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	1976424	683297	232860	34.6	10.4
4 राजस्व व्यय	2929000	876012	942360	29.9	35.8
4.1 ब्याज भुगतान	809701	225817	198584	27.9	28.0
5 पूंजी व्यय	554236	128428	111849	23.2	27.1
6 कुल व्यय (4+5)	3483236	1004440	1054209	28.8	34.7
7 राजस्व घाटा (4-1)	1140576	206863	714958	18.1	117.4
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1506812	321143	821349	21.3	103.1
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	697111	95326	622765	13.7	706.6

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020		2021				
		जुला. 31	जून 25	जुला. 2	जुला. 9	जुला. 16	जुला. 23	जुला. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5676	24530	10543	10321	11259	10616	11000	9355
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16740	20849	34544	32265	33597	33955	25219	23157
1.3 राज्य सरकारें	13347	31204	41982	43982	41482	41482	45482	47982
1.4 अन्य	52802	148881	160981	174471	164985	159460	162217	159946
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	67473	159639	127372	128922	129898	125984	120093	119323
2.2 प्राथमिक व्यापारी	30966	58945	58473	62377	57435	56953	57212	54786
2.3 राज्य सरकारें	9436	12972	11839	11945	12945	12945	12945	15355
2.4 अन्य	31800	96263	99532	106713	108976	109807	112205	113457
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	119024	133242	134123	129082	131494	124770	124133	120838
3.2 प्राथमिक व्यापारी	154197	75696	135126	135468	136509	136187	130828	123281
3.3 राज्य सरकारें	18510	12213	17983	17983	17983	17983	18133	19825
3.4 अन्य	174501	126462	97843	98760	89460	90649	89695	94163
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	220351	139180	124998	94156	73175	128742	177522	159116
4.4 अन्य	747	552	685	810	514	1172	422	314
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	694471	900895	930341	952289	936023	920791	909160	901468

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ				स्वीकृत बोलियाँ				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2021-22												
जून 30	15000	110	51656	2001	41	14999	2001	17000	99.15	3.4443		
जुला. 7	9000	93	30758	5706	39	8994	5706	14700	99.15	3.4439		
जुला. 14	9000	108	31343	2311	35	8989	2311	11300	99.15	3.4341		
जुला. 20	9000	105	36181	11204	22	8996	11204	20200	99.15	3.4190		
जुला. 28	9000	107	36504	6532	33	8999	6532	15531	99.16	3.3880		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2021-22												
जून 30	15000	182	44896	894	70	14993	894	15888	98.18	3.7200		
जुला. 7	4000	118	20827	1006	15	3994	1006	5000	98.23	3.6199		
जुला. 14	4000	135	29445	11	18	3989	11	4000	98.24	3.5950		
जुला. 20	4000	127	26568	2	7	3998	2	4000	98.25	3.5624		
जुला. 28	4000	121	26270	2205	18	3995	2205	6200	98.27	3.5298		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2021-22												
जून 30	6000	98	25631	0	28	6000	0	6000	96.27	3.8898		
जुला. 7	4000	114	20681	0	23	4000	0	4000	96.31	3.8419		
जुला. 14	4000	130	25952	0	15	4000	0	4000	96.34	3.8099		
जुला. 20	4000	130	22982	1200	26	4000	1200	5200	96.37	3.7744		
जुला. 28	4000	141	22648	1600	16	4000	1600	5600	96.41	3.7299		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
जुला.	1, 2021	1.90-3.40	3.12
जुला.	2, 2021	1.90-3.40	3.11
जुला.	3, 2021	2.70-3.30	2.90
जुला.	5, 2021	1.90-3.40	3.15
जुला.	6, 2021	1.90-3.40	3.11
जुला.	7, 2021	1.90-3.40	3.13
जुला.	8, 2021	1.90-3.40	3.17
जुला.	9, 2021	1.90-3.40	3.17
जुला.	12, 2021	1.90-3.40	3.20
जुला.	13, 2021	1.90-3.40	3.18
जुला.	14, 2021	1.90-3.40	3.21
जुला.	15, 2021	1.90-3.40	3.19
जुला.	16, 2021	1.90-3.40	3.15
जुला.	17, 2021	2.70-3.40	2.91
जुला.	19, 2021	1.90-3.40	3.21
जुला.	20, 2021	1.90-3.45	3.20
जुला.	22, 2021	1.90-3.40	3.20
जुला.	23, 2021	1.90-3.40	3.20
जुला.	26, 2021	1.90-3.40	3.23
जुला.	27, 2021	1.90-3.40	3.21
जुला.	28, 2021	1.90-3.40	3.18
जुला.	29, 2021	1.90-3.40	3.18
जुला.	30, 2021	1.90-3.45	3.23
जुला.	31, 2021	2.70-3.60	3.04
अग.	2, 2021	1.90-3.40	3.24
अग.	3, 2021	1.90-3.40	3.18
अग.	4, 2021	1.90-3.40	3.17
अग.	5, 2021	1.90-3.40	3.14
अग.	6, 2021	1.90-3.45	3.20
अग.	7, 2021	2.70-3.25	2.92
अग.	9, 2021	1.90-3.40	3.18
अग.	10, 2021	1.90-3.40	3.19
अग.	11, 2021	1.90-3.40	3.22
अग.	12, 2021	1.90-3.45	3.21
अग.	13, 2021	1.90-3.45	3.15

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2020		2021		
	जुला. 31	जून 18	जुला. 2	जुला. 16	जुला. 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	104705.00	68209.42	69299.52	64586.90	64304.10
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	1292.97	6209.13	8817.62	270.74	950.89
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.39-4.45	3.44-4.11	3.44-4.21	3.68-4.21	4.05-4.85

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2020		2021		
	जुला. 31	जून 15	जून 30	जुला. 15	जुला. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	374817.20	404804.90	376117.85	471218.00	414981.65
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	53608.10	73440.40	97928.00	117197.20	149052.15
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.18-12.33	3.36-11.32	3.43-13.03	3.32-12.80	3.38-12.94

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2021						
		जुला. 31	जून 25	जुला. 2	जुला. 9	जुला. 16	जुला. 23	जुला. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17461	23100	13148	11021	12416	14387	14355	13281
2 नोटिस मुद्रा	2604	1192	1009	3090	486	3048	403	3801
3 मीयादी मुद्रा	757	594	568	624	815	326	809	575
4 त्रिपक्षीय रिपो	421118	352688	476714	613769	517546	595711	498517	652552
5 बाजार रिपो	337341	348069	329177	393590	317971	351699	279810	337951
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2990	2112	8737	4750	6960	9508	14177	7200
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	63829	73797	72797	60609	73419	72154	77056
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	62490	73654	43103	36377	46770	45650	57285	40423
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5080	3989	6446	5641	6327	4865	4635	5104
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4970	7702	8852	9720	6772	8347	4268	3883
10.2 182-दिवसीय	4870	2885	3881	6120	4085	4242	3221	3251
10.3 364-दिवसीय	4010	1532	2396	6712	2693	1606	2266	5958
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1490	1603						
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	82910	91365	64678	64570	66647	64709	71676	58619
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	—	367	145	142	5029	654	5251	224

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2020-21		2019-20 (अप्रै-जुला.)		2020-21 (अप्रै-जुला.)*		जुला. 2020		जुला. 2021*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	74	102062	10	69051	32	26117	5	15911	10	13252
1ए प्रीमियम	73	97648	10	66114	30	25523	5	13403	9	13073
1.1 पब्लिक	53	38004	8	15527	24	25378	4	15511	8	13198
1.1.1 प्रीमियम	53	34848	8	13028	24	24905	4	13019	8	13061
1.2 राइट्स	21	64059	2	53524	8	739	1	400	2	54
1.2.1 प्रीमियम	20	62800	2	53085	6	618	1	384	1	13
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	16	5806	5	882	10	5389	1	160	4	1808
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	16	5806	5	882	10	5389	1	160	4	1808
3.2.1 पब्लिक	16	5806	5	882	10	5389	1	160	4	1808
3.2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	90	107868	15	69933	42	31506	6	16071	14	15061
4.1 पब्लिक	69	43809	13	16409	34	30767	5	15671	12	15007
4.2 राइट्स	21	64059	2	53524	8	739	1	400	2	54

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2020-21	2020		2021			
			जुला.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड़ ₹	2154339	177306	252670	228877	236584	239047	264034
	मिलियन अमरीकी डॉलर	291164	23643	34711	30733	32290	32498	35428
1.1 तेल	करोड़ ₹	190749	13263	26199	26955	38973	29588	43626
	मिलियन अमरीकी डॉलर	25784	1769	3599	3620	5319	4022	5854
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	1963591	164042	226471	201922	197611	209459	220408
	मिलियन अमरीकी डॉलर	265379	21874	31112	27114	26971	28475	29574
2 आयात	करोड़ ₹	2909937	213500	352365	340719	282480	308002	345815
	मिलियन अमरीकी डॉलर	393611	28469	48407	45751	38554	41872	46401
2.1 तेल	करोड़ ₹	611353	48975	74768	80962	69253	78532	96100
	मिलियन अमरीकी डॉलर	82684	6531	10271	10871	9452	10676	12895
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2298584	164524	277597	259757	213227	229470	249715
	मिलियन अमरीकी डॉलर	310927	21939	38135	34880	29102	31196	33507
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-755597	-36194	-99695	-111842	-45896	-68955	-81781
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-102447	-4826	-13696	-15018	-6264	-9374	-10973
3.1 तेल	करोड़ ₹	-420605	-35712	-48569	-54007	-30280	-48944	-52473
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-56900	-4762	-6672	-7252	-4133	-6654	-7041
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-334993	-482	-51126	-57836	-15615	-20011	-29308
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-45547	-64	-7024	-7766	-2131	-2720	-3933

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2020		2021				
		अग. 28	जुला. 23	जुला. 30	अग. 6	अग. 13	अग. 20	अग. 27
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड़ ₹	3973733	4549373	4617303	4610155	4599392	4588475	4669426
	मिलियन अमरीकी डॉलर	541431	611149	620576	621464	619365	616895	633558
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड़ ₹	3655683	4225412	4287317	4285737	4280124	4261979	4212584
	मिलियन अमरीकी डॉलर	498094	567628	576224	577732	576374	573009	571600
1.2 स्वर्ण	करोड़ ₹	273025	274565	280086	274894	269831	277056	275932
	मिलियन अमरीकी डॉलर	37200	36884	37644	37057	36336	37249	37441
	मात्रा (मैट्रिक टन)	668.25	708.38	711.18	711.18	718.64	722.37	724.24
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1048	1087	1087	1087	1087	1087	13657
	करोड़ ₹	10868	11506	11545	11503	11464	11461	143028
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1481	1546	1552	1551	1544	1541	19407
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड़ ₹	34158	37891	38355	38022	37973	37979	37883
	मिलियन अमरीकी डॉलर	4657	5091	5156	5125	5111	5096	5110

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2020-21	2020	2021		2020-21	2021-22
		जुला.	जून	जुला.	अप्रै.-जुला.	अप्रै.-जुला.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	141895	135092	141529	141786	4332	3122
1.1 एफसीएनआर (बी)	20473	22467	19699	19599	-1777	-874
1.2 एनआर (ई) आरए	102579	96076	102920	102989	5550	3138
1.3 एनआरओ	18842	16549	18910	19198	559	858

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020-21	2021-22	2020	2021	
		अप्रै.-जुला.	अप्रै.-जुला.	जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43955	3056	13433	3584	-692	2235
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	54927	6367	19565	4261	1405	2920
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	81973	16918	27373	5078	4179	4820
1.1.1.1.1 इक्विटी	61088	10064	20868	3167	2777	2966
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	948	107	112	10	39	2
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक	51597	7200	12983	1539	2088	2373
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7091	2305	7320	1500	538	473
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1452	453	453	118	112	118
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	16935	5280	5280	1372	1303	1372
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3950	1574	1225	539	100	482
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	27046	10552	7808	817	2775	1900
1.1.1.2.1 इक्विटी	26983	10540	7562	815	2739	1746
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	63	12	246	2	35	154
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	10972	3311	6131	678	2096	685
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5583	1655	2960	419	587	635
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3013	1004	1004	251	251	251
1.1.2.3 अन्य पूंजी	6688	1121	3145	332	1448	295
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	4313	469	979	325	190	496
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	36137	1114	-2667	472	465	-1600
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	38725	1816	-990	718	995	-1149
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2589	702	1677	246	530	451
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	80092	4170	10766	4056	-227	635

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020	2021		
		जुला.	मई	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	12684.40	995.16	1250.24	1232.22	1308.47
1.1 जमाराशियां	680.37	48.43	68.20	64.32	46.93
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	62.75	5.03	7.85	10.02	6.89
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	471.80	33.84	52.19	66.91	50.21
1.4 उपहार	1586.24	129.75	149.38	178.21	175.22
1.5 दान	12.59	1.42	1.95	1.59	0.78
1.6 यात्रा	3239.67	246.17	294.02	277.65	346.91
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2680.10	243.61	237.27	241.57	243.23
1.8 चिकित्सा उपचार	29.75	2.54	2.57	2.52	2.88
1.9 विदेश में शिक्षा	3836.12	277.50	429.73	380.23	423.35
1.10 अन्य	85.03	6.87	7.07	9.20	12.07

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2019-20	2020-21	2020	2021	
			अग.	जुला.	अग.
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	98.00	93.92	93.48	93.19	93.77
1.2 रीर	103.20	103.46	103.04	104.43	104.80
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.38	93.59	93.10	92.75	93.32
2.2 रीर	102.88	102.96	102.51	103.64	104.05
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.92	88.47	88.15	86.62	87.14
1.2 रीर	103.60	101.78	101.19	101.93	102.69
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.78	93.93	93.59	91.97	92.51
2.2 रीर	103.30	101.49	100.90	101.64	102.39

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2020-21	2020	2021	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1063	96	87	80
1.2 राशि	26799	848	1485	3034
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	13	2	-	1
2.2 राशि	8456	1300	-	400
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1076	98	87	81
3.2 राशि	35255	2148	1485	3434
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.03	8.03	5.12	9.23
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.93	2.40	1.75	2.44
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-13.00	0.00-10.29	0.00-10.25	0.00-10.50

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जन.-मार्च 2020			जन.-मार्च 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2419902	2283860	136042	2449502	2424800	24702
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1137275	1133238	4037	1263718	1323202	-59484
1.1 पण्य	553933	807581	-253649	665312	969572	-304260
1.2 अदृश्य मर्चे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	583342	325657	257686	598406	353629	244776
1.2.1 सेवाएं	384069	224629	159441	408194	237025	171170
1.2.1.1 यात्रा	49657	30461	19197	16819	22896	-6077
1.2.1.2 परिवहन	36311	41701	-5390	44312	41058	3254
1.2.1.3 बीमा	4512	3081	1430	4719	4125	594
1.2.1.4 जीएनआईई	1316	2057	-741	1158	1759	-601
1.2.1.5 विविध	292273	147329	144944	341186	167187	173999
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	168546	15631	152914	195350	24250	171099
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	83051	86341	-3290	97117	93634	3484
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7410	9092	-1682	9166	10220	-1054
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4567	2532	2035	5073	2905	2168
1.2.2 अंतरण	148962	15774	133188	152529	15199	137330
1.2.2.1 आधिकारिक	189	2167	-1978	129	2074	-1945
1.2.2.2 निजी	148773	13607	135166	152400	13125	139275
1.2.3 आय	50311	85253	-34942	37682	101406	-63724
1.2.3.1 निवेश आय	39977	80198	-40221	25637	96153	-70517
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10333	5055	5278	12045	5252	6793
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1276212	1150622	125590	1185784	1096418	89366
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	721222	734119	-12897	788594	716008	72586
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	151075	64481	86594	112193	92670	19523
2.1.1.1 भारत में	139378	29459	109919	99699	57788	41911
2.1.1.1.1 इक्विटी	100781	29401	71380	62338	57537	4801
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	27305	0	27305	32935	0	32935
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	11292	58	11234	4427	251	4176
2.1.1.2 विदेश में	11697	35022	-23324	12493	34882	-22389
2.1.1.2.1 इक्विटी	11697	15253	-3556	12493	8726	3767
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5702	-5702	0	5490	-5490
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	14067	-14067	0	20666	-20666
2.1.2 संविभाग निवेश	570147	669638	-99491	676402	623338	53063
2.1.2.1 भारत में	557238	663952	-106714	674196	614505	59691
2.1.2.1.1 एफआईआई	557238	663952	-106714	674196	614505	59691
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	435547	480491	-44945	593588	537019	56569
2.1.2.1.1.2 ऋण	121691	183461	-61770	80608	77487	3122
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	12909	5686	7223	2206	8833	-6628
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	198653	126862	71791	192758	136479	56279
2.2.1 बाह्य सहायता	14475	10277	4198	39212	10111	29101
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	71	153	-82
2.2.1.2 भारत को	14461	10076	4385	39141	9958	29183
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	118476	43648	74828	86255	41978	44276
2.2.2.1 भारत द्वारा	14351	7622	6729	4975	5433	-459
2.2.2.2 भारत को	104125	36026	68099	81280	36545	44735
2.2.3 भारत को अल्पावधि	65702	72938	-7236	67291	84390	-17099
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	65702	70397	-4695	58799	84390	-25591
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	2541	-2541	8492	0	8492
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	160037	193379	-33343	121962	154215	-32253
2.3.1 वाणिज्य बैंक	159220	193379	-34160	120397	154215	-33818
2.3.1.1 आस्तियां	34842	73992	-39151	30186	58112	-27927
2.3.1.2 देयताएं	124378	119387	4991	90211	96103	-5892
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	121926	101911	20016	82726	86651	-3925
2.3.2 अन्य	817	0	817	1565	0	1565
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	50	-50	0	50	-50
2.5 अन्य पूंजी	196301	96212	100089	82471	89666	-7196
3 भूल-घूक	6415	0	6415	0	5180	-5180
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	136042	-136042	0	24702	-24702
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	136042	-136042	0	24702	-24702

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2020-21		2020				2021	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	193929	482208	182957	418234	190857	480190	193929	482208
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	122726	456947	118442	395426	122489	454603	122726	456947
1.2 अन्य पूंजी	71203	25261	64515	22809	68368	25587	71203	25261
2 संविभाग निवेश	6436	281842	3847	246700	5527	274032	6436	281842
2.1 इक्विटी	840	177278	602	134778	1732	170630	840	177278
2.2 ऋण	5596	104563	3246	111922	3795	103402	5596	104563
3 अन्य निवेश	80897	446867	52412	427500	69382	438780	80897	446867
3.1 व्यापार ऋण	5644	100342	1460	104271	3196	102598	5644	100342
3.2 ऋण	13335	190382	6731	179834	10610	183983	13335	190382
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42436	142069	26011	130761	37343	140683	42436	142069
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19482	14074	18210	12634	18234	11516	19482	14074
4 रिज़र्व्स	576984		477807		585771		576984	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	858246	1210917	717023	1092434	851536	1193002	858246	1210917
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-352671		-375411		-341466		-352671

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक
भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2020-21	2020	2021		वि. व 2020-21	2020	2021	
	1	जुला.	जून	जुला.	5	जुला.	जून	जुला.
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	27.97	2.52	2.90	2.68	161943141	14102229	17144527	16798812
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	11.55	1.22	1.01	0.98	110634315	9407660	11317988	11096031
1.1.1 आउटराईट	6.28	0.73	0.51	0.50	10032187	1146554	774292	744621
1.1.2 रेपो	2.84	0.29	0.27	0.25	43751173	4098668	4653921	3802644
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.43	0.20	0.23	0.24	56850956	4162438	5889775	6548766
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	16.04	1.28	1.82	1.64	48903961	4544294	5408999	5290626
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.38	0.02	0.07	0.07	2404865	150275	417541	412155
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	1591.92	124.76	154.14	167.65	105599849	8335279	10196989	10741314
1.1 ग्राहक लेनदेन	1573.47	123.22	152.92	166.43	91008367	7137945	8887546	9288984
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	18.45	1.55	1.22	1.22	14591482	1197334	1309444	1452331
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	317851.82	21832.34	36684.40	41367.43	33522150	2587356	3029728	3214817
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	11.32	0.86	1.06	1.03	623	45	64	61
2.2 एपीबीएस \$	14372.99	1182.38	1148.34	1045.01	112747	8976	8143	7952
2.3 आईएमपीएस	32783.47	2220.99	3038.45	3524.64	2941500	225775	284111	311310
2.4 एनएसीएच जमा \$	16449.51	1053.54	1498.12	1171.72	1232714	98909	92266	85307
2.5 एनईएफटी	30927.89	2401.03	2923.27	3170.00	25130910	1963113	2097771	2204303
2.6 यूपीआई @	223306.64	14973.54	28075.16	32455.02	4103658	290538	547373	605883
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	10.45	0.91	1.03	1.08	172	15	16	16
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	10440.40	855.71	981.70	986.32	872399	68356	86759	86503
3.1 भीम आधार पे @	160.84	15.96	17.66	17.49	2580	216	417	414
3.2 एनएसीएच नामे \$	9629.61	801.08	878.73	877.08	868906	68083	86215	85980
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	649.96	38.67	85.31	91.75	913	56	128	109
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	57786.60	4481.59	4493.75	5225.86	1291799	95883	113790	135972
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	17641.06	1319.66	1547.01	1820.49	630414	45558	62746	74885
4.1.1 पीओएस आधारित \$	8688.81	601.63	690.40	900.27	280769	20107	23977	30498
4.1.2 अन्य \$	8952.25	718.03	856.61	920.21	349645	25451	38769	44387
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.2)	40145.54	3161.93	2946.74	3405.37	661385	50325	51044	61087
4.2.1 पीओएस आधारित \$	20773.50	1461.94	1505.09	1901.64	377630	25821	28743	36764
4.2.2 अन्य \$	19372.04	1699.99	1441.65	1503.73	283755	24504	22300	24324
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	49392.29	3987.42	4586.00	4959.07	197696	15521	18780	20806
5.1 वॉलेट	39987.01	3205.59	3911.95	4079.19	152065	12892	16088	17053
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	9405.28	781.83	674.05	879.89	45631	2629	2692	3753
5.2.1 पीओएस आधारित \$	437.33	24.49	44.69	63.24	11639	628	552	683
5.2.2 अन्य \$	8967.95	757.34	629.36	816.64	33992	2002	2140	3070
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6703.70	532.38	511.38	596.11	5627189	434072	477430	553256
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6702.53	532.24	511.38	596.11	5625941	433799	477430	553256
6.2 अन्य	1.17	0.14	-	-	1249	272	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	442174.81	31689.45	47257.22	53134.79	41511233	3201188	3726486	4011354
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	443766.73	31814.21	47411.36	53302.44	147111082	11536467	13923476	14752668
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	437063.03	31281.83	46899.98	52706.33	141483892	11102395	13446046	14199411

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2020	2021		वि. व. 2020-21	2020	2021	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	255451.57	17281.26	32127.11	37458.94	9179707	637489	1033735	1149340
1.1 इंटर-बैंक \$	25166.33	1574.10	2829.58	3134.21	1869837	130568	196264	210636
1.2 इंटर-बैंक \$	230231.22	15707.16	29297.53	34324.73	7308472	506921	837471	938704
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	32493.63	2673.76	2703.44	3048.81	41581497	3251167	3468711	3710473
2.1 इंटर-बैंक @	6886.15	582.31	545.84	606.23	20601554	1595612	1501184	1625684
2.2 इंटर-बैंक @	25607.48	2091.45	2157.60	2442.58	20979943	1655556	1967527	2084788
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	60905.81	4687.45	4761.61	5378.72	2889826	232074	229633	254880
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	51.41	3.29	4.31	4.74	2560	167	219	235
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	60602.23	4664.96	4735.38	5348.70	2878025	231210	228681	253780
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	252.17	19.20	21.91	25.28	9240	697	734	865
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	394.77	33.57	7.87	7.45	1533	136	59	62
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	353.50	30.67	7.03	6.15	1484	132	44	43
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	41.27	2.90	0.84	1.30	49	3	15	19
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	9460.43	743.41	856.89	869.89	225420	17469	24187	22973
5.1 ईपीएस @	9460.43	743.41	856.89	869.89	225420	17469	24187	22973

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021 तक	2020	2021	
		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9602.51	9099.87	9688.24	9694.51
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	576.32	628.15	634.14
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8523.55	9060.08	9060.36
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	21952.60	19272.63	22947.96	23388.31
2.1 वॉलेट @	20052.10	17749.31	20864.68	21244.36
2.2 कार्ड @	1900.51	1523.32	2083.28	2143.95
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.39	2.34	2.40	2.40
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.14	2.10	2.14	2.13
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.25	0.24	0.26	0.27
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	4.04	3.06	4.54	4.75
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	47.20	43.57	45.93	46.08
6 भारत क्यूआर @	35.70	22.37	49.33	51.23
7 यूपीआई क्यूआर *	925.22	-	1018.26	1070.08

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2019-20	2019	2020		
		1	नवं	सितं.	अक्टू	नवं
			2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	159573	14106	15218	12857	11446
	बकाया	1078535	999208	1155063	1167887	1179309
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	116389	10876	11962	9626	8378
	बकाया	734807	681695	796745	806371	814749
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	25893	1881	3061	1319	1130
	बकाया	166140	147007	184681	186000	187130
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	36	80	-23	52	-15
	बकाया	3143	3015	3070	3122	3107
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-1	823	-3	-11	-3
	बकाया	9	809	0	-11	-14
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16510	1584	1401	1151	841
	बकाया	209168	201707	214935	216086	216927
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	20334	1706	2032	1851	1569
	बकाया	76042	67394	85480	87331	88900
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41795	3625	4278	3658	3066
	बकाया	166087	148326	184793	188451	191517
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	92618	84270	100944	102272	103207
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7097	6637	7269	7276	7295
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7536	7262	7447	7422	7384
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	58836	50157	69133	71481	73631
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	11821	1177	1216	1606	1789
	बकाया	114222	113441	123790	125396	127185
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	1	0	0	0	1
	बकाया	-25	-25	-25	-25	-24
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	30170	2580	3010	3030	2850
	बकाया	252190	237586	265147	268144	270970
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	19495	1717	1361	1448	1411
	बकाया	117987	107778	124488	125936	127347
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-101	0	-3	0	0
	बकाया	162	-289	159	159	159
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18168	-1090	-821	-603	-561
	बकाया	1135	7753	-3288	-3891	-4452
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	28972	1953	2473	2185	2000
	बकाया	122602	111248	133676	135861	137861
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-4	0	0	0	0
	बकाया	-155	-179	-155	-155	-155
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-24	0	0	0	0
	बकाया	-106	-82	-106	-106	-106
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10565	11357	10373	10340	10316
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	13014	650	246	201	218
	बकाया	91538	79927	93171	93372	93590

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियों हैं। अर्थात् सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020			2021	
	जून	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	6704983	7137069	7357111	7635902	7882533
1. वाणिज्य बैंक	38.98	38.55	37.81	37.77	35.99
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.36	0.34	0.25	0.27	0.34
3. बीमाकृत कंपनियां	26.24	25.33	25.64	25.30	25.83
4. म्यूच्युअल फंड	2.02	2.42	2.62	2.94	2.82
5. सहकारी बैंक	1.86	1.86	1.83	1.82	1.82
6. वित्तीय संस्थाएं	1.19	1.42	1.00	1.00	1.43
7. कॉरपोरेट	0.78	0.94	1.05	1.06	1.39
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	1.79	2.05	2.10	1.87	1.79
9. भविष्य निधियां	4.96	4.77	4.61	4.44	4.04
10. भारतीय रिजर्व बैंक	14.70	15.00	15.71	16.20	17.11
11. अन्य	7.11	7.32	7.37	7.33	7.43
11.1 राज्य सरकार	1.99	1.86	1.76	1.69	1.67

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2020			2021	
	जून	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	3393099	3564979	3721573	3879982	4028849
1. वाणिज्य बैंक	33.54	34.60	34.19	33.69	33.75
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.74	0.54	0.36	0.48	0.39
3. बीमाकृत कंपनियां	30.85	30.26	30.25	30.04	29.67
4. म्यूच्युअल फंड	1.74	1.96	1.92	1.82	1.74
5. सहकारी बैंक	4.38	4.19	4.11	4.05	4.12
6. वित्तीय संस्थाएं	1.96	1.92	1.88	1.86	1.79
7. कॉरपोरेट	0.31	0.39	0.45	0.49	1.45
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	21.70	21.31	21.20	22.00	21.09
10. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.81	0.77	0.88
11. अन्य	4.78	4.80	4.82	4.77	5.10
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

खजाना बिल					
श्रेणी	2020			2021	
	जून	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	881362	982286	839729	690646	901327
1. वाणिज्य बैंक	46.11	53.50	54.75	55.54	52.25
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.48	2.16	1.65	2.82	1.82
3. बीमाकृत कंपनियां	4.64	4.06	4.50	5.61	4.75
4. म्यूच्युअल फंड	23.45	19.90	18.98	17.80	19.93
5. सहकारी बैंक	1.95	1.63	1.61	2.43	1.60
6. वित्तीय संस्थाएं	1.67	1.34	1.11	1.24	2.56
7. कॉरपोरेट	1.43	1.63	2.01	3.16	3.00
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.05	0.00	0.09	0.22	0.10
10. भारतीय रिजर्व बैंक	11.27	4.80	0.68	0.49	2.58
11. अन्य	7.95	10.99	14.63	10.70	11.42
11.1 राज्य सरकार	4.35	7.76	13.27	5.98	7.97

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	3760611	4265969	4515946	5040747	5875914	6470254
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
2. कुल प्राप्तियां	3778049	4288432	4528422	5023352	5779396	6524526
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	952410	1064704	997097	1102729	1408183	1409995
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमा राशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जुला. 2021 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	464	23	2095	22	2192	14
2	अरुणाचल प्रदेश	0		0		0	
3	असम	0		0		0	
4	बिहार	0		0		0	
5	छत्तीसगढ़	901	14	0		0	
6	गोवा	94	14	68	13	0	
7	गुजरात	0		0		0	
8	हरियाणा	0		0		0	
9	हिमाचल प्रदेश	0		295	4	0	
10	जम्मू और कश्मीर	0		876	24	404	7
11	झारखंड	0		0		0	
12	कर्नाटक	0		0		0	
13	केरल	96	1	111	1	0	
14	मध्य प्रदेश	0		0		0	
15	महाराष्ट्र	0		0		0	
16	मणिपुर	0		264	31	155	15
17	मेघालय	80	7	80	5	0	
18	मिज़ोरम	0		100	13	0	
19	नगालैंड	58	31	140	14	0	
20	उड़ीसा	0		0		0	
21	पुदुचेरी	42	1	0		0	
22	पंजाब	249	2	0		0	
23	राजस्थान	0		0		0	
24	तमिलनाडु	0		0		0	
25	तेलंगाना	580	19	1455	19	2910	14
26	त्रिपुरा	0		0		0	
27	उत्तराखंड	0		0		0	
28	उत्तरप्रदेश	127	5	148	1	0	
29	पश्चिम बंगाल	0		0		0	

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जुला. 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8816	870	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1792	3	0	0
3	असम	4054	58	0	0
4	बिहार	5961	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	4988	0	1	4550
6	गोवा	653	330	0	0
7	गुजरात	5221	509	0	0
8	हरियाणा	827	1287	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
11	झारखंड	479	0	0	0
12	कर्नाटक	6155	0	0	12000
13	केरल	2276	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	976	0	0
15	महाराष्ट्र	44885	674	0	17500
16	मणिपुर	163	107	0	0
17	मेघालय	771	44	9	0
18	मिजोरम	374	48	0	0
19	नगालैंड	1750	35	0	0
20	उड़ीसा	11927	1556	90	25433
21	पुदुचेरी	325	0	0	1109
22	पंजाब	1430	0	8	0
23	राजस्थान	0	0	129	4450
24	तमिलनाडु	7072	0	40	17520
25	तेलंगाना	6028	1315	0	0
26	त्रिपुरा	398	10	0	600
27	उत्तराखंड	988	0	180	0
28	उत्तरप्रदेश	3466	135	0	0
29	पश्चिम बंगाल	9471	617	214	0
	कुल	130269	8573	670	83162

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22						2021-22 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	मई		जून		जुला.		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	42415	33444	50896	41915	6000	5417	6000	5420	3750	2242	17750	14379
2	अरुणाचल प्रदेश	1366	1287	767	767	-	-	-	-	-	-	400	400
3	असम	12906	10996	15030	14230	-	-	-	-	500	500	500	500
4	बिहार	25601	22601	27285	24685	2000	2000	2000	2000	4000	4000	8000	8000
5	छत्तीसगढ़	11680	10980	13000	10500	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000
6	गोवा	2600	2000	3354	3054	-	-	300	300	200	200	500	500
7	गुजरात	38900	28600	44780	33280	-	-1000	4500	3500	3000	2000	7500	4500
8	हरियाणा	24677	20677	30000	25550	5000	4000	5000	5000	-	-	10000	7200
9	हिमाचल प्रदेश	6580	4460	6000	3755	-	-	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	7869	6760	9328	6020	400	400	1700	1000	-	-	2600	1900
11	झारखंड	7500	5656	9400	8900	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	48500	42500	69000	61900	-	-	-	-	-	-	-	-
13	केरल	18073	12617	28566	23066	1500	1500	7500	7500	-	-	9000	9000
14	मध्य प्रदेश	22371	16550	45573	38773	-	-	-	-	2000	2000	2000	2000
15	महाराष्ट्र	48498	32998	69000	50022	13500	13500	10500	10500	5750	3750	29750	27750
16	मणिपुर	1757	1254	1302	1044	-	-	200	200	200	200	600	600
17	मेघालय	1344	1070	1777	1587	-	-100	200	200	-	-	400	300
18	मिज़ोरम	900	745	944	677	150	150	-	-	100	100	250	100
19	नगालैंड	1000	423	1721	1366	-	-	250	150	-	-	600	500
20	उड़ीसा	7500	6500	3000	500	-	-	-	-	-	-1000	-	-1500
21	पुदुचेरी	970	470	1390	790	-	-	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	27355	18470	32995	23467	-	-800	3500	1850	1200	-100	4700	-650
23	राजस्थान	39092	24686	57359	44273	4000	3500	8500	7500	3100	3100	19600	18100
24	सिक्किम	809	481	1292	1292	500	500	-	-	-	-	500	500
25	तमिलनाडु	62425	49826	87977	76796	12000	11000	12000	10500	8000	6500	32000	28000
26	तेलंगाना	37109	30697	43784	37365	3500	3083	8500	8080	3000	1908	16500	14071
27	त्रिपुरा	2928	2578	1916	1631	-	-100	-	-50	-	-	-	-150
28	उत्तराखंड	69703	52744	75500	59185	-	-2500	5000	4000	7500	6000	12500	7500
29	उत्तरप्रदेश	5100	4500	6200	5208	-	-	700	700	500	300	1200	500
30	पश्चिम बंगाल	56992	40882	59680	50180	2000	-	8500	5500	5500	3500	16000	5827
	कुल	634521	487454	798816	651777	50550	40550	84850	73850	49300	36200	193850	150827

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

o जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते हैं।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाजारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2021	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिक्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001। एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए।**
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।